कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विदेश दौरे हमेशा विवाद में होते हैं। ताजा ताजा अमेरिका के दौरे पर गए राहुल गांधी के बयानों ने विवाद पैदा कर दिया है। उन्होंने चीन पर, सिखों पर, आरक्षण पर, बेरोजगारी पर, भाजपा व संघ पर ऐसे बयान दिए, जिससे उनकी आलोचना हो रही है। उन्होंने अमेरिका की भारत विरोधी डेमोक्रेटिक सांसद इल्हान उमर से मुलाकात कर जता दिया है कि उन्हें भारत राष्ट्र की छवि की बिल्कुल परवाह नहीं है। इल्हान हमेशा कश्मीर और खालिस्तान को अलग देश बनाए जाने वाली मांग का समर्थन करती रही हैं। अमेरिका में राहुल ने कहा, 1. चीन उत्पादन में सबसे आगे, भारत बहुत पीछे है, 2. भारत में कुशल लोगों का सम्मान नहीं है, 3. भारत में सिखों को पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं है, 4. समान अवसर मिलने पर आरक्षण खत्म करेंगे, 5. भारत में कौशल का सम्मान नहीं होने के चलते बेरोजगारी है, 6. संघ व भाजपा एक तरह के लोगों का भारत चाहते हैं। यह पहली बार नहीं है, जब विदेश की धरती पर राहुल ने विवादित बयान दिए हैं। 2017 में अमेरिका दौरे पर राहुल ने भारत में बढ़ती हिंसक घटनाओं को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा था। अगस्त 2018 में लंदन में कहा था कि आरएसएस की सोच अरब देशों की मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी है। इसी वर्ष सिंगापुर में भाजपा पर बांटने की राजनीति का आरोप लगाया। 2018 में ही जर्मनी व मलेशिया की यात्रा के दौरान मॉब लिंचिंग व नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार को घेरा। 2019 में चुनाव से पहले मेडिटेशन टूर पर कंबोडिया चले गए थे। इसी वर्ष सीएए आंदोलन के बीच दक्षिण कोरिया चले गए। मई 2022 में ब्रिटेन में सीबीआई-ईडी की पाक से तुलना की। मई 2023 में अमेरिका दौरे पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। इसी वर्ष ब्रिटेन में पेगासस जासूसी मुद्दे को उठाया। अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी के विवादित बयानों की हो रही आलोचना पर आजकल का यह अंक...

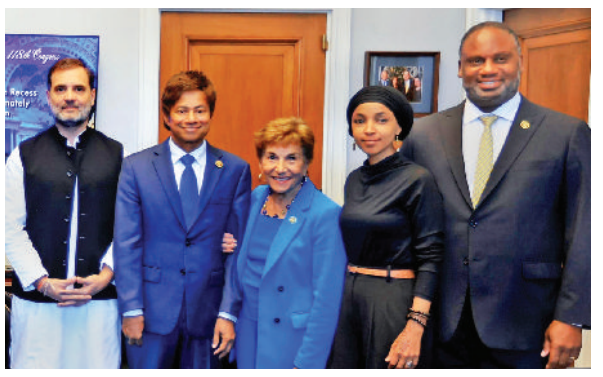

विरोध के अतिवाद में राष्ट्र की छवि खराब न करें राहुल

विश्लेषण

अवधेश कुमार

वरिष्ठ पत्रकार

लोकसभा में विपक्ष का नेता या संवैधानिक दायित्व निभाने वाला कोई व्यक्ति क्या अपने सार्वजनिक वक्तव्यों के बारे में कह सकता है कि यह उस पद का नहीं, मेरा निजी विचार है क्योंकि मैं अपने अंदर दो चरित्र लेकर चलता हूं? राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कुछ बोला, उसे लेकर कांग्रेस के परंपरागत नेताओं में भी असहजता और परेशानी है। देश का नेता विदेश की भूमि पर जाकर यह कहे कि हमारे देश में चारों ओर भय का माहौल है, धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, अल्पसंख्यकों व समाज के पिछड़ों व वंचित वर्गों के विरुद्ध हिंसा हो रही है, विरोधी राजनेताओं को जेल में डाला जा रहा है, भारत की विविधताओं को समाप्त किया जा रहा है तो इसका अर्थ क्या लगाया जाए?

राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर मचा बवंडर बिल्कुल स्वाभाविक है। तीन दिनों की अमेरिका यात्रा में उनके द्वारा दिए गए वक्तव्यों और मुलाकातों के अनेक अंश ऐसे थे जिन पर सम्पूर्ण भारत को आपत्ति होनी चाहिए। विपक्ष का नेता बनने के बाद राहुल गांधी के लिए पहली विदेश यात्रा में विदेश में देश के हितों के प्रति सतर्क एवं उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करने वाले नेता की छवि निर्मित करने का महत्वपूर्ण अवसर था। ओवरसीज कांग्रेस ऑफ इंडिया के प्रमुख सैम पित्रोदा ने कह दिया था कि यह राहुल गांधी की विपक्ष के नेता के रूप में नहीं बल्कि निजी यात्रा है। क्या लोकसभा में विपक्ष का नेता या संवैधानिक दायित्व निभाने वाला कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक वक्तव्यों के बारे में कह सकता है कि उस पद का नहीं, मेरा निजी विचार है क्योंकि मैं अपने अंदर दो चरित्र लेकर चलता हूं? राहुल गांधी ने अमेरिका में जो कुछ बोला, उसे लेकर कांग्रेस के परंपरागत नेताओं में भी असहजता और परेशानी है। भारत का नेता विदेश की भूमि पर जाकर यह कहे कि हमारे देश में चारों ओर भय का माहौल है, धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है, एक संगठन समूह को छोड़कर अन्यों को अपने मजहब, पंथ, संप्रदाय, भाषा के अनुसार और वेशभूषा के साथ निकलने या महत्वपूर्ण जगहों पर प्रवेश करने तक पर खतरा है, अल्पसंख्यकों तथा समाज के पिछड़ों व वंचित वर्गों के विरुद्ध हिंसा हो रही है, विरोधी राजनेताओं को जेल में डाला जा रहा है तथा भारत की विविधताओं को समाप्त किया जा रहा है तो इसका अर्थ क्या लगाया जाए ?

विदेश में भारत की डरावनी तस्वीर पेश

जब उनका कार्यक्रम पहले से तय था तो उन्हें क्या बोलना है इनका निर्धारण भी पहले हो गया होगा। यही बात मुलाकातों के संदर्भ में भी है। हालांकि 2017 से उनकी राजनीतिक विदेश यात्राएं हो रही हैं और अभी तक के उनके वक्तव्य को देखें तो आपको हैरत नहीं होगी। हर यात्रा में उन्होंने विश्व समुदाय के समक्ष भारत की एक झूठी डरावनी तस्वीर पेश की है। वे लगातार कहते रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद आरएसएस का सारी संस्थाओं पर कब्जा है, हम विविधता को मानते हैं, वे एकरूपता के लिए सत्ता की ताकत का उपयोग कर रहे हैं। इसी में वे जोड़ते रहे हैं कि समाज में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और उनके विचार से असहमत होने वालों को हिंसा, प्रताड़ना और अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर विरोधी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। संपूर्ण मीडिया पर कब्जा है और हमारे पास अपनी बात रखने के मंच नहीं हैं। लगभग ये ही बातें थोड़ी अलग या समान शब्दावलियों में उन्होंने इस बार भी बोला है। पिछले चुनाव में मोदी सरकार संविधान खत्म कर देगी, आरक्षण समाप्त कर देगी मनगढ़ंत नैरेटिव का असर उन्हें दिखा इसलिए ये विषय भी प्रमुखता से उठाया। पिछले वर्ष की अमेरिका यात्रा में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कहा था कि जब हमारे पास अपनी बात रखने या जनसंवाद करने का कोई माध्यम नहीं बचा तो हम जनता के बीच यात्रा पर निकल पड़े। इस बार अंतर इतना था कि उन्होंने बताया कि लोगों ने समझा है और चुनाव परिणाम ने इसे साबित किया है। अब नरेंद्र मोदी से लोग डर नहीं रहे, सवाल पूछ रहे हैं और उनका (पीएम मोदी) आत्मविश्वास खत्म हो गया है। वैसे यह बात भारत में वह बोल चुके थे।

मोदी सरकार का विरोध या भारत का

राहुल गांधी के रणनीतिकार, सलाहकार, थिंक टैंक सब प्रफुल्लित होंगे क्योंकि जैसा वे चाहते थे राहुल गांधी पूरी तरह तैयार होकर देश के साथ विदेश में भी उतर चुके हैं। किंतु यह भूल गए कि एक बार आपने देश की छवि विदेशों में खराब कर दी तो यह केवल मोदी सरकार के लिए नहीं संपूर्ण भारत के लिए समस्या और चुनौती बनेगा। कल्पना करिए, जो संस्थाएं उभरते और खड़ा होते हुए भारत को रोकने के लिए झूठी रिपोर्ट के आधार पर विश्व के निरंकुश, अभिव्यक्ति और धार्मिक स्वतंत्रता का दमन करने वाले देशों की सूची में डालने की वकालत कर रहे हैं, उनके लिए तो राहुल गांधी को उद्धृत कर अपनी बात की पुष्टि करना ज्यादा आसान हो जाएगा। उनकी मुलाकातों की सूची में हमने भारत विरोधी और यहां तक कि भारत के विरुद्ध अमेरिकी कांग्रेस में मतदान करने वाली इल्हान उमर की चर्चा है, किंतु पूरी सूची में ऐसे ही लोग थे जो अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, मानवाधिकारों आदि के नाम पर भारत विरुद्ध अभियान चलाते रहे हैं। इनमें पाकिस्तान समर्थक हैं। कोई विदेशी नेता पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का भाग नहीं मानता, कश्मीर में जनमत संग्रह की आवाज उठाता है तथा अमेरिका में भारतीयों के लिए वीजा नियमों को आसान करने वाले विधायक के विरुद्ध मतदान करता है, उसका हमारे देश के किसी नेता के साथ खड़ा होने का अर्थ क्या है ? यह मोदी सरकार का विरोध है या भारत का?

कार्यक्रम में उठाया तथ्यहीन मुद्दा

यह कल्पना नहीं की जा सकती कि कोई नेता अपने कार्यक्रम में इस सीमा तक चला जाएगा कि एक सम्मानित सिख को उठाकर बोलेगा कि लड़ाई इस बात की है कि एक सिख पगड़ी या कड़ा पहनकर कहीं आ-जा सकते हैं या नहीं। यह सिर्फ एक रिलिजन के लिए नहीं बल्कि सभी रिलिजन के लिए है। हालांकि जिस सिख व्यक्ति का नाम पूछ कर उन्होंने यह टिप्पणी की उन भालिंदर सिंह वीरमानी ने कहा कि इस मुद्दे में कोई भी तथ्य मौजूद नहीं है। मैं इसे पहनकर बेझिझक भारत जा सकता हूं। वहां आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उसे पगड़ी और कड़ा पहनने का हक नहीं मिला हो। भालिंदर सिंह ने कहा कि राहुल गांधी 15 -20 मिनट बोलने के बाद बाहर चले गए और हमें उनसे प्रश्न करने का मौका नहीं मिला अन्यथा मैं पूछना चाहता था कि आखिर आपसे किसने कहा है कि ऐसी आजादी नहीं है। क्या वजह, कोई खास एजेंसी है या खास लोग हैं जिन्होंने बातें बताई है? तो जिस अमेरिकी सिख बंधु से उन्होंने सवाल किया, वही असहज हो गया। सिख समुदाय के कुछ मुट्ठी भर अलगाववादी अराजक तत्व दुनिया में यही बात फैला रहे हैं। खालिस्तान की मांग सिखों की धार्मिक आजादी की मांग से जोड़कर अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम जैसे देशों में सिख फॉर जस्टिस या ऐसे दूसरे समूह बीच-बीच में भारत को परेशान करने वाली गतिविधियां करते हैं। ये देश को बदनाम करते रहते हैं।

यह व्यवहार हर दृष्टि से अस्वीकार्य

क्या राहुल गांधी को पता नहीं कि इन तत्वों ने ही भारतीय दूतावास आदि पर हमले किए और महात्मा गांधी तक की मूर्ति को अपमानित किया? लंदन स्थित उच्चायोग में भारतीय तिरंगे को अपमानित किया। सिख फॉर जस्टिस के संचालक और भारत में वांछित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने राहुल गांधी के बयानों को हाथों-हाथ लिया और कहा कि यही तो हम कह रहे थे, आज राहुल गांधी ने इसकी पुष्टि कर दी। दुनियाभर के सिख अलगाववादी समूह राहुल के इस वक्तव्य का उपयोग कर अपने को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। भारत सरकार सभी देशों के साथ कड़ाई से इन तत्वों पर अंकुश लगाने की बात करती रही है। राहुल गांधी ने भारत का पक्ष कमजोर किया। इसका डरावना पहलू यह है कि इसका किंचित भी लाभ उठाकर इन तत्वों ने पंजाब में गड़बड़ी पैदा की तो क्या होगा? हाल के समय में पंजाब के अंदर अलगाववादी गतिविधियों के साथ हिंसा फैलाने के प्रमाण मिले हैं, उग्रवादी गिरफ्तार हुए हैं। भारत की एकता-अखंडता तथा विश्व में इसके प्रभाव बढ़ने, सम्मान मिलने के प्रति समर्पित नेता विदेशी भूमि पर ऐसी बातें नहीं कर सकता। आपको आरएसएस, भाजपा से मतभेद है तो देश के अंदर प्रकट कर सकते हैं। उसमें भी राहुल गांधी अतिवाद में जा रहे हैं जो हमारे अंदर ही तनाव और हिंसा बढ़ाने तथा उथल-पुथल मचाने की क्षमता रखता है। क्या राहुल गांधी का एजेंडा सामान्य राजनीति में कांग्रेस को मजबूत करने और सरकार बनाने तक सीमित नहीं है? अपने देश के बारे में ऐसे दुष्प्रचार उथल-पुथल और हिंसा के द्वारा सत्ता पर कब्जा करने वाले वामपंथी किया करते थे। वो देश व राज्य की भौगोलिक सीमाओं या आंतरिक एकता जैसे राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय भाव आदि को खारिज करते थे और संपूर्ण विश्व में केवल एकवर्गीय व्यवस्था का सपना देखते थे। कम्युनिस्ट देशों में उन्हें शरण मिलती था और वहां से अपने देश के विरुद्ध अभियान चलाते थे, लोगों को सत्ता के विरुद्ध हिंसक विद्रोह के लिए भड़काते थे।

भारत के पक्ष में खड़े होने की अपेक्षा

राहुल गांधी संसदीय लोकतंत्र के अंदर क्या लक्ष्य चाहते हैं, इसे समझने के लिए शोध की आवश्यकता है। संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक-वैचारिक मतभेद देश की भौगोलिक सीमाओं के अंदर हैं। सीमा से निकलते ही हर व्यक्ति भारतीय है और उससे भारत के पक्ष में खड़े होने की अपेक्षा है। यह व्यवहार हर दृष्टि से अस्वीकार्य है तथा इसका विरोध होना चाहिए। वैसे उनकी बातों का तथ्यों से खंडन संभव है और अपने देश से प्रेम करने वाले को इसके विरोध में आना चाहिए।

राहुल का बयान कांग्रेस के लिए मुसीबत

सियासत

रवि शंकर

वरिष्ठ पत्रकार

हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी चकल्लस के बीच अमेरिका में सिख और आरक्षण पर विवादित बयान देकर राहुल गांधी ने कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है। राहुल गांधी का हालिया अमेरिका दौरा खासा चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है, क्योंकि वे इस बार नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार विदेश दौरे पर गए। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में चुनाव की प्रक्रिया चल रही हैं। ऐसे में राहुल के बयानों के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। राहुल के आरक्षण वाले बयान पर जहां सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, वहीं सिख वाले बयान को लेकर समुदाय से जुड़े संगठनों में आक्रोश है। हरियाणा में 20 प्रतिशत दलित और पांच प्रतिशत सिख समुदाय की आबादी है।

चुनाव में हो सकता है नुकसान

कहा जा रहा है कि अमेरिका में दिया गया राहुल का बयान अगर भारत में तूल पकड़ता है तो हरियाणा के दंगल में कांग्रेस के साथ खेल भी हो सकता है। हालांकि, ये पहली बार नहीं है, जब विदेश में दिए गए अपने बयानों की वजह से राहुल गांधी कांग्रेस के चुनावी परफॉर्मेंस के लिए पनौती साबित हुए हैं। इससे पहले भी कांग्रेस को कई बार राहुल गांधी के बयानों से नुकसान उठाना पड़ा है। इसे राहुल गांधी का स्वभाव कहें या उनकी अनिच्छा या आंतरिक कलह, इसे कुछ भी कहें लेकिन इसका नुकसान भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी को लगातार उठाना पड़ रहा है।

पद लेने से बचते रहे हैं राहुल

नेहरू-गांधी परिवार की पांचवीं पीढ़ी का नेतृत्व राहुल गांधी करते हैं, वो परिवार के छठे सदस्य हैं जिन्होंने कांग्रेस संगठन की अध्यक्षता की है। 139 साल की कांग्रेस में नेहरू-गांधी परिवार के सदस्य 51 साल तक अध्यक्ष रहे हैं जिसमें सोनिया गांधी सबसे लंबे समय तक 22 सालों तक अध्यक्ष रहीं। जवाहरलाल नेहरू 11 सालों तक एआईसीसी के प्रमुख रहे, इंदिरा गांधी सात साल, राजीव गांधी छह साल और मोतीलाल नेहरू दो सालों तक इसके अध्यक्ष रहे। राहुल एआईसीसी के 87वें अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल 16 महीनों से भी कम था, वो दिसंबर 2017 से लेकर मई 2019 तक इसके प्रमुख रहे। अहम बात ये है कि राहुल गांधी 2004 में चुनावी राजनीति में आए और तब से कोई भी पद लेने से बचते रहे थे। यहां तक कि उन्होंने पार्टी प्रमुख के पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया था। बता दें, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद वे पहली बार कोई संवैधानिक पद लिया है और लोकसभा में विपक्ष के नेता बने हैं।

ऐसे बयानों से बचना होगा

खैर, राहुल गांधी 55 साल के हो गए हैं। अगर वो ख़ुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर और मज़बूत करना चाहते हैं तो उन्हें देश के अंदर या विदेश में ऐसे बयान देने से बचना होगा जो उनके व्यक्तित्व और पार्टी की छवि पर सवालिया निशान खड़ा करता हो। सामान्य समझ तो यही कहती है कि कोई सफाई देने का लोड तभी लेता है जब लगे कि ऐसा नहीं किया तो बात बिगड़ सकती है। नुकसान का डर नहीं हो तो सफाई की कौन सोचता है भला? राहुल की तरफ से सफाई

आना अपने आप में सबूत है कि आरक्षण पर उन्होंने जो कहा है, उससे कम-से-कम उनके 'चैंपियन' की छवि को बट्टा लगने का डर तो जरूर था। संभवतः यही कारण है कि राहुल गांधी ने बाद में अपने बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण को समाप्त करने के बारे में नहीं सोच रही है। उलटे वे देश में आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और सामाजिक समरसता लाने के लिए आरक्षण की 50 फीसदी की सीमा को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। इसे कांग्रेस का 'डैमेज कंट्रोल' माना जा रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने एक बयान में आरक्षण की समीक्षा किए जाने की बात कह दी थी। कहा जाता है कि भागवत के इस बयान के कारण बिहार में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ।

अपनी बढ़त खो सकती है कांग्रेस

यदि कांग्रेस इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती तो उसे भी इसका नुकसान होने वाले विधानसभा चुनावों में हो सकता है। ज्ञात है, पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने संविधान का मुद्दा उठाकर ही ओबीसी, दलित और आदिवासी मतदाताओं के बीच अपनी पैठ बनाई है। यदि वे इस मामले को नहीं संभाल पाती है तो उसे इस बढ़त को भी खोना पड़ सकता है। इसे देखते हुए ही कांग्रेस के सीनियर नेता तुरंत पार्टी का पक्ष रखने के लिए सामने आ गए। खैर,गौर करने वाली बात ये है कि पहले देश की राजनीति में इस तरह के कई उदाहरण मौजूद थे जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग विदेश की धरती पर अपने देश की बात नहीं करते थे और ना ही किसी की निंदा करते थे।

प्रतिद्वंद्वियों की निंदा का ट्रेंड

पहले विदेश में देश की छवि को लेकर राजनीतिक दल एक हो जाया करते थे। याद कीजिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने तब विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को संयुक्त राष्ट्र भेजा था ताकि भारत के पक्ष को मज़बूती से रख पाएं। पहले विदेश में सत्ता और विपक्ष के नेता एक ही बोली बोलते थे।

खुद बतौर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इसका अनुसरण करते हुए कभी सोनिया गांधी तो कभी सलमान ख़ुर्शीद को भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश भेजा जबकि वो विपक्ष में थे। लेकिन अब न सिर्फ़ विपक्ष के नेता, बल्कि सत्ता पक्ष के लोग भी विदेशी दौरों के दौरान अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की आलोचना करने से चूकते नहीं है। बीते एक दशक में इसका ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। 2014 में जब पीएम मोदी शासन में आए, तो उन्होंने कई बार विदेशी धरती पर कांग्रेस के शासनकाल और उसके प्रधानमंत्रियों की निंदा की। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में सत्ता पक्ष के नेता भी विदेशों में जाकर देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु की आलोचना करते हुए कहते रहे हैं कि पिछले 60 सालों में भारत में कुछ नहीं हुआ था और जो कुछ हो रहा है या हुआ है वो सिर्फ़ बीजेपी की सरकार बनने के बाद संभव हो पाया है। इसलिए अगर राजनीतिक शिष्टाचार खत्म हुआ है, तो उसके लिए दोनों ही पक्ष दोषी है, किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

विदेश में देश की साफ छवि रहे

साफ है अब भारत में लोकतंत्र शोरशराबे वाला बनने की राह पर है। सोशल मीडिया हो या एक दूसरे की व्यक्तिगत आलोचना हो। राजनीति का अब यही स्वरूप उभर रहा है जिसमें मर्यादा की सीमा की कोई गुंजाइश ही नहीं नज़र आती है। इसलिए सतापक्ष के साथ विपक्षी पाटियों के नेताओं को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे कोई भी आंतरिक मुद्दों को विदेशी धरती पर न उठाया जाए जिससे देश की छवि खराब हो।

कांग्रेस राज में ही पिछड़ा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र

दो टूक

शंभू भद्र

वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार

शायद राहुल गांधी को भी लगने लगा है कि राष्ट्र निर्माण वर्ष 2014 में ही शुरू हुआ है। अपनी तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा के दौरान जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत में मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति पर 'ज्ञान' बांच रहे थे, तो लग रहा था मानो भारत के औद्योगिक विकास के आर्किटेक्चर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा राष्ट्र निर्माण की बुनियाद रखने के लिए किए गए औद्योगिक कार्यों को भी नकार रहे थे। मोदी सरकार की ओर से किए गए नीतिगत बदलाव व मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में किए कार्यों का विरोध करने में कांग्रेस सांसद भूल ही गए कि भारत आजादी के वक्त से ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है। इस दिशा में देश की तकरीबन सभी दलों की सरकारों ने काम किया है। एचएएल, सेल, भेल, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, एचपी, बीपी, टाटा, टिस्को, बिड़ला, महिंद्रा समेत एक हजार से अधिक बड़ी सरकारी व निजी कंपनियां हैं, जो विनिर्माण में योगदान दे रही हैं। सूक्ष्म, लघु व मध्यम (एमएसएमई) कंपनियां तो देश में छह करोड़ से अधिक हैं। आज भारत टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल समेत कई क्षेत्रों में बहुत आगे है।

कांग्रेस सरकार की नीतिगत चूक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार आने के बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति जरूर मिली है। पर कांग्रेस सरकार ने दो महत्वपूर्ण अवसर गंवाए। अस्सी के दशक में जब ब्रिटेन व अमेरिका में डॉटकॉम क्रांति हो रही थी, तब भारत में कांग्रेस सरकार मूकदर्शक बनी हुई थी, डिजिटल सेक्टर में बड़ा निवेश नहीं किया, भविष्य की अर्थव्यवस्था को नजरअंदाज किया, नहीं तो आज भारत सर्च इंजन के लिए गूगल का उपभोक्ता नहीं होता। भारत के पास भी अपनी सर्च इंजन कंपनी होती। सिलिकॉन वैली भारत में होती। निजी क्षेत्र के प्रयासों से भारत सॉफ्टवेयर सेक्टर में सुपरपावर जरूर बना, लेकिन कांग्रेस नेताओं में दूरदर्शिता के अभाव के चलते डिजिटल सेक्टर में पिछड़ गया। डिजिटल सेक्टर की यह कमी मोदी सरकार पूरी कर रही है।

कांग्रेस सरकार की दूसरी चूक उदारीकरण अपनाने के वक्त हुई, जब भारत ने अपना बाजार खोला, उस वक्त विश्व के बाजार भी खुले। उस समय अगर सरकार अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तेजी से बढ़ावा देती, तो आज राहुल गांधी को यह नहीं कहना पड़ता कि मैन्युफैक्चरिंग में चीन भारत से बहुत आगे है। पीवी नरसिम्हाराव सरकार की शिथिलता के चलते उदारीकरण के दौर में भारत केवल विश्व का उपभोक्ता ही बना, निर्यात का खिलाड़ी नहीं बना। कांग्रेस सरकार की दो अवसरों पर नीतिगत चूक ने मैन्युफैक्चरिंग में भारत को पीछे धकेल दिया।

मोदी सरकार बदल रही तस्वीर

नरेन्द्र मोदी की सरकार देश में मैन्युफैक्चरिंग की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रही है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ब्रांड भारत, आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया, पीएलआई स्कीम, मुद्रा योजना आदि अभियान से मोदी के नेतृत्व वाली राजग

सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती दे रही है। यह सरकार अर्थव्यवस्था को ग्लोबल जरूरतों के हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर रही है। सरकार चीन से आयात पर निर्भरता कम कर रही है। सरकार जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर- रेल, रोड, एयरपोर्ट, पोर्ट, सी-रिवर रूट को विश्वस्तरीय बना रही है, वहीं ग्रीन हाइड्रोजन, सौर ऊर्जा, बायो एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सेक्टर (एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, आईओटी, रोबोटिक्स) आदि नए सेक्टर को पीएसयू (पब्लिक सेक्टर यूनिट) व निजी स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है। सरकार डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है, वह एग्रीटेक, फिनटेक और नैनोटेक को भी आगे बढ़ा रही है। मोदी सरकार की उदार नीति के चलते ही हाल के वर्षों में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां चीन से भारत शिफ्ट हो रही हैं।

मात्र मोदी सरकार का विरोध

भारत डिजिटल भुगतान में वैश्विक रिकार्ड बना रहा है। राहुल गांधी भारत में हो रहे इस बदलाव को नहीं देख रहे होंगे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि उन्हें मोदी सरकार का विरोध करना है, इसलिए अमेरिका में भी अपने ही नए भारत की विकास यात्रा को शर्मिंदा करने में भी गुरेज नहीं करते हैं। अमेरिका में राहुल गांधी ने कहा कि भारत में मैनुफैक्चरिंग सेक्टर की हालत खराब है। तो क्या उन्होंने कभी सोचा कि ऐसी हालत कब से हुई, क्यों हुई? अगर पूर्व की कांग्रेस सरकार ने 80, 90 के दशक में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान दिया होता तो चीन की तरह भारत में भी रोजगार की कमी नहीं होती। वर्ष 2014 से पीएम मोदी की राजग सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट दे रही है। राहुल गांधी ने अगर भारत के मैनुफैक्चरिंग इतिहास का अध्ययन किया होता तो अमेरिका में अनभिज्ञ सरीखे कतई नहीं बोलते। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले ज्यादातर उत्पाद हाथ से बने होते थे। भारत हुनर की वैश्विक राजधानी था। लकड़ी का कोयला जलाकर लोहा बनाने की पहली कोशिश 1830 में तमिलनाडु में हुई थी। 1868 में जमशेदजी टाटा ने टाटा ग्रुप शुरू किया। आजादी के बाद (1951-91) पंचवर्षीय योजना लाकर भारत ने उद्योगों पर फोकस किया। 1956 में औद्योगिक नीति बनाई गई। इससे लोहा, स्टील, भारी इंजीनियरिंग और फर्टिलाइजर उद्योग तेजी से बढ़े। हालांकि, कांग्रेस सरकार में लाइसेंस राज व करप्शन के कारण औद्योगिक विकास की रफ्तार सुस्त रही। उदारीकरण के दौर में भारत वैश्विक उत्पादों का डंपिंग ग्राउंड बन रहा था।

मोदी सरकार ने पैटर्न को तोड़ा

पीएम मोदी की सरकार ने इस पैटर्न को तोड़ा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर मैनुफैक्चरिंग के वैक्यूम को भरना शुरू किया। पीएलआई स्कीम, एफडीआई नियम में ढील, बेकार कानूनों का खात्मा, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी, मुद्रा योजना आदि से मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में जान फूंकी गई। जीडीपी में 17 फीसदी हिस्सेदारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की है। आईबीईएफ की रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2022 से जून 2024 के बीच भारत की मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री में 40 फीसदी की वृद्धि हुई है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 2014 से 2024 के बीच मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में 165 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी निवेश आया, जबकि, 2004 से 2014 के बीच 98 अरब डॉलर का एफडीआई आया था। यूपीए के दस वर्ष की तुलना में एनडीए के दस वर्ष में मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में एफडीआई में 69 फीसदी की वृद्धि हुई। भारत ने 2025 तक 5 अरब डॉलर के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है। मोदी सरकार अगले पांच साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर में 11 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च करने जा रही है। राजनीति अपनी जगह रहे, लेकिन विपक्ष के नेता भी देश के विकास की वैश्विक ब्रांडिंग करें। इससे भारत एक सुलझा हुआ एकीकृत व शक्तिशाली राष्ट्र बनकर उभरेगा।

संस्कृति के नैतिक विकास का सबसे ऊंचा स्तर तब आता है, जब हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लें।

- चार्ल्स डार्विन

चांद का काला चेहरा

दूसरी नजर

पी चिदंबरम

मणिपुर संदेह, छल और जातीय संघर्ष के जाल में फंसा हुआ है। मणिपुर में शांति बनाए रखना और सरकार चलाना कभी आसान नहीं था। भाजपा द्वारा संचालित केंद्र सरकार की लापरवाही और राज्य सरकार की अक्षमता के कारण यह अकल्पनीय रूप से बदतर हो गया है।

पिछले स्तंभों को पलटते हुए, देखा कि मणिपुर के बारे में मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, इसके लिए खुद को कोसा। मैंने आखिरी बार 30 जुलाई, 2023 को मणिपुर पर लिखा था। अब उसे तेरह महीने से ज्यादा हो गए हैं। यह अक्षम्य है। यह उन सभी भारतीयों के लिए भी बिल्कुल माफ करने लायक नहीं है, जिन्होंने मणिपुर को अपनी सामूहिक चेतना के सबसे गहरे अंधेरे कोने में दबा दिया है।

जब मैंने पिछले वर्ष लिखा था, तो संकेत अशुभ थे। मैंने कहा था, 'यह नस्ली सफाए की शुरुआत है'। मैंने कहा था 'आज, मुझे जो भी रपटें मिली हैं या पढ़ी हैं, उनमें इंफल घाटी में व्यावहारिक रूप से कोई कुकी-जोमी नहीं रह गया है और कुकी-जोमी के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में कोई मैतेई नहीं बचा है'। मैंने कहा था कि 'मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अपने घर से दफ्तर के काम करते हैं और प्रभावित क्षेत्रों की यात्रा नहीं करते या नहीं कर सकते हैं'। मैंने यह भी कहा था कि 'कोई भी जातीय समूह मणिपुर पुलिस पर भरोसा नहीं करता' और 'कोई भी हताहतों की आधिकारिक संख्या पर विश्वास नहीं करता है'।

कठघरे में तीन

मैंने जो कुछ लिखा था, दुर्भाग्य से उसका एक एक शब्द सच साबित हुआ। संसदीय लोकतंत्र में, मणिपुर की इस दुखद स्थिति के लिए, एक या उससे अधिक सत्ताधीशों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यहां तीन ऐसे लोग का जिक्र जरूरी है, जो सत्ता में हैं-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीः उन्होंने संकल्प लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे मणिपुर का दौरा नहीं करेंगे। उनका रवैया ऐसा लगता है कि 'मणिपुर को जलने दो, मैं मणिपुर की धरती पर कदम नहीं रखूंगा'। 9 जून, 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से, प्रधानमंत्री ने इटली (13-14 जून), रूस (8-9 जुलाई), आस्ट्रिया (10 जुलाई), पोलैंड (21-22 अगस्त), यूक्रेन (23-24 अगस्त), ब्रुनेई (3-4 सितंबर) और सिंगापुर (4-5 सितंबर) की यात्रा करने का समय निकाला। 2024 के बाकी बचे महीनों के लिए भी उनके कार्यक्रम तय हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका, लाओस, समोस, रूस, अजरबैजान और ब्राजील की यात्राएं शामिल हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा, समय या ऊर्जा की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए नहीं किया है, क्योंकि वे इस बदकिस्मत राज्य का दौरा करना ही नहीं चाहते हैं।

मणिपुर का दौरा करने से उनका इनकार, उनकी जिद का सबूत है। गुजरात दंगों, सीएए विरोधी प्रदर्शनों और तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी हमें इसकी झलक मिली थी और तब भी जब उन्होंने अपने मंत्रियों को संसद के दोनों सदनों में सभी स्थगन प्रस्तावों का विरोध करने का निर्देश दिया था- चाहे वह कोई भी जरूरी मामला रहा हो।

गृहमंत्री अमित शाहः मणिपुर के शासन से जुड़े हर पहलू पर उनके निर्देश शामिल होते हैं, चाहे वह राज्य सरकार में वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति से जुड़ा मामला हो या सुरक्षा बलों की तैनाती का। वे मणिपुर सरकार का हिस्सा हैं। उनके कार्यकाल में हिंसा तेजी से बढ़ी है। मणिपुर के लोग सिर्फ बंदूकों और बमों से एक-दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं। स्वतंत्र भारत में पहली बार राकेट और हथियारबंद ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। पिछले एक हफ्ते में दो जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्कूल और कालेज बंद कर दिए गए हैं, पांच जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है और इंफल की सड़कों पर पुलिस छात्रों से लड़ रही है। मणिपुर में पहले से तैनात 26,000 कर्मियों को मजबूत करने के लिए सीआरपीएफ की दो और बटालियन (2000 पुरुष और महिलाएं) भेजी गई हैं।

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंहः वे अपनी ही बनाई जेल में बंदी हैं। वे और उनके मंत्री इंफल घाटी में भी कहीं नहीं जा पा रहे हैं। कुकी-जोमी उनसे नफरत करते हैं। मैतेई लोगों ने सोचा था कि वे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, लेकिन उनकी पूरी तरह से विफलता ने उन्हें मणिपुर में सबसे अलोकप्रिय व्यक्ति बना दिया है, जिसमें मैतेई भी शामिल हैं। प्रशासन का कोई नामोनिशान नहीं है। उनका अयोग्य और पक्षपातपूर्ण शासन नागरिक अशांति का कारण बना। अब वे खुद एक समस्या हैं और सभी पक्षों के लिए उकसावे का कारण बन रहे हैं। उन्हें कई महीने पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनका पद पर बने रहना मोदी साहब और शाह साहब के निरंकुश, कभी अपनी गलती न मानने वाले रवैये को दर्शाता है।

वास्तव में विभाजित

मणिपुर वास्तव में दो राज्य है। चूड़ाचांदपुर, फेरजवाल और कांगपोकपी जिले पूरी तरह से कुकी लोगों के नियंत्रण में हैं, और तेंग्नौपाल जिला (जिसमें सीमावर्ती शहर मोरेह भी शामिल है) जिसमें कुकी-जोमी और नगा की मिश्रित आबादी है, व्यावहारिक रूप से कुकी-जोमी के नियंत्रण में है। कुकी-जोमी एक अलग प्रशासन चलाते हैं। कुकी-जोमी नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी मैतेई सरकारी कर्मचारी नहीं है; वे घाटी के जिलों में बसे हुए हैं। कुकी-जोमी ऐसे राज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहते, जहां मैतेई बहुमत में हों (60 सदस्यों वाले सदन में 40 विधायक)। मैतेई मणिपुर की पहचान और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं। समुदायों के बीच दुश्मनी का स्तर बहुत ऊंचा और गहरा है।

किसी के बीच कोई बातचीत नहीं है- सरकार और जातीय समूहों के बीच या मैतेई और कुकी-जोमी के बीच। नगा लोगों की केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक शिकायतें हैं और वे मैतेई बनाम कुकी-जोमी संघर्ष में उलझना नहीं चाहते।

कहीं कोई रोशनी नहीं

मणिपुर संदेह, छल और जातीय संघर्ष के जाल में फंसा हुआ है। मणिपुर में शांति बनाए रखना और सरकार चलाना कभी आसान नहीं था। भाजपा द्वारा संचालित केंद्र सरकार की लापरवाही और राज्य सरकार की अक्षमता के कारण यह अकल्पनीय रूप से बदतर हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री को शायद यह एहसास हो गया है कि संघ के एक राज्य, मणिपुर की उनकी यात्रा चंद्रमा के अंधेरे पक्ष की यात्रा जितनी खतरनाक होगी।

कभी चुप भी रहें

वक्त की नब्ज

तवलीन सिंह

दे शद्रोह का आरोप इतनी आसानी से लगाते हैं मोदी भक्त कि जैसे राष्ट्रवाद का ठेका लेने का अधिकार सिर्फ उनको है। सोचने की तकलीफ नहीं करते हैं ये लोग कि उनको किसी ने हक नहीं दिया है फैसला करने का कि देशद्रोही कौन हैं और देशभक्त कौन। गांधी परिवार को निशाना काफी दिनों से बनाए रखा है मोदी भक्तों ने, लेकिन हाल में मैंने देखा है कि उनकी इस मुहिम में एक नई चीज दिखने लगी है : घबराहट।

कभी-कभी समझना मुश्किल है कि राहुल गांधी मदद करते हैं मोदी सरकार की या मोदीजी के मंत्री मदद कर रहे हैं राहुल गांधी की। बात कर रही हूं नेता प्रतिपक्ष की हाल में हुई विदेश यात्रा की। राहुल गांधी अक्सर जब विदेश गए हैं पिछले दस वर्षों में, कुछ न कुछ ऐसी बात कर आते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ इस्तेमाल करती है। पिछले दौरों में उन्होंने कई उल्टी-सीधी बातें कही हैं, जैसे कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो चुका है और इसको दुबारा जीवित करने के लिए पश्चिमी लोकतांत्रिक राजनेताओं की मदद चाहिए। इस बार उनकी पहली विदेश यात्रा थी बतौर नेता प्रतिपक्ष, इसलिए मैंने सोचा समझदारी से बातें करेंगे। मिलेंगे ऐसे लोगों से, जो भारत के दुश्मन न हों, ताकि उनके दौरे का गंभीरता से विश्लेषण हो देश में।

ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मालूम नहीं क्या है विदेश की हवा-पानी में कि राहुल गांधी पर असर ऐसा होता है कि उल्टी-सीधी बातें फौरन करना शुरू कर देते हैं। इस बार उन्होंने पहले तो सिखों के बारे में कहा कि उनको भारत में साफा और कड़ा पहनने का अब अधिकार नहीं है। एक तो ये सरासर झूठ है, ऊपर से उन्होंने इस बात को कहकर कनाडा में बसे खालिस्तानी अलगावादियों के दिल इतने खुश किए कि उन्होंने उनकी बातों से खुल कर सहमति जताई। अपने देश में नतीजा यह हुआ कि भाजपा के बड़े नेताओं ने फौरन याद दिलाया गांधी परिवार के इस वारिस को कि सिखों के साथ अत्याचार अगर कभी हुआ था, तो उनके पिताजी के दौर में, जब हजारों सिखों ने अपनी जान गंवाई थी, ऐसे हत्यारों के हाथों जो कांग्रेस पार्टी के जाने-पहचाने कार्यकर्ता थे। जो हुआ, कोई दंगा नहीं था। दंगा होता तो कम से कम एक हिंदू मिलता मरनेवालों में। जनसंहार था और इस जनसंहार को राहुल जी के पिताश्री ने जायज ठहराया यह कहकर कि 'बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है'। यानी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ऐसा होना ही था।

आगे राहुलजी ने यह भी कहा कि हाल में हुए लोकसभा चुनावों में धांधली न हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी होती। इतना तो सोच लिया होता राहुल गांधी ने कि धांधली करनी थी अगर नरेंद्र मोदी को तो इतना तो गारंटी करते कि पूर्ण बहुमत मिले तीसरी बार। यहां भी नहीं रुके कांग्रेस के आला नेता। आगे यह भी कह डाला अमेरिका में कि भारत की नब्बे फीसद आबादी का हाल इतना बुरा है कि आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित रहते हैं जातिवाद के कारण। अपने इस सबसे पसंदीदा विषय पर बोलने के बाद उन्होंने अपनी फोटो खिंचवाई इल्हान उमर नाम की एक अश्वेत, मुसलिम सांसद के साथ, जो बार-बार स्पष्ट कर चुकी हैं कि उसकी नजर में भारत में मुसलमानों के साथ इतना जुल्म होता है कि अमेरिका को हमारे साथ रिश्ता तोड़ना चाहिए। यानी राहुल गांधी ने अपने पांव पर कुल्हाड़ी इतनी बार मारी पिछले दिनों कि किसी और को हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं थी।

पलटवार करने में लेकिन मोदी के मंत्री इतने उतावले रहते हैं कि गृहमंत्री का बयान आया पिछले सप्ताह जिसमें राहुल गांधी की बातों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया। राहुल गांधी ने कहा था एक सवाल का जवाब देते हुए कि जातियों के आधार पर आरक्षण तभी समाप्त किया जाएगा जब भारत में हर जाति को बराबर के अवसर मिलने शुरू होंगे। इस पर गृहमंत्री जी ने कहा कि साबित हो गया है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है। कैसे इस बात को कही उन्होंने, समझना मुश्किल है इसलिए कि पिछले कुछ महीनों से राहुल ने अपने आप को पिछड़ी जातियों के मसीहा के रूप में पेश किया है।

जब मोदी के वरिष्ठ मंत्री इस तरह के बयान देते हैं, तो देर नहीं लगती है छुटभैयों को हल्ला मचाने में। सोशल मीडिया पर भाजपा की ट्रोल सेना हावी हो गई यह साबित करने में कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं। देशद्रोह का आरोप इतनी आसानी से लगाते हैं मोदी भक्त कि जैसे राष्ट्रवाद का ठेका लेने का अधिकार सिर्फ उनको है। सोचने की तकलीफ नहीं करते हैं ये लोग कि उनको किसी ने हक नहीं दिया है फैसला करने का कि देशद्रोही कौन हैं और देशभक्त कौन। गांधी परिवार को निशाना काफी दिनों से बनाए रखा है मोदी भक्तों ने, लेकिन हाल में मैंने देखा है कि उनकी इस मुहिम में एक नई चीज दिखने लगी है : घबराहट। दिखने लगी मुझे घबराहट पहली बार, जब लोकसभा के परिणाम ऐसे आए कि 'चार सौ पार' तो दूर की बात, तीन सौ पार भी सपना बन कर रह गया।

अब घबराहट इतनी ज्यादा दिखने लगी है मोदी के मंत्रियों और भक्तों में कि ऐसा कहना जरूरी हो गया है कि उनको वास्तव में राहुल गांधी से खतरा दिखने लगा है। अभी तक तो आसानी से कहते फिरते थे ये लोग कि गांधी परिवार के वारिस सिर्फ पप्पू हैं और भविष्य में भी पप्पू ही रहेंगे। लेकिन पप्पू शब्द इन दिनों कम सुनाई देता है। घबराहट इसमें भी दिखती है कि राहुल गांधी के हर बयान को खंडन करने पूरी फौज खड़ी हो जाती है भक्तों की। जैसे कि नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाला एक ही व्यक्ति है और वह है राहुल। शायद यह बात सच भी है, लेकिन जिस तरह से उनको बदनाम करने में लग जाते हैं मोदी के समर्थक, उससे फायदा राहुल गांधी का होता है ज्यादा, मोदी का कम। राहुल गांधी अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने में इतने माहिर हैं कि जरूरत ही नहीं है किसी और को वार करने की। मोदी भक्तों को एक पूर्व भक्त से सुझावः कभी-कभी चुप रहना बेहतर होता है।

बुद्धि और विवेक का समन्वय

शिक्षा

जगमोहन सिंह राजपूत

ज्ञा न का सदुपयोग करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए बुद्धि और विवेक का प्रश्रय अवश्य लेना होगा। जिस कालखंड में आधुनिक विज्ञान में ज्ञान प्राप्ति की पराकाष्ठा थी, परमाणु विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता पाना, वह मिली, लेकिन उसके विवेकहीन दुरुपयोग का परिणाम था हिरोशिमा और नागासाकी।

उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के अंत से पहले ही यह चर्चा शुरू हो चुकी थी कि 'भविष्य के साम्राज्य ज्ञान के साम्राज्य होंगे'। कितने ही शोषित और हर प्रकार से संसाधन-विहीन नव-स्वतंत्र देशों के समक्ष समस्याओं और चुनौतियों के नए-नए परिदृश्य उभर रहे थे और स्वतंत्रता से बड़ी-बड़ी आशाएं लगाए आमजन इनके संपूर्ण समाधान की अपेक्षा अपने नए शासकों से कर रहे थे। जिन देशों को समर्पित और भविष्य-दृष्टि से युक्त नेतृत्व मिला था, वे यह भली भांति समझते थे कि विकास और प्रगति का रास्ता शिक्षा केंद्रों से ही होकर गुजरेगा। जो इस सच्चाई को समझ सके, जिन्होंने शिक्षा के प्रचार-प्रसार और गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया, उच्च शिक्षा और शोध के लिए संस्थान बनाए, वे ही आगे बढ़ सके। भारत इसी दिशा में आगे बढ़ने वाला उदाहरण माना जाता है। यहां के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व समझता था कि शिक्षा ही प्रगति का मार्ग पुनः प्रशस्त कर सकती है, जिसे विदेशी शासकों द्वारा जानबूझ कर अवरुद्ध किया गया था। संविधान में 6-14 वर्ष के हर बच्चे को निश्शुल्क शिक्षा का अत्यंत विषम परस्थितियों में प्रावधान करना एक साहसपूर्ण कदम था।

आज विश्व में भारत का जो अग्रणी स्थान अंतरिक्ष विज्ञान, संचार तकनीक, नाभिकीय विज्ञान और शोध के क्षेत्र में बना है, उसका श्रेय देश को आजादी के बाद मिले राजनीतिक और वैज्ञानिक नेतृत्व को ही दिया जाना चाहिए। यह भी अब अध्ययन, शोध और विश्लेषण के आधार पर सिद्ध हो चुका है कि प्राचीन भारत को जो वैश्विक स्तर पर श्रेष्ठता मिली थी, वह उसकी बौद्धिक क्षमता के मूल आधार पर ही स्थापित हुई थी। ज्ञान-विज्ञान, दर्शन, अध्यात्म जैसे अनेक क्षेत्रों में नव-ज्ञान सृजन की जो परंपरा भारत ने स्थापित की थी, उसी से प्रभावित होकर विदेशों से अनेकानेक जिज्ञासु भारत में अध्ययन करने आते थे। यहां का दर्शन स्पष्ट थाः व्यक्ति स्वयं का जीवन सुचारु रूप से निर्वहन कर सके, 'सर्वभूत हिते रतः' के लक्ष्य का क्रियान्वयन करे, धनार्जन अवश्य करे, लेकिन सदाचरण यानी धर्म के मार्ग पर चल कर ही करे। इस प्रकार के जीवन निर्वाह के लिए विनयशीलता आधारशिला थी। आज भारत को इसी सोच को व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। परिपूर्ण शिक्षा नीति और उसका अनुपालन इसी चिंतन के इर्द-गिर्द व्यवस्थि किया जाना चाहिए।

स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्षों में गहन विचार-विमर्श और बौद्धिक चर्चाओं में बर्ट्रेंड रसेल जैसे चिंतकों का यह विचार भी चर्चित रहा कि मनुष्य अगर केवल ज्ञान प्राप्ति के पीछे पड़ा रहा, तो अपने को समाप्त कर लेगा! ज्ञान प्राप्ति के प्रयास पवित्र प्रेरणा का परिणाम माने जाते रहे हैं। ज्ञान का सदुपयोग करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए बुद्धि और विवेक का प्रश्रय अवश्य लेना होगा। जिस कालखंड में आधुनिक विज्ञान में ज्ञान प्राप्ति की पराकाष्ठा थी, परमाणु विखंडन से ऊर्जा प्राप्त करने में सफलता पाना, वह मिली, लेकिन उसके विवेकहीन दुरुपयोग का परिणाम था हिरोशिमा और नागासाकी। बुद्धि, विवेक, विश्लेषण और 'सर्वजन-हिताय, सर्वजन-सुखाय' के लिए ज्ञान के उपयोग की समझ अगर विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ बढ़ी होती, तो आज मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में घोर बिगाड़ आने के कारण उत्पन्न समस्याएं इस पृथ्वी के अस्तित्व पर ही प्रश्नचिह्न न लगा रही होतीं!

इस समय जब विद्वत वर्ग में चर्चा इस वैचारिकता की ओर मुड़ती है, तो इसकी 'अव्यावहारिकता' को लेकर ही अधिकाधिक विचार सामने रखे जाते हैं। अनेक व्यक्तिगत अनुभव यह सिद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो सकते हैं कि जहां शिक्षा केवल अधिकाधिक धनार्जन के अर्जुन-लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ाई जाती है, वहां इस सोच को स्वीकार्यता कैसे मिलेगी? एक उदाहरण जो सबसे अधिक दोहराया जाता है वह है किसी भी युवा के डाक्टर बनने का। कितनी स्कूली पढ़ाई, कितनी कोचिंग, कितनी भारी-भरकम फीस, कठिन प्रतियोगी परीक्षा, सफलता को लेकर कितना लंबा असमंजस, कितने वर्ष, तब मिलती है पहली डिग्री। फिर परा-स्नातक उपाधि पाना तो इससे कठिन होगा ही! इस सबमें परिवार पर कितना बोझ पड़ता होगा? यह समस्या केवल मेडिकल तक सीमित नहीं है। यह स्थिति हर शिक्षित युवा के समक्ष किसी न किसी ढंग से अनेक प्रकार के तनाव और आशंकाएं पैदा कर रही है।

इस स्थिति से निपटने के लिए भारत की प्राचीन संस्कृति और साहित्य में बहुत कुछ उपलब्ध है। भारत की आध्यात्मिक समझ उसके विचारकों और दार्शनिकों की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों में गिनी जा सकती है। जहां लालच नहीं होगा, वहां ईर्ष्या, द्वेष तथा अनावश्यक मनमुटाव स्वतः कमजोर हो जाएंगे। समाज को हिंसा और संघर्ष में अपनी ऊर्जा व्यय नहीं करनी होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इस मूलभूत मूल्यों और दर्शन-तत्त्व को देश की नीतियों में समुचित स्थान मिला होता, प्राचीन परंपराओं में जो व्यावहारिक थीं उन्हें भी कृत्रिम आधार पर छोड़ न दिया गया होता, तो संभवतः पिछले सात दशक में सामाजिक परिदृश्य तेजी से सकारात्मकता की ओर बढ़ा होता। आज ऐसा नहीं है, हर ओर अविश्वास पसरा हुआ है, व्यग्रता और उग्रता अनेक प्रकार से लगातार हर तरफ बढ़ते ही दिखाई दे रहे हैं। इनके परिणामस्वरूप हिंसा बढ़ी है। महिलाओं के खिलाफ जो दरिंदगी की घटनाएं सामने आती हैं, उसका मुख्य कारण सार्वभौमिक स्तर पर नैतिकता और मूल्यों के ह्रास तथा परंपरागत संस्कृति तथा उससे लगातार बढ़ती दूरी ही है।

सामस्याओं के तात्कालिक समाधान आवश्यक हैं, लेकिन दीर्घकालीन तथा सशक्त समाधान की रणनीति भी बनाने की आवश्यकता है। केवल शिक्षा-व्यवस्था या कानून-व्यवस्था के अनुपालन पर सारा उत्तरदायित्व नहीं डाला जा सकता, इसमें समाज का उत्तरदायित्व प्रथम स्थान पर स्वीकार करना होगा।

एक बहस ऐसी भी

बाखबर

सुधीश पचौरी

एक अंग्रेजी चैनल में आई 'प्राइम टाइम' की एक नायाब बहस, जिसमें दिखी कुछ 'ज्ञानियों' के बीच 'डब्लूडब्लूएफ' छाप 'ज्ञान की कुश्ती', 'सोशल मीडिया' वाले नित्य के 'दंगली सीन', कि जैसे ही 'एक' ज्ञानी ने दूसरे की 'पोल' खोली, वैसे ही 'दूसरे' ने पहले की 'पोल' खोल दी। उसके बाद सारी बहस 'मिनी महाभारत' का आनंद देने लगी।

एक दिन 'देश की बेटी' 'राज्य की बेटी' बता दी गई, तो राष्ट्रवादी चिढ़े कि 'देश की बेटी' एक 'राज्य की बेटी' कैसे हो गई? अरे भई, जब बेटी को आपत्ति नहीं, तो आप कौन?

फिर एक पड़ोसी प्रशासक कह उठे कि हिंदुओं पर हमले सांप्रदायिक नहीं, राजनीतिक हैं। अपने चैनलों ने जवाब दिया कि तब तो इधर होने वाली 'लिंचिंगें' भी सांप्रदायिक नहीं, राजनीतिक हैं। हत्याओं का ऐसा 'औचित्यीकरण' कब देखा-सुना?

खबर आई कि जिस 'याचक' ने 'याचिका' दी थी कि 'इंडिया' के अपने 'हथियार' मानवाधिकारों का हनन करने वाले देशों को बेचने पर रोक लगे, उसे बड़ी अदालत ने नहीं माना। बताइए, इसके बाद कोई क्यों न रोए कि न्यायपालिका दबाव में है!

इसके बाद आया खांटी 'जाति विमर्श'। एक 'अपराधी' का 'एनकाउंटर' हुआ, तो 'विमर्शकार' बोले कि जाति देखकर 'एनकांउटर' किए जा रहे हैं! कितनी बुरी बात कि हर गोली पर लिखा है 'जाति' का नाम!

एक दिन अमेरिका से उवाचे एक नेता कि उनकी सोच आसानी से समझ नहीं आती।... देखा तो बात सही ठहरी, क्योंकि जो बोला वह हमारे जैसे उच्च बुद्धि वालों को ही समझ नहीं आया कि चुनाव के बाद 'डर' निकल गया है... कि न्यायपालिका और मीडिया भारत में खत्म है... कि अपनी भूमिका देश को तानाशाही से बचाना है... कि भारत में फर्नीचर, कपड़े सब चीन के हैं! जरा देखिए, तो एक लाइन में 'डर' निकल गया, दूसरी में वापस आ गया... ऐसी 'उलटबांसियों' पर भी कुछ जलोकड़े जल उठे कि विदेश में क्यों बोले, कि देशद्रोह का मुकदमा चले। तो जवाब आया कि उन्होंने तो सच का आईना दिखाया! जवाब में पक्षधर फिर भी देते रहे 'आंकड़े' पर 'आंकड़े', लेकिन जो उनने चिपकाया वह तो चिपका रह गया न!

भाई जी! ये 'चिपक राजनीति' के दिन हैं। वे चिपकाएं तो तुम भी चिपकाओ। कोरी हाय हाय से कुछ नहीं होने का।

फिर बरसा विदेश से कुछ अनमोल 'आध्यात्म' कि देवता 'भगवान' नहीं होते, 'भगवान' पारदर्शी होते हैं। ये हुई न ऊंची सोच, जो बड़े-बड़े विद्वानों को समझ आती नहीं दिखी! फिर भी एक 'वैदिक विद्वान' समझाए कि देवता का मतलब 'लीला करने वाला', चमत्कारी, यही 'भगवान' बन जाते हैं! गनीमत कि यह 'सोच' सचमुच किसी को समझ न आई और सब 'बोर' होने से बच गए।

फिर आए कुछ 'आदर्श विचार' कि जब 'आदर्श स्थिति' होगी, तो आरक्षण हटा देंगे। लेकिन यहीं सर जी 'फंसे'। एक आरक्षणवादी नेता बोलीं कि ये रही इनकी असिलयत! मगर आरक्षण कभी नहीं हटेगा। लेकिन फिर जैसे ही दूर की हांकी कि 'इंडिया' में सिख पगड़ी, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते, वैसे ही बहुत से सिख नेता बरस पड़े कि यह सच नहीं... कि, हम कुछ भी पहन सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं... कि वे एक खतरनाक नैरेटिव गढ़ रहे हैं। दो एंकर, एक प्रवक्ता ने अपने हाथ में पहने कड़े भी दिखाए!

पहला सबकः जब 'ऊंचा ज्ञान' बघरता है, तो ऊपर से निकल जाता है।

दूसरा सबकः इन दिनों आंकड़े नहीं चिपकते, चिपकती हैं दो-तीन लाइन की 'सूक्तियां'! ये 'मिनीमलिज्म' का जमाना है आदरणीय!

बहरहाल, इस 'बेदर्द जमाने' में, एक दिन दीदी जी ने कह दिया कि जनहित में इस्तीफा दे दूंगी। लेकिन किसी भी मुए ने यकीन नहीं किया, बल्कि कटाक्ष ही किए कि ये एक 'चतुर चाल' है!

अब देखिए न कि मुख्य न्यायाधीश ने एक दिन अपने घर 'गणेश पूजा' की, तो वीडियो में प्रधानमंत्री भी दिख गए। जैसे ही दिखे, वैसे ही शुरू हो गई 'हाय हाय' कि यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है... कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर संदेह है... लेकिन अगले दिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को 'बेल' दे दी, तो फिर होने लगी 'वाह वाह'! 'अपनी सी' हो तो 'वाह' नहीं तो 'हाय'! इन दिनों की राजनीति भी चाकलेट की तरह है। मिले तो 'वाह वाह', न मिले तो 'हाय हाय'!

इसके बाद एक अंग्रेजी चैनल में आई 'प्राइम टाइम' की एक नायाब बहस, जिसमें दिखी कुछ 'ज्ञानियों' के बीच 'डब्लूडब्लूएफ' छाप 'ज्ञान की कुश्ती', 'सोशल मीडिया' वाले नित्य के 'दंगली सीन', कि जैसे ही 'एक' ज्ञानी ने दूसरे की 'पोल' खोली, वैसे ही 'दूसरे' ने पहले की 'पोल' खोल दी। उसके बाद सारी बहस 'मिनी महाभारत' का आनंद देने लगी। फिर 'दूसरे' के जले पर, 'तीसरे' के जले पर नमक छिड़क दिया, तो तुरंत आस्तीनें चढ़ीं, भुजाएं फड़कीं और 'देख लूंगा' कि 'देख लूंगा' कि 'आ जा' कि 'आ जा' होने लगा। शेष ज्ञानी आनंदित भए और 'बिचौलिए' बनकर 'ज्ञान फाइटरों' को रोक कर पुण्य कमाए। एक का तो 'पोडियम' तक बदल दिया गया।

शुरू में चकित, फिर थकित, फिर हंसित एंकर जी आखिर में कहने लगीं कि 'जूस' पीके जाना जी!

बहरहाल, जिसने भी 'कुश्ती बहस' देखी, वही मस्त हुआ। जिसने न देखी, वह 'यूट्यूब' पर देखे! सिद्ध हुआ कि हमारी पत्रकारिता में आज भी बड़ी जान है!

https://t.me/AllNewsPaperPaid

गरीबों के लिए उचित प्रावधान करना ही सभ्यता की असली परीक्षा है।
-सैमुएल जॉनसन

जार से लेकर कम्युनिस्टों के शासन तक और अब पुतिन तक, रूस-यूक्रेन का एक अतीत है, जिसे सत्ता संचालित मेगामर्डर, डेमोसाइड, जेनोसाइड और क्रूरतम सामूहिक हत्याओं ने लिखा है। यूक्रेन-रूस का भूगोल इतना दुर्भाग्यशाली है कि यहां कुछ जघन्यतम हत्याएं आर्थिक नीतियों की वजह से भी हुईं।

यूक्रेन का होल्डोमॉर

दुनिया का सबसे जघन्य जनसंहार

स्टालिन के सबसे करीबी मोल्टोव ने यूक्रेन की सीमाएं बंद कर दी हैं। गांव छोड़कर जाने पर रोक लगा दी गई, ताकि मजदूर भाग न जाएं। जिस गांव ने अनाज का कोटा पूरा नहीं किया, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। थोड़े से अनाज के लिए हिंसा शुरु हो गई। अब आप यूक्रेन का होल्डोमॉर देख रहे हैं, यानी ऐसी भुखमरी, जो शासकों ने पैदा की है।

होल्डोमॉर की 'कड़वी बचपन की स्मृति' प्रतिमा, जो राष्ट्रीय संग्रहालय के सामने खड़ी है।

अंशुमान तिवारी
वरिष्ठ लेखक-पत्रकार

अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्यूमेंटरी निर्माता मैक्स वेक्स्टर बुढ़ापे से खौफजदा थे। वर्ष 2011 में उन्होंने एक खास फिल्म बनाई, जिसका नाम था-*हाउ टु लिव फॉर एवर*। वेक्स्टर ने उम्रदराज लोगों से बात की, ताकि लंबी उम्र का रहस्य पता चल सके। इसी फिल्म में एक सौ साला बुजुर्ग से सवाल किया गया कि आपकी जिंदगी में सबसे खुशी का दिन कौन-सा था। बुजुर्ग का जवाब था- 11 नवंबर, 1918 यानी पहले विश्वयुद्ध की समाप्ति का दिन, जब उत्तर पूर्व फ्रांस के कस्बे कॉपिग्ने में संधि पर दस्तखत हुए थे। इतनी खुशी क्यों? बुजुर्ग ने कहा, क्योंकि युद्ध हमेशा के लिए खत्म होने वाले थे। पहले विश्वयुद्ध में दो करोड़ लोग मारे गए थे और इतने ही घायल हुए। और फिर, करीब बीस साल बाद दूसरा विश्वयुद्ध हुआ और फिर युद्ध रह-रहकर होते रहे। जैसे कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया। सैकड़ों मिसाइलें यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में बरस पड़ीं।

विश्व के कुछ ही भूगोल इतने अधिक अभागे होंगे, जितना कि रूस-यूक्रेन है। यहां 21वीं सदी भी युद्ध से खाली नहीं गई। जार से लेकर कम्युनिस्टों के शासन तक और अब पुतिन तक, रूस-यूक्रेन का एक अतीत है, जिसे सत्ता संचालित मेगामर्डर, डेमोसाइड, जेनोसाइड और क्रूरतम सामूहिक हत्याओं ने लिखा है। यूक्रेन-रूस का भूगोल इतना दुर्भाग्यशाली है कि यहां कुछ जघन्यतम हत्याएं आर्थिक नीतियों की वजह से भी हुईं। चौंकिए नहीं, आर्थिक नीतियों ने हजारों लोगों को मार डाला। पकड़िए टाइम मशीन में अपनी सीट। यह यात्रा हमें कुछ ऐसा दिखाएगी, जो कभी नहीं होना चाहिए था। सो चलिए इस सफर पर...

यह पहले विश्वयुद्ध के बाद का दौर है। ऑस्ट्रिया और रूस के साम्राज्यों के बीच बंटा इतिहास सिमट रहा है। यह 1917 है। रूस में जार शासन को उखाड़कर व्लादिमीर लेनिन के बोल्शेविकों ने सत्ता संभाल ली है। इधर यूक्रेन में स्वतंत्र सरकार बन गई। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन नाम का नया देश नक्शे पर उभर आया है। अब हम मास्को में हैं। बोल्शेविक यूक्रेन को खत्म करने जा रहे हैं। लाल सेना यूक्रेन पर चढ़ आई है। यूक्रेन की अस्थायी सरकार ने रूस से जमकर लोहा (1918 से 1921) लिया, लेकिन अंततः हार गया। अब यह मुल्क नए सोवियत संघ यानी सोशलिस्ट रिपब्लिक का हिस्सा है।

टाइम मशीन
अतीत से सुनें वर्तमान की धड़कन ▪ हर पखवाड़े

जार शासन के तख्तापलट के बाद रूस में सिविल वार शुरू हो गई है। लेनिन आर्थिक ताकत का केंद्रीकरण कर रहे हैं। वह रेड आर्मी की ताकत बढ़ाने के लिए उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने लगे हैं। यहां तक कि अनाज का उत्पादन भी सरकार के कब्जे में आ गया है। इससे लेनिन की सेना तो मजबूत हुई, मगर दमनकारी नीति ने अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया है। उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। किसानों ने पैदावार सीमित कर दी है। शहरों में सामान की किल्लत साफ दिख रही है। फैक्टरी में कामगार नहीं है। हड़तालें हो रही हैं। यह 1921 का साल है। जो लोग लेनिन की क्रांति की सबसे बड़ी ताकत थे, वे अब विरोधी हो गए हैं। विरोध और दबाव के कारण व्लादिमीर लेनिन को नई आर्थिक नीति लानी पड़ी है। मार्च, 1921 में लेनिन ने नई नीति का एलान कर दिया है। अनाज पर बलपूर्वक कब्जे की नीति खत्म। इसके बदले एक टैक्स लगा दिया गया है। कुछ उद्योगों को निजी क्षेत्र को दे दिया गया। उत्पादन बढ़ा है, शहरों में लोग आने लगे हैं, लेनिन का नया पूंजीवाद उभर रहा है।

यह 1924 है। व्लादिमीर लेनिन नहीं रहे। जोसेफ स्टालिन ने सत्ता संभाल ली है और लेनिन की 1921 वाली नीति खत्म कर दी गई है, जिसमें निजी उद्यमिता को वरीयता दी गई थी। स्टालिन पंचवर्षीय योजना लेकर आए हैं। यूक्रेन के लिए स्टालिन की पहली पंचवर्षीय योजना मौत का फरमान साबित हुई है।

यह 1932 है। स्टालिन ने यूक्रेन की पूरी अर्थव्यवस्था बदल दी है। खेती का सामूहिकीकरण और सरकारीकरण हो गया है। निजी खेतों पर कब्जा कर सामूहिक कोलहोप्स फार्म में बनाए जा रहे हैं, जिनमें किसान मजदूर की तरह काम कर रहे हैं। कभी ये किसान इन खेतों के मालिक थे। स्टालिन अनाज उत्पादन में सोवियत संघ को बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं। मगर यूक्रेन के अधिकांश किसान छोटी जोत वाले हैं, जो जीविका के लिए खेती करते हैं। स्टालिन की इस नीति के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गए हैं। यूक्रेन में ऐसे करीब 4,000 आंदोलन हुए हैं, जिन्हें स्टालिन की सोवियत पुलिस ने सख्ती से कुचल दिया है। किसानों को लेबर कैंप में भेज दिया गया है। स्टालिन की कृषि नीति के विरोध को राष्ट्रविरोधी घोषित कर दिया गया है।

स्टालिन ने (1932) फाइव स्टेक्स ऑफ ग्रेन की कुख्यात नीति लागू कर दी है। प्रत्येक गांव के लिए अनाज का कोटा तय कर दिया है। अनाज की जबरन खरीद हो रही है। अनाज पहले सरकार को देना होता है, इसके बाद जो बचा, वह खाने को मिलता है। घर-घर में अनाज का संकट हो गया है। अगर कोई बच्चा भी अनाज ले जाता मिल जाए, तो उसे जेल में बंद करने या गोली मारने के आदेश हैं। कोटे से अधिक अनाज घर में मिलना यानी सोशलिस्ट प्रॉपर्टी की लूट। 1933 की शुरुआत तक 55 हजार लोग जेल में बंद किए गए। 2,000 को मौत की सजा दी गई। अब यूक्रेन में भुखमरी शुरू हो गई है। गांव खाली कर लोग भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाने लगे हैं।

यूक्रेन के भयावह युग को देखते हुए आपने वायश्लेव मोल्टोव का नाम सुना होगा, जो स्टालिन के सबसे करीबी हैं। मोल्टोव ने यूक्रेन की सीमाएं बंद कर दी हैं। गांव छोड़कर जाने पर रोक लगा दी गई, ताकि मजदूर भाग न जाएं। जो गांव अनाज का कोटा पूरा नहीं करता, उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अनाज के लिए हिंसा शुरू हो गई। अब आप यूक्रेन का होल्डोमॉर देख रहे हैं। यानी ऐसी भुखमरी, जो शासकों ने पैदा की है। लोग घास, सड़ा अनाज, यहां तक कि कुत्ते-बिल्ली भी मारकर खा रहे हैं। सोवियत पुलिस घर-दीवारें खोदकर अनाज तलाश रही हैं।

यह होल्डोमॉर दुनिया के इतिहास का सबसे जघन्य जनसंहार है। यूक्रेन के डेमोग्राफी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट (2015) बता रही है कि 1932-33 के बीच होल्डोमॉर से यूक्रेन में 39 लाख लोग मारे गए। वर्ष 1932 में सोवियत शासन ने 42.7 लाख टन अनाज लूटा, जिससे करीब 1.2 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता था। यह स्टालिन का ऐसा जनसंहार था, जो बरसों तक दुनिया से छिपा रहा।

अनाज भंडारगृह पर तैनात सैनिक का फाइल फोटो।

अब हम 2019 के बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हैं। यहां पोलैंड के मशहूर फिल्म निर्देशक एग्निज्का हॉलैंड की फिल्म दिखाई जा रही है, जो पत्रकार गैरेट जोन्स और होल्डोमॉर पर केंद्रित है। गैरेट जोन्स ब्रिटेन के पत्रकार थे, जो 1933 में यूक्रेन गए थे। वह इस मेगामर्डर के शायद अकेले गवाह थे। यूक्रेन से लौटने के बाद उन्होंने होल्डोमॉर के बारे में बताया, लेकिन तब इसे शायद नात्जी प्रचार का हिस्सा मान लिया गया। जोन्स की मौत के लंबे समय के बाद उनके कुछ संस्मरण मिले। तब तक होल्डोमॉर को लेकर अन्य जानकारियां भी सामने आने लगी थीं। दुनिया को जब इस जनसंहार के बारे में पता चला, तो दिल दहल उठे। पत्रकार जोन्स यूक्रेन के हीरो हो गए। यह फिल्म देखकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि यूक्रेन का अभिशाप खत्म क्यों नहीं होता... टाइम मशीन इस दर्दनाक सफर को अब खत्म करना चाहती है।

फिर मिलते हैं अगली यात्रा में...

जानना जरूरी है
संस्कृति के पन्नों से

आशुतोष गर्ग
लेखक एवं अनुवादक

याज्ञक, काले वस्त्र पहनकर यज्ञ करने लगे। उन्होंने सर्पों के नाम ले-लेकर अग्नि में आहुतियां देनी शुरू कीं, जिससे छोटे-बड़े, बूढ़े-जवान असंख्य सर्प अग्नि में गिरे और जलकर भस्म हो गए।

तक्षक की नागयज्ञ से कैसे हुई रक्षा?

जनमेजय की आज्ञा से नागयज्ञ की तैयारी आरंभ हो गई। तभी एक वास्तुशास्त्री ने भविष्यवाणी की 'जिस स्थान और समय में यज्ञ-कार्य आरंभ हुआ है, उसे देखकर लगता है कि एक ब्राह्मण के कारण यज्ञ पूर्ण नहीं होगा!' परंतु जनमेजय ने यज्ञ का कार्य जारी रखा।

याजक, काले वस्त्र पहनकर यज्ञ करने लगे। उन्होंने सर्पों के नाम ले-लेकर अग्नि में आहुतियां देनी शुरू कर दीं, जिससे असंख्य सर्प अग्नि में गिरे और जलकर भस्म हो गए। यह देख तक्षक घबरा गया और देवराज इंद्र की शरण में चला गया। यज्ञ के प्रभाव से नागराज वासुकि को भी चक्कर आने लगे। उनकी रक्षा के लिए देवतागण, ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने कहा कि ऋषि जरत्कारु ने वासुकि की बहन जरत्कारु से विवाह किया था। उनके पुत्र आस्तीक ही सर्पों की रक्षा कर सकते हैं। तब माता जरत्कारु ने आस्तीक से अपने भाई वासुकि को बचाने की प्रार्थना की।

धूप आने दो

आस्तीक तुरंत यज्ञ-स्थल पर पहुंचा और राजा जनमेजय, ऋत्विजों, आदि की स्तुति आरंभ कर दी। आस्तीक ने जनमेजय के यज्ञ की तुलना वरुणदेव, ब्रह्मा, इंद्र, राजा रंतिदेव, यमराज, गय, शशबिंदु, कुबेर, नृग, अजमीढ़, श्रीराम और युधिष्ठिर के यज्ञों से की और कहा कि जनमेजय का यज्ञ इन सबके यज्ञों के समान श्रेष्ठ है। आस्तीक ने ऋत्विजों और अन्य सदस्यों की भूरि-भूरि प्रशंसा की, जिसे सुनकर सब प्रसन्न हो गए। जनमेजय इतना प्रसन्न हुआ कि उसने आस्तीक से मनवांछित वर मांगने को कह दिया। लेकिन ऋत्विज ने कहा कि वर देने से पहले तक्षक को अग्नि में गिरने दिया जाए।

मंत्रों के प्रभाव से अधिकतर सर्प, यज्ञाग्नि में गिरकर भस्म हो चुके थे, किंतु तक्षक अब भी बचा हुआ था। अग्निदेव ने बताया कि तक्षक, इंद्रदेव का मित्र है और उनके विमान में छिपा बैठा है।

तब जनमेजय ने कहा कि मंत्रोच्चारण इस तरह किया जाए, ताकि तक्षक के साथ इंद्र भी अग्नि में गिर पड़ें। यह जानकर इंद्र ने तक्षक का साथ छोड़ दिया। यज्ञ के होता ने जैसे ही तक्षक के नाम की आहुति डाली, तो तक्षक आकाश में दिखने लगा। वह धीरे-धीरे यज्ञाग्नि की ज्वाला के समीप आ रहा था। ऋत्विज बोले-'महाराज, तक्षक को अग्नि में गिरने से कोई नहीं रोक सकता, इसलिए अब आप इस ऋषि-कुमार को वर दे सकते हैं।'

आस्तीक को इसी क्षण की प्रतीक्षा थी। तक्षक अग्नि में गिरने ही वाला था कि आस्तीक बोला-'महाराज! मैं वर मांगता हूं कि आपका यज्ञ तत्काल बंद हो जाए।' फिर आस्तीक ने तक्षक को लक्ष्य करके तीन बार कहा-'ठहर जा!' ऐसा कहते ही तक्षक अधर में ठहर गया। जनमेजय वचनबद्ध था, उसने कहा-'यज्ञ समाप्त किया जाए और सभी नाग अब कुशलपूर्वक रहें!' यह कहते ही यज्ञ रुक गया।

आस्तीक ने तक्षक समेत शेष सभी सर्पों की रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर वासुकि ने उससे वर मांगने को कहा। आस्तीक ने मांगा, 'जो मेरे इस उपाख्यान का पाठ करे, उसे कभी सर्पों का भय न हो!' तब नागराज वासुकि ने असित, आर्तिमान और सुनीथ नाम के तीन मंत्र दिए, जिनका पाठ करने से मनुष्य को सर्प का भय नहीं रहता। ये मंत्र हैं-

यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारौ महायशाः।
आस्तीकः सर्पसत्रे वः पन्नगान्योऽभ्यरक्षत।
तं स्मरन्तं महाभागा न मां हिंसितुमर्हथ।।

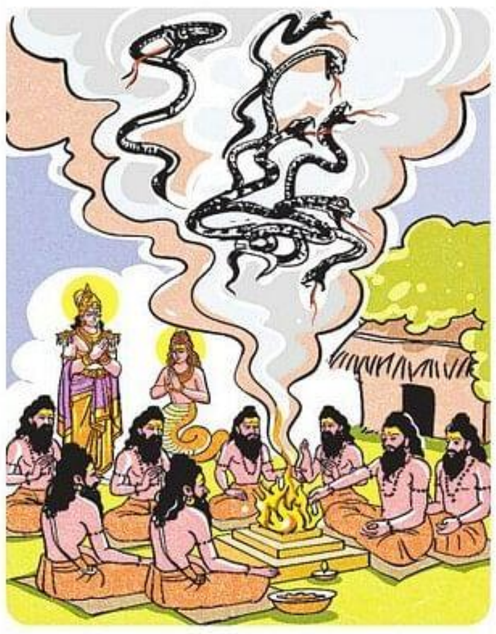

(जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नागकन्या से जो आस्तीक नामक यशस्वी ऋषि उत्पन्न हुए तथा जिन्होंने सर्पसत्र में तुम सर्पों की रक्षा की थी, उनका मैं स्मरण कर रहा हूं। महाभाग्यवान सर्पो! तुम लोग मुझे मत डंसो।)

सर्पापसर्प भद्रं ते गच्छ सर्प महाविष।
जनमेजयस्य यज्ञान्ते आस्तीकवचनं समर

(महाविषधर सर्प! भाग जाओ! तुम्हारा कल्याण हो! जनमेजय के यज्ञ समाप्ति में आस्तीक को तुमने जो वचन दिया था, उसका स्मरण करो।)

आस्तीकस्य वचः श्रुत्वा यः सर्पो न निवर्तते
शतधा भिद्यते मूर्ध्नि शिंशवृक्षफलं यथा

(जो सर्प आस्तीक के वचन सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे।) ▪

किंचिदेव ममत्वेन यदा भवति कल्पितम्।
तदेव परितापार्थे सर्वे सम्पद्यते तथा।।

अर्थात मनुष्य जब पदार्थों में ममत्व कर लेता है, तब वे उसके दुख का कारण बन जाते हैं। (आशय है कि अत्यधिक ममत्व से सावधान रहना चाहिए।)
- शांतिपर्व 174/44
(पुत्र निधन से शोकाकुल राजा सेनजित को ब्राह्मण का उपदेश)

प्रस्तुति : विवेक चौरसिया

अनंत अंतरिक्ष का थैला और हम

नीलाक्षी वीरवथिना
टेक्सस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर

अंतरिक्ष में बेशक हवा न होकर निर्वात हो। लेकिन यह खाली नहीं है।

कल्पना कीजिए कि आपका कोई दोस्त किसी विशाल इमारत, स्टेडियम या संग्रहालय के बारे में शेखी बघार रहा है। आप जब उस इमारत को देखते हैं, तो वह आपको विशाल या खाली लगती है? लेकिन, विशाल शब्द का अर्थ हमेशा खाली नहीं होता। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसके अंदर मौजूद वस्तुओं के घूमने के लिए पर्याप्त जगह है। इसी तरह अंतरिक्ष भी पूरी तरह खाली नहीं है। यह विशाल है और हमेशा विस्तृत होता रहता है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। बचपन में हम अक्सर सोचते हैं कि बादल कितनी दूर है, पृथ्वी से परे क्या है और अंतरिक्ष कितना विशाल है! वास्तव में पृथ्वी विभिन्न गैसों की कई परतों से घिरी हुई है। समुद्र तल पर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रति घन सेंटीमीटर लगभग 100 अरब अणु होते हैं। जैसे-जैसे हम ऊपर जाते हैं, वायुमंडल पतला होता जाता है। लगभग 50 से 62 मील (80 से 100 किमी) की ऊंचाई पर विमानों के उड़ने के लिए पर्याप्त हवा नहीं होती। इस सीमा, जो पृथ्वी के वायुमंडल को बाहरी अंतरिक्ष से अलग करती है, को कार्मन रेखा कहा जाता है, जिसका नाम भौतिक विज्ञानी थियोडोर वॉन कार्मन के नाम पर रखा गया है। इसके ऊपर की हर चीज को अंतरिक्ष कहा जाता है। अंतरिक्ष एक विशाल, लगभग पूरी तरह निर्वात (खाली) है, जिसमें अधिकांशतः पदार्थ नहीं होते। हालांकि, यह पूरी तरह से खाली नहीं है। अंतरिक्ष में पदार्थ बिखरे हुए हैं, जिन्हें अंतरतारकीय माध्यम कहा जाता है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम परमाणु शामिल हैं। इसमें ब्रह्मांडीय धूल भी होती है-कार्बन और सिलिकॉन सहित विभिन्न तत्वों के छोटे कण, जो पूरे अंतरिक्ष में बिखरे हुए हैं। उच्च ऊर्जा वाले कण, जिन्हें कॉस्मिक किरणें कहा जाता है, अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं। अंतरिक्ष में कई तरह के विकिरण भरे पड़े हैं, जिनमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन भी शामिल है। तारों, ग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी अंतरिक्ष में व्याप्त हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डार्क मैटर ब्रह्मांड के द्रव्यमान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। इसी तरह डार्क एनर्जी ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को प्रेरित कर रहा है। अंतरिक्ष में कणों, विकिरणों, चुंबकीय क्षेत्रों और पदार्थ एवं ऊर्जा के रहस्यमय रूपों का मिश्रण है। अंतरिक्ष की कल्पना एक 3डी खेल के मैदान के रूप में करें, जिसके अंदर तारे, ग्रह, नेबुला और आकाशगंगाएं जैसी वस्तुएं मौजूद हैं और ये सब मिलकर हमारा आकर्षक और जटिल ब्रह्मांड बनाते हैं।

(द कन्वर्सेशन से)

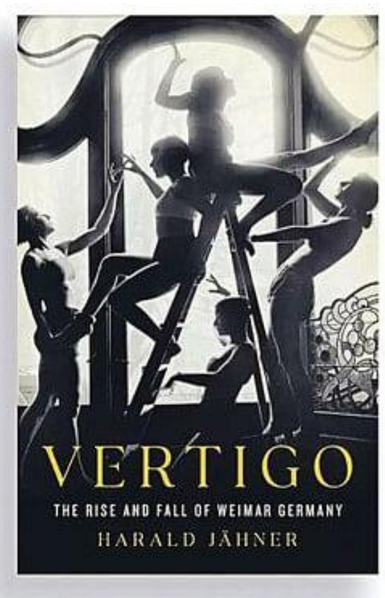

अध्ययन कक्ष

वर्टिगो
द राइज एंड फाल ऑफ वाइमर जर्मनी
लेखक : हेराल्ड जाह्नेर
प्रकाशक : डब्ल्यू एच एलन
मूल्य : रुपये 1921 (पेपरबैक)

एक लोकतंत्र, जिसे असफल नहीं होना था

वाइमर गणराज्य सांस्कृतिक प्रयोगों का केंद्र था। जाह्नेर की नई पुस्तक *वर्टिगो* नाजियों से पहले के जर्मनी के बारे में बताती है। इतिहास इस काल को गणतंत्र की राह में पहली बार ठोकर खाने के अनुभव की तरह याद रखेगा।

1918 का जर्मनी। पहला विश्वयुद्ध खत्म हो चुका है। राजशाही गिर चुकी है और लोकतंत्र की जीत हुई है। विश्वयुद्ध की छाया से बाहर आते ही जर्मनी ने एक अभूतपूर्व राजनीतिक परियोजना शुरू की। इसकी पहली लोकतांत्रिक सरकार की वाइमर गणराज्य के रूप में स्थापना हुई। बाद के वर्षों में राजनीतिक अतिवाद, आर्थिक उथल-पुथल और क्रांतिकारी हिंसा बदलते हुए जर्मनी के विशिष्ट लक्षण बन गए। मुक्त जीवन शैली के उभरने से परंपराएं अपनी जगह छोड़ती दिखने लगीं। छोटे बालों वाली महिलाएं शाम को अकेले बाहर घूमती व टेनिस कोर्ट जाती दिखने लगीं। लिंग को लेकर जो फर्क थे, वे मिटने लगे। डिपार्टमेंटल स्टोर की संस्कृति बढ़ते भौतिकवाद को बढ़ावा देने वाली तो थी ही, लोगों के बदलते मिजाज की ओर भी इशारा करती थी।

युद्धों के बीच बदलाव के उन्मादी माहौल में इस छोटे-से गणराज्य के जीवन की झांकी की झलक देती यह किताब *वर्टिगो : द राइज एंड फॉल ऑफ वाइमर जर्मनी* नए गणतंत्र में उन लोगों का परिचय भी कराती है, जो खुद को इस नए माहौल से जोड़ कर नहीं देख पा रहे थे और बाद में यही इसके पतन का कारण भी बने। पुस्तक के लेखक, जो *बर्लिनर जिटुंग* अखबार के पूर्व संपादक, और *आफ्टरमाथ* के लेखक भी हैं, हेराल्ड जाह्नेर, वाइमर गणराज्य के बारे में लिखने में सबसे बड़ी परेशानी यह बताते हैं कि यह 'इतिहास के सबसे आत्म-जागरूक युग के रूप में हमारे सामने है'। कहने का आशय यह है कि जर्मनी के उस दौर के बारे में लिखने के लिए बहुत कम चीजें रह गई हैं, क्योंकि काफी दिलचस्प ढंग से बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इतिहास गवाह है कि वाइमर गणराज्य शुरू से ही संकटग्रस्त था, लेकिन जाह्नेर का तर्क है कि इसका विफल होना पहले से तय नहीं था।

किताब के अनुसार, वाइमर को समझने के दो मुख्य तरीके हैं, इसे एक तरह से सांस्कृतिक और सामाजिक प्रयोग के अंतिम पड़ाव के रूप में देखना, जो बाद में आए फासीवाद से कभी उबर नहीं पाया, या आधुनिक लोकतंत्रों को किन चीजों से बचना चाहिए, यह जानने के लिए नैतिक शिक्षा के स्रोत के रूप में। जाह्नेर ने इसे दोनों तरह से समझने की कोशिश की है, जिसमें तत्कालीन लोगों के भावनात्मक अनुभवों के साथ थोड़ी-सी उपदेश की चाशनी मिलाई गई है।

जाह्नेर बताते हैं, पुराने जर्मन अभिजात वर्ग ने सोचा था कि वे हिटलर और उसके समर्थकों का उपयोग एक सत्तावादी राज्य के लिए लोकप्रिय समर्थन जुटाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अंततः उन्होंने चीजें उलटी कर दीं। यह हिटलर ही था, जिसे वाइमर लोकतंत्र को उसके सत्तावादी मूल तक सीमित करने के तरीके से अधिक लाभ हुआ। वाइमर के बारे में लिखी गई किताब हमें 1933 के पहले की जर्मन चेतना के बारे में अधिक बताती है। यह काल हमें इस तरह याद रहेगा कि आधुनिक जीवन में पहली बार ठोकर खाने का अनुभव कैसा था।

अभियान

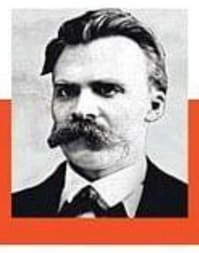

हम जीवन से प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि हम जीने के आदी हैं, बल्कि इसलिए कि हम प्यार करने के आदी हैं। -फ्रेडरिक नीत्शे, जर्मन दार्शनिक

amarujala.com
अमर उजाला

Hindi@mithelesh
■ मिथिलेश बारिया

गोल चबूतरा

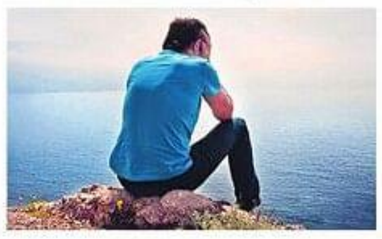

उम्मीदों, ख्वाहिशों के इस पार आ गया,
कोई शख्स मुझमें समझदार आ गया...

.....

इक तरफ आदमी जलता है, इक तरफ तंबाकू,
राख यहां रोज, दोनों तरफ होती है...

5 किलोवाट का ट्रांसमीटर, सामान्य स्टूडियो और डीडी

1959 में आज के ही दिन दिल्ली में दूरदर्शन यानी डीडी का सार्वजनिक प्रसारण शुरू हुआ था। उस समय पांच किलोवाट के ट्रांसमीटर के साथ सामान्य स्टूडियो में एक प्रयोग के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। तब यह आल इंडिया रेडिया का हिस्सा था और कवरेज क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी के आसपास केवल 40 किलोमीटर तक ही था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया था। शुरुआत में प्रतिदिन एक घंटे की अवधि के लिए सप्ताह में केवल दो दिन कार्यक्रम प्रसारित किए जाते थे। उसके बाद 1964 में दिल्ली में स्कूली बच्चों के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किया गया। दूरदर्शन से कार्यक्रमों का दैनिक प्रसारण 1965 में शुरू हुआ। इसके बाद किसानों पर केंद्रित 20 मिनट का कार्यक्रम 'कृषि दर्शन' शुरू हुआ, जिसमें उन्हें कृषि से जुड़े पहलुओं के बारे में जानकारी दी जाती थी। धीरे-धीरे ट्रांसमीटर रेंज में वृद्धि होती गई और दूरदर्शन का प्रसारण क्षेत्र बढ़ता गया। 1975-76 में प्रसारण के लिए सैटेलाइट का प्रयोग किया गया। 1975 तक सात शहरों तक टीवी सेवा पहुंच गई थी। 1976 में रेडियो और टेलीविजन सेवाओं को अलग कर दिया गया। इसके बाद दूरदर्शन वर्षों तक लोगों के मनोरंजन का प्रमुख साधन रहा। आज दूरदर्शन की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है।

झरोखा
15 सितंबर

■ चंबा से पीतांबर लाला

अखाड़े के बाहर
गामा पहलवान

यह तस्वीर 1940 में खींची गई थी, जब पंजाब के पटियाला शहर में काफी समय बाद गामा पहलवान और उनके शिष्य रंजीत सिंह एक-दूसरे से मिले थे।

■ फरीदकोट से हरभजन लाल

ग्रामोफोन

वेटर को बुलाया, बन गया 'रमैया वस्तावैया'

1955 में आई राज कपूर की फिल्म 'श्री 420' का गाना 'रमैया वस्तावैया' बहुत मशहूर हुआ था। इसके बनने की कहानी भी कम रोचक नहीं है। शंकर, जयकिशन, हजरत जयपुरी और शैलेंद्र एक बार खंडाला जाते समय ढाबे पर रुके। वहां रमैया नाम का एक लड़का काम करता था, जो तेलुगु भाषी था। शंकर हैदराबाद में रहे थे और तेलुगु बोल सकते थे। अपने ऑर्डर का इंतजार कर रहे शंकर ने लड़के को तेलुगु में आवाज लगाई- 'रमैया वस्तावैया', जिसका मतलब था, 'यहां कब आओगे?' शैलेंद्र को ये शब्द अच्छे लगे और उन्होंने बार-बार ये शब्द सुर में बोलने शुरू कर दिए। जब वह बार-बार दो शब्द बोल रहे थे तो हसरत जयपुरी ने कहा, 'बस इतना ही?' तो शैलेंद्र ने आगे कहा, 'मैंने दिल तुझको दिया।' सब बोल उठे, 'वाह!' इस तरह बना गाना 'रमैया वस्तावैया'। शैलेंद्र के इस गीत की धुन भी शंकर-जयकिशन ने ही बनाई और आवाज दी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और मुकेश ने। परदे पर इसे नरगिस, राज कपूर और शैला वाज ने गाया।

■ दिव्या सैनी, दिल्ली

सरकार हर साल जलभराव जैसी समस्या से निपटने के लिए करोड़ों रुपये खर्च करती है, मगर हर बरसात में यह समस्या बनी रहती है। क्या प्रशासन के साथ-साथ हम भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं?

लाइलाज समस्या है जलभराव

आमजन को कब मिलेगी निजात?

देश के अधिकांश हिस्सों में वर्षा, जल निकासी की समस्या एक जैसी है। चाहे बड़े महानगर हों या फिर छोटे शहर, कई वर्षों से बाढ़ या जलभराव जैसी समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं। वर्षा जल की निकासी की बेहतर व्यवस्था न होने से अनेक समस्याएं पैदा होती जा रही हैं।

चिट्ठी 1

सरकार हर वर्ष जल निकासी के बेहतर उपाय करने का भरोसा दिलाती है। इसके लिए करोड़ों रुपये का बजट जारी होता है, लेकिन जमीनी हकीकत में कोई परिवर्तन नहीं दिखता। इसी तरह सरकारें बाढ़ और जलभराव से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए भी योजनाएं बनाती हैं, लेकिन अधिकारियों के लापरवाह रवैया के चलते यह भी कागजों तक ही सीमित रहता है। जलभराव जैसी स्थिति पैदा होने के लिए प्रशासन के साथ आम लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। निर्माण करते समय हम सड़क और नालियों पर अतिक्रमण कर देते हैं। कूड़ा-कचरा बेतरतीब ढंग से फेंकते हैं। इससे नालियां जाम हो जाती हैं। बची कसर जिम्मेदार अधिकारी पूरी कर देते हैं, जो न अनियोजित बसावट रोकने के लिए आगे आते हैं और न ही समय रहते नालियों की सफाई कराते हैं। इसके चलते कुछ देर की बरसात में ही शहर जलमग्न हो जाते हैं और वर्षा रूकने के बाद भी जल निकासी नहीं होती है। पूरा शहर थम जाता है। जलभराव आर्थिक नुकसान के साथ-साथ बीमारियों का भी कारण बनता है। जमा पानी में मच्छर पनपने से डेंगू, मलेरिया जैसी संक्रामक बीमारियां फैलने लगती हैं। इनके चलते लोगों को जान तक गंवानी पड़ती है।

ऐसे में इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए सरकारों के साथ आम नागरिकों को भी अपनी आदतों में सुधार करना होगा। हमें जिम्मेदारी समझनी होगी।

■ शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, फिरोजाबाद

फ्रांस से हम कुछ सीखेंगे?

फ्रांस के बाद अब स्वीडन ने भी 12 वर्ष तक के बच्चों के मोबाइल स्क्रीन देखने के अधिकतम दो घंटे तय कर दिए हैं। अपने देश में ऐसी कोई सुगबुगाहट अभी तक नहीं दिखती है, जबकि हालात अत्यधिक गंभीर होते जा रहे हैं।

आज स्कूली बच्चे 15-15 घंटे मोबाइल स्क्रीन पर आंखें टिकाए रहते हैं। माता-पिता भी छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। वह बोल नहीं पाता है, लेकिन रील देखता है। हम मोबाइल के आदी बन चुके हैं। अपने होम वर्क और प्रोजेक्ट वर्क के लिए गूगल सर्च पर निर्भर होते जा रहे हैं। हमारी मदद और कल्पनाओं में उड़ान भरने के लिए बनी यह टेक्नोलॉजी किस तरह पूरे समाज को बर्बाद कर सकती है, भारत इसका उदाहरण है। पढ़ने-लिखने और रचनात्मक दिशा में मोबाइल का उपयोग करने वाले चंद ही लोग होंगे। कुछ एप तो ऐसे हैं कि बे मोबाइल फोन में प्री-इंस्टाल होते हैं और हमारे पास उनको हटाने की भी आजादी नहीं होती है।

चिट्ठी 2

बच्चों में इसका सबसे भयावह असर अपराधों के रूप में देखने को मिल रहा है। हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। आज देश को इंटरनेट पर नियंत्रण के लिए एक नियामक संस्था की सख्त जरूरत है, जो इसके उपयोग को लेकर दिशा-निर्देश बनाए और अपने समाज तथा बच्चों को एक सकारात्मक दिशा की तरफ ले जा सके। इसका सही प्रयोग हो।

■ गोपाल निठल्लानंद, अल्मोड़ा

हर मोड़ पर अतिक्रमण

आजादी के बाद यूं तो हमने हर क्षेत्र में अपनी सुविधानुसार आजादी ढूंढी है, लेकिन अतिक्रमण का मसला अब सिर से ऊपर निकल चुका है। यह समाज के लिए कोढ़ बन चुका है। देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के साथ यह समस्या बढ़ती जा रही है। इसका समाधान भी आसान नहीं दिख रहा है। अब यह सरकारों के लिए एक ऐसा नासूर है, जिसे हटाना लोहे के चने चबाने जैसा है।

चिट्ठी 3

देश में हर मोड़, हर शहर, हर गांव, हर गली, हर स्कूल, हर धार्मिक स्थल के आसपास भयंकर अतिक्रमण है। सबसे अधिक अतिक्रमण व्यस्त बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस अड्डों के पास मिलेगा। इसका सीधा अर्थ है कि जहां भी ज्यादा पैसे कमाने की संभावना दिखती है, वहां अतिक्रमण बढ़ता चला जाता है। कई जगह तो ये हालात हैं कि 60 फीट चौड़ी सड़क आठ फीट की संकरी गली में बदल गई है। अतिक्रमण से अतिक्रमण को जन्म देता है। कई बार प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कोशिश करता है तो राजनीतिक दबाव में कदम पीछे खींचने पड़ते हैं। सरकारों की मजबूत इच्छा शक्ति के बिना यह करना असंभव-सा ही है। अतिक्रमण का सबसे अधिक प्रभाव यातायात पर पड़ता है। एक तरफ लोग घटों जाम में फंसे रहते हैं, दूसरी तरफ बेकार में तेल जलने और हॉर्न बजने से वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। जल्दी के चक्कर में दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। लड़ाई-झगड़ा होता है। नए अतिक्रमण को रोकने के साथ अतिक्रमण विरोधी दस्ते को पूरे अधिकारी देने होंगे, तभी कुछ समाधान हो सकता है।

■ मनीषा पांडे, अंबाला

इनकी चिट्ठियां भी सराहनीय रहीं

जालंधर से राजेश कुमार चौहान, मंडी से नरेन्द्र भारती, आगरा से डॉ. संजय कमठानिया 'शेखर', रायपुर से संजीव ठाकुर, श्रीनगर गढ़वाल से लक्ष्मण पुंडीर, बरेली से दिलीप कुमार गुप्ता, बाड़मेर से किशनलाल वडेरा, कन्नौज से शिवमंगल सिंह, आजमगढ़ से अवनीश कुमार गुप्ता, मुरादाबाद से डॉ. राकेश चक्र, मैनपुरी से दीपक तिवारी 'दिव्य'।

हमें लिखें
abhiyan@amarujala.com

कुछ अलग

बिज्जू का हथियार दुर्गंध है!

नेवला की तरह दिखने वाले हनी बेजर यानी बिज्जू किसी भी जानवर से भिड़ जाते हैं और ज्यादातर जीत भी जाते हैं।

अफ्रीका और दक्षिण-पश्चिम एशिया में पाए जाने वाले हनी बेजर यानी बिज्जू ताकतवर और फुर्तीले होने के साथ ही बेहद दृढ़ भी होते हैं। ये दुनिया में खतरनाक माने जाने वाले जीवों- बिच्छू, अजगर और जहरीले सांपों को अपना शिकार बनाते हैं। साथ ही धमकी मिलने पर तेंदुआ और लकड़बग्घा जैसे बड़े शिकारियों को भी मार गिराते हैं। यहां तक कि भैंस और घोड़े जैसे बड़े आकार के जानवरों को भी पकड़ लेते हैं।

आक्रमण के साथ इनके शरीर की खास बनावट दूसरे जानवरों के हमले को भी निस्तेज कर देती है। लगभग तीन फीट लंबे और काले रंग के बिज्जू के शरीर पर सिर से पैर तक एक सफेद पट्टी होती है। मजबूत दांत इनके आक्रमण को धार देते हैं। ये दांतों से हड्डी से लेकर दुनिया में कठोरतम माने जाने वाले कछुए के खोल तक को कुचलने में सक्षम होते हैं। इनकी मोटी त्वचा आक्रमण के समय इनके लिए ढाल का काम करती है।

खासकर इनकी गर्दन की मोटी एवं ढीली त्वचा आसानी से दूसरे जानवरों की पकड़ से बाहर निकलने में सहायक होती है। इनकी त्वचा पर मधुमक्खी के डंक से लेकर शाही के पंख तक के हमले बेअसर होते हैं। इनके शरीर में एक खास जीन पाया जाता है, जिससे ये दमघोंटू दुर्गंधयुक्त तरल पदार्थ निकालते हैं। इसका उपयोग हनी बेजर अपना इलाका तय करने और शिकारियों को रोकने के लिए करते हैं। इसकी दुर्गंध इतनी तेज होती है कि मधुमक्खी भी अपने छत्ते से बाहर नहीं निकलती है। प्रकृति से मिली खास शारीरिक संरचना हनी बेजर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली और क्रूर जीव बनाती है।

■ जम्मू से पुष्पराज कोठारी

मणिपुर में उम्मीद की कोई किरण नहीं

मणिपुर संदेह, अविश्वास और जातीय संघर्षों के जाल में उलझ गया है। वहां की स्थिति सोच से परे हो गई है। ऐसे में वहां शांति बहाल करना बेहद चुनौतीपूर्ण है।

अपने पिछले कॉलम्स को जब मैं पलट कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने मणिपुर के बारे में उतना नहीं लिखा, जितना लिखना चाहिए था। मैंने मणिपुर पर आखिरी बार 30 जुलाई, 2023 को लिखा था। अब इसे 13 महीने से अधिक समय हो चुका है। यह सभी भारतीयों के साथ मेरे लिए भी शर्मनाक है कि हम सबने इसे अपनी सामूहिक चेतना के अंधेरे कुएं में फेंक दिया है।

पिछले साल जब मैंने लिखा था, तब स्थिति बहुत खराब थी। मैंने तब कहा था, यह जातीयता के खत्म होने की शुरुआत है। मैंने कहा था, "मुझे जो भी रिपोर्ट्स मिली हैं या मैंने पढ़ी हैं, उनसे यही पता चलता है कि इंफाल घाटी में व्यवहारिक रूप से कोई कुकी-जोमी नहीं है और कुकी-जोमी बहुल क्षेत्रों में कोई मैतेई नहीं है। मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अपने गृह कार्यालयों के बाहर तो काम करते हैं, लेकिन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं करते। मैंने यह भी कहा था कि "कोई भी जातीय समूह न तो मणिपुर पुलिस पर भरोसा करता है और न ही कोई हताहतों की आधिकारिक संख्या पर विश्वास करता है।"

सवालों के घेरे में

मैंने जो भी लिखा, वह सब दुर्भाग्य से सच साबित हुआ। संसदीय लोकतंत्र में मणिपुर की दुखद स्थिति के लिए एक या उससे अधिक सत्ताधारियों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। मैं यहां सत्ता में बैठे तीन नामों की चर्चा करूंगा-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

ऐसा लगता है, उन्होंने तय कर रखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मणिपुर की यात्रा नहीं करेंगे। उनके व्यवहार से प्रतीत होता है कि 'जलने दो मणिपुर को, मैं उस धरती पर कदम नहीं रखूंगा।' 9 जून, 2024 को अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से पीएम को इटली (13-14 जून), रूस (8-9 जुलाई), ऑस्ट्रिया (10 जुलाई), पोलैंड (21-22 अगस्त), यूक्रेन (23-24 अगस्त), ब्रुनेई (3-4 सितंबर) और सिंगापुर (4-5 सितंबर) की यात्रा का समय मिल गया। 2024 के बचे हुए महीने में उन्हें अमेरिका, लाओस, सामोस, रूस, अजरबैजान और ब्राजील की यात्रा पर जाना है। समय की कमी से मणिपुर की यात्रा उन्होंने नहीं की, ऐसा नहीं है। उन्होंने इस बेचारे राज्य में न जाने का मन बना रखा है।

मणिपुर की यात्रा न करना उनकी जिद को दिखाता है। गुजरात दंगों, सीएए विरोधी प्रदर्शनों और तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हमें इसकी झलक मिली और तब भी, जब उन्होंने अपने मंत्रियों को संसद के दोनों सदनों में सभी स्थगन प्रस्तावों का विरोध करने का निर्देश दिया, चाहे वह कितना भी जरूरी मामला क्यों न हो।

गृह मंत्री अमित शाह

मणिपुर सरकार में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर राज्य में सुरक्षा बलों की तैनाती तक हर मामले में

पी चिदंबरम
पूर्व केंद्रीय मंत्री

गृह मंत्री अमित शाह शामिल रहे हैं। वह मणिपुर की 'सरकार' हैं। उनके सामने मणिपुर में तेजी से हिंसा बढ़ी है। मणिपुर के लोग सिर्फ बंदूकों और बमों से नहीं लड़ रहे, बल्कि स्वतंत्र भारत में पहली बार एक-दूसरे के खिलाफ लड़ाई में रॉकेट और हथियारबंद ड्रोन प्रयोग हुआ। बीते सप्ताह ही दो जिलों में कर्फ्यू लगाया गया। स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए। पांच जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया। इंफाल की सड़कों पर पुलिस छात्रों से लड़ रही है। सुरक्षा बलों को मजबूती देने के लिए राज्य में सीआरपीएफ की दो अतिरिक्त बटालियन भेजी गई हैं, जबकि राज्य में पहले से ही 26 हजार सुरक्षा बल तैनात हैं।

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह

वह अपने द्वारा बनाए गए हालात में ही घिरे हैं। वह और उनके मंत्री इंफाल घाटी में नहीं घूम पा रहे हैं। कुकी-जोमी समुदाय के लोग उनसे नफरत करते हैं। मैतेई ने सोचा कि वह उनकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन ऐसा करने में उनकी असफलता ने उन्हें पूरे मणिपुर में और मैतेई लोगों के बीच भी अलोकप्रिय बना दिया। लोगों का प्रशासन पर कोई भरोसा नहीं रहा। राज्य में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। उन्हें कई महीने पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनका लगातार पद पर बने रहना कभी गलती न मानने वाली मोदी और शाह की हठधर्मिता को दर्शाता है।

अपनी सोच, अपनी सरकार

सही मायने में मणिपुर में दो राज्य बन गए हैं। चूड़ाचांदपुर, फेरजवाल और कांगपोकपी जिले पूरी तरह कुकी समुदाय के नियंत्रण में हैं। वहीं, तेंग्नौपाल जिले (जिसमें सीमावर्ती शहर मोरेह भी शामिल है) में कुकी-जोमी और नागा समुदाय की मिश्रित आबादी है और यह कुकी-जोमी समुदाय के नियंत्रण में है। यहां पर कुकी-जोमी अपना अलग प्रशासन चलाते हैं। कुकी-जोमी नियंत्रित क्षेत्र में कोई भी मैतई सरकारी कर्मचारी नहीं है, वे घाटी के जिलों में बसे हुए हैं। 60 सदस्यों वाले मणिपुर में 40 मैतेई विधायक हैं और कुकी-जोमी ऐसे राज्य का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, जहां मैतेई बहुमत में हों।

वहीं, मैतेई मणिपुर की पहचान और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं। इसी को लेकर दोनों समुदायों के बीच लड़ाई है। सरकार और दोनों जातीय समूहों- मैतेई एवं कुकी-जोमी के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही है। नागाओं की केंद्र और राज्य सरकारों के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक शिकायतें हैं और वे मैतेई बनाम कुकी-जोमी संघर्ष में उलझना नहीं चाहते हैं।

कहीं कोई रोशनी नहीं!

मणिपुर संदेह, अविश्वास और जातीय संघर्षों के जाल में उलझ गया है। ऐसे में वहां शांति बहाल करना और सरकार चलाना बेहद कठिन है। केंद्र सरकार की उदासीनता और भाजपा द्वारा संचालित राज्य सरकार की अक्षमता के कारण वहां की स्थिति सोच से परे हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री को शायद इस बात का अहसास हो गया है कि केंद्र के एक राज्य मणिपुर की उनकी यात्रा चंद्रमा के अंधेरे हिस्से की यात्रा की तरह खतरनाक हो सकती है।

Licensed by The Indian Express Limited

खुशी का अवसर हो तो 'झोड़ा'

डॉ. राजेन्द्र सिंह क्वीरा

खुला आकाश

विवाह, जनेऊ संस्कार या घर में भगवान की कथा आदि कोई भी शुभ अवसर हो तो 'झोड़ा' की याद आ ही जाती है।

उत्तराखंड के पहाड़ों में कोई शुभ कार्य हो और उसमें झोड़ा न हो, यह लगभग असंभव है। आखिर झोड़े को इसी वजह से मांगल गीत भी कहा जाता है। झोड़ा एक खास लोक नृत्य है, जो सामूहिक गीतों के साथ किया जाता है। पहाड़ों में शुभ कार्य से पहले झोड़ा करने की परंपरा रही है। सभी लोग एक गोल घेरे में खड़े होकर एक दूसरे से हाथ एवं कंधा और कदम मिलाते हुए गाते हैं। घर में शांति और नए कार्य की शुरुआत करने से पहले उसको सफल बनाने की प्रार्थना के रूप में इसका विशेष महत्व है। नए कार्य के साथ इसे विवाह या जनेऊ संस्कार से पहले या घर में भगवान की कथा समेत अन्य अवसर पर भी करने का रिवाज है। यहां की महिलाएं आभूषणों के साथ अपनी पारंपरिक वेशभूषा घाघरा, पिछौड़ा, नथ आदि पहनकर तैयार होती हैं और मंगल (झोड़ा) गीत गाकर शुभ कार्यों की शुरुआत करती हैं। झोड़ा गायन को एकता का प्रतीक भी समझा जाता है, क्योंकि सभी लोग इसे मिल-जुलकर गाते हैं और नृत्य करते हैं।

वहीं, चांचरी की बात करें तो यह कुछ हद तक झोड़ा जैसा ही दिखता है, लेकिन दोनों में अंतर होता है। झोड़ा नृत्य में जहां

हुड़का वादक के साथ नाचने वाले लोग गीत दोहराते हैं, वहीं चांचरी में दो समूह होते हैं। एक समूह दूसरे के बोलों को दोहराता है। इसके लोक गीत खास लोक देवता के साथ-साथ प्रेम-प्रसंग, जीवन-शैली पर आधारित होते हैं। कहा जाता है कि कुमाऊं के जनपद बागेश्वर के दानपुर क्षेत्र की चांचरी को सबसे मनमोहक माना जाता है। 'खोल दे माता खोल भवानी धार में किवाड़ा' एक प्रसिद्ध चांचरी गीत है।

कुमाऊं में झोड़ा गीतों के भी दो रूप प्रचलित हैं। पहला मुक्तक और दूसरा प्रबंधात्मक झोड़ा। इसमें मुक्तक झोड़ा चांचरी जैसा होता है, वहीं प्रबंधात्मक झोड़े में लोक देवी-देवताओं और ऐतिहासिक महापुरुषों का गुणगान होता है। इसके नृत्य की गायन शैली धार्मिक, शृंगारिक और सामाजिक होती है। इसमें महिलाओं के साथ पुरुष भी गोल घेरा बनाकर पारंपरिक गीत गाते और कदम से कदम मिलाकर झूमते हैं।

उत्तराखंड में बढ़ते पलायन के साथ यहां की समृद्धि संस्कृति की पहचान ये लोक नृत्य भी पीछे छूटते जा रहे हैं। अब ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। शहरी क्षेत्रों से तो पूरी तरह गायब ही हो गए हैं। हल्द्वानी और देहरादून जैसे शहरों में आपको किसी खास सांस्कृतिक उत्सव का ही इंतजार करना पड़ता है।

https://t.me/AllNewsPaperPdf

संपादकीय जागरण

(12) रविवार, 15 सितंबर, 2024: भाद्रपद शुक्ल - 12 वि. 2081

मनुष्य की पहचान उसकी संगत और वार्तालाप से हो जाती है

अवैध धार्मिक स्थल

हिमाचल प्रदेश में जिस तरह एक के बाद एक अवैध तरीके से अथवा अतिक्रमण करके बनाई गईं मस्जिदों के मामले सामने आ रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि जब ये अवैध निर्माण हो रहे थे, तब उन्हें कोई रोकने-टोकने वाला नहीं था। इसका पता इससे भी चलता है कि शिमला के बाद मंडी, बिलासपुर समेत कई अन्य जिलों में भी अवैध तरीके से मस्जिद निर्माण के मामले सामने आ गए हैं। शिमला में जिस मस्जिद को अवैध तरीके से बना कहा जा रहा है और जिसके खिलाफ धरना-प्रदर्शन का सिलसिला कायम हुआ, उसे लेकर नगर निगम यह बता सकने की स्थिति में नहीं कि वस्तुस्थिति क्या है। इस मस्जिद का मामला 14 वर्षों से लंबित बताया जा रहा है। यह लापरवाही की हद ही है। शिमला में मस्जिद कमेटी ने मामला शांत करने के लिए यह लिखकर तो दे दिया कि मस्जिद की पांच में से तीन अवैध मंजिलों को वह खुद गिराने को तैयार है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या पहली दो मंजिलें वैध हैं? जब राजधानी शिमला में यह हाल है तो दूरदराज की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। निःसंदेह बात केवल अवैध तरीके से बनी मस्जिदों की ही नहीं है। कहीं पर कोई भी धार्मिक स्थल अवैध रूप से निर्मित नहीं होना चाहिए- वह चाहे मस्जिद हो या मंदिर अथवा अन्य कोई धार्मिक स्थल। यह विडंबना ही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी न तो अवैध तरीके से धार्मिक स्थलों के निर्माण का सिलसिला थम रहा है और न ही अतिक्रमण करके बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाया जा पा रहा है। परिणाम यह है कि अपने देश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण थम नहीं रहा। हिमाचल प्रदेश में मामला केवल मस्जिदों के अवैध तरीके से निर्माण का ही नहीं, डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी में बदलाव का भी है। वास्तव में इसी बदलाव के कारण अवैध तरीके से बनी मस्जिदों पर लोगों की निगाह गई है। डेमोग्राफी में बदलाव की बात खुद राज्य सरकार के मंत्री ने स्वीकार की है। निःसंदेह समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों की डेमोग्राफी में कुछ न कुछ बदलाव होता ही रहता है, लेकिन समस्या तब होती है, जब उसमें असंतुलन कायम होता हुआ दिखता है। यह देखना हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि डेमोग्राफी में असामान्य-अस्वाभाविक बदलाव न हो और वह सामाजिक असंतुलन का कारण न बनने पाए। डेमोग्राफी में असामान्य बदलाव का मुद्दा केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, उत्तराखंड और अन्य अनेक राज्यों अथवा उनके कुछ इलाकों में भी उठ रहा है। चिंता की बात यह है कि कई स्थानों और विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी में बदलाव का कारण घुसपैठ बन रही है। यह किसी से छिपा नहीं कि देश के अनेक इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से भारतीय नागरिक के तौर पर बस रहे हैं।

पर्यावरण संरक्षण की पहल

जलवायु परिवर्तन वैश्विक चिंता का विषय बन चुका है। पर्यावरण संरक्षण के लिए दुनिया भर में सम्मेलन हो रहे हैं, विज्ञानी चेतावनी दे रहे हैं। समय रहते नहीं चेते तो आनी वाली पीढ़ियों को दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। पर्यावरण को हो रहे नुकसान से कोई भी अछूता नहीं है। बिहार की ही बात करें तो भीषण गर्मी, मानसून में सूखी धरती देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि पहले और अब में कितना अंतर आ चुका है। यह अच्छी बात है कि राज्य सरकार पर्यावरण को लेकर गंभीर है और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। अब सरकार ने विभिन्न विभागों से तीन वर्षों की कार्ययोजना मांगी है कि वे पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या करेंगे। इसमें भवन निर्माण विभाग को विशेष रूप से यह बताना है कि वह कितने सरकारी भवनों में जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) की व्यवस्था करेगा। यह सराहनीय पहल है, जिससे वर्षा जल संचयन के प्रति जागरूकता भी आएगी और इसका सदुपयोग भी हो सकेगा। अभी भी राज्य में इसके प्रति बहुत अधिक जागरूकता नहीं है, जबकि भूगर्भीय जलस्तर को मानक के अनुरूप बनाए रखना अनिवार्य है। गर्मी के दिनों में जलस्तर इतना नीचे चला जाता है कि हैंडपंप बेकार हो जाते हैं। दूसरी ओर बोरिंग लगाकर भूगर्भीय जल का दोहन अलग। इसका संतुलन बना रहे, इसके लिए वर्षा जल संचयन जरूरी है। इसी तरह वायु प्रदूषण कम करने के लिए पेड़-पौधों का संरक्षण भी अनिवार्य है। इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। हालांकि, इस वर्ष जैसी गर्मी रही, उसे देखते हुए लोगों में पौधारोपण के प्रति रुचि भी देखी गई। गर्मी तो हर वर्ष पड़ती है, पर जब पेड़-पौधे होते हैं तो उसका अहसास नहीं होता।

पर्यावरण संरक्षण के लिए हर व्यक्ति को आगे आने की जरूरत है, तभी यह अभियान सार्थक सिद्ध हो सकेगा। इसमें आमजन की सहभागिता जरूरी है।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने से हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को लाभ मिलेगा?

आज का सवाल
क्या बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जूनियर डाक्टरों का धरने पर डटे रहना सही है?

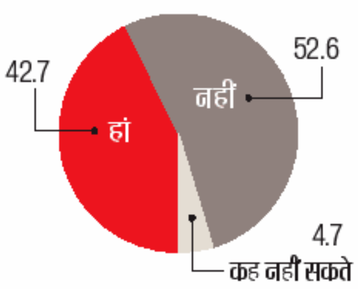

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

कांग्रेस को अलग राह पर ले जाते राहुल

संजय गुप्त

राहुल गांधी का रवैया ऐसा है, जैसे उन्हें नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की कांग्रेस से कोई लेना-देना ही नहीं

राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जो बयान दिए, उन्हें लेकर भारत में विवाद होना ही था और वह हुआ भी। उनके इस बयान पर सबसे अधिक आपत्ति जताई गई कि भारत में लड़ाई इसकी है कि सिख पगड़ी, कड़ा धारण कर पाएंगे या नहीं और गुरुद्वारा जा सकेंगे या नहीं? उन्होंने यह बात अपने कार्यक्रम में उपस्थित एक सिख पत्रकार भलिंदर सिंह विरमानी का नाम पूछने के बाद कही। भाजपा नेताओं ने तो इसका जोरदार विरोध किया ही, खुद भलिंदर सिंह और अन्य सिखों ने भी उस पर आपत्ति जताई। यह इसीलिए जताई, क्योंकि यह बयान वास्तव में उकसावे और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ाने-भिड़ाने वाला है। भारत में वैसा कुछ भी नहीं है, जिसकी आशंका राहुल गांधी जता रहे हैं। क्या कोई और यहां तक कि सिख यह कह सकते हैं कि किसी सिख को पगड़ी, कड़ा धारण करने या फिर गुरुद्वारे जाने से रोका जा रहा है या फिर ऐसा कुछ होने की आशंका दिख रही है।

राहुल गांधी का सिखों को लेकर दिया गया बयान कितना भड़काऊ है, इसे इससे समझा जा सकता है कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उनके कहे को सही करार दिया। एक तरह से राहुल ने खालिस्तानी आतंकियों का ही काम आसान किया। यह तय है कि अब वे उनके बयान का सहारा लेकर भारत के खिलाफ और अधिक दुष्प्रचार करेंगे, लेकिन राहुल गांधी के रवैये से यह साफ है कि उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वह इस पर गौर करने को तैयार नहीं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के कुछ अन्य शहरों में सिखों के खिलाफ जो भीषण दंगे हुए, उन्हें रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया था और उलटे यह कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वास्तव में यही वह दौर था, जब सिख अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित थे। राहुल इसका संज्ञान लेने को भी तैयार नहीं दिख रहे कि इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले को खड़ा करने का जो काम किया, उसके देश को भयावह नतीजे भोगने पड़े। वह पंजाब के संदर्भ में इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक भूलों की अनदेखी ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि खालिस्तानियों को रास आने वाले बयान भी दे रहे हैं। कांग्रेस ने अमेरिका में राहुल गांधी की ओर से सिखों को लेकर दिए गए बयान को सही साबित करने के लिए पंजाब के अपने नेताओं प्रताप सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी को जिस तरह मैदान में उतारा, उससे यही पता चलता है कि राहुल के नेतृत्व में पार्टी यह दर्शाना चाहती है कि उसे कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों से मतलब नहीं। शायद

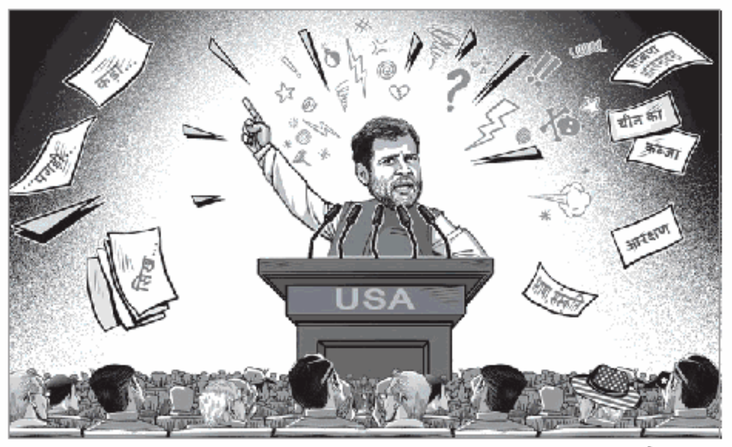

अवधेश राजपूत

इसीलिए इन दोनों नेताओं से यह भी कहलवाया गया कि आपरेशन ब्लूस्टार में भाजपा और आरएसएस का हाथ था। यह केवल खतरनाक नैरेटिव खड़ा करने वाला ही नहीं, बल्कि लोगों को बरगलाने वाला भी झूठ है, लेकिन शायद राहुल गांधी कांग्रेस को अलग राह पर ले जाने के लिए छल-कपट का सहारा लेने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। हैरानी नहीं कि इसी कारण अमेरिका में उन्होंने यह भी कहा कि भारत में तमिल, तेलुगु आदि भाषियों से यह कहा जा रहा है कि उनकी भाषा, संस्कृति और खानपान कमतर है।

राहुल गांधी ने अमेरिका में अपने चिरपरिचित अंदाज में यह भी कहा कि चीन ने भारत की सैकड़ों किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी उससे निपट नहीं पा रहे हैं। वह यह बात न जाने कबसे दोहरा रहे हैं। साफ है कि वह यह भूलना पंसद कर रहे हैं कि चीन ने भारत की भूमि पर उस समय कब्जा किया था, जब कांग्रेस सत्ता में थी। चीन के प्रति जवाहरलाल नेहरू की नरम नीति के नतीजों की अनदेखी कर राहुल गांधी यही रेखांकित कर रहे हैं कि नेहरूजी ने जो भारी भूल की, उससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं।

राहुल ने अमेरिका में यह भी कहा कि जब स्थितियां अनुकूल होंगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जब इसका विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि वह तो आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक करना चाहते हैं। इससे यदि कुछ साफ होता है तो यही कि राहुल इस तथ्य को ओझल करना चाहते हैं कि कांग्रेस किस तरह नीतिगत स्तर पर सदैव आरक्षण के खिलाफ रही। सब जानते हैं कि जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था तो राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया था। आज राहुल गांधी यह सब भूलकर खुद को आरक्षण का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने में लगे हुए हैं। वह कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों के साथ-साथ पार्टी की पुरानी नीतियों से भी किनारा कर रहे हैं। इसका प्रमाण केवल आरक्षण बढ़ाने की उनकी मांग ही नहीं, जातिगत गणना कराने का उनका वादा भी है। ध्यान रहे कि कांग्रेस ने किस तरह सत्ता में रहते समय जातिगत जनगणना कराने से बार-बार इन्कार किया। आज राहुल गांधी जातिगत जनगणना पर जोर देते समय यह बताने को तैयार नहीं कि आखिर कांग्रेस सत्ता में रहते समय जातिगत जनगणना कराने से क्यों इन्कार करती रही? स्पष्ट है कि वह कांग्रेस को बदलने में लगे हुए हैं और इस क्रम में नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की रीति-नीति से भी पल्ला झाड़ रहे हैं। राहुल इसकी कहीं कोई परवाह करते नहीं दिख रहे कि कांग्रेस को नया रूप-स्वरूप देने की उनकी कोशिश पार्टी के पुराने नेताओं को रास आ रही है या नहीं?

भाजपा कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों के आधार पर राहुल गांधी को घेरने की हर संभव कोशिश तो कर रही है, लेकिन वह यही दिखा रहे हैं कि इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी का रवैया ऐसा है, मानो वह यह कहना चाहते हों कि नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की कांग्रेस से उनका कोई नाता नहीं और इन नेताओं ने जो कुछ अच्छा-बुरा किया, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी के इस रुख का सामना कांग्रेस किस तरह करेगी, यह तो वही जाने, लेकिन भाजपा को यह समझ लेना चाहिए कि वह कांग्रेस की गलतियों और उसकी नीतियों का जिक्र करके राहुल को घेरने में कामयाब नहीं होने वाली। स्पष्ट है कि उसे अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा।

response@jagran.com

माइक, मंच और सितंबर का महीना

हास्य-व्यंग्य

अर्चना चतुर्वेदी

फिर आ गया सितंबर, जब हिंदी और हिंदी लेखकों की चर्चा होती है। जय हो सितंबर माह। जय हो हिंदी पखवाड़ा

दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने डाकिया बाबू खड़े थे। हाथ में कुछ किताबों के पैकेट लिए थे। हम किताब लेकर मुड़ते कि उन्होंने प्रश्न दागा-मैडम आप क्या करती हैं? हमने प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो बोले, आपके यहां तीन दिन से किताबें ही आ रही हैं। आज के जमाने में कौन किताब पढ़ता है? पूरी सोसायटी में सिर्फ आपके यहां किताब लेकर आता हूं। एक सांस में अपनी बात कहकर उन्होंने लंबी सांस ली। जैसे ही मैंने कहा कि हम लेखक हैं, उनकी सांसें कुछ पल के लिए थम सी गईं। हिंदी लेखक? उनके मुंह से ऐसे ही कुछ शब्द प्रस्फुटित हुए। हम थोड़े फूले, गर्दन भी थोड़ी अतिरिक्त अकड़ी और चेहरे पर हल्का दंभ टपका। डाकिया बाबू पर कोई असर नहीं पड़ा। वह हमें ऐसे घूरने लगे, मानो हम विलुप्त होती प्रजाति के अंतिम प्राणी हों।

'अच्छा तभी इतनी फ्री किताबें आती हैं आपके घर।' उन्होंने फ्री शब्द पर अतिरिक्त वजन डालते हुए हमारी अकड़ के फूले हुए गुब्बारे में मानो सुई चुभोई। हम थोड़े भिनभिनाए, क्या मतलब है आपका? मैडम जी, हमारा कोई गलत मतलब नहीं। हमने तो इसलिए कहा कि आजकल अंग्रेजी का जमाना है, घर में माताएं भी बच्चे को सेब, केला नहीं, एपल और बनाना खिलाती हैं। सबके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। लोग हिंदी की बात केवल हिंदी दिवस पर हैप्पी हिंदी डे बोलकर करते हैं। डाकिया बाबू ने यह भी पूछा कि मैडम जी आपको तो पता होगा कि लोग केवल हिंदी पखवाड़े में ही हिंदी को क्यों याद करते हैं? बाकी साल क्या करते हैं? हम चुपचाप हिंदी और हिंदी लेखक की दशा पर शोक मनाने की अवस्था को प्राप्त होने ही वाले थे कि डाकिया बाबू फिर उवाचे, वैसे मैडम जी यदि आप जैसे लेखक न हों तो पोस्ट आफिस खत्म ही समझो। हमारी रोजी-रोटी चलाने में लेखकों का बड़ा योगदान है। मुझे लगा कि वह ठंडे पानी के छींटे मारकर हमारे अंदर की बेहोश होती लेखिका को होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। क्या पोस्ट से सिर्फ किताबें ही आती हैं? हमने पूछा। डाकिया बाबू बोले, सिर्फ किताबें तो नहीं, पर ज्यादातर लेखकों और सरकारी कार्यों के लिए ही काम आता है मैडम। सबसे ज्यादा किताबें ही इधर-उधर जाती हैं। इसीलिए तो कहा कि लेखक नहीं होते तो पोस्ट आफिस कबके बंद हो जाते। मैडम अब तो कूरियर और आनलाइन का जमाना आ गया है। इसीलिए शायद सरकार ने भी बुक पोस्ट की सस्ती सेवा बहाल कर रखी है। डाकिया बाबू इतना बोलकर चले गए।

हम भी अपने लटके हुए मुंह और वजनी काया को लिए ड्राइंग रूम में बिछे सोफे पर धम्म से बैठ गए और हिंदी लेखक और हिंदी भाषा की दशा और दिशा पर चिंतन करने लगे। वाकई लेखक और अकादमी न हों तो पोस्ट आफिस में भीड़ भी न हो और हो भी तो केवल रक्षाबंधन के चंद दिन पहले। जो हिंदी 75 वर्ष में राष्ट्रभाषा का दर्जा न पा सकी, वह कमाई की भाषा कैसे ही बन पाएगी? अभी ऐसे विचार हमारे मन में आने की तैयारी कर ही रहे थे कि मोबाइल की घंटी बजी। नया नंबर देख हमने थोड़ी हिचक के साथ फोन उठाया। उधर से आवाज आई, आप फलानी लेखिका बोल रही हैं। जी हां, हमने बड़े ही कोमल भाव से जवाब दिया। जी आपका नंबर हमें ढिकाने लेखक जी से प्राप्त हुआ है। हम आपको हिंदी पखवाड़े के कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहते हैं। यह सुनकर हमारे मन में लड्डू फूटने ही वाले थे कि उधर से आवाज आई, मैडम हमारा बजट थोड़ा कम है। हम ज्यादा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। यह कहकर उन्होंने जो राशि बताई, उसे सुनकर हमारे मन में कई लड्डू एक साथ फूटे और हमने तुरंत हां कर दी और सोचा वैसे कुछ न देते, तब भी हिंदी लेखक कहां मना करता। पिछली बार सितंबर माह में ही तो हिंदी और हिंदी लेखकों की पूछ-परख हुई थी।

फोन कट करते ही हमारे अंदर ऊर्जा का नया संचार हुआ और हम अपने आप से बोले, देखा हम न कहते थे, अपना टाइम आएगा। आ गया फिर से सितंबर, जब हम हिंदी लेखक और गणेश जी सब एक साथ पूजे जाते हैं। जय हो सितंबर माह। जय हो हिंदी पखवाड़ा।

response@jagran.com

ऊर्जा

संसार का सत्य

भारतीय परंपरा में हमारे प्राज्ञों ने अपने ज्ञान और भाषा-कौशल से इस जगत् का जो विश्लेषण किया है, वह है- 'गच्छतीति जगत्'। अर्थात जो निरंतर गमनशील है और कभी भी एक क्षण के लिए रुकता नहीं है वह जगत् है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब से चला है, अभी तक चल रहा है और यह कब तक चलेगा, इसका किसी को पता नहीं है इसीलिए यह जगत् है। इसके बाद जब यह जिज्ञासा की गई कि यहां का चलने वाला प्राणी कहां से चला है, क्या लेकर चला है और कहां जाएगा तो इसका भी निश्चयात्मक उत्तर आज तक कोई दे नहीं सका। इसी के साथ कोई भी यह नहीं बता सका कि इसके साथ दूसरा और कोई था या नहीं?

शास्त्रों ने जब बहुत अधिक विचार-मंथन किया और दार्शनिकों ने अपनी तर्क दृष्टि रखी तो यह कहा गया कि कोई एक सत्, चित् ब्रह्म है और सभी जीव जिसके अंश हैं, उसी के अंश इस जगत् में आते हैं। इनके साथ न तो कोई होता है और न ही ये साथ में कुछ लाते हैं तथा न ही अपने साथ कुछ ले जाते हैं। यह तो प्रत्यक्ष ही है कि सभी के सभी प्राणी इस धरती पर नग्न होकर आते हैं और वापस नग्न होकर ही जाते हैं। इस जगत् की जैसी स्थिति है उसके अनुसार एक दूसरी परिभाषा भी दी गई है, वह है- 'जागर्तीति जगत्।' इसका अभिप्राय यह होता है कि जो निरंतर जागता रहता है, उसे जगत् कहते हैं। यहां पर भी हम यह तो प्रत्यक्ष देखते ही हैं कि इस धरती का जीव मात्र समयानुरूप जागता ही है, किंतु जागते हुए भी वह इस संसार के सत्य को यथार्थ रूप में नहीं देख पाता। इसीलिए वह अपने शरीर, अपने परिवारी जनों तथा मित्रों को भी अपना मानने लगता है और अपने साथ उनके संबंध को अपना मानकर मोहाविष्ट हो जाता है। फलतः दुखी रहता है और नित्य स्वरूप आत्मा को देखना भूल जाता है। यही कारण है कि हमारे विज्ञ निरंतर चलते हुए और जागते हुए भी संसार में व्याप्त परम सत्य का अनुभव करके मनुष्य को कल्याण के मार्ग पर चलने का निर्देश करते हैं। इसी से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है।

डा. गदाधर त्रिपाठी

तथ्य-कथ्य

भारत के कृषि उत्पादों का निर्यात

(आंकड़े लाख करोड़ रुपये में)

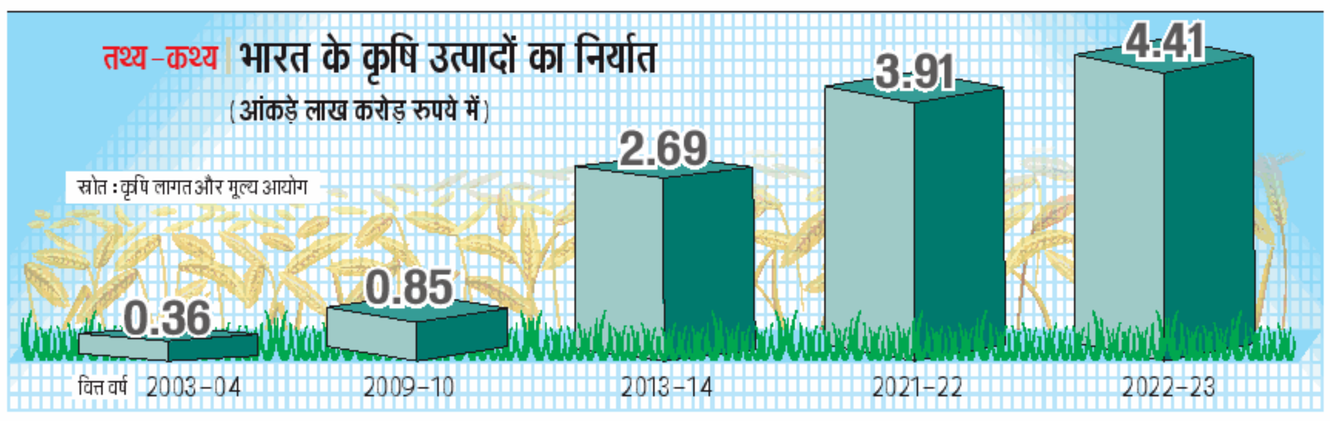

एक अनार सौ बीमार

कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के ऊपर तलवार लटकी हुई है। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है और राज्यपाल मामला चलाने की इजाजत दे चुके हैं। फिलहाल गेंद कोर्ट के पाले में है। इस बीच हालांकि सिद्दरमैया खुद बार-बार कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो, वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन सरकार के अंदर ही दावेदारी ऐसी शुरू हुई है कि एक दो नहीं, 11 मंत्री यह जता चुके हैं कि अवसर मिले तो वे क्यों नहीं? ऐसा भी नहीं कि पर्दे के पीछे केवल नेतृत्व से यह बात बताई हो, खुलेआम जी परमेश्वरा, सतीश जारकीहोली, एमबी पाटिल जैसे कई नेता कह चुके हैं कि फिलहाल तो सिद्दरमैया हैं, उन्हें पार्टी का समर्थन भी है, लेकिन अगर रिक्ति हुई तो उनमें भी काबिलियत है। उपमुख्यमंत्री शिवकुमार, जो दावेदारी में सबसे आगे हैं, हाल में अमेरिका के उस शहर भी पहुंच गए, जहां राहुल गांधी रुके हुए थे, पर इस सबमें सबसे रोचक एंट्री एक ऐसे नेता की हुई है, जो पहले दूर-दूर तक दावेदार नहीं दिख रहे थे। कर्नाटक के एक ज्योतिषी प्रशांत कीनी ने एक्स पर कहा है कि 2025 में सिद्दरमैया मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो उनकी जगह एक महिला लक्ष्मी हेब्बालकर मुख्यमंत्री बनेंगी। ध्यान रहे कुछ माह पहले ही कर्नाटक में शिवकुमार को छोड़कर तीन और उपमुख्यमंत्री बनाने की भी बात उठी थी।

राजरंग

भवन की किस्मत

सरकार की तरह ही सरकारी भवनों का भी अपना रुतबा होता है। कई बार यह रुतबा वक्त के साथ बढ़ता या घटता रहता है। ऐसा ही हुआ है नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन के साथ। कभी प्रवासी भारतीय मंत्रालय के कार्यालय के तौर पर इसका निर्माण हुआ, लेकिन बाद में यह मंत्रालय ही खत्म हो गया। उसके बाद से यहां लंबे समय तक वीरानगी का माहौल रहा, फिर जी-20 का आयोजन हुआ तो यहां एक साल तक चहल-पहल रही, लेकिन फिर वीरानगी का आलम शुरू हो गया था कि पीएम मोदी के एक बयान ने इसकी किस्मत को फिर से चमका दिया। पीएम ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को कहा कि अब वे सूचनाओं-जानकारियों के प्रचार-प्रसार पर ज्यादा ध्यान दें। इसका नतीजा यह हुआ कि एक के बाद एक मंत्रालय सुषमा स्वराज भवन में कार्यक्रम करने लगे हैं। दो सप्ताह के भीतर कृषि, पशुपालन और स्वच्छता से जुड़े तीन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आने वाले दिनों में भी दूसरे मंत्रालयों की तरफ से बुकिंग करवाई गई है।

समय से पहले

नेता-मंत्री अक्सर प्रेस कांफ्रेंस में देर से आने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक ऐसे मंत्री भी हैं, जो निर्धारित समय से पहले पहुंच जाते हैं और प्रेस कांफ्रेंस शुरू करने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है। हाल में पत्रकारों को कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी देने के लिए शाम साढ़े सात बजे का समय निर्धारित किया गया था। पत्रकार भी अमूमन यह मानकर चलते हैं कि मंत्रीजी की प्रेस कांफ्रेंस पांच-सात मिनट देर से शुरू होगी, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव समय से पहले पहुंच गए और कैबिनेट के फैसले का प्रस्तुतीकरण देने की तैयारी करने लगे कि वहां मौजूद अधिकारी ने उन्हें ध्यान दिलाया कि अभी साढ़े सात नहीं बजे हैं। प्रेस कांफ्रेंस का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण भी होता है और वह तय समय पर ही लाइव होता है। अधिकारी की बात को समझते हुए मंत्रीजी को कुछ समय इंतजार करना पड़ा और फिर निर्धारित समय पर उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस शुरू की।

जनवरी का इंतजार

जनवरी का इंतजार सिर्फ अमेरिका को ही नहीं है, जब वहां नया राष्ट्रपति आएगा। भारत में भी है, खासतौर पर भाजपा में, जब नया अध्यक्ष पार्टी को मिलेगा। नए अध्यक्ष को लेकर असमंजस की स्थिति भाजपा पदाधिकारियों के इंतजार को भारी बना रही है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। सुनील बंसल, विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक कई नाम हवा में तैर रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन बनेगा या फिर इससे बाहर का कोई व्यक्ति बाजी मार जाएगा, समय ही बता सकेगा। हां, इतना तय है कि नया अध्यक्ष पूरे संगठन को नए सिरे से खड़ा करेगा। इसमें किस-किस का पत्ता कट जाएगा, कोई नहीं जानता। पार्टी के सभी पदाधिकारी चुपचाप समय का इंतजार कर रहे हैं और खुद को केवल रूटीन के काम तक सीमित रखे हुए हैं। शायद यही कारण है कि पार्टी मुख्यालय की दूसरी और तीसरी मंजिल, जहां पार्टी महासचिव और सचिव बैठते हैं, आजकल सूनी नजर आती हैं।

पोस्ट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं। जमानत की दो शर्तें दिलचस्प हैं। एक, वह अपने सरकारी आफिस नहीं जा सकते। दो, किसी सरकारी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। फिर भी वह मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। क्यों? यह सत्ता का कैसा मोह है? संजय निरुपम@sanjaynirupam

चीफ जस्टिस के घर पर पीएम मोदी की तस्वीरें देखकर लोकतंत्र की हत्या का केस रजिस्टर कराकर लौटा इकोसिस्टम केजरीवाल की सशर्त जमानत पर लोकतंत्र के बर्थ डे सेलिब्रेशन का कार्ड बांट रहा है। यही हाल ईवीएम का कर रखा है, जब मन मार देते हैं, जब मन जिंदा कर देते हैं। सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

लोग जब मुझसे कहते हैं कि हिंदी में तकनीक और उद्योग के काम वैश्विक स्तर पर कैसे किए जा सकते हैं? तो मैं उनसे ही पूछता हूं कि चीन, जापान और जर्मनी ने क्या अपनी भाषा को साथ लेकर प्रगति नहीं की?

अनिल अग्रवाल@AnilAgarwal_Ved

सभी धार्मिक स्थलों पर सभी तरह के वीआइपी दर्शन की व्यवस्था तुरंत प्रतिबंधित कर देनी चाहिए। ईश्वर के सामने कोई भी विशिष्ट नहीं है। कृपया इस कुप्रथा पर रोक लगाइए। प्रयाग@theprayagtiwari

जनपथ

सैंतालिस में था दिया जिसने भारत तोड़,
वही रहे हैं आज भी आजादी को गोड़।
आजादी को गोड़ घूमते रूठे-रूठे,
चाह रहे हैं आज देश यह फिर से टूटे!
लीपापोती और बहाने करिये चालिस,
पर दोहराना आप चाहते हैं सैंतालिस!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एजीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त

जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प, बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 25 अंक 155

****

दैनिक जागरण

मनुष्य की पहचान उसकी संगत और वार्तालाप से हो जाती है

अवैध धार्मिक स्थल

हिमाचल प्रदेश में जिस तरह एक के बाद एक अवैध तरीके से अथवा अतिक्रमण करके बनाई गईं मस्जिदों के मामले सामने आ रहे हैं, उनसे यह स्पष्ट है कि जब ये अवैध निर्माण हो रहे थे, तब उन्हें कोई रोकने-टोकने वाला नहीं था। इसका पता इससे भी चलता है कि शिमला के बाद मंडी, बिलासपुर समेत कई अन्य जिलों में भी अवैध तरीके से मस्जिद निर्माण के मामले सामने आ गए हैं। शिमला में जिस मस्जिद को अवैध तरीके से बना कहा जा रहा है और जिसके खिलाफ धरना-प्रदर्शन का सिलसिला कायम हुआ, उसे लेकर नगर निगम यह बता सकने की स्थिति में नहीं कि वस्तुस्थिति क्या है। इस मस्जिद का मामला 14 वर्षों से लंबित बताया जा रहा है। यह लापरवाही की हद ही है। शिमला में मस्जिद कमेटी ने मामला शांत करने के लिए यह लिखकर तो दे दिया कि मस्जिद की पांच में से तीन अवैध मंजिलों को वह खुद गिराने को तैयार है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या पहली दो मंजिलें वैध हैं? जब राजधानी शिमला में यह हाल है तो दूरदराज की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। निःसंदेह बात केवल अवैध तरीके से बनी मस्जिदों की ही नहीं है। कहीं पर कोई भी धार्मिक स्थल अवैध रूप से निर्मित नहीं होना चाहिए- वह चाहे मस्जिद हो या मंदिर अथवा अन्य कोई धार्मिक स्थल। यह विडंबना ही है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी न तो अवैध तरीके से धार्मिक स्थलों के निर्माण का सिलसिला थम रहा है और न ही अतिक्रमण करके बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाया जा पा रहा है। परिणाम यह है कि अपने देश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण थम नहीं रहा।

हिमाचल प्रदेश में मामला केवल मस्जिदों के अवैध तरीके से निर्माण का ही नहीं, डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी में बदलाव का भी है। वास्तव में इसी बदलाव के कारण अवैध तरीके से बनी मस्जिदों पर लोगों की निगाह गई है। डेमोग्राफी में बदलाव की बात खुद राज्य सरकार के मंत्री ने स्वीकार की है। निःसंदेह समय के साथ विभिन्न क्षेत्रों की डेमोग्राफी में कुछ न कुछ बदलाव होता ही रहता है, लेकिन समस्या तब होती है, जब उसमें असंतुलन कायम होता हुआ दिखता है। यह देखना हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि डेमोग्राफी में असामान्य-अस्वाभाविक बदलाव न हो और वह सामाजिक असंतुलन का कारण न बनने पाए। डेमोग्राफी में असामान्य बदलाव का मुद्दा केवल हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, उत्तराखंड और अन्य अनेक राज्यों अथवा उनके कुछ इलाकों में भी उठ रहा है। चिंता की बात यह है कि कई स्थानों और विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी में बदलाव का कारण घुसपैठ बन रही है। यह किसी से छिपा नहीं कि देश के अनेक इलाकों में बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से भारतीय नागरिक के तौर पर बस रहे हैं।

दूर की जाएं भ्रांतियां

बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण करा रही है। इसके लिए अभियान चल रहा है। सरकार की सदिच्छा और अभियान की आवश्यकता पर कोई प्रश्न नहीं है। यह प्रमाणित तथ्य है कि भूमि विवाद अपराध का बड़ा कारण है। आंकड़े बताते हैं कि अपराध की साठ प्रतिशत से अधिक घटनाएं इसके कारण होती हैं। इसके अलावा विभिन्न अदालतों में भी भूमि विवाद से जुड़े ढेर सारे मामले लंबित हैं। यह ऐसा विवाद बन चुका है, जिसमें संबंधों की कोई प्रतिष्ठा नहीं रखी जाती है। सगे भाइयों के बीच भी जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हो जाता है। भूमि सर्वेक्षण का लक्ष्य यह है कि राज्य के कुल रकबा का रिकार्ड बन जाए, ताकि भूमि पर स्वामित्व को लेकर छोटा या बड़ा विवाद न हो, किन भू धारियों के एक हिस्से में सर्वेक्षण को लेकर बेचैनी है। कारण कुछ भी हो, सच यह भी है कि सर्वेक्षण को लेकर सुनियोजित तरीके से कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। इसके तहत प्रचारित किया जा रहा है कि सरकार ऐसी सभी जमीन छीन लेगी, जिसपर किसी का पक्का दावा प्रमाणित नहीं होगा। सरकार बार-बार दोहरा रही है कि उसका इरादा किसी को उसके वैध कब्जे वाली पुश्तैनी, केबाला, पर्चा या अन्य कागजात के आधार पर हासिल जमीन से बेदखल करने का नहीं है। जमीन पर दावा के लिए कई विकल्प दिए गए हैं। फिर भी सभी लोग भूमि सर्वेक्षण से भविष्य में होने वाले लाभ से परिचित नहीं हैं। यह समय है कि सरकार अपना पक्ष आम आदमी को बताए। उन्हें यह भी बताए कि कुछ शक्तियां क्यों इस ऐतिहासिक और राज्य के लिए आवश्यक अभियान का विरोध कर रही हैं।

कुछ शक्तियां राज्य के लिए आवश्यक भूमि सर्वेक्षण अभियान का विरोध कर रही हैं। आमजन की भ्रांतियों को दूर करना जरूरी है

कांग्रेस को अलग राह पर ले जाते राहुल

संजय गुप्त

राहुल गांधी का रवैया ऐसा है, जैसे उन्हें नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की कांग्रेस से कोई लेना-देना ही नहीं

अवधेश राजपूत

राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान जो बयान दिए, उन्हें लेकर भारत में विवाद होना ही था और वह हुआ भी। उनके इस बयान पर सबसे अधिक आपत्ति जताई गई कि भारत में लड़ाई इसकी है कि सिख पगड़ी, कड़ा धारण कर पाएंगे या नहीं और गुरुद्वारा जा सकेंगे या नहीं? उन्होंने यह बात अपने कार्यक्रम में उपस्थित एक सिख पत्रकार भलिंदर सिंह विरमानी का नाम पूछने के बाद कही। भाजपा नेताओं ने तो इसका जोरदार विरोध किया ही, खुद भलिंदर सिंह और अन्य सिखों ने भी उस पर आपत्ति जताई। यह इसीलिए जताई, क्योंकि यह बयान वास्तव में उकसावे और अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों को लड़ाने-भिड़ाने वाला है। भारत में वैसा कुछ भी नहीं है, जिसकी आशंका राहुल गांधी जता रहे हैं। क्या कोई और यहां तक कि सिख यह कह सकते हैं कि किसी सिख को पगड़ी, कड़ा धारण करने या फिर गुरुद्वारे जाने से रोका जा रहा है या फिर ऐसा कुछ होने की आशंका दिख रही है।

राहुल गांधी का सिखों को लेकर दिया गया बयान कितना भड़काऊ है, इसे इससे समझा जा सकता है कि खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने उनके कहे को सही करार दिया। एक तरह से राहुल ने खालिस्तानी आतंकियों का ही काम आसान किया। यह तय है कि अब वे उनके बयान का सहारा लेकर भारत के खिलाफ और अधिक दुष्प्रचार करेंगे, लेकिन राहुल गांधी के रवैये से यह साफ है कि उन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और वह इस पर गौर करने को तैयार नहीं कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के कुछ अन्य शहरों में सिखों के खिलाफ जो भीषण दंगे हुए, उन्हें रोकने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया था और उलटे यह कहा था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। वास्तव में यही वह दौर था, जब सिख अपनी सुरक्षा को लेकर आशंकित थे। राहुल इसका संज्ञान लेने को भी तैयार नहीं दिख रहे कि इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले को खड़ा करने का जो काम किया, उसके देश को भयावह नतीजे भोगने पड़े। वह पंजाब के संदर्भ में इंदिरा गांधी की ऐतिहासिक भूलों की अनदेखी ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि खालिस्तानियों को रास आने वाले बयान भी दे रहे हैं। कांग्रेस ने अमेरिका में राहुल गांधी की ओर से सिखों को लेकर दिए गए बयान को सही साबित करने के लिए पंजाब के अपने नेताओं प्रताप सिंह बाजवा और चरणजीत सिंह चन्नी को जिस तरह मैदान में उतारा, उससे यही पता चलता है कि राहुल के नेतृत्व में पार्टी यह दर्शाना चाहती है कि उसे कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों से मतलब नहीं। शायद इसीलिए इन दोनों नेताओं से यह भी कहलवाया गया कि आपरेशन ब्लूस्टार में भाजपा और आरएसएस का हाथ था। यह केवल खतरनाक नैरेटिव खड़ा करने वाला ही नहीं, बल्कि लोगों को बरगलाने वाला भी झूठ है, लेकिन शायद राहुल गांधी कांग्रेस को अलग राह पर ले जाने के लिए छल-कपट का सहारा लेने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। हैरानी नहीं कि इसी कारण अमेरिका में उन्होंने यह भी कहा कि भारत में तमिल, तेलुगु आदि भाषियों से यह कहा जा रहा है कि उनकी भाषा, संस्कृति और खानपान कमतर है।

राहुल गांधी ने अमेरिका में अपने चिरपरिचित अंदाज में यह भी कहा कि चीन ने भारत की सैकड़ों किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी उससे निपट नहीं पा रहे हैं। वह यह बात न जाने कबसे दोहरा रहे हैं। साफ है कि वह यह भूलना पसंद कर रहे हैं कि चीन ने भारत की भूमि पर उस समय कब्जा किया था, जब कांग्रेस सत्ता में थी। चीन के प्रति जवाहरलाल नेहरू की नरम नीति के नतीजों की अनदेखी कर राहुल गांधी यही रेखांकित कर रहे हैं कि नेहरूजी ने जो भारी भूल की, उससे उन्हें कोई मतलब ही नहीं।

राहुल ने अमेरिका में यह भी कहा कि जब स्थितियां अनुकूल होंगी तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। जब इसका विरोध हुआ तो उन्होंने कहा कि वह तो आरक्षण को 50 प्रतिशत से अधिक करना चाहते हैं। इससे यदि कुछ साफ होता है तो यही कि राहुल इस तथ्य को ओझल करना चाहते हैं कि कांग्रेस किस तरह नीतिगत स्तर पर सदैव आरक्षण के खिलाफ रही। सब जानते हैं कि जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था तो राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया था। आज राहुल गांधी यह सब भूलकर खुद को आरक्षण का सबसे बड़ा पैरोकार साबित करने में लगे हुए हैं। वह कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों के साथ-साथ पार्टी की पुरानी नीतियों से भी किनारा कर रहे हैं। इसका प्रमाण केवल आरक्षण बढ़ाने की उनकी मांग ही नहीं, जातिगत गणना कराने का उनका वादा भी है। ध्यान रहे कि कांग्रेस ने किस तरह सत्ता में रहते समय जातिगत जनगणना कराने से बार-बार इन्कार किया। आज राहुल गांधी जातिगत जनगणना पर जोर देते समय यह बताने को तैयार नहीं कि आखिर कांग्रेस सत्ता में रहते समय जातिगत जनगणना कराने से क्यों इन्कार करती रही? स्पष्ट है कि वह कांग्रेस को बदलने में लगे हुए हैं और इस क्रम में नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की रीति-नीति से भी पल्ला झाड़ रहे हैं। राहुल इसकी कहीं कोई परवाह करते नहीं दिख रहे कि कांग्रेस को नया रूप-स्वरूप देने की उनकी कोशिश पार्टी के पुराने नेताओं को रास आ रही है या नहीं?

भाजपा कांग्रेस की ऐतिहासिक भूलों के आधार पर राहुल गांधी को घेरने की हर संभव कोशिश तो कर रही है, लेकिन वह यही दिखा रहे हैं कि इससे उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी का रवैया ऐसा है, मानो वह यह कहना चाहते हों कि नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी की कांग्रेस से उनका कोई नाता नहीं और इन नेताओं ने जो कुछ अच्छा-बुरा किया, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं। राहुल गांधी के इस रुख का सामना कांग्रेस किस तरह करेगी, यह तो वही जाने, लेकिन भाजपा को यह समझ लेना चाहिए कि वह कांग्रेस की गलतियों और उसकी नीतियों का जिक्र करके राहुल को घेरने में कामयाब नहीं होने वाली। स्पष्ट है कि उसे अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार करना होगा।

response@jagran.com

माइक, मंच और सितंबर का महीना

हास्य-व्यंग्य

अर्चन चतुर्वेदी

फिर आ गया सितंबर, जब हिंदी और हिंदी लेखकों की चर्चा होती है। जय हो सितंबर माह। जय हो हिंदी पखवाड़ा

दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने डाकिया बाबू खड़े थे। हाथ में कुछ किताबों के पैकेट लिए थे। हम किताब लेकर मुड़ते कि उन्होंने प्रश्न दागा-मैडम आप क्या करती हैं? हमने प्रश्नवाचक निगाह से देखा तो बोले, आपके यहां तीन दिन से किताबें ही आ रही हैं। आज के जमाने में कौन किताब पढ़ता है? पूरी सोसायटी में सिर्फ आपके यहां किताब लेकर आता हूं। एक सांस में अपनी बात कहकर उन्होंने लंबी सांस ली। जैसे ही मैंने कहा कि हम लेखक हैं, उनकी सांसें कुछ पल के लिए थम सी गईं। हिंदी लेखक? उनके मुंह से ऐसे ही कुछ शब्द प्रस्फुटित हुए। हम थोड़े फूले, गर्दन भी थोड़ी अतिरिक्त अकड़ी और चेहरे पर हल्का दंभ टपका। डाकिया बाबू पर कोई असर नहीं पड़ा। वह हमें ऐसे घूरने लगे, मानो हम विलुप्त होती प्रजाति के अंतिम प्राणी हों।

'अच्छा तभी इतनी फ्री किताबें आती हैं आपके घर।' उन्होंने फ्री शब्द पर अतिरिक्त वजन डालते हुए हमारी अकड़ के फूले हुए गुब्बारे में मानो सुई चुभोई। हम थोड़े भिनभिनाए, क्या मतलब है आपका? मैडम जी, हमारा कोई गलत मतलब नहीं। हमने तो इसलिए कहा कि आजकल अंग्रेजी का जमाना है, घर में माताएं भी बच्चे को सेब, केला नहीं, एपल और बनाना खिलाती हैं। सबके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं। लोग हिंदी की बात केवल हिंदी दिवस पर हैप्पी हिंदी डे बोलकर करते हैं। डाकिया बाबू ने यह भी पूछा कि मैडम जी आपको तो पता होगा कि लोग केवल हिंदी पखवाड़े में ही हिंदी को क्यों याद करते हैं? बाकी साल क्या करते हैं? हम चुपचाप हिंदी और हिंदी लेखक की दशा पर शोक मनाने की अवस्था को प्राप्त होने ही वाले थे कि डाकिया बाबू फिर उवाचे, वैसे मैडम जी यदि आप जैसे लेखक न हों तो पोस्ट आफिस खत्म ही समझो। हमारी रोजी-रोटी चलाने में लेखकों का बड़ा योगदान है। मुझे लगा कि वह ठंडे पानी के छींटे मारकर हमारे अंदर की बेहोश होती लेखिका को होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। क्या पोस्ट से सिर्फ किताबें ही आती हैं? हमने पूछा। डाकिया बाबू बोले, सिर्फ किताबें तो नहीं, पर ज्यादातर लेखकों और सरकारी कार्यों के लिए ही काम आता है मैडम। सबसे ज्यादा किताबें ही इधर-उधर जाती हैं। इसीलिए तो कहा कि लेखक नहीं होते तो पोस्ट आफिस कबके बंद हो जाते। मैडम अब तो कूरियर और आनलाइन का जमाना आ गया है। इसीलिए शायद सरकार ने भी बुक पोस्ट की सस्ती सेवा बहाल कर रखी है। डाकिया बाबू इतना बोलकर चले गए।

हम भी अपने लटके हुए मुंह और वजनी काया को लिए ड्राइंग रूम में बिछे सोफे पर धम्म से बैठ गए और हिंदी लेखक और हिंदी भाषा की दशा और दिशा पर चिंतन करने लगे। वाकई लेखक और अकादमी न हों तो पोस्ट आफिस में भीड़ भी न हो और हो भी तो केवल रक्षाबंधन के चंद दिन पहले। जो हिंदी 75 वर्ष में राष्ट्रभाषा का दर्जा न पा सकी, वह कमाई की भाषा कैसे ही बन पाएगी? अभी ऐसे विचार हमारे मन में आने की तैयारी कर ही रहे थे कि मोबाइल की घंटी बजी। नया नंबर देख हमने थोड़ी हिचक के साथ फोन उठाया। उधर से आवाज आई, आप फलानी लेखिका बोल रही हैं। जी हां, हमने बड़े ही कोमल भाव से जवाब दिया। जी आपका नंबर हमें ढिकाने लेखक जी से प्राप्त हुआ है। हम आपको हिंदी पखवाड़े के कार्यक्रम में आमंत्रित करना चाहते हैं। यह सुनकर हमारे मन में लड्डू फूटने ही वाले थे कि उधर से आवाज आई, मैडम हमारा बजट थोड़ा कम है। हम ज्यादा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। यह कहकर उन्होंने जो राशि बताई, उसे सुनकर हमारे मन में कई लड्डू एक साथ फूटे और हमने तुरंत हां कर दी और सोचा वैसे कुछ न देते, तब भी हिंदी लेखक कहां मना करता। पिछली बार सितंबर माह में ही तो हिंदी और हिंदी लेखकों की पूछ-परख हुई थी।

response@jagran.com

ऊर्जा

संसार का सत्य

भारतीय परंपरा में हमारे प्राज्ञों ने अपने ज्ञान और भाषा-कौशल से इस जगत् का जो विश्लेषण किया है, वह है- 'गच्छतीति जगत्'। अर्थात जो निरंतर गमनशील है और कभी भी एक क्षण के लिए रुकता नहीं है वह जगत् है। जब से चला है, अभी तक चल रहा है और यह कब तक चलेगा, इसका किसी को पता नहीं है इसीलिए यह जगत् है। इसके बाद जब यह जिज्ञासा की गई कि यहां का चलने वाला प्राणी कहां से चला है, क्या लेकर चला है और कहां जाएगा तो इसका भी निश्चयात्मक उत्तर आज तक कोई दे नहीं सका। इसी के साथ कोई भी यह नहीं बता सका कि इसके साथ दूसरा और कोई था या नहीं?

शास्त्रों ने जब बहुत अधिक विचार-मंथन किया तो यह कहा गया कि कोई एक सत्, चित् ब्रह्म है और सभी जीव जिसके अंश हैं, उसी के अंश इस जगत् में आते हैं। इनके साथ न तो कोई होता है और न ही ये साथ में कुछ लाते हैं तथा न ही अपने साथ कुछ ले जाते हैं। यह तो प्रत्यक्ष ही है कि सभी प्राणी नग्न होकर आते हैं और नग्न होकर ही जाते हैं। इस जगत् की जैसी स्थिति है उसके अनुसार एक दूसरी परिभाषा भी दी गई है, वह है- 'जागर्तीति जगत्।' इसका अभिप्राय यह होता है कि जो निरंतर जागता रहता है, उसे जगत कहते हैं। यहां पर भी हम यह तो प्रत्यक्ष देखते ही हैं कि इस धरती का जीव मात्र समयानुरूप जागता ही है, किंतु जागते हुए भी वह इस संसार के सत्य को यथार्थ रूप में नहीं देख पाता। इसीलिए वह अपने शरीर, अपने परिवारी जनों तथा मित्रों को भी अपना मानने लगता है और अपने साथ उनके संबंध को अपना मानकर मोहाविष्ट हो जाता है। फलतः दुखी रहता है और नित्य स्वरूप आत्मा को देखना भूल जाता है। यही कारण है कि हमारे विज्ञ निरंतर चलते हुए और जागते हुए भी संसार में व्याप्त परम सत्य का अनुभव करके मनुष्य को कल्याण के मार्ग पर चलने का निर्देश करते हैं।

डा. गदाधर त्रिपाठी

तथ्य-कथ्य

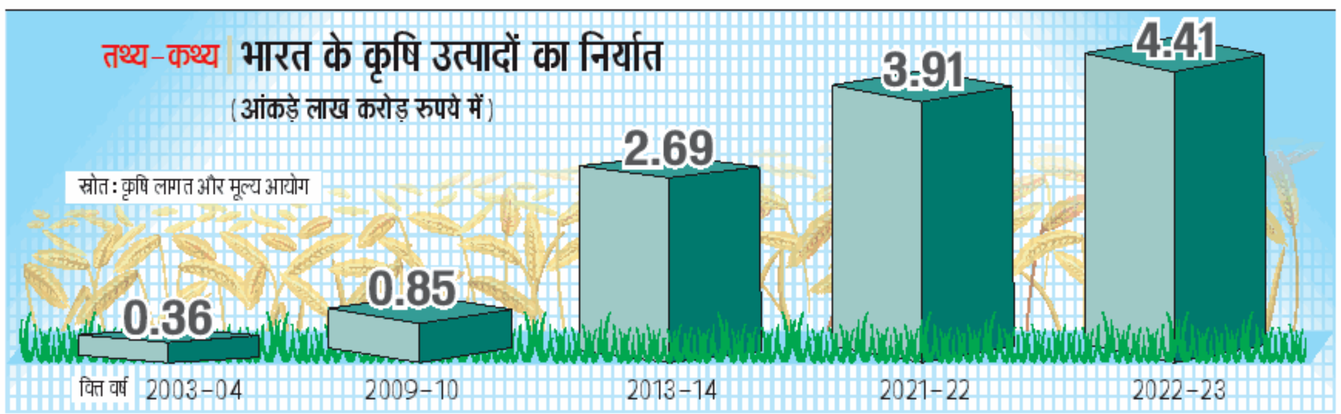

पृथ्वी के आंतरिक कोर का रहस्य

मुकुल व्यास

धरती की सतह से लगभग 2,890 किमी की दूरी पर तरल धातु की एक विशाल गेंद है। यह हमारे ग्रह का सबसे भीतरी भाग है

हमारे पैरों के नीचे लगभग 2,890 किलोमीटर की दूरी पर तरल धातु की एक विशाल गेंद है। यह हमारे ग्रह का आंतरिक कोर (सबसे भीतरी भाग) है। विज्ञानी पिछले काफी समय से इस आंतरिक भाग के रहस्यों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। भूकंप द्वारा उत्पन्न भूकंपीय तरंगों का उपयोग कोर के आकार और संरचना को 'देखने' के लिए किया जाता है। शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि भूमध्य रेखा के चारों ओर कोर का डोनट (मोटे छल्ले जैसी पेस्ट्री) के आकार का क्षेत्र है, जो कुछ सौ किलोमीटर मोटा है, जहां भूकंपीय तरंगें कोर के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग दो प्रतिशत धीमी गति से यात्रा करती हैं। विज्ञानियों को लगता है कि इस क्षेत्र में सिलिकान और आक्सीजन जैसे अधिक हल्के तत्व हैं। ये तत्व कोर के माध्यम से बहने वाली तरल धातु की विशाल धाराओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करती हैं। भूकंप द्वारा उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के अधिकांश अध्ययन बड़ी प्रारंभिक तरंगों को देखते हैं, जो भूकंप के बाद एक घंटे या उससे अधिक समय में दुनिया भर में यात्रा करती हैं। पिछले अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला था कि बाहरी कोर की 'छत' की चारों ओर हर जगह तरंगें अधिक धीमी गति से चलती हैं। शोधकर्ताओं ने ताजा अध्ययन में दिखाया है कि कम वेग वाला क्षेत्र केवल भूमध्य रेखा के पास है।

पृथ्वी के बाहरी कोर का अर्द्धव्यास करीब 3,480 किमी है। इसमें मुख्यतया लोहा और निकल होता है। इसमें सिलिकान, आक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन, कार्बन जैसे हल्के तत्वों के कुछ अंश भी होते हैं। बाहरी कोर का निचला हिस्सा ऊपर से ज्यादा गर्म होता है। तापमान के अंतर के कारण तरल धातु उबलते पानी की तरह हिलता है। अगर बाहरी कोर में हर जगह एक ही सामग्री भरी हुई है, तो भूकंपीय तरंगों को भी हर जगह समान गति से यात्रा करनी चाहिए। तो ये तरंगें डोनट के आकार वाले क्षेत्र में धीमी क्यों हो जाती हैं?

विज्ञानियों को लगता है कि इस क्षेत्र में हल्के तत्वों की मात्रा अधिक होने के कारण तरंगें धीमी हो जाती हैं। बाहरी कोर में एक और ग्रह-स्तरीय प्रक्रिया भी काम कर रही है। पृथ्वी का घूर्णन व छोटा ठोस आंतरिक कोर बाहरी कोर के तरल को उत्तर-दक्षिण दिशा में चलने वाली लंबी भंवरों में व्यवस्थित करता है। इन भंवरों में तरल धातु की अशांत गति 'जियोडायनेमो' बनाती है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह चुंबकीय क्षेत्र हमारे ग्रह को विकिरण से बचाता है, जिससे सतह पर जीवन संभव होता है। बाहरी कोर की बनावट का विस्तृत दृश्य हमें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।

(लेखक विज्ञान के जानकार हैं)

एक अनार सौ बीमार

कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्दरमैया के ऊपर तलवार लटकी हुई है। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप है और राज्यपाल मामला चलाने की इजाजत दे चुके हैं। फिलहाल गेंद कोर्ट के पाले में है। इस बीच हालांकि सिद्दरमैया खुद बार-बार कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो, वह मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन सरकार के अंदर ही दावेदारी ऐसी शुरू हुई है कि एक दो नहीं, 11 मंत्री यह जता चुके हैं कि अवसर मिले तो वे क्यों नहीं? ऐसा भी नहीं कि पर्दे के पीछे केवल नेतृत्व से यह बात बताई हो, खुलेआम जी परमेश्वरा, सतीश जारकीहोली, एमबी पाटिल जैसे कई नेता कह चुके हैं कि फिलहाल तो सिद्दरमैया हैं, लेकिन अगर रिक्ति हुई तो उनमें भी काबिलियत है। उपमुख्यमंत्री शिवकुमार, जो दावेदारी में सबसे आगे हैं, हाल में अमेरिका के उस शहर भी पहुंच गए, जहां राहुल गांधी रुके हुए थे, पर इस सबमें सबसे रोचक एंट्री एक ऐसे नेता की हुई है, जो पहले दूर-दूर तक दावेदार नहीं दिख रहे थे। कर्नाटक के एक ज्योतिषी प्रशांत कीनी ने एक्स पर कहा है कि 2025 में सिद्दरमैया मुख्यमंत्री पद से हटेंगे तो उनकी जगह एक महिला लक्ष्मी हेब्बालकर मुख्यमंत्री बनेंगी।

राजरंग

भवन की किस्मत

सरकार की तरह ही सरकारी भवनों का भी अपना रुतबा होता है। कई बार यह रुतबा वक्त के साथ बढ़ता या घटता रहता है। ऐसा ही हुआ है नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन के साथ। कभी प्रवासी भारतीय मंत्रालय के कार्यालय के तौर पर इसका निर्माण हुआ, लेकिन बाद में यह मंत्रालय ही खत्म हो गया। उसके बाद से यहां लंबे समय तक वीरानगी का माहौल रहा, फिर जी-20 का आयोजन हुआ तो यहां एक साल तक चहल-पहल रही, लेकिन फिर वीरानगी का आलम शुरू ही हुआ था कि पीएम मोदी के एक बयान ने इसकी किस्मत को फिर से चमका दिया। पीएम ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को कहा कि अब वे सूचनाओं-जानकारियों के प्रचार-प्रसार पर ज्यादा ध्यान दें। इसका नतीजा यह हुआ कि एक के बाद एक मंत्रालय सुषमा स्वराज भवन में कार्यक्रम करने लगे हैं।

समय से पहले

नेता-मंत्री अक्सर प्रेस कांफ्रेंस में देर से आने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक ऐसे मंत्री भी हैं, जो निर्धारित समय से पहले पहुंच जाते हैं और प्रेस कांफ्रेंस शुरू करने के लिए उन्हें इंतजार करना पड़ता है। हाल में पत्रकारों को कैबिनेट में हुए फैसले की जानकारी देने के लिए शाम साढ़े सात बजे का समय निर्धारित किया गया था। पत्रकार भी अमूमन यह मानकर चलते हैं कि मंत्रीजी की प्रेस कांफ्रेंस पांच-सात मिनट देर से शुरू होगी, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव समय से पहले पहुंच गए और कैबिनेट के फैसले का प्रस्तुतीकरण देने की तैयारी करने लगे कि वहां मौजूद अधिकारी ने उन्हें ध्यान दिलाया कि अभी साढ़े सात नहीं बजे हैं। मंत्रीजी को कुछ वक्त इंतजार करना पड़ा। फिर निर्धारित समय पर उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस शुरू की।

जनवरी का इंतजार

जनवरी का इंतजार सिर्फ अमेरिका को ही नहीं है, जब वहां नया राष्ट्रपति आएगा। भारत में भी है, खासतौर पर भाजपा में, जब नया अध्यक्ष पार्टी को मिलेगा। नए अध्यक्ष को लेकर असमंजस की स्थिति भाजपा पदाधिकारियों के इंतजार को भारी बना रही है। कोई समझ नहीं पा रहा है कि अध्यक्ष कौन बनेगा। सुनील बंसल, विनोद तावड़े, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक कई नाम हवा में तैर रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन बनेगा या फिर इससे बाहर का कोई व्यक्ति बाजी मार जाएगा, समय ही बता सकेगा। हां, इतना तय है कि नया अध्यक्ष पूरे संगठन को नए सिरे से खड़ा करेगा। इसमें किस-किस का पत्ता कट जाएगा, कोई नहीं जानता। पार्टी के सभी पदाधिकारी चुपचाप समय का इंतजार कर रहे हैं और खुद को केवल रूटीन के काम तक सीमित रखे हुए हैं। शायद यही कारण है कि पार्टी मुख्यालय की दूसरी और तीसरी मंजिल, जहां पार्टी महासचिव और सचिव बैठते हैं, आजकल सूनी नजर आती हैं।

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक- स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए; नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

एक्स से

मणिपुर के आज जो हालात हैं, उसे देखते हुए वहां राष्ट्रपति शासन और राज्यपाल के अधीन एक प्रभावी एकीकृत कमान की आवश्यकता है- वीपी मलिक/ पूर्व सेनाध्यक्ष

हर बात पर धर्म की दुहाई देने वाले यह भी जान लें कि दुनिया में एक अरब डॉलर की मिल्कियत वाली 20 कंपनियों के सीईओ हिंदू हैं। इन कंपनियों के मुख्यालय जिन मुल्कों में हैं, वहां ईसाइयों का बाहुल्य है। इनके निदेशक मंडल ने अगर धार्मिक चश्मा पहना होता, तो वे समूची दुनिया में व्यापार कैसे कर पाते?

स्कैन करें
आजकल स्तंभ के तहत प्रकाशित आलेखों के लिए

ढाका भला काबुल क्यों बने

शशि शेखर

आजकल

बांग्लादेश की नवनियुक्त सरकार अगले महीने की शुरुआत में एक बड़े इम्तिहान से गुजरेगी। उस दौरान वहां पर दुर्गापूजा के विशाल आयोजन किए जाएंगे और समूची दुनिया देखेगी कि वहां पर हिंदुओं की स्थिति क्या है? क्या वे अपना सबसे बड़ा त्योहार पुरानी आबरू के साथ मना पाएंगे?

इन सवालों को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी के एक बयान से और हवा मिली है। वह फरमाते हैं- 'नमाज के दौरान ऐसी गतिविधियां बंद होनी चाहिए और अजान से पांच मिनट पहले इस तरह की गतिविधियों पर रोक लगानी होगी।' इस तरह की गतिविधियों से उनका आशय वाद्ययंत्रों और लाउडस्पीकरों के प्रयोग से है।

इसमें दो राय नहीं कि कुछ हफ्ते बांग्लादेशी हिंदुओं पर बहुत भारी पड़े हैं। शेख हसीना के दुर्भाग्यजनक पलायन के बाद से हिंदू आबादी पर जिस तरह हमले हुए, उन्होंने बांग्लादेश के धर्मनिरपेक्ष चेहरे पर खरोंचे छोड़ दी हैं। 'बांग्लादेश नेशनल हिंदू गार्ड एलायन्स' के मुताबिक, हसीना सरकार के पतन के बाद से देश के 48 जिलों में हिंदुओं को हिंसक हमलों और खून-खराबे का सामना करना पड़ा। पहले यह माना गया था कि कुछ अराजक तत्व नए उपजे हालात का लाभ उठाकर अपने हाथ सेंक रहे हैं। ऐसा सोचने वाले गलत साबित हुए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गुजरी 5 अगस्त से मुल्क के विभिन्न स्कूलों में पढ़ा रहे 50 हिंदू शिक्षकों से जबरन इस्तीफे लिखवा लिए गए।

वहां के हालात किस कदर संवेदनशील हैं, इसकी जानकारी एक और तथ्य से मिलती है। बांग्लादेश के सरकारी दफ्तरों को पिछले दिनों एक हुक्मनामा हासिल हुआ कि आप जल्दी से जल्दी अपने हिंदू कर्मियों की सूची मुहैया करवाएं। इससे इन खबरों को बल मिला कि नवनियुक्त सरकार जान-बूझकर अल्पसंख्यकों को उनके रोटी-रोजगार के हक से वंचित करना चाहती है। हालांकि, बाद में सरकारी नुमाइंदे ने सफाई दी कि ऐसा हर साल होता है। तब तक देर हो चुकी थी। अफवाहों ने अपने पंख खोल लिए थे और वे समूचे मुल्क में आशंकाओं के अपशकुन रोप रही थीं।

वहां के अल्पसंख्यक समुदाय का कहना है कि हम पुलिस की मौजूदगी में भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह की खूंरेजी का सामना उन्हें करना पड़ा, उसमें उन्हें खाकी वर्दी वालों की अनुपस्थिति या उदासीनता बेहद खली। खौफजदा ये लोग अक्सर पिछली 6 सितंबर को हुई हिंसक वारदात का उदाहरण देते हैं, जब 15 साल के किशोर को खुलना शहर में सरेआम पीट-पीटकर मार डाला गया था। उस पर आरोप था कि उसने सोशल मीडिया पर मोहम्मद साहब के विरुद्ध तथाकथित टिप्पणी की है। हमारे देश में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, मगर भारत में समय रहते उस पर कार्रवाई की जाती है। बांग्लादेश में ऐसा नहीं हुआ।

अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं पर होने वाले हमलों को अतिरंजित बता रही है। उसका कहना है कि खास किस्म के लोगों ने जान-बूझकर ऐसी स्थिति पैदा की है, ताकि बांग्लादेश का नाम बदनाम हो सके। सरकारी प्रवक्ता ने इस तरह के अराजक तत्वों को चेतावनी देते हुए कहा भी- 'अगर किसी ने पूजा-पंडालों में हंगामा किया, पूजा में बाधा डाली या लोगों को परेशान किया, तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। बांग्लादेश की आइन के मुताबिक हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और शांति-व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।'

जो नहीं जानते, उन्हें बताने में हर्ज नहीं कि दुर्गापूजा के मौके पर नौ दिनों तक दुर्गा पंडाल सजाए जाते हैं। समूची दुनिया में बिखरा बंगाली समुदाय इस उत्सव को बढ़-चढ़कर मनाता है। उम्मीद है, बांग्लादेश की सरकार अपने दावे के अनुरूप काम करने में सफल होगी। अगर उन्हें अपने मुल्क को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह नहीं बनाना है, तो

उन्हें सांप्रदायिकता की आंधी से खुद को दूर रखना ही होगा।

मैंने यहां पाकिस्तान अथवा अफगानिस्तान का उदाहरण क्यों दिया?

पाकिस्तान में पिछले सात दशकों में हिंदुओं की संख्या में करीब 11 फीसदी की कमी आई है। वर्ष 1951 में वहां 12.9 प्रतिशत हिंदू हुआ करते थे, अब सिर्फ 2.17 फीसदी रह बचे हैं? यह अल्पसंख्यक आबादी के कम होते जाने का सुबूत है। वहां हाल इतना बुरा है कि वर्ष 2021 में एक हिंदू महिला ने जब डीएसपी का इम्तिहान पास किया, तो वह अखबारों की सुर्खियां बन गई। मनीषा रोपेटा पाकिस्तान की स्थापना के बाद ऐसी पहली हिंदू महिला हैं, जो इस पद को हासिल कर सकीं। पाकिस्तान इस पर इतरा सकता था, मगर भारत के लिए हैरत की बात थी? हिन्दुस्तान में तो जाकिर हुसैन वर्ष 1967 में ही राष्ट्रपति बन गए थे।

अपने पड़ोसी पाकिस्तान के मुकाबले अफगानिस्तान का हाल बेहद बदतर है। अफगान अराजकता के बाद वहां तालिबान आए और तालिबानी परंपराओं के विकास के साथ ही हिंदुओं और सिखों के हालात खराब होते चले गए। अब वहां सौ से भी कम हिंदू और सिख रह बचे हैं। वे भी मौका मिलते ही कहीं न कहीं भाग जाना चाहते हैं। भरोसा न हो, तो नई दिल्ली के विभिन्न मोहल्लों में बिखरे पड़े अफगान शरणार्थियों पर नजर डाल देखिए। खुद बांग्लादेश का हाल भी बहुत अच्छा नहीं है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के बाद वहां पहली मर्दुमशुमारी 1974 में हुई थी। उसके मुताबिक, उस समय वहां हिंदुओं की तादाद 13.5 फीसदी थी। पिछले पांच दशकों में इसमें 5.5 फीसदी की जबरदस्त गिरावट आई है।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, भारत में भी मुसलमानों के मुकाबले हिंदुओं की आबादी के प्रतिशत में कमी आई है, लेकिन वे अभी भी जबरदस्त बहुमत में हैं और आने वाले सैकड़ों साल तक इस स्थिति में बहुत बड़ा फर्क आता दिखाई नहीं दे रहा है। अपने देश में जो लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान अथवा किसी अन्य देश का भय दिखाकर आशंका की तिजारत करते हैं, उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। इससे बांग्लादेश या पाकिस्तान में उनके स्वधर्मियों पर जुल्म बढ़ जाता है।

उन्हें भूलना नहीं चाहिए कि कई मुस्लिम देश ऐसे भी हैं, जहां हिंदुओं ने अपनी मेहनत से खास मुकाम बनाया है। वे वहां की संस्कृति, सभ्यता, समाज और आर्थिक उन्नति में योगदान कर रहे हैं। कट्टर माने जाने वाले संयुक्त अरब अमीरात में तो हिंदुओं की तादाद 10 फीसदी तक आंकी जा रही है। इसी वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां 700 करोड़ रुपये की लागत से बने हिंदू मंदिर का लोकार्पण किया। इसी तरह, कुवैत में 15 प्रतिशत और कतर में 10 फीसदी तक हिंदू रहते हैं। यहां इंडोनेशिया के बारे में भी जानना जरूरी है। इंडोनेशिया में दो फीसदी से भी कम हिंदू बसते हैं और संसार के सर्वाधिक मुसलमान वहां रहते हैं। इसके बावजूद वहां के तमाम सरकारी आयोजनों में हिंदू रिवाजों का अनुपालन किया जाता है।

हर बात पर धर्म की दुहाई देने वाले यह भी जान लें कि दुनिया में एक अरब डॉलर की मिल्कियत वाली 20 कंपनियों के सीईओ हिंदू हैं। इन कंपनियों के मुख्यालय जिन मुल्कों में हैं, वहां ईसाइयों का बाहुल्य है। इनके निदेशक मंडल ने अगर धार्मिक चश्मा पहना होता, तो वे समूची दुनिया में व्यापार कैसे कर पाते?

पता नहीं, लंदन की महफूज फिजां में बरसों गुजारने के बावजूद मुहम्मद यूनुस साहब इस तथ्य को कितना जानते-मानते हैं।

@shekharkahin
@shashishekhar.journalist

जीना इसी का नाम है

जस कालरा
समाजसेवी

बच्चों को कैसी विरासत सौंप रहे, आप देखिए

पिछले ही महीने उम्र के 25वें साल में कदम रखने वाले जस कालरा ने अब तक करीब 3,000 लावारिस शवों को सद्गति दी है, 1,500 परित्यक्त बुजुर्गों का उद्धार किया है। इनमें से कई को उनके परिवार ने दोबारा अपना लिया। ऐसे नौजवान के लिए भला कौन दुआ नहीं करेगा?

संपन्न परिवारों में पले-बढ़े किशोरों-नौजवानों के बारे में हम अक्सर यही पढ़ते-सुनते हैं कि किसी ने मदहोशी के आलम में फुटपाथ पर सोए गरीबों के ऊपर अपनी गाड़ी दौड़ा डाली, तो दौलत के मद में डूबे किसी युवा के हाथ सरकारी मुलाजिम के गिरेबान तक पहुंच गए। इस तरह की खबरों ने धनाढ्य युवाओं की एक ऐसी छवि बना दी है, मानो वे सभी निर्मम, दुर्गुणों की खान हैं। समाज और मीडिया ने इनके लिए 'बिगड़े रईसजादे' या 'बिगड़ैल अमीरजादे' जैसे जुमले गढ़ लिए हैं। मगर नहीं! यह सच नहीं है। जस कालरा जैसे नौजवान इसके बड़े प्रमाण हैं। अमीर घरों के युवा भी करुण, सेवाभावी होते हैं, बल्कि पूरी मानवता के प्रेरणा-पुंज बन सकते हैं।

जस के पिता रवि कालरा तो इतने साधारण परिवार में पैदा हुए थे कि कभी-कभी उनके पास बस भाड़ा देने तक के पैसे नहीं होते थे। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक रवि शिक्षा के जरिये जब खुद को साबित नहीं कर पाए, तो उन्होंने ताइक्वांडो का प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसकी ट्रेनिंग देने को अपना करियर बना लिया। वह पुलिस बटालियन और सैन्य बलों को मार्शल आर्ट सिखाया करते थे। फिर ऐसा संयोग बना कि बतौर गुप्तचर उन्हें दुनिया के विभिन्न देशों में काम करने का मौका मिला और एक दिन अमेरिकी फौज ने उनके साथ एक ऐसा अनुबंध किया, जिसके तहत उन्हें युद्धग्रस्त देशों में अमेरिकी फौज के साथ काम करने के लिए लोगों की भर्तियां करनी थीं। रवि ज्यादातर नेपाल की रॉयल आर्मी से स्वैच्छिक तौर पर सेवानिवृत्त होने वाले फौजियों की इसमें भर्तियां करने लगे। इस काम से उन्होंने काफी पैसे कमाए। दौलत इतनी बरसी कि वह जूते खरीदने मिलान (इटली), सिंगापुर, हांगकांग तक चले जाते थे।

दिसंबर 2007 में रवि कालरा किसी काम से दिल्ली में कहीं जा रहे थे। उनकी महंगी कार एक लाल बत्ती पर रुकी। अचानक उनकी नजर एक दृश्य पर अटक गई। उस दृश्य में उन्होंने कचरे के ढेर से एक छोटे बच्चे और कुत्ते को साथ-साथ कुछ उठाकर खाते देखा। गरीबी और अमीरी के दो ध्रुवों को जी चुके रवि को झटका लगा- मेरी हैसियत क्या है? ऊपर जब जाऊंगा, तो क्या जवाब होगा मेरे पास? ड्राइवर को गाड़ी किनारे लगाने को बोल वह उस यतीम बच्चे के पास पहुंचे, उसकी फौरी मदद की और वहां से वह सीधे श्मशान घाट चले गए, चिता भस्म का तिलक लगाया और उसी दिन से अपने लिए जीना छोड़ दिया। चंद महीनों में ही 'द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन' वजूद में आ गया था।

इतने संपन्न परिवार की स्नेहिल छांव में पले-बढ़े जस कालरा की जिंदगी में पिता रवि कालरा का वह कायांतरण बहुत सुखद मोड़ लेकर नहीं आया, क्योंकि मां को यह बदलाव मंजूर न था। वह जस और उनकी बहन जिया को लेकर घर

से निकल गई थीं। जस का ननिहाल पक्ष भी समृद्ध कारोबारी घराना है। जाहिर है, बिछोह के उन दिनों में भी जस और उनकी बहन की अच्छी तालीम जारी रही। अच्छी बात यह भी हुई कि जस और जिया जब बड़े हुए, तो पिता से मिलने आने लगे, बल्कि उनके सेवा कार्यों में भी उनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। जस जब भी पिता के साथ आश्रम जाते, तो वहां रह रहे सैकड़ों बीमार, बेसहारा बुजुर्गों-महिलाओं-बच्चों की आंखों में उनके लिए प्रेम व कृतज्ञता देखकर अभिभूत हो उठते। उनके मन में उन्हीं दिनों यह बात कहीं गहरे पैठ गई कि आगे चलकर वह भी पिता के सेवा मार्ग को अपनाएंगे।

मेलबर्न यूनिवर्सिटी से 'क्रिमिनोलॉजी ऐंड साइकोलॉजी' में स्नातक करने के बाद जब जस गुड़गांव लौटे, तो पिता ने एक दिन उनका मन टटोला। जस ने तत्काल आश्रम-सेवा से जुड़ने के बारे में सोचा नहीं था। 21 साल के युवा के आगे सारा संसार खुला होता है। फिर जस तो मेलबर्न में एक अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल लीग के सेंटर प्लेयर रह चुके थे। उन्होंने पिता से कहा, 'पापा, मेरी इतनी एजुकेशन हो चुकी है, मेरा बिजनेस एक्सपोजर भी इतना हो चुका है कि मैं सालाना 70-80 लाख कमा लूंगा। आप मुझसे शर्त लगा लो।' पिता खुश हुए और बोले, 'बेटे, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बात बताओ, ऊपर तो एक दिन सबको जाना है। जब आप जाओगे, तब भगवान जी को अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे या अपने कर्मों का हिसाब दोगे?' पिता की वह बात बेटे के भीतर उतर गई और अगस्त 2021 में नौजवान जस जिंदगी की सारी रंगीनियों का न्योता ठुकरा सेवा की दुनिया में उतर गए।

अपने अंतरराष्ट्रीय पेशेवर उद्यम को संभालने के साथ-साथ जस ने 'द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन' के उपाध्यक्ष की हैसियत से गुड़गांव के बंधवाड़ी व मंडावर गांव स्थित आश्रमों में सेवा का काम शुरू कर दिया। पिता के साथ दीन-दुखियों की तिमारदारी करके उन्हें काफी सुकून मिलता। मगर अंदाजा न था कि पिता इतनी जल्दी अपनी सारी जिम्मेदारी उन्हें सौंप देंगे। दिसंबर 2021 की एक सुबह महज 53 साल की उम्र में वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। जस के पास शोक मनाने का भी अवकाश न था, क्योंकि अगले दिन से ही संस्था के प्रेसिडेंट की हैसियत से सैकड़ों लोगों की सारी जिम्मेदारी उनकी थी। जस ने पिता की अपेक्षाओं को कभी मायूस नहीं किया। उन्हें निराश्रितों के घाव साफ करने या लावारिश लाशों की अंतिम क्रिया करने में कभी कोई हिचक नहीं हुई।

पिता खुश हुए और बोले, 'यह तो अच्छी बात है, पर यह बताओ कि ऊपर तो एक दिन सबको जाना है। जब आप जाओगे, तब भगवान को अपना बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे या अपने कर्मों का हिसाब दोगे?' पिता की वह बात बेटे के भीतर उतर गई और महज 21 वर्ष के जस सेवा की दुनिया में उतर गए।

पिछले ही महीने उम्र के 25वें साल में कदम रखने वाले जस कालरा ने अब तक करीब 3,000 शवों को सद्गति दी है, 1,500 परित्यक्त बुजुर्गों का उद्धार किया है। इनमें से कई को उनके परिवार ने दोबारा अपना लिया। जस के आश्रमों में लगभग 1,200 लावारिस बच्चे, परित्यक्त बुजुर्ग व मानसिक रूप से अक्षम लोग रह रहे हैं, जिनके हर सुख-दुख का वह ख्याल रखते हैं। ऐसे सहृदय, सेवाभावी नौजवान के लिए भला कौन दुआ नहीं करेगा?

प्रस्तुति : चंद्रकांत सिंह

वो लम्हा

एम विश्वेश्वरैया
भारत रत्न इंजीनियर

उपहार में मिले एक शब्दकोश का कमाल

अंग्रेज प्रिंसिपल इस छात्र की ऐसी दुष्कर दिनचर्या सुनकर दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि ऐसे छात्र को जरूर बल देना चाहिए। जो छात्र अपनी पढ़ाई के लिए किसी से पैसे नहीं मांग रहा, स्वयं मेहनत से खर्च निकाल रहा है, उसे तो कुछ ऐसा देना चाहिए, जो ताउम्र काम आए।

कर्नाटक के कोलार ने देश-दुनिया को बेहिसाब सोना दिया है। कोलार गोल्ड फील्ड से अंग्रेज कितना सोना निकाल ले गए, कोई नहीं जानता, पर जब अंग्रेज दोनों हाथों से लूटने में लगे थे, तब उसी कोलार की उर्वर भूमि पर एक गुदड़ी के लाल का अवतरण हुआ था। उसके पिता विद्वान थे, उनका ज्यादा समय धर्मग्रंथों और तीर्थयात्रा में लगता था, तो परिवार में अभावों का सिलसिला रहता था। छह भाई-बहनों में दूसरे नंबर का यह बालक खास था। वह अभाव का साया पढ़ाई पर नहीं पड़ने दे रहा था। घर में ही बच्चों की पढ़ाई शुरू हुई, पर जब लगा कि बच्चे तेज हैं, तो स्कूल भेजना जरूरी लगा। स्कूली पढ़ाई के लिए ही परिवार गांव छोड़कर चिकबल्लापुर आ गया। सरकारी स्कूल में उस बालक ने टॉप करना शुरू कर दिया। मां ने हाईस्कूल की पढ़ाई के लिए बेटे को उसके मामा के पास बेंगलुरु भेज दिया। बेटे ने मैट्रिक में पूरे मैसूर राज्य में टॉप करके दिखा दिया। मां ने समझ लिया कि बेटे को रोकना ठीक नहीं।

टॉपर को सेंट्रल कॉलेज में इंटरमीडिएट में आसानी से दाखिला मिल गया। पल-पल पढ़ाई करते टॉपर पर कॉलेज के अंग्रेज प्रिंसिपल चार्ल्स वाटर्स की निगाह पड़ गई। प्रिंसिपल ने पता लगाया कि यह छात्र तो बहुत मुश्किलों से गुजरते हुए पढ़ रहा है। पैसे बचाने के लिए बेंगलुरु के एक छोर पर रहता है और दूसरी छोर पर कॉलेज है, पर एक तीसरा जरूरी छोर भी है, जहां वह ट्यूशन पढ़ाने जाता है। सुबह आंख ट्यूशन वाले घर में ही खुलती है। वहां सुबह ही बच्चों को पढ़ाने के बाद अपने डेरे पर आना पड़ता है, जहां भोजन करते ही कॉलेज का वक्त हो जाता है। कॉलेज से छूटकर फिर डेरे पर भोजन और देर रात से पहले ही ट्यूशन वाले घर पर पहुंचना पड़ता है। सारी दूरियां पैदल ही तय होती हैं। कमाल देखिए, क्या मजाल कि कहीं भी पहुंचने में विलंब हो जाए। कहीं कोई बहाना नहीं, चेहरे पर शिकन का एक कतरा नहीं। अंग्रेज प्रिंसिपल छात्र की ऐसी दुष्कर दिनचर्या सुन दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि ऐसे छात्र को जरूर बल देना चाहिए। जो छात्र अपनी पढ़ाई के लिए किसी से पैसे नहीं मांग रहा, स्वयं मेहनत से खर्च निकाल रहा है, उसे तो कुछ ऐसा देना चाहिए, जो ताउम्र काम आए। प्रिंसिपल ने बहुत सोच-विचार के बाद अपने संघर्षशील छात्र को वेबस्टर डिक्शनरी भेंट की।

पहली बार किसी ने ऐसे उपहार दिया था। अब तक भेंट में ज्यादातर मुड़ी-तुड़ी किताबें ही मिलती थीं, पर अब हाथों में एक नया-मोटा चमकदार शब्दकोश था, तमाम पुरानी किताबों के बीच सिरमौर। प्रिंसिपल साहब की भलमनसाहत ने छात्र को भाव-विभोर कर दिया। उत्साह एक ऐसे ज्वार की तरह जागा कि ठान लिया, प्रिंसिपल साहब ने पढ़ने के लिए दिया है, तो वाकई पढ़कर और कुछ अच्छा बनकर दिखा देना है। उपहार हुनरमंद मानकर उम्मीद से दिया है, तो खरा उतरकर दिखा देना है।

फिर क्या, छात्र ने ऊंचे अंकों से कॉलेज पास करके दिखा दिया। प्रिंसिपल साहब पीछे लग गए कि 'तुम्हें शिक्षा निदेशालय में लगा देता हूं, तुम्हारे संघर्ष के दिन पूरे हो गए', पर छात्र ने कहा, 'सर, अभी और पढ़ूंगा, पक्की नौकरी में लग गया, तो मुश्किल हो जाएगी। सर, मुझे इंजीनियरिंग में जाना है।'

सुखद संयोग रहा कि पूना में इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति का इंतजाम हो गया। पूना पहुंचते ही ख्याति फैलने लगी। देश के नामी-गिरामी लोग जानने लगे कि अद्भुत विद्यार्थी मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया ने तीन साल का पाठ्यक्रम ढाई साल से पहले ही पूरा कर लिया है। फिर टॉप किया है, तो जेम्स बर्कले पुरस्कार भी मिला है। मात्र 23 की उम्र में ही बॉम्बे लोक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता के पद से बेमिसाल इंजीनियरिंग सेवा की शुरुआत हुई। देश में उनके नाम-काम का डंका बजने लगा। कहीं पेयजल आपूर्ति, कहीं बाढ़ रोकथाम, तो कहीं सिंचाई सुविधा, पूरा देश जान गया कि हमारे पास एक ऐसा माहिर इंजीनियर है, जो नदियों, पहाड़ों को भी दशा-दिशा देता है, जो बाढ़ और सूखे का इलाज जानता है।

15 सितंबर को जन्मे एम विश्वेश्वरैया (1860-1962) को यह देश कभी भूल नहीं सकता। उनके जन्मदिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है और उन्हें भारत ही नहीं, विदेश में भी खूब याद किया जाता है। पूरी सादगी और विद्वता की महानता के साथ अनेक पदों और सेवाओं को सुशोभित करने वाले पूरे 101 साल जीवित रहने वाले विश्वेश्वरैया अपने अंत तक अपने प्रिंसिपल की खास भेंट- शब्दकोश को दिल से लगाए रहे। अब वह शब्दकोश मुडेनहल्ली के संग्रहालय में इस संदेश के साथ शोभायमान है कि यदि किसी विद्यार्थी को कोई उपहार दिया जाए, तो कुछ ही ऐसा हो, जो प्रेरणा से भर दे।

प्रस्तुति : ज्ञानेश उपाध्याय

हिंदी : एक दिन की च्यूइंगम

तिरछी नजर

सुधीश पचौरी हिंदी साहित्यकार

हिंदी दिवस ने हिंदी को बहुत कुछ दिया है : उसने हर केंद्रीय दफ्तर में एक हिंदी प्रकोष्ठ दिया और उसमें सिर झुकाए बैठा एक हिंदी अधिकारी दिया, जो 'राजभाषा अधिनियम' के अनुसार कामकाज की रिपोर्ट बनाता रहता है। उसके कमरे की दीवारों पर कहीं भारतेंदु, कहीं गांधी, तो कहीं टैगोर के साथ हिंदी के पुराने संघर्षी साहित्यकारों के चित्र लटके दिखते हैं। पूरे साल हिंदी के इस 'लगे रहो मुन्ना भाई' की झुकी पीठ एक दिन के लिए सीधी हो जाती है। वह कुरता-धोती व जैकेट के साथ माथे पर तिलक लगाकर एक दिन का दूल्हा बन जाता है। दफ्तर-परिसर में 'हिंदी राजभाषा है', 'देश को जोड़ने वाली भाषा' जैसी सूक्तियों के बैनर लटक जाते हैं। हिंदी उत्साही इस दिवस को खींचकर पखवाड़ा या माह में बदल देते हैं। ये दिन ऊंट के मुंह में जीरे बराबर बजट को निपटाने के होते हैं!

इस दिन हिंदी विद्वान आते हैं। हिंदी में कामकाज की रिपोर्ट पेश की जाती है। दफ्तर में छिपी प्रतिभाएं कविता-कहानी निबंधनुमा सुनाकर अपने जौहर दिखाती हैं। मुख्य अतिथि किसी को प्रतिभा पुंज, किसी को उभरती प्रतिभा कहकर खुश करते हैं। कुछ गैर-हिंदीभाषियों की रचनाओं को भी भूरि-भूरि करके सम्मानित किया जाता है। इस तरह हिंदी सबका खयाल रखती है। इस हिंदी उत्सव में हर दिन चाय के साथ समोसे, गुलाब जामुन और कुछ वेफर्स के डिब्बे 'टोमेटो सॉस' के 'सैशे' के साथ दिए जाते हैं। कुछ प्रातिभ सैशे की तुक ऐश और फिर कैश से भिड़ाकर व्यंग्यश्री की उपाधि प्राप्त करते हैं। सच! हिंदी किसी को नाराज नहीं करती। सबको खुश रखती है, क्योंकि वह राजभाषा है।

अंत में मुख्य अतिथि शुद्ध हिंदी में आशीर्वाद देकर सबको दंग करते हैं, फिर लंच या डिनर... फिर एक बाबू मुख्य अतिथि जी से एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने को कहते हैं- वह एक कैंसिल चेक तथा पैनकार्ड की कॉपी वाट्सएप पर भेज दें, ताकि ऑनलाइन पेमेंट भेजा जा सके। अतिथि जी को लिफाफे की जगह ऑनलाइन नाम सुनते ही जूड़ी आने लगती है। वह किसी तरह धन्यवाद दे-ले दफ्तरी गाड़ी में निकल जाते हैं।

जब काफी दिनों तक उनके खाते में पैसे नहीं आते, तो उनका हिंदी संघर्ष शुरू हो जाता है। अंत में *जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान* के वीतरागी हो जाते हैं और अगले हिंदी दिवस पर कहीं न जाने का संकल्प ले लेते हैं। पर दिल है कि मानता नहीं के हिसाब से अगले 'दिवस' फिर हिंदी के लिए कुर्बानी देने को तैयार हो जाते हैं और 'पेमेंट' के नए संघर्ष में लग जाते हैं।

अपना हिंदी दिवस हर बार एक दिन का जुशांदा या एनर्जी ड्रिंक या च्यूइंगम होता है, जिसे आम हिंदी वाला पूरे साल चुभलाता रहता है, इसीलिए जब हिंदी के दुश्मन उसे कूटते हैं, तो इसका एक भी महान सपूत प्रतिकार तक नहीं करता कि हिंदी का अपमान बंद करो! जिसे अपने ही इज्जत नहीं देते, उसे दूसरे पर कोई कैसे 'थोप' सकता है?

हिंदी साहित्यकार हैं ही ऐसे। वे हिंदी की खाते हैं, लेकिन अंग्रेजी की गाते हैं और हिंदी के दुश्मन कहते हैं कि हिंदी भाषा ही नहीं है; वह ज्ञान की नहीं, नाचने-गाने की भाषा है; वह हिंदू भाषा है। फिर भी बहुत से अहिंदीभाषी इसी हिंदी में आकर मरते हैं और वह फिर भी 'मैं चुप रहूंगी' बनी रहती है। कभी-कभी तो लगता है कि हिंदी साहित्यकार हिंदी के होते हुए भी हिंदी के नहीं होते। होते, तो हिंदी के लिए कुछ तो बोलते?

आप किसी दस-पांच करोड़ की भाषा को 'टच' करके देखिए। देखिए कि उसके लोग कैसा झपट्टा मारते हैं। लेकिन पचास-साठ करोड़ की भाषा होते हुए भी हिंदी एक अनाथ भाषा है। उसका न कोई 'ऑनर' है, न उसकी कोई 'एडवोकेसी' है, न 'एजेंसी' ही, क्योंकि हिंदी में न माल है, न पावर है, न उसका कोई रखवाला है। वह तो इतने से ही खुश है कि वह राजरानी है, जबकि वह 'एक दिन की च्यूइंगम' भर है। साल भर चबाते रहो और नाचते-गाते रहो!

कटाक्ष

राजेंद्र धोड़पकर

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

जम्मू-कश्मीर में आतंक का दंश

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान के संबंध में दावे चाहे जो भी हों लेकिन वास्तविकता यही है कि वहां आए दिन आतंकवादियों के हमले हो रहे हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़े जम्मू-कश्मीर के लोग मतदान का इंतजार कर रहे हैं। पहले चरण में 18 सितम्बर को मतदान होना है। ऐसे समय पर आतंकवादी चुनाव पर असर डालने की फिराक में हैं। 5 अगस्त, 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में अमन की वापसी और विकास के नए दौर की शुरूआत हुई है लेकिन आतंकवादी संगठनों का दंश देश के सुरक्षा बलों को झेलना पड़ रहा है। सुरक्षा बलों के अधिकारी और जवान शहीद हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुनावी रैली से पहले किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में दो जवानों की शहादत ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने तीन आतंकवादियों को भी मार गिराया है। चार दशकों में डोडा में किसी प्रधानमंत्री की पहली रैली हुई है। डोडा, किश्तवाड़ और रामवन जिलों में 8 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान होगा। इसके साथ ही दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और पुलगाम जिलों में भी 16 सीटों पर मतदान होने वाला है। जम्मू-कश्मीर चुनावों में सुरक्षा की चुनौती बनी हुई है। पिछले चार महीनों में लगभग दो दर्जन से भी ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं।

जम्मू क्षेत्र आमतौर पर कई वर्षों से कश्मीर की अपेक्षा ज्यादा शांत रहा है। मगर बीते कुछ समय से इसके कुछ इलाकों में भी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं। लोकसभा चुनावों में जिस तरह से राज्य के लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया उससे विधानसभा चुनावों में भी लोगों के बढ़-चढ़कर भाग लेने की उम्मीद बन रही है। आतंकवादी संगठनों के पाकिस्तान में बैठे आकाओं को यह सब सहन नहीं हो रहा। अगर राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती मिलती है और लोग अधिक से अधिक वोट डालकर लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, सरकार में जनता की भागीदारी बढ़ती है तो इससे आतंकवादी गिरोहों के नापाक इरादों पर पानी फिर जाएगा। यही कारण रहा कि आतंकवादी सुरक्षा बलों या रोजी-रोटी कमाने के लिए बाहर से आए प्रवासी लोगों की हत्याएं करने में लगे हुए हैं। आतंकवादियों ने कभी बिहार के मजदूरों को निशाना बनाया तो कभी उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को। 90 के दशक में जम्मू खासकर कठुआ आतंकवादियों का ठिकाना हुआ करता था। कश्मीर के सबसे अस्थिरता के दौर में कठुआ पनाहगार बना हुआ था। अब एक बार फिर ऐसा ही दिख रहा है। दरअसल इस जिले की बनावट ऐसी है जहां छिपना-छिपाना आसान है। जंगलों से सटे क्षेत्र में हमले के बाद आतंकवादी गायब हो जाते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चुनावी रैली से पहले किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में दो जवानों की शहादत ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि सुरक्षा बलों ने तीन आतंकवादियों को भी मार गिराया है। चार दशकों में डोडा में किसी प्रधानमंत्री की पहली रैली हुई है। डोडा, किश्तवाड़ और रामवन जिलों में 8 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण का मतदान होगा। इसके साथ ही दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और पुलगाम जिलों में भी 16 सीटों पर मतदान होने वाला है। जम्मू-कश्मीर चुनावों में सुरक्षा की चुनौती बनी हुई है। पिछले चार महीनों में लगभग दो दर्जन से भी ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। जम्मू क्षेत्र आमतौर पर कई वर्षों से कश्मीर की अपेक्षा ज्यादा शांत रहा है। मगर बीते कुछ समय से इसके कुछ इलाकों में भी आतंकवादी गतिविधियां बढ़ी हैं।

जिले के एक तरफ हिमाचल की सीमा लगती है तो दूसरी तरफ हिमाचल और पंजाब हैं। आतंकवादी गुट लगातार हमले कर क्षेत्र में अस्थिरता और डर पैदा करना चाह रहे हैं ताकि राजनीतिक ढांचे के साथ-साथ आम लोगों की भावनाओं से भी छेड़छाड़ की जा सके। घाटी में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कई आतंकवादी गुट छद्म नामों से सक्रिय हो चुके हैं। टीआरएफ, जम्मू-कश्मीर गजनबी फोर्स, कश्मीर टाइगर्स, जम्मू-कश्मीर रजिडैंट्स फोर्स, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट इन्हीं में से हैं। इन छद्म संगठनों को बड़े आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का संरक्षण प्राप्त है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जम्मू-कश्मीर में माहौल काफी बदला है। आतंकवादी घटनाओं पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है। एक दौर था जब श्रीनगर का लाल चौक एक जनाजागढ़ बन गया था। आतंकवादियों के बड़े-बड़े जनाजे हुआ करते थे। आज लाल चौक में तिरंगे लहरा रहे हैं। घाटी के बाजारों में रौनक है। होटल, हाऊस बोट और रेस्त्रां चलाने वाले भी खुश हैं, क्योंकि भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। केन्द्र सरकार के आंकड़े बताते हैं कि साल 2020 से लेकर 2024 तक 6 करोड़ पर्यटक जम्मू-कश्मीर पहुंचे। इस बार के विधानसभा चुनावों में खास बात यह है कि किसी ने भी चुनावों के बहिष्कार का आह्वान नहीं किया। प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के नेता भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि नेशनल कॉफ्रेंस, पीडीपी, राशिद इंजीनियर की आवामी इत्तेहाद पार्टी अनुच्छेद 370 की वापसी का मुद्दा बना रहे हैं।

जम्मू-कश्मीर के बारे में हमेशा एक बात कही जाती रही है कि चुनावों में आइना बदल जाता है, चेहरे वही रहते हैं। जम्मू-कश्मीर में शेख अब्दुला के जमाने से नेशनल कॉफ्रेंस और मुफ्ती मोहम्मद सैय्यद के नेतृत्व वाली पीडीपी बारी-बारी से सत्ता सुख भोगते रहे हैं। नेशनल कॉफ्रेंस का नेतृत्व अब फारुख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला कर रहे हैं, जबकि पीडीपी का नेतृत्व महबूबा मुफ्ती कर रही हैं। कौन नहीं जानता कि घाटी में जब-जब आतंकवाद बढ़ा तो फारुख अब्दुल्ला जैसे लोग विदेशों में जाकर बैठ जाते थे। हुर्रियत कॉफ्रेंस के नेताओं ने पाकिस्तान की आईएसआईएस से धन लेकर देश-विदेश में अपनी अथाह सम्पत्ति बनाई लेकिन कश्मीरी आवाम के बच्चों के हाथों में बंदूकें और पत्थर थमा दिए। जम्मू-कश्मीर में अब अलगाववादी विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं बची है लेकिन आतंकवाद कैसे समाप्त हो यह बड़ी चुनौती है। स्थानीय लोगों के बीच आतंकवाद के खिलाफ राय को मजबूत बनाने का काम राजनीतिक दलों को ही करना होगा। उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर के लोग अपना वोट डालकर आतंकवाद को एक बार फिर आइना दिखाएंगे।

आदित्य नारायण चोपड़ा

Adityachopra@punjabkesari.com

Review Paper Paid

देश के कोने-कोने से ऐसे कृत्य...

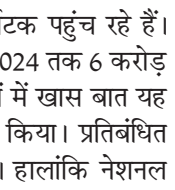

गीता पाढा

वैसे तो वे मंदिर में दुर्गा माता को भेंट चढ़ाते हैं,
पर भरे आंगन में अपनी बहू-बेटियों की इज्जत नीलाम कराते हैं,
देश के कोने-कोने से ऐसे कृत्य जब सामने आते हैं,
तो मगरिम के मुल्क भी हम को नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं...!!

भाजपा अध्यक्ष को लेकर माथा पच्ची

मिर्च मसाला

त्रिदीब रमण

gossipguru.in

'तुम तो कच्चे रंग की तितली हो
बरसात में इधर-उधर फिरा करती हो
कैसे यकीं कर लूं तेरे रंगों पर
एक फूल से दूजे फूल पर गिरा करती हो'

भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर भगवा पार्टी व संघ के दरम्यान पेंच फंस गया है। 24 के चुनावी नतीजों के बाद थोड़ी बैकफुट पर आ गई भाजपा अब संघ को खेलने के लिए खुद ही एक बड़ा सियासी मैदान मुहैया करा रही है। भगवा राजनीति में भाजपा के अभ्युदय से हालात बदले हैं साथ ही भाजपा अपने बड़े रणनीतिक फैसलों में संघ की मंशाओं को उनका मनचाहा आसमां नहीं दे पा रही थी, सो संघ दुलारे सुनील बंसल के नाम पर भी भगवा पार्टी विचार करने से नहीं हिचक रही। भाजपा ने कहा कि उन्हें अध्यक्षीय कुर्सी दिए जाने पर योगी आदित्यनाथ नहीं मानेंगे।'

वैसे भी बंसल विस्तारित वैश्य समाज से ही आते हैं और भाजपा पर पहले से ही बनियों की पार्टी होने का ठप्पा भी लगता रहा है। कहते हैं इसके बाद भाजपा शीर्ष की तरफ से संघ को पार्टी अध्यक्ष पद के लिए केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल का नाम भेजा गया, जिसे संघ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मोदी व शाह दोनों ही गुजरात से हैं, ऐसे में अगर भाजपा अध्यक्ष भी गुजरात का हो जाएगा तो पार्टी कैडर में क्या संदेश जाएगा?' फिर महाराष्ट्र चुनाव की आसन्न आहटों को भांपते संघ की ओर से विनोद तावड़े का नाम आगे किया गया, पर तावड़े पर गडकरी करीबी होने का आरोप लगा भाजपा शीर्ष ने इस नाम को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया।

नाम तो वसुंधरा राजे, रवि शंकर प्रसाद, संजय विनायक जोशी के भी चले, पर इन नामों पर भी किंचित गंभीरता से विचार नहीं हो पाया। भूपेंद्र यादव का

नाम तो एक सदाबहार नाम है, पर संघ को लगता है कि यादव भाजपा के चाहे कितने भी खास हों, पर वे अध्यक्ष पद के लिए थोड़े जूनियर हैं।' सो, ले देकर अभी देवेंद्र फड़णवीस का नाम ही माहौल में गर्मी पैदा कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि देवेंद्र फड़णवीस को पिछले दिनों दिल्ली के लुटियंस जोंस में केंद्र सरकार की ओर से एक सरकारी आवास भी आवंटित हुआ है, जो इन कयासों को बल देता है कि फिलहाल तो अध्यक्ष पद को लेकर उनका ही दावा सबसे मजबूत है।

राहुल के लिए नरम पड़ता संघ?

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हमेशा से संघ की नीतियों व कार्यक्रमों पर निशाना साधा है, गाहे- बगाहे उन्होंने संघ पर सीधा हमला भी बोला है। बावजूद इसके हालिया दिनों में संघ का शीर्ष नेतृत्व राहुल के प्रति किंचित नरम पड़ता नज़र आ रहा है। क्या संघ देश में बदलती सियासी बयार की थाह पा गया है या राहुल के हालिया 'सॉफ्ट हिंदुत्व' के स्टैंड पर मोहित हो गया है? अभी राहुल

गांधी के हाल के अमेरिकी दौरे में जिस तरह वहां से अप्रवासी भारतीयों ने उन्हें हाथों हाथ लिया है, यह भी संघ को उनकी भाव-भंगिमा बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। जैसा कि संघ से जुड़े एक विश्वसनीय सूत्र का दावा है कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है, सो उसका किसी राजनैतिक दल से कोई निजी वैर-भाव नहीं, इसी सूत्र का दावा है कि आने वाले दिनों में संघ का शीर्ष नेतृत्व सीधे राहुल गांधी से अपने तार जोड़ने के प्रयास करेगा, यह भी बताया जा रहा है कि संघ नेतृत्व की ओर से 'मिशन राहुल' की कमान कृष्ण गोपाल के हाथों में सौंपी गई है जो एक अच्छे अध्येता व विचारक भी हैं।

क्या बागी बिगाड़ सकते हैं खेल?

हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बागियों को लेकर परेशां हाल है। बात करें कांग्रेस की तो पार्टी के कोई 56 नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है, इनमें से लगभग 42 नेता 34 अलग-अलग सीटों पर निर्दलीय मैदान में भी

उतर गए हैं। वहीं भाजपा के लगभग 78 नेताओं ने बगावती सुर अख्तियार कर रखे हैं जो लगभग 49 सीटों पर भाजपा का खेल बिगाड़ सकते हैं, इनमें से 47 तो ऐसे हैं जो बतौर निर्दलीय चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

हरियाणा भाजपा के सबसे वरिष्ठ माने जाने वाले राम विलास शर्मा को जब पार्टी ने टिकट देने से मना कर दिया तो वे निर्दलीय ही मैदान में उतर गए, शर्मा सबसे ज्यादा खट्टर से नाराज़ बताए जा रहे थे। बाद में दिल्ली के शीर्ष नेता ने उन्हें फोन कर मनाया तब जाकर उन्होंने अपना पर्चा वापिस लिया। कांग्रेस की ओर से पार्टी के बागियों को मनाने का जिम्मा भूपिंदर सिंह हुड्डा को सौंपा गया है, वे एक-एक बागी नेता से व्यक्तिगत तौर पर मिल कर उन्हें मनाने के प्रयास कर रहे हैं। बीते शुक्रवार को बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष करण देव कम्बोज ने भी बगावत का बिगुल फूंक दिया था, उन्होंने भाजपा छोड़ कर आनन-फानन में कांग्रेस ज्वॉइन कर ली, भाजपा सीएम नायब सिंह सैनी से तो उन्होंने हाथ मिलाने से भी इंकार कर दिया था।

भिवानी की बवानी खेड़ा सीट से कांग्रेस ने प्रदीप नरवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। नरवाल को टिकट मिलते ही तीन बार के विधायक रामकिशन फौजी और सतवीर रतेरा ने बगावत कर दी। बवानी खेड़ा सीट से राम किशन फौजी और सतवीर रतेरा दोनों ही निर्दलीय मैदान में उतर आए हैं।

केजरीवाल को लेकर भाजपा का गेम प्लॉन

क्या यह महज़ इत्तफाक है कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला 5 सितंबर को ही सुरक्षित रख लिया जाता है और उन्हें जमानत दी जाती है तब जब हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर गुजर जाती है और इसके ठीक एक रोज बाद शीर्ष कोर्ट जांच एजेंसियों पर कुछ कड़ी टिप्पणियों के साथ 13 सितंबर को केजरीवाल को जमानत दे देता है। एक कांग्रेसी नेता का दावा है कि केजरीवाल की रिहाई में बस इस वजह से देर लगाई गई है ताकि हरियाणा विधानसभा चुनाव

में आप व कांग्रेस का चुनावी गठबंधन न हो पाए और भाजपा अपने इस मकसद में कामयाब भी रही। वैसे भी केजरीवाल रणभूमि में एक ऐसे योद्धा की तरह हैं जो लड़ाई के मैदान में तो हैं, पर उनके दोनों हाथ बांध दिए गए हैं। कहना न होगा कि इस बार का पूरा हरियाणा चुनाव वैसे भी भाजपा दूसरों के भरोसे लड़ रही है।

भाजपा के लिए असली चिंता की वजह यह है कि कोई 10 साल बाद इस दफे के विधानसभा चुनाव में दलित व जाट वोटर खुल कर कांग्रेस के पक्ष में कदमताल कर रहे हैं। सो, उसकी काट के लिए भगवा पार्टी ने अपनी 'बी टीम' कहे जाने वाली मायावती की बसपा को काम पर लगा दिया है। बसपा बड़े चौटाला की पार्टी के साथ गठबंधन में हैं तो चंद्रशेखर आजाद दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी के साथ कदमताल कर रही है। जेजेपी का असली मकसद तो जाट वोटरों को कांग्रेस से तोड़ना है और अपरोक्ष तौर पर भाजपा को फायदा पहुंचाना है। बाकी कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालने के लिए तो केजरीवाल हैं न।

...और अंत में

हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस संगठन में एक व्यापक फेरबदल मुमकिन है। सूत्र बताते हैं कि हरियाणा कांग्रेस के एक प्रमुख नेता रणदीप सुरजेवाला को पार्टी महासचिव पद से हाथ धोना पड़ सकता है, अगर ऐसा

हुआ तो फिर उनके हाथ से कर्नाटक का प्रभार भी जाता रहेगा। कहते हैं सुरजेवाला ने राज्य की एक अन्य प्रमुख महिला नेत्री के साथ मिल कर कांग्रेस के सीएम पद उम्मीदवार भूपिंदर हुड्डा की राहों में कांटे बिछाए हैं, यह बात राहुल गांधी को पसंद नहीं आई है।

राहुल के विवादित बोल वचन

खरी-खरी बात

-वीरेन्द्र कपूर

राहुल गांधी ने छवि निर्माण की अपनी अंतहीन कवायद के तहत अमेरिका की अपनी हालिया यात्रा में उन्होंने हमेशा की तरह अपनी बड़ी गलती की, खुद को पूरी तरह अपरिपक्व बनाया और इस प्रक्रिया में भारत विरोधी तत्वों को अपनी बेतुकी टिप्पणियों का फायदा उठाने का एक नया मौका दे दिया।

इस सप्ताह के शुरू में वाशिंगटन में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता ने कहा कि भारत में सिखों को पगड़ी, कड़ा (स्टील का कड़ा) पहनने या गुरुद्वारे में प्रार्थना करने से डर लगता है। उन्होंने दावा किया कि वे मोदी सरकार द्वारा फैलाए गए भय के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। अब तक, उनका लक्ष्य भारतीय मुसलमानों को मोदी सरकार के तहत भेदभावपूर्ण व्यवहार का शिकार बनाना था, ताकि वे अपनी पार्टी के लिए वोट करने के लिए उन्हें लुभा सकें। अब ऐसा लगता है कि उन्होंने जाल को और चौड़ा कर दिया है, और सिखों को भी इसमें शामिल कर लिया है।

जैसा कि अनुमान था, भारत में सिखों के मुश्किल में होने के बारे में राहुल का बयान स्वयंभू खालिस्तानी नेताओं को रास आया। इस पर तत्काल प्रतिक्रिया गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से आई, जो भारत में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए वांछित एक नामित आतंकवादी है। राहुल द्वारा अपने रुख का समर्थन करने का स्वागत करते हुए पन्नू ने एक बयान में कहा कि राहुल ने "भारत में सिखों के अस्तित्व के लिए खतरे" को पहचान लिया है। भारत में सिखों के बारे में राहुल का बयान न केवल साहसिक और अग्रणी है, बल्कि 1947 के बाद से भारत में लगातार शासन के तहत सिखों को जो कुछ भी सामना करना पड़ा है, उसके तथ्यात्मक इतिहास पर भी पूरी तरह आधारित है और यह सिखों की मातृभूमि खालिस्तान की स्थापना के लिए पंजाब स्वतंत्रता जनमत संग्रह के औचित्य पर सिख फॉर जस्टिस फ्रंट के रुख की भी पुष्टि करता है। सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) एक प्रतिबंधित संगठन है। इसके बावजूद पन्नू अमेरिका और कनाडा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बिना किसी परेशानी के अपनी नापाक भारत विरोधी गतिविधियां जारी रखता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल हमेशा एक ही बात चिल्लाते रहते हैं कि सिखों, मुसलमानों, दलितों और ओबीसी आदि के खिलाफ भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव के लिए वह हमेशा मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं लेकिन वह यह भूल गए हैं कि उनकी अपनी पार्टी ने आजादी के बाद से पचास वर्षों तक शासन किया है।

राहुल के हालिया अमेरिकी दौरे के उद्धरणों पर लौटें तो वे कई 'ज्ञान के रत्न' दे रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है, जब तक कि आप उनके प्रति दयालु न हों और उनकी टिप्पणियों को जबान की फिसलन के रूप में माफ न कर दें। वे अपनी सार्वजनिक सभाओं में जो कहते हैं, उससे अक्सर उपहास होता है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल हमेशा एक ही बात चिल्लाते रहते हैं कि सिखों, मुसलमानों, दलितों और ओबीसी आदि के खिलाफ भेदभाव हो रहा है। इस भेदभाव के लिए वह हमेशा मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं लेकिन वह यह भूल गए हैं कि उनकी अपनी पार्टी ने आजादी के बाद से पचास वर्षों तक शासन किया है। खासकर नेहरू-गांधी परिवार के सदस्य कांग्रेस सरकारों की विफलता से खुद को दूर नहीं रख सकते हैं। यहां सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार इस बात का कोई संकेत नहीं देते हैं कि वह मुसलमानों के सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान कैसे करेंगे।

उधर लोकसभा में विपक्ष के नेता से बोलते समय महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिम्मेदारी के साथ बोलने की अपेक्षा थी। लेकिन नेता विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी को हराने, उनसे नहीं डरने, सिख भी पगड़ी पहनने से डरते हैं जैसे राग को अलापना बकवास की पराकाष्ठा है।

यह अलग बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य लोग उनकी टिप्पणियों का बचाव करने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन ऐसा करना सार्वजनिक उपहास को आमंत्रित करता है। अब, अगर राजनीति में कहीं डर है तो वह परिवार संचालित कांग्रेस पार्टी में है। हालांकि, आप सिखों के बारे में राहुल गांधी की टिप्पणी को जिस भी तरह से व्याख्या करें लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति उनका बचाव नहीं कर सकता। विशेष रूप से ऐसे समय में जब पंजाब राजनीतिक मंथन के दौर से गुजर रहा है, जिसमें एक घोषित खालिस्तान समर्थक प्रचारक को लोकसभा के लिए चुना गया है। किसी चरमपंथी कोने में खालिस्तानी उत्साह भड़काना बेहद गैर-जिम्मेदाराना और मूर्खतापूर्ण होने के समान था। अब समय आ गया है कि वह हमेशा एक तैयार स्क्रिप्ट के अनुसार सार्वजनिक रूप से बोलें। भले ही उनके कई दरबारी उनके बुद्धिजीवी होने का दावा करते हैं पर यह तेजी से शर्मिंदगी का कारण बनता जा रहा है।

बुजुर्गों की उम्मीदों का एक कदम और...

श्रीमती किरण चोपड़ा
डायरेक्टर- पंजाब केसरी दैनिक समाचार लि.
चेयरपर्सन- वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब
मुख्य संरक्षिका- दीपांत
सदस्या- राष्ट्रीय सलाहकार मण्डल, एकल संरक्षिका- भारतीय लोक विकास परिषद
f/kiranchopra01
kiranchopra@punjabkesari.com
kiranchopradesk@gmail.com

मुझे 20 साल हो रहे हैं बुजुर्गों के लिए कार्य करते हुए। सभी का अक्सर यह कहना होता है कि विदेशों की तरह हमारे देश में भी सामाजिक सुरक्षा और मुफ्त इलाज की सुविधा होनी चाहिए। मेरा मानना है कि जब बालों में सफेदी आने लगती है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं यानि उम्र 60 का आंकड़ा पार कर लेती है तो सही मायनों में अपने परिवार के लोगों की जरूरत पड़ती है, जिनके लिए बुजुर्गों ने जीवनभर खुद को कुर्बान किया हो। औलाद उनसे अगर उनकी प्रोपर्टी, धन-दौलत यानि सुख छीन ले और उन्हें अकेलेपन के लिए छोड़ दे तो वे बहुत पछताते हैं। हमारे पास ऐसी चिट्ठियां बहुत आती हैं, खुद भी आते हैं, जिनमें घरों के बुजुर्ग अपना दर्द बयान करते हैं। उनकी इस पीड़ा को हमने व्यक्तिगत रूप से समझा और वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब की स्थापना की थी। आज देशभर में 20 केन्द्र हैं, 2 गांवों में इसलिए मुझे बुजुर्गों की व्यक्तिगत कठिनाइयों और दिक्कतों के बारे में पता चलता रहता है, जिसमें उनके सम्मान का आहत होना भी शामिल है। इन सब में इस उम्र में उनकी सेहत पर असर जरूर पड़ता है। वे हैल्थ संबंधी सुविधाओं की मांग भी करते हैं, ऐसे में अगर मोदी सरकार उनके लिए 5 लाख तक का मुफ्त इलाज अर्थात हैल्थ इंश्योरेंस कवर लाई तो हम सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो बुजुर्गों का सम्मान करेगा, उनकी तकलीफें दूर करेगा वह भारत तो क्या दुनिया पर राज करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मोदी सरकार।

दुनियाभर की आबादी में लगभग 30 से 35 प्रतिशत लोग बुजुर्ग हैं और वे 60 वर्ष की उम्र पार करते-करते खुद को उपेक्षित मानते हैं। इसीलिए बुजुर्गों के लिए सरकारें उन्हें खुश रखने के लिए तरह-तरह की सुविधाएं प्रदान करती रहती हैं। उन्हें तीर्थस्थल भेजने के लिए मुफ्त ट्रेन सेवा व हवाई सेवा सुविधाएं दी जा रही हैं परन्तु सबसे जरूरी सेहत है। हैल्थ इज वैल्थ, सबसे पहले इस उम्र में हैल्थ फिर पैसा यानि आर्थिक मदद या सुविधा, सामाजिक सुरक्षा फिर ट्रांसपोर्ट जरूरी है।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा 2018 के केन्द्रीय बजट में आयुष्मान भारत की घोषणा की गई थी जिसके मुख्य लक्ष्य थे कि देश में एक लाख हैल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करना और 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख प्रतिवर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवच से जोड़ना। मोदी सरकार की इस योजना की तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा चलाई गई ओबामा केयर योजना से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को हैल्थ बीमा मुहैया कराना है। आयुष्मान योजना का लाभ देशभर के निम्न आय परिवारों को मिला।

सच बात तो यह है कि भारत के वरिष्ठ नागरिक जो आर्थिक रूप से सम्पन्न नहीं हैं, की हमेशा मांग रही है कि उन्हें उपचार मुफ्त में उपलब्ध कराया जाना चाहिए। जीवनभर की इनकी बचत पर बैंक इतना ब्याज नहीं देते कि वह अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। सामाजिक स्तर पर भी हम वरिष्ठ नागरिकों को कई तरह की परेशानियों से जूझते हुए देखते हैं। मैं कई वर्षों से वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का संचालन कर रही हूं और मुझे व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ नागरिकों की व्यथा का अहसास है। इसीलिए हमने उनके स्वास्थ्य के लिए देश के जाने-माने अस्पतालों के डॉक्टरों तथा संस्थाओं के सहयोग से हैल्थ कैम्प आयोजित करवाए तथा उनके लिए मनोरंजन के साधन के साथ-साथ उन्हें व्यस्त रखने का काम किया। अब आयुष्मान भारत योजना का लाभ 70 या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को मिल सकता है। मोदी मंत्रिमंडल ने इस संबंधी फैसले को मंजूरी भी दे दी है। इसे बुजुर्गों के लिए मोदी सरकार का बड़ा तोहफा माना जा रहा है। नौकरीपेशा लोग हमेशा अपनी वृद्धावस्था को लेकर चिंतित रहते हैं और सरकार का दायित्व भी बनता है कि वह अपने नागरिकों के भविष्य को सुरक्षित करे। मोदी कैबिनेट फैसले के अनुसार 4.5 करोड़ परिवारों के करीब-करीब 6.25 करोड़ सीनियर सिटीजन को मुफ्त हैल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा जिसमें हमारे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के सैंकड़ों सदस्यों भी लाभान्वित होंगे। तीन दिन पहले जब यह खबर आई मुझे तब से ही हमारे अनेक बुजुर्ग सदस्यों के फोन आए जिसमें उन्होंने सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। इसका क्या तरीका है, वो सरल और सबको समझ आने वाला होना चाहिए। मेरा मानना है कि पीएम मोदी को हमारे बुजुर्गों का सीधा आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि यद्यपि सरकार ने हैल्थ की दिशा में बहुत कुछ किया है। दिल्ली के एम्स की तरह राज्यों में भी एम्स बन रहे हैं परन्तु फिर भी एक गुजारिश मोदी जी से रहेगी कि हर भारतीय के निःशुल्क इलाज की व्यवस्था अगर हो जाए तो फिर देश का भला हो जाएगा। जब कोरोना का मोदी जी के मंत्रों के दम पर थाली बजाकर, दीये जलाकर कष्ट को दूर किया गया। निःशुल्क इलाज की राष्ट्रीय व्यवस्था भी हो सकती है लेकिन बुजुर्गों के लिए जो कुछ किया उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। मोदी जी आपने बुजुर्गों की उम्मीदों पर एक कदम और उठाया है बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुकमा में 8 नक्सली दबोचे

सुकमा, (भाषा): छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में सुरक्षाबलों ने एक इनामी नक्सली समेत आठ नक्सलियों को गिरफ्तार कर उनके पास से विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 12 सितंबर को जगरगुंडा थाना क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), जिला बल, बस्तर फाइटर और जिला रिजर्व गार्ड की संयुक्त टीम को गश्त के लिए रवाना किया गया था।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83

पंजाब केसरी

दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

अंग्रेजी दिवस कोई नहीं मनाता...फिर भी हर कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है; फिर भी हर कोई अपने बच्चों को अंग्रेजी ही पढ़ाना चाहता है; फिर भी हर कोई हिंदी वाला अंग्रेजी वाले के सामने कमजोर ही महसूस करता है। कड़वा है लेकिन यह सच है

अरविंद चोटिया, पत्रकार @arvindchotia

आपदा प्रबंधन

भारत डोगरा

प्रकृति के रौद्र रूप को नियंत्रित करें

प्रतिकूल मौसम के दौर में बेशक, आपदाएं बढ़ रही हैं, पर उचित नीतियों को अपना कर इन्हें बहुत हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन आपदा से होने वाली क्षति और दुख-दर्द को कई स्तरों पर रोकने से जुड़ा है। जहां हो सके तो आपदा की विनाशकारी संभावना को कई तरह से कम किया जा सके, लोगों को इसका सामना बेहतर करने की क्षमता को बढ़ाया जाए, बाद में उनकी सहायता और पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था हो-यह सब आपदा प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। आपदा प्रबंधन के उद्देश्य अल्पकालीन नहीं हैं अपितु दीर्घकालीन और व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए आपदाओं से होने वाली क्षति को कैसे कम किया जाए यह आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है।

कुछ क्षेत्रों विशेषकर दक्षिण एशिया के संदर्भ में अध्ययन बताते हैं कि पिछली लगभग एक शताब्दी के दौरान भूकंप पहले से अधिक जानलेवा बन गए हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि इस दौरान भूकंप से बचाव के भवन बनाने की तकनीक में काफी प्रगति होने के दावे किए गए। 'साइंस' पत्रिका में विश्व के जाने-माने भू-वैज्ञानिकों, कोलोरेडो विश्वविद्यालय के प्रो. रॉजर बिलहेम और भारत स्थित गणितीय मॉडलिंग केंद्र के प्रो. विनोद गौड़ ने लिखा है कि 1900 के बाद आए भूकंपों में केवल भारत और पाकिस्तान में जितनी मौतें हो चुकी हैं, वे इससे पहले की शताब्दियों में भूकंप के कारण हुईं मौतों से कहीं अधिक हैं। इन विशेषज्ञों के अनुसार भूकंपों में हुईं अधिक मौतों का कारण इस दौर में इन देशों में निर्माण के ऐसे तौर-तरीकों का उपयोग है जो कम मजबूत सिद्ध हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि यहां बेहतर तकनीक उपलब्ध नहीं है। वे उपलब्ध तो हैं, पर उनका उपयोग बहुत कम है। कई ठेकेदारों द्वारा निर्माण के नियम-कानूनों की उपेक्षा की जा रही है, जबकि स्वयं आवास बनाने वाले अनेक लोगों के पास जानकारी का भी अभाव है। भूकंप-रोधी तकनीकों का उपयोग सार्वजनिक भवनों में तो प्रायः हो जाता है पर आवासीय भवनों में इनका उपयोग प्रायः नहीं होता। इन वैज्ञानिकों ने कहा है कि जितनी जानकारी अभी उपलब्ध है, यदि केवल इसका उपयोग सुरक्षित निर्माण के लिए किया जाता है तो भविष्य में भूकंप से होने वाली मानवीय जीवन की क्षति में भारी कमी की जा सकती है।

दूसरी ओर यदि निर्माण कार्यों में ऐसा सुधार नहीं किया गया तो भूकंपीय चेतावनी के अधिक महंगे और खर्चीले उपाय भी मानवीय जीवन बचाने में सफल सिद्ध नहीं होंगे। मानव इतिहास में समुद्री तूफान एवं बहुत विनाशक आपदा के रूप में जाने गए हैं। समुद्र से उठने वाले चक्रवात तटीय क्षेत्रों में तूफानी आंधी और वर्षा से और समुद्री लहरों के प्रवेश से बहुत विनाश कर सकते हैं। इस कारण जो उग्र वर्षा होती है और आंधियां उठती हैं, वह समुद्र से काफी दूर तक भी क्षति कर सकती हैं। जब समुद्र तल में भूकंप आने से बहुत भारी मात्रा में पानी विस्थापित होता है तो उसके कारण उठीं लहरों को सुनामी कहते हैं। यह तटीय क्षेत्रों में बहुत ऊंचाई से प्रवेश कर भयंकर तबाही मचा सकती हैं। 12-13 अक्टूबर, 2013 को ओडिशा और आंध्र प्रदेश में चक्रवात से मानव-जीवन की रक्षा में हमारे देश ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यदि ऐसा ही चक्रवात कुछ दशक पहले आता तो इससे हजारों लोगों की मृत्यु हो सकती थी। पर इस वर्ष हम ऐसी त्रासदी से बच सके। चक्रवात ने आजीविका और संपत्ति की क्षति तो की, पर मानव-जीवन की क्षति को इस चक्रवात के उग्र वेग के दौर में हम बचा सके।

इस उपलब्धि पर देश गर्व कर सकता है। विज्ञान पत्रिका 'ज्योलोजी' ने हाल में उपलब्ध जानकारी और आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि विश्व में भू-स्खलन के कारण होने वाली मौतों की संख्या वास्तव में पहले के अनुमानों की अपेक्षा दस गुणा अधिक है। इस ओर विशेष ध्यान देना जरूरी है कि पर्वतीय क्षेत्र में किन मानवीय कारणों और गलतियों से भू-स्खलन के कारण होने वाली क्षति बढ़ी है। एक बड़ी वजह तो यह है कि विभिन्न निर्माण कार्यों (विशेषकर बांध निर्माण) तथा खनन के लिए, पर्वतीय क्षेत्रों में विस्फोटकों का अंधाधुंध उपयोग किया गया है। इस कारण भू-स्खलन की संभावना बढ़ गई है। इसको नियंत्रित और नियमित करना जरूरी है। वन-विनाश भी भू-स्खलन की संभावना बढ़ने का एक अन्य बड़ा कारण रहा है। बाढ़ और बाढ़-नियंत्रण के बारे में कुछ नये सिरे से सोचने की जरूरत महसूस की जा रही है। 1953-2010 के बीच देश में (2010-11 की कीमतों पर) बाढ़-नियंत्रण पर 124000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। इसके बावजूद लगभग 5 करोड़ हैक्टेयर आज बाढ़ प्रभावित है, जबकि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने 1980 में 4 करोड़ हैक्टेयर बाढ़ प्रभावित होने का अनुमान लगाया गया था।

अनेक बड़े बहुउद्देशीय बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए। 35000 किमी. के नदी तटबंध बनाए गए। इसके बावजूद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ इसके अनेक कारण बताए जाते हैं। जैसे जल निकासी के रास्तों को अवरुद्ध करते हुए नई बस्तियां बसाना (विशेषकर शहरी क्षेत्रों में शहरीकृत हो रहे क्षेत्रों में) सड़कों, नहरों और रेल मार्गों के निर्माण के समय निकासी की पर्याप्त व्यवस्था न करना, संसाधनों के अभाव या दुरुपयोग के कारण वर्षा से पहले नालों की सफाई जैसे जरूरी कार्य न करना आदि। अलग-अलग जगहों पर ये सभी कारण महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं, कहीं कम तो कहीं ज्यादा, पर केवल इनके आधार पर यह नहीं समझा जा सकता है कि बाढ़ नियंत्रण पर कई हजार करोड़ रुपये खर्च करने के बाद भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में इतनी वृद्धि क्यों हुई है।

वास्तविकता तो यह है कि बाढ़ का बढ़ता क्षेत्र और इसकी बढ़ती जानलेवा क्षमता को तभी समझा जा सकता है जब यदि बाढ़ नियंत्रण के दो मुख्य उपायों-तटबंधों और बांधों पर खुली बहस द्वारा जानने का प्रयास किया जाए कि अनेक स्थानों पर क्या बाढ़ नियंत्रण के इन उपायों ने ही बाढ़ की समस्या को तो नहीं बढ़ाया है और उसे अधिक जानलेवा तो नहीं बनाया है? हाल में एक अध्ययन में पांच बड़ी आपदाओं से 45 वर्षों के दौरान (1967-2012) भारत में होने वाली मौतों संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण किया है। फैसल इलियास, केशव मोहन, शिबु मणि और एपी प्रदीप कुमार द्वारा किए गए इस अध्ययन ने बताया है कि इस दौरान इन आपदाओं में से जहां 39 प्रतिशत मौतें आकाशीय बिजली गिरने से हुईं, वहां 18 प्रतिशत मौतें बाढ़ से हुईं, 15 प्रतिशत भू-स्खलन से हुईं, 15 प्रतिशत हीट स्ट्रोक से हुईं और 13 प्रतिशत कोल्ड स्ट्रोक से हुईं।

आकाशीय बिजली गिरने संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान और जरूरी जानकारियां एकत्र करने के कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इस आपदा से होने वाली क्षति को कम करने का सबसे महत्त्वपूर्ण उपाय तो यही है कि जिन भवनों में बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं कम से कम वहां अच्छी गुणवत्ता के लाइटनिंग कंडक्टर जरूर लगने चाहिए। ऐसे उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए और इनका समुचित उत्पादन अपने देश में होना चाहिए। विशेषकर स्कूलों और अस्पतालों में ये उपकरण अवश्य लगने चाहिए। झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने संबंधी सबसे दर्दनाक हादसे स्कूलों में ही हुए हैं।

आपदा प्रबंधन आपदा से होने वाली क्षति और दुख-दर्द को कई स्तरों पर रोकने से जुड़ा है। जहां हो सके तो आपदा की विनाशकारी संभावना को कई तरह से कम किया जा सके, लोगों को इसका सामना बेहतर करने की क्षमता को बढ़ाया जाए, बाद में उनकी सहायता और पुनर्वास की बेहतर व्यवस्था हो-यह सब आपदा प्रबंधन के महत्त्वपूर्ण पक्ष हैं। आपदा प्रबंधन के उद्देश्य अल्पकालीन नहीं हैं अपितु दीर्घकालीन और व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए आपदाओं से होने वाली क्षति को कैसे कम किया जाए यह आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है। कुछ क्षेत्रों विशेषकर दक्षिण एशिया के संदर्भ में अध्ययन बताते हैं कि पिछली लगभग एक शताब्दी के दौरान भूकंप पहले से अधिक जानलेवा बन गए हैं। सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि इस दौरान भूकंप से बचाव के भवन बनाने की तकनीक में काफी प्रगति होने के दावे किए गए

किसी के भौंपू किसी के हरकारे

मीडिया

सुधीश पचौरी

टीवी भी बड़ा ही जानलेवा माध्यम है। यकीन न हो तो एंकरों, रिपोर्टरों और डेस्ककर्मियों से पूछिए। न वक्त की चिंता, न धूप ताप या आंधी, बरसात की फिक्र! बस लगे रहो मुन्ना भाई! न रात, न दिन, बस देते रहो कहीं ट्रेन हादसे की लाइव खबर, कहीं दंगे की लाइव खबर। जान की बाजी लगाते हुए और जल्दी 'बर्नआउट' हो गए या दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो बॉस की कृपा रही तो एक लाइन में सिमट गए।

बॉस किसी काम से खुश नहीं होते। गलती हुई या नहीं, बॉस का मूड खराब तो तू अभी जा! फिर कितने बॉस और बॉसों के बॉस...लेकिन जब दिखो तब चमकते-दमकते, सज-संवरे दिखो। ऐसे जालिम मीडियम के बावजूद टीवी में काम करते लाखों युवा-युवती, उसके रिपोर्टर या एंकर बनने के लिए बावले हुए रहते हैं! ऐसी प्यारी मरीचिका है कि अभ्यर्थियों की लाइनें लगी रहती हैं। कई चैनलों के मीडिया स्कूल भी हैं। दाखिला लो, पढ़ो, इंटर्नशिप करो और फिर काम खोजो...। 'मिल जाए तो मिट्टी है खो जाए तो सोना है...।' फिर भी हम कहेंगे कि टीवी कुछ की बेरोजगारी तो दूर करता ही है और फिर कोई एक मीडिया सबको नौकरी कैसे दे सकता है? एक बार आप टीवी में आ गए और कुछ बन गए जैसे रिपोर्टर, एंकर रिपोर्टर या डेस्क वर्कर ही, तो आप 'सेलीब्रिटी' हो गए। एक बार हो गए तो बहुत दिनों तक हो गए। लोग देखते ही कहेंगे वो देखो वो जा रहा है/जा रही है एंकर, कि हमने आज उस चैनल के उस एंकर को देखा, उस रिपोर्टर को देखा...और ये नामी एंकर, रिपोर्टर भी अपने को किसी हीरो या हीरोइन से कम नहीं समझते। उनको लगता है कि वे समाज को चलाते हैं, हिलाते, डुलाते, सुलाते हैं। वे ही समाज को सही दिशा दिखाने वाले हैं...

चलिए, टीवी के प्रोफेशनल तो ऐसे ही होते हैं। इतराएं, नखरे दिखाएं, तो समझ में आता है लेकिन वे भी अपने को कम नहीं समझते जो चैनलों की बहसों व चरचाओं में आते हैं। कई चेहरे हैं जो या तो पत्रकार हैं या पूर्व पत्रकार हैं या टीचर/प्रोफेसर हैं या संपादकीय पेजों पर लेख लिखने वाले 'लेखक' हैं या 'ऑथर' हैं या फिर किसी बड़े कोर्ट के वकील हैं जो कानून के दांव-पेच बताने वाले कानूनी विशेषज्ञ माने जाते हैं या फिर 'आनलाइन पेपर' निकालने वाले होते हैं या कुछ 'यूट्यबर' होते हैं। ज्ञान इनकी जेब में रहता है!

'यूट्यूबर' तो यों भी डिजिटल मीडिया के हीरो/हीरोइन माने जाते हैं लेकिन वे भी टीवी चैनलों में आने के लिए जेवड़ा तुड़ाते रहते हैं और वे भी जेवड़ा तुड़ाते रहते हैं जो पत्रकार हैं, प्रोफेसर हैं या किसी राजनीति के एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन जब 'ज्ञान की आंधी' आती है तो 'अज्ञान' के 'छप्पर टप्पर' सब उड़ जाते हैं, और इस चक्कर में कभी-कभी ऐसे 'ज्ञानी' भी उड जाते हैं! ऐसे ज्ञानी इन दिनों अपने चैनलों पर आए दिन प्राइम टाइम की बहसों में सज-धज कर आ बिराजते हैं, और अपने ज्ञान का पिटारा खोल कर बांटते रहते हैं। आए दिन ज्ञान की गठरी बांटते देख हमारे जैसे अधम अज्ञानी भी इनको अपना उस्ताद मान लेते हैं, और क्यों न मानें? हमें तो लगता है कि आज इंडिया की 'ज्ञान' की असली 'क्रीमी लेअर' यही है, बाकी अज्ञानी और असभ्य इंडिया को यही ज्ञानी और सुसभ्य बना सकते हैं क्योंकि यहां जो कुछ ज्ञान बचा है, इन्हीं के पास बचा है!

और रोज-रोज अपने को ज्ञान देते देख, ये भी समझने लगते हैं कि इस युग के वे ही प्लेटो-स्लेटो, अरस्तू-फरस्तू हैं और फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले बचे-खुचे देसी 'वोल्तेअर', 'हॉब्स', 'लॉक' और 'रूसो' आदि हैं जो अज्ञान के अंधेरे में डूबी जनता के लिए 'जनतंत्र' बचा सकते हैं, उसे 'सेकूलर' बना सकते हैं, 'तानाशाही' रोकने वाले हैं और देश की तानाशाही और फासिज्म के खिलाफ सबसे बड़े योद्धा हैं और अगर ये सब रुका है तो उन्होंने ही रोका है। लेकिन कुछ ऐसे 'ज्ञानी' भी, जो अतीत में गोते लगा कर अपने विरोधियों का जवाब देते हुए हम जैसे भुलक्कड़ों को भी अपने अतीत की महानता के किस्से सुनाकर चकित-थकित करते रहते हैं कि 'जो वहां है वह यहां है' बल्कि ये चोट्टे अपना ही माल ले गए हैं...और अंग्रेजी की छन्नी में छान कर हमें ही पिलाते रहते हैं और जो इनके विपरीत हैं, देशद्रोही हैं, गद्दार हैं। इन सबका 'डिकॉलोनाइज' करना हैं...चूंकि अपने देश में अभी जनतंत्र है, चैनलों में तो है ही, इसलिए ये भी अपने को टीवी में कभी 'ऑथर', 'चिंतक' 'विश्लेषक', 'एक्सपर्ट' के रूप में देख चढ़े रहते हैं। लेकिन आजकल के विभक्त दिनों में जब तब इनके बीच 'फाइट' हो जाती हैं तो साफ हो जाता है कि हैं ये किसी के भौंपू, किसी के हरकारे, किसी के लठैत!

चूंकि अपने देश में अभी जनतंत्र है, चैनलों में तो है ही, इसलिए ये भी अपने को टीवी में कभी 'ऑथर', 'चिंतक' 'विश्लेषक', 'एक्सपर्ट' के रूप में देख चढ़े रहते हैं। लेकिन आजकल के विभक्त दिनों में जब तब इनके बीच 'फाइट' हो जाती हैं तो साफ हो जाता है कि हैं ये किसी के भौंपू, किसी के हरकारे, किसी के लठैत

'मीडिया युद्ध' में अमेरिका की हार

वैश्विकी

डॉ. दिलीप चौबे

सूचना विस्फोट के युग में एक अनोखी घटना हुई यह हुई कि अमेरिका ने लगता है कि मीडिया-युद्ध में अपनी हार मान ली है। विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने रूस के प्रमुख मीडिया समूह आरटी (रसिया टुडे) पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। यह विडंबना है कि अभिव्यक्ति की आजादी के स्वयंभू संरक्षक अमेरिका ने दुनिया के प्रमुख मीडिया समूह को निशाना बनाया है। आरटी मीडिया समूह टेलीविजन, वेबसाइट और अन्य माध्यमों से विश्व मामलों पर रूस का नजरिया पेश करता है। भारत में भी आरटी का व्यापक नेटवर्क है और इसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश के प्रमुख विदेश नीति जानकार और राजनीतिक विशेषज्ञ आरटी के जरिए अपनी बात रखते हैं। कुछ समय पहले तब दुनिया की सूचना तंत्र पर अमेरिका और पश्चिमी देशों का एकाधिकार था। टेलीविजन के विस्तार के बाद इन देशों के चैनल दुनिया पर छा गए थे। सबसे पहले कतर के टेलीविजन चैनल 'अल जजीरा' ने हम ने इस एकाधिकार को तोड़ा। अल जजीरा अरब और इस्लामी जगत के नजरिए को पेश करता रहा है। लेकिन अन्य विश्व मामलों पर वह अमेरिका की हां में हां मिलता है।

शीत युद्ध के दौरान तत्कालीन सोवियत संघ का लगभग आधी दुनिया पर प्रभाव था। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर भारत सहित विभिन्न देशों के वामपंथी राजनीतिक दल और संगठन उसका पक्ष प्रस्तुत करते थे, लेकिन सोवियत संघ के विघटन और वहां साम्यवादी विचारधारा की हार के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। कहने के लिए चीन आज भी एक कम्युनिस्ट देश है, लेकिन वह मार्क्सवाद और लेनिनवाद के विचारधारा का दुनिया में प्रचार-प्रसार नहीं करता। इन हालात में विश्व जनमत को प्रभावित करने के लिए अमेरिका के सामने खुला मैदान था। इसकी एक झलक भारत के मीडिया कवरेज से भी मिलती है। भारत के मीडिया का एक बड़ा वर्ग पश्चिमी देशों के मीडिया माध्यमों का ही अनुसरण करता रहा है। हाल के वर्षों में इस स्थिति में क्रमशः बदलाव आया है। इसमें आरटी और ग्लोबल साउथ के मीडिया संस्थानों की भी प्रमुख भूमिका है। उदाहरण के लिए यूक्रेन युद्ध के संबंध में भारतीय मीडिया ने अमेरिका के हां में हां मिलाने से इनकार कर दिया है। कुछ सीमा तक इसकी सहानुभूति रूस के साथ है। अमेरिका ने यह हास्यास्पद बयान दिया है कि आरटी के कारण ग्लोबल साउथ का जनमत यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा। भारत सहित ग्लोबल समूह के साउथ के अधिकतर देश यूक्रेन युद्ध के लिए एकमात्र दोष रूस को नहीं देते। भारत में तो रूस के प्रति समर्थन सबसे अधिक देखा गया है। पिछले वर्ष हुए एक विश्वव्यापी सर्वे के अनुसार भारत में रूस के प्रति समर्थन चीन से भी अधिक है। भारत के 51% लोग रूस को एक रणनीतिक साथी मानते हैं। साथ ही 29% लोग रूस को एक आवश्यक सहयोगी तसलीम करते हैं। इस प्रकार 80% भारतीयों का मत रूस के पक्ष में है। केवल 04 फीचर लोग रूस को भारत का विरोधी मानते हैं। इतना ही नहीं एक ताकतवर विश्व नेता के रूप में भारत में पुतिन की रेटिंग सबसे अधिक है।

अमेरिका ने यह हास्यास्पद बयान दिया है कि आरटी के कारण ग्लोबल साउथ का जनमत यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा। भारत सहित ग्लोबल समूह के साउथ के अधिकतर देश यूक्रेन युद्ध के लिए एकमात्र दोष रूस को नहीं देते। भारत में तो रूस के प्रति समर्थन सबसे अधिक देखा गया है

आश्चर्य की बात है कि रूसी नागरिकों से भी अधिक भारतीय नागरिकों का पुतिन के नेतृत्व में भरोसा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रूस के प्रति दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रूस के प्रति यह समर्थन अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। अमेरिकी विश्लेषक हैरान हैं कि हाल के वर्षों में भारत और अमेरिका के संबंधों में व्यापक में विस्तार होने के बावजूद भारतीय जनमत रूस को क्यों तरजीह देता है। अमेरिका का यह तर्क किसी के गले नहीं उतर सकता कि आरटी और अन्य रूसी माध्यमों के कारण ऐसा हो रहा है। वास्तव में भारत में रूस के प्रति समर्थन की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। सन 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारत के समर्थन में रूस ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने आरोप लगाया है कि आरटी केवल एक मीडिया संस्थान नहीं है बल्कि वह रूस के खुफिया तंत्र का हिस्सा है। ब्लिंकन का यह कथन 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' जैसा है। सूचना युद्ध में अमेरिका की यह हार इस बात का एक और संकेत है कि दुनिया बहुध्रुवीय बन रहा है जिसमें भारत एक ध्रुव के रूप में उभर रहा है।

मनोवैज्ञानिक समाधान की है दरकार

अंधविश्वास

संजीव ठाकुर

अशिक्षा और अज्ञानता अंधविश्वास तथा धार्मिक कट्टरता के पीछे गहरा मनोवैज्ञानिक मानवीय पहलू छुपा हुआ है। इसका समाधान सर्वप्रथम हमें खोजना होगा, यह सामाजिक तौर पर भी बड़ी समस्या है।

यदि कम पढ़ा-लिखा आदमी धार्मिक अंधविश्वास को मानता है तो बात समझ आती है किंतु इस वैज्ञानिक युग में अत्यंत शिक्षित एवं पढ़े-लिखे लोग भी अंधविश्वास तथा धार्मिक कट्टरता के पीछे भागने लगें तो समाज और देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। यह तो तय है कि शिक्षा, ज्ञान अज्ञानता के अंधकार को मिटा कर विवेकपूर्ण विचारों को सोचने की शक्ति प्रदान करती है और इसके पश्चात ही मनुष्य वैज्ञानिक आधार पर तर्क रख कर अपनी बात को मानना शुरू करता है। पूर्व में हम मानते थे कि पृथ्वी चपटी है किंतु वैज्ञानिक प्रयोगों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के अनुसार सिद्ध हो गया कि पृथ्वी गोल है अब लोगों ने लॉजिक और वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर मान लिया है कि पृथ्वी गोल ही है।

शहीद भगत सिंह ने आजादी के लिए एक संगठन नौजवान भारत सभा का गठन किया और उसके घोषणापत्र में कहा था कि धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता हमारी प्रगति के बहुत बड़े बाधक हैं, हमारे रास्ते की बाधा साबित हुए हैं, उनसे हमें हर हाल में छुटकारा पा लेना चाहिए जोकि आजाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे समाप्त हो जाना चाहिए इसी प्रकार अन्य बहुत सारी कमजोरियां भी हैं, जिन पर हमें विजय प्राप्त करना होगा, इस कार्य के लिए सभी समुदाय के क्रांतिकारी उत्साह रखने वाले नई सोच के नौजवानों की आवश्यकता है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था क्योंकि युवा शक्ति ही देश में नये विचारों की क्रांति ला सकती और अंधविश्वास को समूल नष्ट करने में इनकी ऊर्जा इस कार्य के लिए लगाई जा सकती है, पर दूसरी तरफ शिक्षा का प्रचार-प्रसार होना भी नितांत आवश्यक है। शिक्षा ही ऐसा मूल मंत्र है जिससे अंधविश्वास एवं आडंबर की पोल खोली जा सकती है। शिक्षा से हमारा तात्पर्य विज्ञान से भी है। विज्ञान ने अनेक अंधविश्वास को जनसूचियों में अविश्वास के रूप में में स्थापित किया है और शिक्षा तथा विज्ञान, तकनीकी ऐसे मार्ग हैं, जिन पर चल कर हम न सिर्फ चांद पर पहुंचे हैं, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरी दुनिया एक परिवार की तरह एक दूसरे के एकदम करीब आ चुकी है।

ऐसे में अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरता एवं संप्रदायवाद की जगह कहां बच जाती है भला? शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो जाना चाहिए की इन अंधविश्वासी बातों और मिथकों का अस्तित्व ही मूल रूप से विस्मृत किया जाना चाहिए। बिल्ली के रास्ता काटने से काम रुक जाता है, किसी की छींक से अशुभ संकेत स्थापित होने लगते हैं। यदि कौवा बोलता है तो मेहमान आने का संकेत माना जाना इन सब बातों की कोई तार्किक अथवा वैज्ञानिक आधार नहीं है और जनमानस द्वारा अपने दिमाग का प्रयोग कर ऐसी अतार्किक और वैज्ञानिक बातों में विश्वास करना भी अंधविश्वास को सामाजिक स्तर पर मान्यता प्रदान करता है। यह भी अशिक्षा का बड़ा परिणाम है। शिक्षा विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान समाज में तर्कसंगत बातों का विश्वास करने पर भरोसा दिलाता है और धीरे-धीरे अंधविश्वास तथा धार्मिक कट्टरता से मनुष्य को परे ले जाता है। मूलतः अंधविश्वास दूर करने के लिए हमें शिक्षा जैसे अस्त्र का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर

अर्थव्यवस्था

प्रह्लाद सबनानी

भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 3.93 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है जबकि जापान के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.21 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है एवं जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.59 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 8 प्रतिशत प्रति वर्ष बनी हुई है और जापान एवं जर्मनी की आर्थिक विकास दर लगभग स्थिर है अथवा इसके ऋणात्मक रहने की भी प्रबल संभावना है। इस दृष्टि से मार्च, 2025 तक भारत जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा एवं मार्च, 2026 तक भारत जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाल के समय में जर्मनी व जापान की अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न प्रकार की समस्याएं दृष्टिगोचर हैं, जिनके कारण इन दोनों देशों की आर्थिक विकास दर आगे आने वाले वर्षों में विपरीत रूप से प्रभावित रह सकती है।

वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव भी जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है एवं अब पूरे विश्व में गैर-वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। प्रत्येक विकसित एवं विकासशील देश अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलंबी बनना चाहता है। अतः जर्मनी जैसे देशों से मशीनरी एवं कारों का निर्यात कम हो रहा है। इन उत्पादों की तकनीक भी लगातार बदल रही है जिसे जर्मनी की विनिर्माण इकाइयां उपलब्ध कराने में असफल सिद्ध हुई हैं। बिजली पर चलने वाली कारों का जर्मनी में उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर चीन से इन कारों का भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है। अपनी आर्थिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जर्मनी ने यूक्रेन को टैंकों की आपूर्ति भी रोक दी है। दरअसल, कोरोना महामारी के बाद से ही, 2020 के बाद से, जर्मनी की अर्थव्यवस्था अभी तक सही तरीके से पूरे तौर पर उबर ही नहीं सकी है।

एक अनुमान के अनुसार जर्मनी अर्थव्यवस्था का आकार 2024 में भी कम होने जा रहा है, यह 2023 में भी कम हुआ था और इसके 2025 में भी सुधरने की संभावना कम ही दिखाई दे रही है। जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद में 2024 के दौरान 0.1 प्रतिशत की कमी की संभावना व्यक्त की जा रही है। बेरोजगारी की दर भी 6.1 प्रतिशत के स्तर तक ऊपर जा सकती है। जर्मनी अर्थव्यवस्था केवल चक्रीय ही नहीं, बल्कि संरचनात्मक क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना कर रही है। इसमें सुधार की कोई संभावना आने वाले समय में नहीं दिख रही है। हालांकि यूरोपीयन यूनियन में जर्मनी की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परंतु फिर भी भारत, उक्त कारणों के चलते, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को मार्च, 2026 तक पीछे छोड़ देगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है।

इसी प्रकार, पिछले लगभग 30 वर्षों के दौरान जापान की अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, ब्याज दरें एवं येन की कीमत स्थिर रही है परंतु, हाल ही के समय में येन का अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवमूल्यन हो रहा है एवं यह 160 येन प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गया है, जो 2009 के बाद से कभी नहीं रहा है। जापान की अर्थव्यवस्था कई उत्पादों के आयात पर निर्भर करती है। जापान अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं का 90 प्रतिशत एवं खाद्य सामग्री का 60 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। जापान द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने से जापान में भी आयातित मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही है, जो पिछले एक दशक के दौरान लगातार स्थिर रही है। 1955 से वर्ष 1990 के बीच जापान की अर्थव्यवस्था औसत 6.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आगे बढ़ती रही। 1990 तक जापान का स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ता रहा एवं अचानक 1990 में यह बुलबुला फट पढ़ा और जापान में आवासीय मकानों की कीमत 50 प्रतिशत तक गिर गई एवं व्यावसायिक मकानों की कीमत 85 प्रतिशत तक गिर गई। जापान के पूंजी बाजार में निक्के स्टॉक सूचकांक भी 75 प्रतिशत तक गिर गया।

जापान की अर्थव्यवस्था में तेजी के दौरान आस्तियों की बढ़ी हुई कीमत पर ऋण लिए गए थे परंतु जैसे ही इन आस्तियों की कीमत बाजार में कम हुई, नागरिकों को ऋणराशि की किश्तें चुकाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और इससे भी जापान में आर्थिक समस्याएं बढ़ी थीं। दिवालिया होने वाले नागरिकों की संख्या बढ़ी और देश में अपस्फीति की समस्या प्रारंभ हो गई थी। जापान की सरकार ने आर्थिक तंत्र में नई मुद्रा की मात्रा बढ़ाई और ब्याज दरों को लगभग शून्य कर दिया। इन समस्त उपायों से भी जापान में आर्थिक समस्याओं का हल नहीं निकल सका। 2022 में जापान में भी विश्व के अन्य देशों की तरह मुद्रास्फीति बढ़ने लगी थी परंतु जापान ने ब्याज दरों को नहीं बढ़ाया। कुल मिलाकर जापान अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है एवं वहां पर आगे आने वाले समय में आर्थिक विकास के पटरी पर आने की संभावना कम ही नजर आती है। अतः भारत जापान की अर्थव्यवस्था को मार्च, 2025 तक पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 3.93 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है जबकि जापान के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.21 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है एवं जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.59 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 8 प्रतिशत प्रति वर्ष बनी हुई है और जापान एवं जर्मनी की आर्थिक विकास दर लगभग स्थिर है अथवा ऋणात्मक रहने की भी प्रबल संभावना है। इस दृष्टि से मार्च, 2025 तक भारत जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा एवं मार्च, 2026 तक भारत जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3,4, सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 705-706, सातवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 23352368, 23352369, 23352371, 23352372, फैक्स - 23352370, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750

वर्ष-34, अंक 32

आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026

*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

फिल्म 'थंगलान' दलितों के इतिहास और अन्यायों को उजागर करती है, लेकिन उत्तर भारत में यह फिल्म स्क्रीनिंग के लिए समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे संवेदनशील विषयों की स्क्रीनिंग को समर्थन मिलना चाहिए ताकि इसका संदेश व्यापक रूप से पहुंच सके।
—अंकित पचौरी, पत्रकार @ankit_Mooknayak

धर्म

गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की लें शपथ

ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि समय आ गया है कि गौमाता में विराजमान 33 करोड़ देवताओं की तरह देश की जनता शपथ ले कि गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिला कर ही चैन लेना है। अयोध्या से 22 सितम्बर को पूरे देश में 33 दिनों की यात्रा से हिन्दू जागरूकता और एकता का अलख जगाएंगे। पद यात्रा में दिल्ली समेत सभी सुदूरवर्ती राज्य भी शामिल हैं। पदयात्रा 25 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी और 26 अक्टूबर को वृंदावन में इसका समापन होगा। उनका कहना है कि जिस तरह से देश में वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर देश में तत्परता दिखाई जा रही है, उसी तरह से गौमाता को लेकर बात क्यों नहीं होती। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अयोध्या में राममंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी चर्चा में रहे थे। उन्होंने मंदिर के प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर आपत्ति जताते हुए मंदिर अधूरा होने का संदेश देशवासियों को दिया था कि अधूरे मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा नहीं होती। एक बार शंकराचार्य फिर चर्चा में हैं। उनसे **हमारे संवाददाता भारत पाण्डेय** ने गौमाता को लेकर प्रस्तावित पदयात्रा के बारे में विस्तार से बातचीत की।

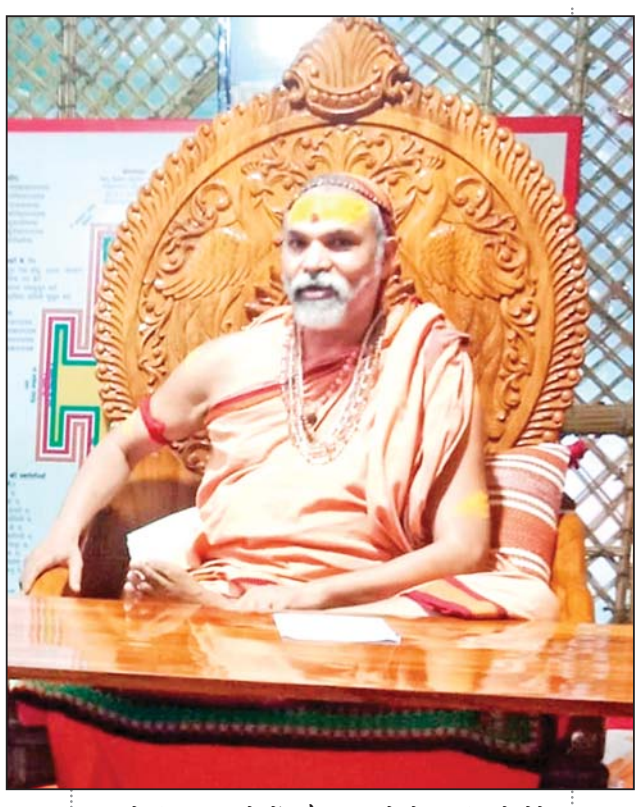

बातचीत के दौरान शंकराचार्य ने कहा कि वे गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर पूरे देश में पदयात्रा कर संवाद करेंगे। पदयात्रा के माध्यम से करोड़ों लोगों को जागरूक करेंगे कि गौमाता की रक्षा के लिए उठ खड़े हों। गौ संरक्षा को लेकर भी खड़े होने की जरूरत पर उन्होंने बल दिया है, क्योंकि गौमाता ही भगवान के अवतार का कारण बनी थी। शंकराचार्य ने इस बात पर एतराज जताया कि कुछ पार्टियां अपने को हिन्दू पार्टी बताती हैं, लेकिन गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की दिशा में कोई प्रयास नहीं कर रही हैं। शंकराचार्य के अनुसार देश में तमाम पार्टियों ने अपनी सरकार तो बनाई लेकिन गौहत्या पर किसी की भी सरकार ने रोक नहीं लगाई। इस बार वह सनातन धर्मप्रेमियों से अपील जरूर करेंगे कि गौहत्या को बढ़ावा देने वाले किसी भी नेता का खुलेआम चुनाव में विरोध करते हुए उनसे शपथ पत्र लें कि वे चुनाव जीतने के बाद गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने का काम करेंगे।

चार माह पहले भी शंकराचार्य ने गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए पैदल यात्रा की थी। यह यात्रा उनके लिए भले ही कष्टकारी रही,लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। गौर करने वाली बात है कि वर्ष 1966 में गौभक्तों पर तत्कालीन सरकार ने गोलीबारी की थी। गौभक्त लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन अब सरकार से गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वे कहते हैं कि उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि गौहत्या को बढ़ावा देने वाले कांग्रेस के हैं, या बीजेपी के लोग हैं, लेकिन सनातन धर्म के 100 करोड़ लोगों की यह मांग है कि गौमाता की हत्या बंद होनी चाहिए और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। वे कहते हैं कि गाय सिर्फ हमारी और भारत की नहीं, बल्कि पूरे विश्व की माता है।

सनातन धर्म में गौहत्या महापाप है। देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और रामजी के आने की बात कही जा रही है। तब भी अमृत (दूध) देने वाली गौमाता की हत्या होती रहे तो यह सरासर अन्याय है। देश का हर हिन्दू और सनातनी चाहता है कि भारत में गौहत्या को दंडनीय अपराध माना जाए और गौमाता को पशु सूची से निकाल कर राष्ट्रमाता का सम्मान दिया जाए। जिस प्रकार देश में राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय पक्षी आदि को संविधान में सम्मान प्राप्त है, वैसे ही गौमाता को भी राष्ट्रमाता का सम्मान प्राप्त हो। लोग गौरक्षा और गौ संरक्षण का संकल्प लें और भारत से गौहत्या बंद करने के लिए आगे आएं। जगतगुरु शंकराचार्य के अनुसार गौहत्या सरेआम हो रही है। गौमांस भी सरेआम बिक रहा है, लेकिन देश की सरकार अब तक चुप और मौन है। गौहत्या को लेकर किसी तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया है। सनातन और हिन्दू समाज यह चाहता है कि गौहत्या के लिए कड़े से कड़ा नियम-कानून बने, साथ ही गौहत्या करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चहिए। गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा भी दिया जाए। हालांकि, दिल्ली में शंकराचार्य का चातुर्मास शुरू हो गया है, लेकिन पदयात्रा आयोजन से जुड़े सनातन प्रेमी, कार्यकर्ता पूरे देश में इसे लेकर अलख जगाएंगे। साथ ही, करोड़ों लोगों को जागरूक करेंगे कि चाहे नंगे पाव ही क्यों न घर से निकलना पड़े, अब समय आ गया है कि गौमाता के लिए खड़े हों। चाहे इसकी कोई कीमत ही न चुकानी पड़े। उन्होंने कहा कि वे एक अच्छे काम के लिए देश भर में पदयात्रा करेंगे।

उनका कहना है कि शंकराचार्य की गद्दी पर बैठकर उनका मन धिक्कारता है कि गौमाता की लगातार हत्या हो रही है। अब हिन्दू भावनाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। गौ जय-पराजय और राजनीति का विषय नहीं है। यह हम सब की मां है। जब वे संकट में है तो हम कैसे अपने को संकटविहीन समझ लें। गौ को ट्रकों में भरकर कत्लगाहों में भेजने पर भी उन्होंने चिंता जताई। गौहत्या को महापाप बताते हुए उन्होंने मांग की कि इस पर पूरे देश में कानून बनाने की जरूरत है। सभी राज्यों में कानून लागू हो। इसे नजरंदाज करना करोड़ों सनातनी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत में गाय (गौ) को माता का दर्जा दिया गया है। इसे गौमाता कहा जाता है और हिन्दू धर्म में इसे विशेष रूप से पवित्र माना जाता है। गाय की पूजा की जाती है और उसे जीवनदायिनी के रूप में देखा जाता है क्योंकि वह दूध, गोबर और अन्य उपयोगी चीजें प्रदान करती है। ■

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अयोध्या से 22 सितम्बर को पूरे देश में 33 दिनों की यात्रा से हिन्दू जागरूकता और एकता का अलख जगाएंगे। पद यात्रा में दिल्ली समेत सभी सुदूरवर्ती राज्य भी शामिल हैं। पदयात्रा 25 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी और 26 अक्टूबर को वृंदावन में इसका समापन होगा। उनका कहना है कि जिस तरह से देश में वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर देश में तत्परता दिखाई जा रही है, उसी तरह से गौमाता को लेकर बात क्यों नहीं होती।

स्वस्थ जीवनशैली और होम्योपैथी

डॉ. बी.के. साहू

होम्योपैथी का इतिहास बहुत समृद्ध है, जिसकी शुरुआत 1796 में जर्मनी में डॉ. सैमुअल हैनीमैन के साथ हुई थी। यह दुनिया भर में लोकप्रिय हो गई है। खासकर भारत में जहां यह आयुष चिकित्सा का अभिन्न अंग है। आयुष मंत्रालय और विभिन्न नियामक निकाय भारत में आयुष दवाओं के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और विनियमन को सुनिश्चित करते हैं। आयुष दवाओं के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम लागू किया है और केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न औषधि नियंत्रण संगठन, निदेशालय और विभाग स्थापित किए हैं।

आयुष डॉक्टर केंद्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और जिला अस्पतालों में आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। होम्योपैथी उपचारों के वैज्ञानिक आधार को समझने के प्रयास जारी हैं, जिनमें चिकित्सा की विज्ञान-आधारित प्रणाली के रूप में इसकी क्षमता पर जोर दिया गया है। होम्योपैथी की स्थायी लोकप्रियता का महत्त्वपूर्ण कारण इसका समग्र दृष्टिकोण है, जो व्यक्तियों के समग्र स्वास्थ्य को संबोधित करता है। पारंपरिक चिकित्सा के विपरीत होम्योपैथी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक पहलुओं को शामिल करते हुए पूरे व्यक्ति के उपचार पर ध्यान केंद्रित करती है। यह रोगी-केंद्रित दृष्टिकोण विशेष रूप से उन लोगों के लिए आकर्षक है, जो अधिक व्यापक स्वास्थ्य देखभाल चाहते हैं।

प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होम्योपैथिक उपचार उनके उच्च कमजोर पड़ने और महत्त्वपूर्ण दुष्प्रभावों की कमी के कारण सुरक्षित माने जाते हैं। प्राकृतिक उपचार की यह धारणा उन व्यक्तियों के लिए आकर्षक है, जो दवाओं और उनके संभावित दुष्प्रभावों से सावधान हैं। होम्योपैथी भारत जैसे देशों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में गहराई से अंतर्निहित है, जिसमें सरकारी सहायता और समर्पित होम्योपैथिक कॉलेज हैं। इसकी सामर्थ्य और गैर-आक्रामक प्रकृति इसे पारंपरिक चिकित्सा देखभाल के लिए एक सुलभ विकल्प बनाती है, खासकर संसाधन-विवश सेटिंग्स में। कई लोग पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए होम्योपैथी की ओर रुख

करते हैं, जो पारंपरिक चिकित्सा से अच्छी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं। इनमें अस्थमा, गठिया, माइग्रेन और त्वचा रोग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, होम्योपैथी को अक्सर निवारक देखभाल के लिए माना जाता है, चिकित्सकों का मानना है कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा दे सकती है और दीर्घकालिक इलाज को बढ़ावा दे सकती है। हालांकि, होम्योपैथी के बारे में कई गलत धारणाएं भ्रम पैदा करती हैं, और इसे एक व्यवहार्य उपचार विकल्प के रूप में विचार करने में बाधा डालती हैं। होम्योपैथी और इसके उपचार की क्षमता को बेहतर ढंग से समझने के लिए इन मिथकों को दूर करना आवश्यक है। एक प्रचलित मिथक यह है कि होम्योपैथी केवल एक प्लेसीबो के रूप में कार्य करती है। आलोचकों का तर्क है कि होम्योपैथिक उपचारों के प्रभाव शारीरिक की बजाय विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक हैं। इस गलत धारणा को दूर करने के लिए व्यक्तियों को शिक्षित करना और जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। लोगों को विश्वसनीय अध्ययन और व्यक्तिगत प्रशंसापत्रों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करना उन्हें होम्योपैथी के दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभावों की सराहना करने में मदद कर सकता है।

एक और गलत धारणा यह है कि होम्योपैथी परिणाम दिखाने में धीमी है जबकि होम्योपैथी एक सौम्य उपचार है, यह तीव्र स्थितियों में तेजी से सुधार कर सकता है। हालांकि पुरानी स्थितियों में सुधार होने में अधिक समय लग सकता है, क्योंकि होम्योपैथी का उद्देश्य केवल लक्षणों को नहीं, बल्कि मूल कारण को संबोधित करना है। एक आम गलत धारणा है कि होम्योपैथिक उपचार केवल चीनी की गोलियां हैं, और इस प्रकार कोई संभावित दुष्प्रभाव नहीं होने के कारण हानिरहित है। होम्योपैथी को आपातकालीन चिकित्सा हस्तक्षेपों की जगह नहीं लेनी चाहिए, लेकिन यह चिकित्सा पद्धति कई पुरानी और जटिल स्थितियों के लिए पारंपरिक उपचारों की पूरक है। कई लोग होम्योपैथी को हर्बल दवा के साथ भ्रमित करते हैं क्योंकि दोनों प्रणालियों का प्राकृतिक पहलू है। यह अपनी तैयारी प्रक्रिया और उपचार दर्शन में हर्बल दवा से काफी अलग है। होम्योपैथी के समग्र स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में लागत-प्रभावशीलता और पुरानी बीमारियों के प्रबंधन में कथित लाभ महत्त्वपूर्ण हैं। हालांकि, संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना, स्पष्ट संचार विकसित करना और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से साक्ष्य-आधारित जानकारी को प्राथमिकता देना महत्त्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण व्यक्तियों को होम्योपैथी के संभावित लाभों को स्वीकार करते हुए आवश्यक होने पर साक्ष्य-आधारित चिकित्सा उपचारों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करता है। होम्योपैथी के लाभों को अधिकतम करने के लिए, इसे स्वस्थ जीवन शैली के साथ उपयोग करें। ■

...पूरी दुनिया मांगेंगे

के. विक्रम राव

कुर्बान जाऊं इन सर्वज्ञ टीवी एंकरों और उनके मेधावी प्रसारकों की कुशाग्रता पर! 12 सितम्बर, 2024 की संध्या बुलेटिन में घंटे भर तक कांग्रेस के स्वर्गीय अध्यक्ष और सोनिया के हरीफ सीताराम केसरी बक्सर वाले को इन महारथियों ने मार डाला। पहली बार केसरी का निधन 24 अक्टूबर, 2000 को हुआ था। तब वे सांसद थे और पार्टी मुखिया देवेगौड़ा को हटाकर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश में रहे। यह भयंकर भूल-सुधार देर से हुआ। तब तक फूहड़ मजाक फैल चुका था। जैसे द्रोणपुत्र अश्वत्थामा नहीं, वरन कोई अन्य मरा था। बाद में पता चला नामाराशी हाथी था।

कामरेड येचूरी सीताराम हमारे संगोत्रीय नियोगी विप्र थे। हम तेलुगुभाषी अपनी वंशानुगत नाम को पहले जोड़ते हैं। आम कम्युनिस्ट शिक्षा पर बहुत जोर देते हैं। हर माता-पिता सीताराम जैसा ही ऊंचा पढ़ा-लिखा बेटा चाहेगा। सीताराम भारत के राजनेताओं में बहुत कम उच्च कोटि की शिक्षा पाए लोगों में थे। सीताराम जी को मैंने उनके जेएनयू के छात्रों के हुजूम का नेतृत्व करते पहली बार (जून, 1976) में तीस हजारी कोर्ट्स के सामने देखा था। हम वहां तिहाड़ जेल से बड़ौदा डाइनामाइट केस के मुलजिम बनाकर लाए गए थे। वे सब नारा लगा रहे थे : 'जेल के फाटक टूटेंगे। हमारे साथ ही छूटेंगे।' तब जॉर्ज फर्नांडिस, मैं (अभियुक्त नंबर 2), प्रभुदास पटवारी (बाद में राज्यपाल, तमिलनाडु) तथा वीरेन शाह (पश्चिम बंगाल के राज्यपाल) तथा 19 अन्य मीसा कानून के तहत कैद लोग थे। सबको आजीवन कारावास या फांसी मिलती यदि इंदिरा गांधी दुबारा प्रधानमंत्री बनतीं।

येचूरी कांग्रेस के डार्लिंग थे। निजी संस्कारों से बुर्जवा। सरदार हरकिशन सिंह सुरजीत के लाड़ले रहे थे। तभी से सोनिया (कांग्रेस) से याराना रहा। अमूमन चुनावी हार के बाद पार्टी मुखिया पद तज देता है। मगर ऐसा करना नैतिकता होगी, जो क्रांतिकारी धर्मिता नहीं होती है। कमजोरी होती है। यहां नई पीढ़ी को बता दूं कि भारतीय राजनीति के दलदल में माकपा एकमात्र ऐसी पार्टी थी जो निख़ालिस सैद्धान्तिक थी। उसके पुरोधा गांधीवादी सादगी की मिसाल थे। इनमें एक आज भी बचे हुए हैं, सौ साल के वीएस अछूतानंदन।

सीताराम की सियासत समझ के परे थी। इंदिरा गांधी ने जेएनयू के कुलाधिपति से उन्हें हटवाया। मगर उनकी बहू सोनिया से बड़ी यारी थी। उनकी नजर में राजीव गांधी एक मूढ़, अपरिपक्व प्रधानमंत्री थे पर उनका निकट प्रतिद्वंद्वी मूर्खता में उनका पुत्र राहुल गांधी हैं, जिसके सीताराम सरपरस्त रहे। आपसी वैमनस्य का ही अंजाम था कि सीताराम येचूरी को वृंदा करात अर्थात इस श्रीमती प्रकाश करात ने ही राज्य सभा से बाहर ही रखा। हानि दोनों की निजी थी। पार्टी को ढेर सारी क्षति भी हुई। फिलहाल हम श्रमजीवी पत्रकारों का कामरेड सीताराम को लाल सलाम। कामरेड येचुरी के साथ हम पसीनाजीवी लोग कविता दुहराते हैः 'हम मेहनतकश जब इस दुनिया से अपना हिस्सा मांगेंगे। एक खेत नहीं एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे।' ■

राग रंग | आलोक पराड़कर

रंगकर्म का जज्बा और जुनून

रंगकर्म महंगे वातानुकूलित सभागारों में ही नहीं होते, आकर्षक मंच सज्जा, आधुनिक प्रकाश और ध्वनि व्यवस्था भी इसके लिए बहुत जरूरी नहीं है, बल्कि ये चीजें जुटा पाना अगर मुश्किल हुआ जा रहा हो जो प्रायः होता ही है, तो भी इनके प्रत्याख्यान में वैकल्पिक मंच तलाशा जा सकता है। नाटक के लिए अधिक जरूरी प्रभावपूर्ण नाट्यालेख, मेहनती रंगकर्मियों का दल, सधा हुआ निर्देशन और अभिनय है। प्रयागराज के कुछ रंगकर्मियों ने अगर एक पुराने घर के छोटे-से आंगन में नाटकों के मंचन की जगह बना ली है, ऐसे आंगन में जहां बमुश्किल 25-30 लोगों के बैठने की जगह, दान में मिले पंखे हैं, मंचन करते हुए रंगकर्मी पसीने से भीग जाते हैं, जुगाड़ से अपेक्षित प्रकाश व्यवस्था का प्रबंध किया जाता है, अधिक से अधिक दर्शकों को शामिल करने के लिए कई-कई प्रदर्शन किए जाते हैं तो निश्चय ही इनके जज्बे और जुनून को सराहने का मन करता है।

हिन्दी के कई रंगकर्मियों ने नाटकों के मंचन के लिए वैकल्पिक स्थलों की तलाश की है। अल्काजी से लेकर भानु भारती तक कई रंगकर्मी नाटकों को पुराने किलों, प्राचीन इमारतों तक लेकर गए हैं। लखनऊ में राज बिसारिया ने बोटैनिकल गार्डन का चुनाव किया था। कई बार सभागारों की एकरसता को तोड़ने के लिए ऐसा होता है, तो कुछ रंगकर्मी महंगे खर्चों और मंचन की अनुमति की जटिल प्रक्रियाओं से बचने के लिए ऐसा करते हैं। दिल्ली, लखनऊ, बनारस तक कई रंगकर्मियों ने नाटकों के लिए स्थायी वैकेल्पिक स्थान बना लिए हैं। कोरोना काल में जब सभागारों में प्रदर्शन बंद थे तो कई रंगकर्मियों ने कभी अपने घरों की छतों पर मंचन किए तो कभी किसी भवन के बड़े कमरों में। लेकिन प्रयागराज के अजीत बहादुर ने रंगकर्म की एक समानान्तर व्यवस्था बनाने की कोशिश की है, जो उन रंगकर्मियों की शरणस्थली है, जो नाटक करने के उत्साह और ललक से भरे हुए हैं, लेकिन इसके लिए जेबें फिलहाल खाली हैं, छोटे-मोटे काम करके अपना पालन-पोषण तो कर ही रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नाटक करना चाहते हैं, लेकिन नाटकों के लिए पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं। ऐसे उत्साही स्थानीय भी हो सकते हैं, और आसपास या दूरदराज नगरों के भी। अगर प्रयागराज आकर काम करना चाहते हैं, और ठहरने-खाने का प्रबंध नहीं है तो अजीत उनके लिए इसी घर में जगह भी मुहैया करा देते हैं। घर प्रयागराज के मुट्ठीगंज नामक पुराने इलाके में है, पुराने ढंग से बना है, छोटा-सा आंगन है, रोशनी और हवा की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है लेकिन जुनून ऐसा है कि नाटकों के मंचन के समय छोटे-से ब्लैक बॉक्स जैसा लगने लगता है। घर के छोटे से आंगन को ऊपर से ढक दिया गया है और पास के दो कमरों का इस्तेमाल ग्रीन रूम के रूप में हो जाता है। नाम दिया गया है स्टूडियो थिएटर। 1993 से लंबे समय तक पूर्वाभ्यास के लिए इसका उपयोग किया गया, बाद में इसमें नाटकों के मंचन भी शुरू हुए और अब तक 25 से अधिक नाटकों के मंचन हो चुके हैं जिनमें 'हमजमीन', 'अंधों का हाथी', 'मोहना', 'सफरनामा', 'लोवर डेफ्थ', 'सन 2025', 'दया शंकर की डायरी', 'एक चट्टान गिरती है खामोशी की नींद में', 'हड़प्पा हाउस', 'बहुत बड़ा सवाल' और 'नशा' जैसे नाटकों के मंचन शामिल हैं। कभी यहां फिल्मों और वृत्तचित्रों का प्रदर्शन भी कर लिया जाता है।

स्टूडियो थिएटर में नाटकों के मंचन के क्रम में नवीनतम प्रस्तुति 'नदी प्यासी थी' जिसे हरमेंद्र सरताज के निर्देशन में 7-8 सितम्बर को प्रस्तुत किया गया। धर्मवीर भारती लिखित इस नाटक की चार प्रस्तुति हुईं। सरताज युवा निर्देशक हैं, लेकिन उन्होंने सीमित संसाधनों में प्रस्तुति को प्रभावपूर्ण बनाने में सफलता पाई है। इसमें महत्त्वपूर्ण योगदान कलाकारों के अच्छे अभिनय का भी है। बाढ़ से घिरे गांव के इस अंधविश्वास कि नदी का पानी बली लेकर ही लौटता है, नाटक की पृष्ठभूमि में है, लेकिन इसमें मुख्य कथा मानव मन की द्वंद्वात्मकता, प्रेम त्रिकोण तथा जीवन जीने और इससे पलायन करने के विचारों की है। हर्षराज पाल, चाहत जायसवाल, अनुकूल सिंह, ऋितक श्रीवास्तव, हीर नृत्यकांत जैसे युवा कलाकारों की मेहनत बताती है कि संघर्ष किस प्रकार प्रतिभा को मांजती है। लखनऊ स्थित भारतेंदु नाट्य अकादमी से प्रशिक्षित अजीत कहते हैं कि इस जगह की खास बात यह है कि इसका उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से किया जा सकता है, दर्शकों के बैठने की जगह बदल जाती है। कलाकारों और दर्शकों के बीच महज दो फीट का फासला होता है जिससे छोटी से छोटी हरकत भी दर्शकों तक पहुंच जाती है। नाटक के मंचन के बाद दर्शकों से बातचीत भी होती है। अजीत इस यात्रा में शामिल अपने साथियों का जिक्र करना भी नहीं भूलते। वे बताते हैं कि राजकुमार रजक, रंगोली अग्रवाल, वीरभान जी, दीपक कुमार वृक्ष और सिद्धार्थ पाल के सहयोग ने इस प्रयास को बल दिया और उत्साह कभी कम नहीं पड़ने दिया। ■

कैनवस | जय त्रिपाठी

मोम सी सादृश्य दृष्टि

कला जैसी आज है वैसी ही हमेशा नहीं रही। कला निर्माण में नये-नये कलाकार और समूह कला जगत में बराबर आते रहे हैं। पूर्व में भी कला सदा एक सी ही नहीं रही। समकालीन कला में जो कलाकार या कला धारणाएं काम कर रही हैं वे नये-नये उपयोग से प्रयोग की सतह को आलोड़ित-विलोड़ित कर रही हैं। नई दिल्ली के बीकानेर हाऊस की मुख्य कला दीर्घा में एनकॉस्टिक माध्यम के रूप में अमूर्तन दृष्टिकोण से गढ़ी कृतियों की प्रदर्शनी प्रदर्शित है, वैसे तो यह दुनिया के सबसे प्राचीनतम कला रूपों में से एक है। जिसे जॉनी एम एल द्वारा क्यूरेट किया गया है। 'एनकॉस्टिक एनकाउंटरस' शीर्षक से प्रदर्शित एकल प्रदर्शनी में अपनी मूर्तन दृष्टि से अमूर्त को परिभाषित करती कलाकार बी जया लक्ष्मी कृतियों के माध्यम से अपेक्षाकृत प्रभावित करती हैं।

जया कलाकार के साथ साथ विज्ञान शिक्षाविद भी हैं। अतः वैज्ञानिक सोच और अपनी संवेदनशील भाव से एनकॉस्टिक तत्वों को सौंदर्यवादी संयोजन के रूप में देखती हैं। अपने कलात्मक अभ्यास और परिपक्व दृष्टिकोण से कृतियों में विशेष प्रभाव प्रदान करती कलाकार सौंदर्य को प्रतिबिंबित करने का प्रयास करती प्रतीत होती हैं। लक्ष्मी ने अपनी रचनात्मक दृष्टि से विज्ञान और कला, दोनों में सुंदर संतुलन देखा है। यह ग्लोबल वार्मिंग को जीवन के अंत की ओर अग्रसर जैसा देखती हैं। जया जीवनानुभव से कलाकार की तरह ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के तौर पर एन्कास्टिक कला 'मोम' को अपने माध्यम के रूप में उपयोग करती हैं और बताती हैं कि वह इस सामग्री का इस्तेमाल इसीलिए करती हैं क्यों कि यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और वर्षों तक उसी रूप में रखा जा सकता है। जिस तरह से गढ़ा गया है। यह बात इससे भी समझी जा सकती है कि पहली शताब्दी में रोमन चित्रों और पौराणिक कथाओं में पैनलों परएनकॉस्टिक पेंटिंग का इस्तेमाल किया गया था। रोमन खंडहरों में कई एनकॉस्टिक कार्य पाए गए हैं, जो प्रभावशाली स्थायित्व के सबूत प्रदान करते हैं।

यह रचनात्मक एनास्टिक आर्टिस्ट सृजनात्मकता से अपने को अभिव्यक्ति करती हैं, कुछ दशक पहले ही एक अमेरिकी कलाकार ने उनको इस माध्यम से अवगत था। जया ने जल्द ही अपनी कलात्मक क्षमता से स्वयं के भावों को मूर्त-अमूर्त रूप में गढ़ने लगीं। बी जया लक्ष्मी की कृतियों को देख कर समझ आता है कि वह आस-पास होने वाले जलवायु परिवर्तन के क्रियाकलाप को इस माध्यम में सरलता से साथ जोड़ पाती हैं, और अपने विचारों को विषयवस्तु के अनुरूप प्रदर्शित कर पाती हैं। कलाकार के कामों को देख कर लगता है कि वह एनास्टिक से प्रेरित कला में ही जीती हैं और कला से ही सारे जगत को परोक्ष या अपरोक्ष रूप में देखती हैं। इस कला प्रक्रिया में मधुमक्खी के मोम को रंगद्रव्य के साथ मिश्रित करके, मूल माध्यम के रूप में उपयोग करती हैं। आकृतियों को मूर्त अमूर्त रूप में बोर्ड, पेड़ों की छाल आदि की सतह पर ब्लो टॉर्च का उपयोग कर गढ़ती हैं। प्रतीकात्मक रूप से कहें तो मोम और डामर रेजिन के मिश्रण को एनकॉस्टिक माध्यम कहा जाता है जो एनकॉस्टिक का आधार है।

सृजनात्मकता की इसी कड़ी में कलात्मक दृष्टि से ही कलाकार की सृजनात्मकता के मूल तत्व (एनकॉस्टिक) को समझा जा सकता है। जहां वह अपनी रचनात्मक दृष्टि द्वारा कलाकृतियों में सक्षम प्रयोग करने का प्रयास करती हैं, जो एक सर्जक के रूप में उनकी स्वाभाविक क्षमता को भी दर्शाती है। इनकी कलाकृतियों में गतिशील वृत्ताकार बिंबों के रूप में भी आकार लेते हैं। कलाकार की रचना शैली की बात करें तो इसे हम मूर्त से अमूर्तन की यात्रा के तौर देख सकते हैं। इनकी अमूर्त कलाकृतियां अपने आप में एक आकृष्ट शक्ति से आवृत्त रहती हैं। कृतियों की प्रमुख विशेषता है कि एनकॉस्टिक माध्यम का पारदर्शी प्रयोग। पगमेंट के साथ रंगीन मोम-आधारित पेंट रूपाकार और रंगानुभूति से होते हुए अमूर्तन का वह रूप देती हैं, जहां उनकी मूर्त शैली रूपांकित होती है। रंगानुभूति दृष्टि की संवेदनशीलता का भी इनकी शैली में अनुभव किया जा सकता है। देश के प्रतिष्ठित कलाविद और कला इतिहासकार जॉनी एम एल के क्यूरेशन में 17 सितम्बर तक प्रदर्शित इस एकल प्रदर्शनी में कलाकार बी जया लक्ष्मी के विचार और 'एनकॉस्टिकोस' कलात्मकता एक दूसरे के संपूरक हैं। जहां हर एक कृति की गहराई सादृश्य के बहाने प्रेक्षक से बातें करती है। मूर्त अभिव्यक्तिवादी मोम रंग चित्रकार के मानवीय अनुभव को दर्शाते हैं। मोम पिगमेंटेड का संलयन,स्ट्रोक्स एक कलात्मक प्रतिबिंबित की तरह हमारी अंतरतम भावनाओं में गूंजता है। ■

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मोक्ष ग्रंथ है श्रीमद्भागवत महापुराणः मुख्यमंत्री

महंत दिग्विजयनाथ व महंत अवेद्यनाथ की पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा सत्य और जीवन के रहस्यों को समझाने वाली कथा है। यह सफलता के चरम उत्कर्ष और जीवन के परम सत्य तक पहुंचने की कथा है। हमारे जीवन की दैनिक, पारिवारिक, समाजिक और व्यावहारिक घटनाएं श्रीमद्भागवत कथा के इर्दगिर्द घूमती दिखाई देती हैं।

सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 55वीं एवं राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ महाराज की 10वीं पुण्यतिथि समारोह के उपलक्ष्य में शनिवार अपराह्न श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ के शुभारंभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। मंदिर के दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में व्यासपीठ का पूजन करने के बाद उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत महापुराण मोक्ष ग्रंथ है। मोक्ष का अर्थ केवल जीवन से मुक्ति तक सीमित नहीं है। मोक्षदायी भागवत कथा का अर्थ व्यक्ति जिस क्षेत्र में हो, उसमें पारंगत होने, उसके रहस्यों को जानने और सफलता के चरम पहुंचने की कथा से है।

सीएम योगी ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा और भगवान श्रीराम की लीला से जुड़ी कथाएं सनातन जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय हैं। सनातन धर्म के इन दो देवों (श्रीराम और श्रीकृष्ण) ने जनमानस को जितना प्रभावित किया है, उतना व्यापक दृष्टांत पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि ऐसे दौर में जब हर व्यक्ति व्यस्त है, उन स्थितियों में भी श्रद्धालुओं का सप्ताहभर घंटों कथा श्रवण से जुड़ने की परंपरा है। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा अपने अतीत व विरासत को झांकने अवसर भी प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाभारत के भीषण संघर्ष में हर प्रकार की व्यापक हानि उन्हीं वेद व्यास जी के सामने हुई जिनके आशीर्वाद से वंश परंपरा आगे बढ़ी। सोचा जा सकता है कि वेद व्यास जी के लिए महाभारत का समय कैसा रहा होगा। वेद व्यास ने मन:शांति के लिए श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना की। वेद व्यास द्वारा 5200 वर्ष पूर्व रचित श्रीमद्भागवत महापुराण निरंतर सनातन धर्मावलंबियों के जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हुए प्रेरणास्रोत बना हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विचारणीय है कि कितने मत, मजहब और सम्प्रदाय का इतिहास पांच हजार वर्ष पुराना होगा? पर, श्रीमद्भागवत कथा पांच हजार वर्ष पूर्व से मानवीय सभ्यता, आध्यात्मिक उन्नयन और भौतिक विकास के उत्कर्ष का रहस्योद्घाटन करती है।

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोक्ष अचानक नहीं प्राप्त हो सकता। इसके लिए धर्म का आचरण करते हुए नैतिक माध्यम से अर्थोपार्जन करना होगा। इस मार्ग पर चलकर कामनाओं की सिद्धि होने पर मोक्ष प्राप्ति में भी सफलता मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा मोक्ष प्राप्ति के इसी रहस्य को समझाती है। श्रीमद्भागवत महापुराण में लीला भगवान श्रीकृष्ण की है लेकिन शब्दावली वेद व्यास की है जो जीवन के रहस्यों का उद्घाटन, सनातन मूल्यों और उत्कर्ष से जुड़ी है। योगी ने कहा कि सनातन में यह अक्षुण्ण मान्यता है कि धर्म केवल उपासना विधि नहीं है। पूजा पद्धति, धर्म का एक हिस्सा हो सकता है लेकिन सम्पूर्ण धर्म नहीं हो सकती। इसीलिए सच्चा हिंदू किसी एक पूजा पद्धति पर लकीर का फकीर नहीं रहा है। सीएम ने कहा कि जिस धर्म (सनातन) में इतनी व्यापकता हो, जीवन के उतार-चढ़ाव को समभाव से वही देख सकता है। किसी भी उतार-चढ़ाव में सनातन की व्यापकता बनी रही है। मुख्यमंत्री के संबोधन के उपरांत श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा का रसपान व्यासपीठ पर विराजमान कथा व्यास, श्रीराम मंदिर गुरुधाम काशी से पधारे जगद्गुरु अनंतानंद द्वाराचार्य काशीपीठाधीश्वर स्वामी डॉ. रामकमल दास वेदांती जी ने कराया। कथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से शाम 6 बजे तक सुनाई जाएगी। इसका विराम 20 सितंबर को होगा।

वैदिक मंत्रोच्चार के बीच निकली शोभायात्रा

श्रीमद्भागवत महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ के शुभारंभ से पूर्व गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में मुख्य मंदिर से कथा स्थल तक बैंडबाजे, शंख ध्वनि की गूंज तथा वेदपाठी विद्यार्थियों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महापुराण की पोथी शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा के कथा स्थल पहुंचने पर गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने अखंड ज्योति स्थापित की। पोथी प्रतिष्ठा और कथा व्यास के विराजमान होने के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य यजमान ने व्यासपीठ की पूजा की।इस अवसर पर गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, दिगम्बर अखाड़ा अयोध्या के महंत सुरेश दास, काशी से आए महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, बड़े भक्तमाल अयोध्या के महंत अवधेश दास, सुदामा कुटी वृंदावन के महंत सुतीक्ष्ण दास, कालीबाड़ी के महंत रविंद्र दास, पंचानन पुरी, विधायक विपिन सिंह, महेंद्रपाल सिंह, पूर्व महापौर सीताराम जायसवाल समेत यजमान और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

देश को जोड़ने की व्यावहारिक भाषा है हिंदीः सीएम योगी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी लोगों को राजभाषा हिंदी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हिंदी देश को जोड़ने की एक व्यावहारिक भाषा है। इसका मूल देववाणी संस्कृत है। मुख्यमंत्री ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के 'निज भाषा उन्नति' वाले उद्धरण का उल्लेख करते हुए कहा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का भाषा के प्रति यह भाव आज भी आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि यदि भाव और भाषा खुद की नहीं होगी तो हर स्तर पर प्रगति बाधित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में देश-दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, वह अभिनंदनीय है।

समसामयिक विषयों पर सम्मेलन आज राज्यसभा के उपसभापति होंगे मुख्य अतिथि

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ गोरखपुर

गोरक्षपीठ के मूर्धन्य पीठाधीश्वरद्वय युगपुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज की 55वीं और राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ महाराज की 10वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में समसामयिक विषयों पर सम्मेलन की शुरुआत रविवार (15 सितंबर) को होगी। पहले दिन के सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण उपस्थित रहेंगे जबकि अध्यक्षता मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ करेंगे।

यह आयोजन गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में सुबह 10.30 बजे से होगा। पहले दिन 'लोकतंत्र की जननी है भारत' विषयक सम्मेलन में मुख्यमंत्री, राज्यसभा के उपसभापति के अलावा स्थानीय वक्ता प्रो. सदानन्द गुप्त पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, लखनऊ होंगे। सम्मेलनों का क्रम 19 सितंबर तक जारी रहेगा।

भाजपा के तमाम नेता बड़े भूमाफिया के रूप में कर रहे कार्यः अखिलेश यादव

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जबसे बीजेपी की सरकार आई है, भाजपा के तमाम नेता, पदाधिकारी प्रदेश में सबसे बड़े भूमाफिया के रूप में काम कर रहे है। इन लोगों ने केवल जमीनें ही नहीं, कई जगह तालाबों पर कब्जा कर लिए हैं। लखनऊ में ही कई तालाब समाप्त हो गए हैं, प्लाटिंग हो रही है।

अखिलेश यादव ने शनिवार को प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि अयोध्या की पावन धरती पर जमीनों की खरीद-फरोख्त में भारी भ्रष्टाचार और लूट हुई है। तो कल्पना कीजिए प्रदेश के अन्य जिलों में क्या हाल होगा। वाराणसी में हुई हत्या का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। पूरे उत्तर प्रदेश के आंकड़े देखें, और एनसीआरबी के आंकड़ों को निकाला जाय तो पता चलेगा की हत्या, लूट, महिलाओं से जुड़े अपराध की सबसे ज्यादा घटनाएं यूपी में हो रही है। ऐसा इसलिए देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुलिस विभाग साजिश और षडयंत्र करने में लगा है। अगर पुलिस कोई फर्जी एनकाउण्टर करती है तो उसके तार जोड़ने के लिए घंटों साथ बैठती है। सुल्तानपुर मामले में 3:30 बजे फर्जी एनकाउण्टर हुआ। 5 बजे प्रेसनोट आ गया। फिर तार मिलाया कि बैग कहां से आया, मोटर साइकिल कहां से आयी और नए कपड़े कैसे मिले। मंगेश यादव का पूरा परिवार यहां आकर मुझसे मिला। परिवार के सदस्यों ने बताया कि पुलिस 2 सितम्बर रात 2 बजे उठाकर ले गयी और 5 सितम्बर 2024 को हत्या कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में जितने भी फर्जी एनकाउण्टर हुए हैं, सबको लेकर समाजवादी पार्टी ने समय-समय पर आवाज उठाने का काम किया है।

प्रदेश में बढ़ता जा रहा है गलाघोंटू बीमारी का प्रकोपः अनिल यादव

- कांग्रेस का आरोप, आजमगढ़ संभल व उन्नाव में अब तक हो चुकी 10 बच्चों की मौत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, प्रभारी संगठन अनिल यादव ने कहा है कि प्रदेश में गलाघोंटू बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अभी तक प्रदेश के तीन जिलों आजमगढ़, संभल और उन्नाव में उक्त बीमारी के लक्षण देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस बात को दावे से इसलिए कह रहा हूं कि मैं स्वय भी जनपद आज़मगढ़ से आता हूं, जब मैंने वहां जमीनी स्तर पर जाकर देखा तो मुझे पता चला कि स्थिति कितनी भयावह है।

अनिय यादव शनिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त 2024 को जनपद आज़मगढ़ के मिर्जापुर ब्लाक में गलाघोंटू बीमारी से एक बच्चे की मौत हुई तब से अब तक कुल 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। स्थानीय बच्चों की मौत को प्रशासन द्वारा यह कहकर छुपाया जा रहा कि बच्चों की मौत डिफ्थीरिया (गलाघोंटू) बीमारी के चलते नहीं बल्कि अन्य कारणों से हुई है। अभी तक दो बच्चों को ही डिफ्थीरिया बीमारी से मरने का प्रमाण पत्र मिला है। जिला अस्पलाल के द्वारा डिफ्थीरिया पीड़ित बच्चों को रेफर कर दिया जा रहा है। अभी कल रात ही एक बच्चे को पीजीआई से बीएचयू रेफर किया गया पीड़ित परिजन 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे मुझे घटना की जानकारी हुई तब मैंने सीएमओ को फोन किया तो उनका जवाब था कि एम्बुलेंस की जिम्मेदारी हमारी नहीं है यह व्यवस्था अब प्राईवेट सेक्टर को सौंप दी गई है। नतीजन उस बच्चे की भी मौत हो गई। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें सांसद राकेश राठौर एवं स्वयं मैंने जनपद आज़मगढ़ जाकर प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया तब बीमारी के भयावह स्थिति का पता चला। वहां के स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि मृतकों के परिजन नट समाज से आते हैं और इन्होंने अपने बच्चों का टीकाकरण नहीं कराया है जबकि परिजनों से बात चीत के दौरान पता चला कि बच्चों का टीकाकरण कराया गया है। यादव ने कहा कि बच्चों की मौत गलाघोंटू बीमारी से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने गला दबा कर की है। उन्होंने मीडिया के माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को घेरते हुए कहा कि यदि जिले के सीएमओ तथा ब्लाक के स्वास्थ्य कर्मियों पर कार्यवाही नही करते तो हम 10 पीड़ित परिवार के परिजनों को लाकर स्वास्थ्य मंत्री के घर पर बैठकर उनसे यह पूछेंगे अगर 10 बच्चों की मौत गलाघोंटू से नहीं हुई तो किस बीमारी से हुई है।

पर्यावरण संरक्षण के साथ ही अब अपनी आय बढ़ने पर भी काम कर रहीं ग्राम पंचायतें

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ/ वाराणसी

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत वाराणसी के गांवों को प्लास्टिक मुक्त किया जा रहा

डबल इंजन सरकार के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायतें पर्यावरण संरक्षण के साथ ही अब अपनी आय बढ़ने पर भी काम कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत वाराणसी के गांवों को प्लास्टिक मुक्त किया जा रहा है। इसके लिए वाराणसी के तीन विकासखंड में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट का संचालन जल्द शुरू होने वाला है। गॉव से एकत्र किये गए प्लास्टिक से प्लास्टिक पिलेट्स बनाया जाएगा, जिसे प्लास्टिक री-साइकिल करने वाली कंपनी को बेचा जायेगा। गांव से निकलने वाले प्लास्टिक से सड़कों के निर्माण की भी योजना है। पीडब्लूएमयू (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट) के जरिये कार्बन क्रेडिट से भी ग्राम पंचायत की आय होगी। ग्रामीण क्षेत्रों को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए थ्री आर मेथड पर कार्य किया जा रहा है। इसमें रिड्यूज, रीयूज, रिसाईकल मेथड को फॉलो कर पर्यावरण संरक्षण का काम हो रहा है। मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा इस्तेमाल करने वाले प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाएगा। इसके लिए गांव में सार्वजनिक स्थलों पर बोरे टांगे गए है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर 100 बोरे लगे हैं। ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है कि प्रयोग की गई प्लास्टिक को इस बोरे में ही डाला जाए। फिर इस प्लास्टिक को तीन विकासखंड पिंडरा ब्लाक के नोहिया, सेवापुरी ब्लाक के भीषमपुर और चिरईगांव के बर्थराकला गांव में लगे पीडब्लूएमयू में ले जाकर रिसाइकल करके प्लास्टिक पिलेट्स बनाया जायेगा। कानपुर की एक कंपनी से इसे उचित दामों पर खरीदने की बात चल रही है। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों से एमओयू भी किया गया है। इसे बेचने से ग्राम पंचायतों की आय भी बढ़ेगी। इसके अलावा चिरईगांव मे लगे पीडब्लूएमयू से निकले प्लास्टिक को पीडब्ल्यूडी, आरईएस और जिला पंचायत की सड़क बनाने के लिए बेचा जायेगा। इससे सड़कों की गुणवत्ता में भी सुधार आयेगा। एडीपीआरओ राकेश यादव ने बताया कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'ओन रिसोर्स रेवेन्यू मॉडल' पर काम हो रहा है। ग्राम पंचायत से कंपनी दो से तीन रुपये में प्लास्टिक पिलेट्स खरीदेगी। कार्बन क्रेडिट से भी ग्राम पंचायतों को आमदनी होगी। एक ब्लॉक से लगभग एक टन हर महीने प्लास्टिक निकलने की संभावना है, जिसे कंपनी रीसाइकल करेगी। एक यूनिट से स्वयं सहायता समूह की लगभग पांच से 10 महिलाओं और मशीन संचालन के लिए अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा।

प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों का वैश्विक महाकुंभ बनेगा यूपीआईटीएस-2024

- पारंपरिक उत्पादों को मिलेगा बड़ा प्लेटफॉर्म, नए निर्यातक, महिला उद्यमी और हस्तशिल्पी भी हैं उत्साहित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

25 से 29 सितंबर के बीच आयोजित होने जा रहा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो- 2024 (यूपीआईटीएस- 2024) प्रदेश के पारंपरिक उद्यमियों के लिए 'वैश्विक महाकुंभ' साबित होगा। इस क्रम में, वाराणसी, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, झांसी मंडलों के 270 से अधिक स्थानीय व पारंपरिक उत्पादों के उद्यमियों ने विभिन्न केटेगरीज के अंतर्गत अब तक रजिस्ट्रेशन करा लिया है। आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया में और तेजी आएगी।

रजिस्ट्रेशन कराने वाले उद्यमी हथकरघा, टेराकोटा, हस्तशिल्प, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई, ओडीओपी समेत विभिन्न श्रेणियों के उद्यमों का संचालन कर रहे हैं, जो इस भव्य आयोजन में हिस्सा लेंगे। वहीं, नए निर्यातक, हस्तशिल्पी व महिला उद्यमी भी आयोजन में सहभागिता को लेकर बेहद उत्साहित और आशान्वित हैं। उनका एक स्वर में कहना है कि सीएम योगी की नीतियां न केवल प्रदेश की परंपरा को संरक्षित कर रही है, बल्कि हमारे उत्पादों के लिए वैश्विक बाजार तक पहुंच को भी सुलभ बना रही है। उनके अनुसार, इससे हमारे उत्पादों की पहुंच दुनिया के विभिन्न देशों तक हुई है। इससे हमारी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। वाराणसी मंडल के 44 हस्तशिल्पी, नए निर्यातक और महिला उद्यमी इंटरनेशनल ट्रेड शो में जाने के लिए पंजीकरण करा चुके है। उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त उमेश सिंह ने बताया कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में वाराणसी मंडल के 4 जिलों वाराणसी ,चंदौली जौनपुर और गाज़ीपुर के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के 20 उद्यमी हिस्सा लेंगे। वहीं, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम (जिसमे लकड़ी के खिलौने, गुलाबी मीनाकारी, दरी, बेवरेज, मेडिकल प्रोडक्ट्स बायो फ़र्टिलाइज़र,मसाला नूडल्स व बनारसी सिल्क उद्योग आदि शामिल है) से जुड़े 16 उद्यमी भी प्रतिभाग करेंगे। बनारसी सिल्क साड़ी तथा कालीन उद्योग से जुड़े 8 नए निर्यातक समेत कुल 44 उद्यमी आयोजन में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि ब्रज क्षेत्र के पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट और आधुनिक उत्पादों को आयोजन के माध्यम से बड़ा मंच उपलब्ध कराया जाएगा।

भ्रष्टाचार में बिजली विभाग के दो अभियंता निलंबित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भ्रष्टाचार मामले में पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने मेरठ के अधीक्षण अभियंता और आजमगढ़ के मुख्य अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। अधीक्षण अभियंता पर ठेकेदारों से रिश्वत लेने की शिकायत हुई थी जबकि मुख्य अभिंयता पर मानकों के अनुरूप उपकरण उपलब्ध नहीं कराने के मामले में दोषी पाया गया था। यूपी सरकार को मेरठ में तैनात अधीक्षण अभियंता वेद प्रकाश कौशल के खिलाफ शिकायत मिली थी। उन पर आरोप लगाए गए हैं कि उपकेंद्रों की मरम्मत, पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए 41 करोड़ के टेंडर जारी करने के लिए ठेकेदारों से छह फीसदी करीब 2.5 करोड़ रुपये की रिश्वत ली गई। इसके अलावा वेद प्रकाश कौशल के खिलाफ भ्रष्टाचार की विभिन्न शिकायतें भी मिली। अधीक्षण अभियंता वेद प्रकाश कौशल वाराणसी से तबादला होकर मेरठ आए थे। मेरठ में सिविल दफ्तर में पहले भी अफसरों और कर्मचारियों पर आरोप लगते रहे हैं। पिछले दिनों अधिशासी अभियंता के तबादले के बाद पीवीवीएनएल में रार हो गई थी। अधिशासी अभियंता ने अधीक्षण अभियंता, निदेशक पीवीवीएनएल और एमडी पर आरोप लगाते हुए शासन से शिकायत की थी। इसके बाद मामला तूल पकड़ा। निलंबित अधीक्षण अभियंता वाराणसी में अपने कार्यकाल के दौरान विभिन्न आरोपों से घिरे रहे। बताया जा रहा है कि विजिलेंस जांच भी इनके खिलाफ चल रही है। इसी तरह भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे आजमगढ़ क्षेत्र के मुख्य अभियंता राघवेंद्र भी नहीं बच सके।

वैश्विक स्तर पर पर्यटन हब के रूप में उभरा यूपीः जयवीर

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में फिर नया कीर्तिमान रचने के लिए तैयार है। मौजूदा वर्ष के बीते छह माह में लगभग 33 करोड़ पर्यटकों ने यहां का रुख किया। अयोध्या ने काशी को भी पीछे छोड़ दिया। यहां छह माह में लगभग 11 करोड़ लोग पहुंचे।

वर्ष 2022 में प्रदेश में जितने पर्यटक आए थे, उससे एक करोड़ से भी अधिक इस वर्ष शुरुआती छह माह में पहुंचे। इसी तरह, वर्ष 2023 के शुरुआती छह माह में आए पर्यटकों की संख्या से 13 करोड़ से भी अधिक है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में हाल के वर्षों में पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ा है। इस वर्ष अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद पर्यटकों का आगमन तेजी से बढ़ा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि छह माह में कुल 32 करोड़ 98 लाख 18 हजार 122 पर्यटक यूपी में भ्रमण के लिए आए, जबकि वर्ष 2022 में पूरे एक वर्ष में लगभग 31 करोड़ 86 लाख पर्यटक आए थे। इसी तरह बीते वर्ष के शुरुआत छह माह में 19 करोड़ 60 लाख 34 हजार 967 पर्यटक आए थे। यानी बीते वर्ष की तुलना में इस साल 13 करोड़ 37 लाख 83 हजार 155 पर्यटक अधिक आए थे। इस वर्ष उत्तर प्रदेश आने वाले कुल पर्यटकों में 32 करोड़ 87 लाख 81 हजार 348 घरेलू, जबकि 10 लाख 36 हजार 774 विदेश से आए पर्यटक हैं। जयवीर सिंह ने बताया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक अयोध्या पहुंचे हैं। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि, उत्तर प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यहां निरंतर पर्यटन स्थलों और पर्यटक सुविधाओं का विकास किया जा रहा है।

चकबंदी कार्यों में प्रदेश सरकार ने स्थापित किया 10 वर्षों का नया कीर्तिमान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

- वर्ष 2024-25 में प्रदेश के 82 ग्रामों में चकबंदी की प्रक्रिया हुई पूरी

प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष सितंबर माह में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान चकबंदी विभाग को किसानों के खेत की सीमा संबंधी विवादों को सुलझाने, गांवों को विकास से जोड़ने, सरकारी योजनाओं का लाभ देने एवं सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए निर्देश दिये थे। साथ ही, गांवों में ग्राम अदालत लगाकर वादों के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिये थे। सीएम योगी की मॉनीटरिंग का ही नतीजा है कि योगी सरकार ने चकबंदी संबंधी कार्यों में पिछले एक वर्ष में 10 वर्षों का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आठ माह में प्रदेश के 40 जिलों के 82 ग्रामों में अब तक चकबंदी करायी जा चुकी है। वहीं पिछले वर्ष 2023-24 में प्रदेश के 74 जिलों के 781 गांवों में चकबंदी करायी गयी। इसके अलावा पिछले साल सितंबर से अब तक 705 ग्राम अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 25,523 वादों का निस्तारण किया जा चुका है।

चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नदाताओं के खेत संबंधी विवादों को पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण तरीके से निपटाने के लिए चकबंदी कराने के निर्देश दिये थे। उन्होंने इसके निस्तारण के लिए अभियान और ग्राम अदालत लगाने के निर्देश दिये थे। इसी क्रम में इस वित्तीय वर्ष में आठ माह में 40 जिलों के 82 ग्रामों में चकबंदी करायी जा चुकी है। वहीं 51 ग्रामों में चकबंदी प्रक्रिया संभव न होने के कारण अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत चकबंदी प्रक्रिया से अलग किया गया। इसी तरह वर्ष 2023-24 में 74 जिलों के 781 ग्रामों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी की गयी। इसमें 330 ग्राम 10 वर्षों से अधिक अवधि के थे। वर्ष 2022-23 में 463 ग्रामों एवं 2021-22 में 231 ग्रामों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी की गयी, जो पिछले 10 वर्षों की तुलना में एक कीर्तिमान है। कुल मिलाकर वर्ष 2021-2022, 2022-23 तथा 2023-24 में 1475 ग्रामों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी हुई है। वहीं, 50 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित 8 ग्राम, 30 वर्ष से 50 वर्ष तक लंबित 72 ग्राम और 10 वर्ष से 30 वर्ष तक लंबित 296 ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया पूरी की गयी। इसमें आजमगढ़ के ग्राम महुवा और गोमाडीह में क्रमशः 63 वर्ष और 56 वर्ष से लंबित, विचाराधीन चकबंदी प्रक्रिया पूरी की गयी। इसके अलावा गाजीपुर के ग्राम सवना व बरेजी चकबंदी प्रक्रिया 59 वर्षों एवं ग्राम बेलसड़ी की चकबंदी प्रक्रिया 55 वर्षों से विचाराधीन थी, जिसे पूरी किया गया। चकबंदी आयुक्त ने बताया कि लखीमपुर खीरी के ग्राम सुआबोझ, सुल्तानपुर के ग्राम मालापुर जगदीशपुर, जौनपुर के ढेमा गांव में क्रमश: 53, 54 और 52 वर्ष से चकबंदी प्रक्रियाधीन थी, जिसे पूरा किया गया। इसके अलावा सुल्तानपुर के ग्राम अन्दारापुर में 48 वर्षों, बरेली के ग्राम मोहनपुर में 41 वर्ष, बिजनौर के ग्राम छाचरी टीप में 35 वर्षों, बदायूं के ग्राम रहेड़िया में 33 वर्षों, मऊ के ग्राम अल्देमऊ में 31 वर्षों, बुलंदशहर के ग्राम याकूबपुर व मुस्तफाबाद डडुवा में 30 वर्षों से चकबंदी प्रक्रियाधीन थी, जिसे पूरी किया गया। इसके साथ ही कन्नौज में 1990 में अग्निकांड की वजह से 35 ग्रामों के अभिलेख जल गये थे, जिससे 34 वर्षों से चकबंदी प्रक्रिया बाधित हो रही थी। इसमें नये अभिलेखों को तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती थी। ऐसे में चकबंदी आयुक्त ने तत्कालीन अपर निदेशक चकबंदी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। साथ ही समिति की संस्तुति के बाद 35 ग्रामों में से 8 ग्रामों को पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में उनके अभिलेख सृजित किये गये। इनमें से दो गांव नन्दलालपुर व करनौली की चकबंदी प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इतना ही नहीं पिछले वर्ष चकबंदी प्रक्रिया में शामिल लखीमपुर खीरी के ग्राम रामपुर मकरन्द की चकबंदी प्रक्रिया एक वर्ष और रामपुर के ग्राम चक रफतपुर में मात्र आठ माह में चकबंदी पूरी की गयी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चकबंदी संबंधी पुराने लंबित वादों को निस्तारित करने के लिए ग्रामों में ग्राम अदालत लगाने के निर्देश दिये थे। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पिछले वर्ष सितंबर से अब तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में 705 ग्राम अदालत का आयोजन किया गया। इसके जरिये 25,523 वादों को निस्तारण किया जा चुका है। इसके अलावा किसानों के हित एवं पारदर्शिता के मद्देनजर एआई, ब्लॉक चैन, ड्रोन एवं रोवर सर्वेक्षण आधारित चकबंदी संचालित करने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के तहत आईआईटी रूड़की के साथ परीक्षण चल रहा है। इसके साथ ही जीआईएस बेस्ड सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप विकसित करने की भी कार्रवाई चल रही है। जल्द ही इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चकबंदी प्रक्रिया संचालित की जाएगी।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

देश में बढ़ती रैगिंग की घटनाएं क्यों नहीं रूकती ?

-नरेन्द्र भारती-

देश में बढती रैगिंग की घटनाएं क्यों नहीं रूकती यह एक यक्ष प्रश्न बनता जा रहा है' हिमाचल का बहुचर्चित अमन काचरु रैगिगं कांड के बाद भी विश्वविद्यालयों व कालेजों में रैगिगं का संक्रमण बढता जा रहा हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायलय ने रैगिंग पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लागू किया है मगर देश में रैगिग के बढते मामलों से यह कानून मजाक बनता जा रहा है। ताजा घटनाक्रम में हिमाचल के वाकनाघाट में एक निजी विश्वविद्यालय में प्रथम वर्ष के एक छात्र से रैगिंग का मामला प्रकाश में आया है रैगिंग के आरोपी तीन छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है व हॉस्टल व यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है'इससे पहले आईआईटी मंडी मे रैगिंग की घटना सामने आई थी' आईआईटी प्रबंधन ने आरोपी 10 छात्रों को छः महीने विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया था तथा 72छात्रों पर 15 से 25हजार रुपए तक का जुमार्ना लगाया गया था' यह मामला बीते 11 अगस्त 2023 को घटित हुआ था' आईआईटी मंडी मे घटित यह बहुत ही संगीन मामला है इस मामले पर प्रशासन को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए' देश में रैगिंग के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं' रैगिंग के कारण प्रताड़ित छात्र आत्महत्या तक कर रहे हैं पिछले दिनों एम्स बिलासपुर मे भी एक मामला हो चूका है वहाँ भी एक छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की थी मगर बच गई थी' यूजीसी के आकड़ों के मुताबिक 2020 में देश में रैगिंग के 219 मामले सामने आये थे' 2021 में रैगिंग के 511मामले हुए थे' 2019 में उतर प्रदेश के इटावा में सैफई मैडिकल विश्वविद्यालय में रैगिंग का मामला घटित हुआ था' जहां सीनियर छात्रों ने 150 छात्रों के सिर मुंडवा दिए थे'यह एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्र थे' ताकि अपराधियों को सजा मिल सके। रैगिंग के मामलों में वृद्धि खतरनाक साबित हो रही है। वर्ष 2018 में ऐसा ही एक मामला मध्यप्रदेश के भोपाल में घटित हुआ था जहां रैगिंग से तंग आकर बीफार्मा की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी, छात्रा के सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने चार लड़कियों व एक अध्यापिका को गिरफतार कर लिया था। रैगिग का यह कोई मामला पहीं हे इस से पहले कई जघन्य वारदातें हो चुकी है। इतनी वारदातें होने के बाद भी इन घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। रैगिग छात्रों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। रैगिग की इन वारदातों से छात्र खौफजदा होते जा रहे हैं। अगर यही हाल रहा तों छात्रों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा सकतें है क्योकि इन बारदातों से अभिभावक भी अपने बच्चों को असुरक्षित समझ रहे है। रैगिग का साधरण सा अर्थ एक दूसरे का परिचय जानना होता था मगर अब इसका स्वरुप बदलता जा रहा है। रैगिगं अब यातना बन गई है छात्रों को मानसिक रुप से प्रताडित किया जाता है, मारपीट की जाती है। आज तक पता नहीं कितने छात्र-छात्राएं रैगिग के कारण असमय मौत के मुह में जा चुंके है। उतरप्रदेश के इटावा में घटित इस घटना ने एक नई बहस को जन्म दिया था' देश के शिक्षण संस्थानों में प्रतिबन्ध के बाद भी यह मामले थमने का नाम नहीं ले रहे है। बीते हादसों से न तो प्रशासन ने सबक सीखा और न ही छात्रों ने सीख ली। यदि कडे कदम उठाए होते तो आज यह हादसा न होता। यह एक यक्ष प्रशन बनता जा रहा है। रैगिग की यह बीमारी विश्वविद्यालयों, कालेजों के बाद अब स्कूलों में भी अपने पांव पसार चुकी है यदि इस पर समय रहतें रोक न लगाई तो आने वाले समय में घातक परिणाम भुगतने पडेगें। दें श में समय समय पर ऐसे दुखद हादसे होते रहते है मगर यह रुकनें के बजाए निर्बाध रुप से बढतें ही जा रहे हैं। समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार मई में मुम्बई के ठाणें में रैगिग से तंग आकर एक छात्र ने ट्रेन के आगे कटकर आत्महत्या कर ली'दिल्ली के स्कूल आफ प्लानिगं एंड आर्किटैक्चर का एक होनहार छात्र रैगिगं के चलतें अपाहिज हो गया आरोप है कि प्रथम वर्ष के छात्र नवीन कुजुर को उसके सीनियर ने ऐसी यातनाएं दी कि वह चलने फिरने के काबिल नहीं रहा। आन्ध्रप्रदेश में एक कालेज में सीनियर छात्राओं ने जूनियर छात्रा की रैगिग ली उनकी यातना से उस छात्रा ने अपनी आवाज खो दी थी। एक अन्य घटना में छात्र को क्लास में लडकी कहा जाता था छात्रों की इस हरकत से तंग आकर उस छात्र ने खुद को आग लगा दी थी। मुम्बई में एक कालेज में सीनियर छात्राओं ने एक जूनियर छात्रा को मिर्ची खिलाई और उठक बैठक करवाई'कोलकाता में एक कालेज में सीनियर जूनियर को ड्रग्स लेने के लिए मजबूर करते है और पिटाई करते हैं उतर प्रदेश में सरकार ने रैगिग के खिलाफ अभियान छेडा है तथा रैगिग करने वाले छात्रों को पांच साल तक दाखिला न देने को कडा फैसला लिया है।

यूक्रेन संघर्ष : कारगर नहीं हुआ भारत का शांति प्रयास

-डॉ. मलय मिश्रा-

राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय राजधानियों और अमेरिका की अपनी लगातार यात्राओं में (वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के साथ) अपनी 10-सूत्री शांति योजना के लिए समर्थन और लड़ाई जारी रखने के लिए हथियारों की लगातार आपूर्ति की पैरवी की है जिसका बाइडेन प्रशासन ने पूरा समर्थन किया है। जैसे-जैसे रूस यूक्रेन के डोनेट्स्क क्षेत्र में पूर्वी शहर पोक्रोव्स्क पर कब्जा करने के करीब पहुंच रहा है, कुर्स्क में यूक्रेन द्वारा हासिल बढ़त का असर कम हो रहा है। रूस, यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में पूर्वी शहर पोक्रोव्स्क पर कब्जा करने के करीब पहुंचते हुए कुर्स्क में यूक्रेन द्वारा हासिल की गई बढ़त को चुनौती दे रहा है। वहां कुर्स्क सैनिकों ने कई रूसी गांवों पर कब्जा कर लिया है। स्थिति में लगातार बदलाव होते रहता है। रूस ने अभी एक रणनीतिक स्थान मेमरिक गांव पर कब्जा करने की घोषणा की है जो कीव के रसद केंद्र पोक्रोव्स्क की ओर जाता है और लगभग 20 किमी दूर है। यूक्रेनी सरकार ने पहले ही पोकवोर्स्क में स्थानीय आबादी को इलाका खाली करने के आदेश दे दिए हैं जो बता रहे हैं कि दो युद्धरत देशों के बीच शांति लगातार घट हो रही है। यह भी लगता है कि शांति स्थापना के नई दिल्ली के प्रयास काम नहीं आए हैं। हालांकि पीएम मोदी की हालिया यूक्रेन यात्रा के दौरान शांति प्रयासों से बहुत उम्मीद नहीं की गई थी। युद्ध एक महत्वपूर्ण दौर में पहुंच गया है और दोनों पक्षों की ओर से राहत के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। अगर पीएम की यह यात्रा उनकी पिछली मॉस्को यात्रा पर नाराजगी को शांत करने के लिए थी तो प्रधानमंत्री के मध्यस्थता के इशारे ने गुस्से को शांत करने कोशिश को कम नहीं किया बल्कि उनके यूक्रेनी मेजबान ने अपनी बाद की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इस संघर्ष के बारे में भारत के दृष्टिकोण में कई विसंगतियों की ओर इशारा करते हुए जो कहा है वह उनकी नाराजगी को बताता है। जुलाई में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के तुरंत बाद पोलैंड (21-22 अगस्त) और यूक्रेन (23 अगस्त) (यूक्रेन के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर) की पीएम मोदी की योजनाबद्ध यात्रा, रूस और यूक्रेन के बीच 30 महीने के संघर्ष में मध्यस्थता का भारत का सीधा प्रयास प्रतीत होता है। भारत ने शांति के लिए एकमात्र मार्ग के रूप में ह्यबातचीत और कूटनीतिह्ल का आह्वान करने में एक सुसंगत रुख अपनाया है और दोनों पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए बातचीत के द्विपक्षीय समाधान के प्रयास किए और दोनों राष्ट्रपतियों जेलेंस्की और पुतिन दोनों के साथ बैठकें कीं। इस सिलसिले में आखिरी बार क्रमशः जून में इटली में जी-7 बैठक और इस साल जुलाई में मास्को में द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के मौके पर बातचीत हुई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों में कारगर साबित हो रहा है आंगनबाड़ी केंद्र

इन आंगनबाड़ी केंद्रों से करणीसर गांव की विभिन्न गर्भवती महिलाएं लाभ उठा रही हैं. इस संबंध में 27 वर्षीय मंगला देवी बताती हैं कि उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है. पति दैनिक मजदूरी करते हैं. जिससे घर की आमदनी काफी कम है. उनके तीन बच्चे हैं जिन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना काफी कठिन था. लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र के कारण उनके बच्चों को समय पर यह सुविधाएं उपलब्ध हो गईं. जिससे वह कुपोषण मुक्त जीवन जीने में सफल हुए हैं. वहीं एक अन्य महिला 24 वर्षीय सुशीला कहती हैं कि गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक आंगनबाड़ी केंद्र से उन्हें काफी मदद मिली है.

-मंजूनाथ-
(लेखिका स्वतंत्र व्यंगकार हैं)

आजादी के बाद देश कई स्तर पर समस्याओं का सामना कर रहा था। जिसमें सबसे प्रमुख महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य था। यह समस्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक देखी जा रही थी। जहां बच्चों के लिए दवाइयां, समय पर उनका टीकाकरण के साथ साथ गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, उनका स्वास्थ्य और अच्छे खानपान की समस्या प्रमुख थी। इसकी कमी के कारण देश में शिशु और मातृ मृत्यु दर काफी बढ़ी हुई थी। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1975 में आंगनबाड़ी केंद्र की शुरूआत की गई। जिससे स्थिति में काफी परिवर्तन आया। इसके माध्यम से देश में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार आया और उनमें कुपोषण की समस्या काफी हद तक कम हो गई।

यह आंगनबाड़ी केंद्र भारत सरकार की आईसीडीएस योजना के तहत संचालित होती है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा समुदाय आधारित कार्यक्रम माना जाता है। जिसके माध्यम से लक्षित समुदाय के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार लाना है। इस योजना ने अब तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लाखों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कुपोषण से मुक्त बनाया है। यही कारण है कि केंद्र से लेकर सभी राज्यों की सरकारों ने न केवल इस योजना को प्रोत्साहित किया बल्कि समय समय पर अन्य कई योजनाओं को भी इससे जोड़ा गया। जिसमें पूरक पोषाहार योजना, स्कूल पूर्व शिक्षा योजना, पोषण एवं स्वास्थ्य परामर्श योजना, स्वास्थ्य जांच योजना और संदर्भ सेवा योजना के अतिरिक्त उड़ान योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) जैसी अनेकों योजनाओं को इससे जोड़कर इसे और भी अधिक सशक्त बनाया गया है। जिसका परिणाम यह है कि जमीनी स्तर पर आज इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इससे देश का ग्रामीण क्षेत्र सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है।

राजस्थान में भी आईसीडीएस योजना के तहत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों से शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को काफी लाभ मिल रहा है। राज्य का करणीसर गांव इसका एक उदाहरण है। बीकानेर जिला के लूणकरणसर ब्लॉक से करीब 40 किमी दूर इस गांव की आबादी करीब पांच हजार से अधिक है। इतनी बड़ी आबादी में दो आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किये जा रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 1 की कार्यकर्ता 27 वर्षीय गीता देवी और सहायिका सरस्वती देवी पिछले तीन सालों से यहां अपनी सेवाएं दे रही हैं। वह बताती हैं कि इस केंद्र पर सरकार की ओर से सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाती हैं। जिससे गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को काफी लाभ हो रहा है। उनका समय पर टीकाकरण किया जाता है। वह बताती हैं कि इस केंद्र पर 26 बच्चे नामांकित हैं। जिनमें अधिकतर नियमित रूप से इस केंद्र पर आते हैं। जिन्हें पौष्टिक भोजन के रूप में दलिया और खिचड़ी उपलब्ध कराया जाता है। जबकि गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत पोषण योजना का लाभ दिया जाता है। इसके साथ साथ इस केंद्र पर उड़ान योजना के तहत किशोरियों को मुफ्त में सेनेट्री पैड भी दिए जाते हैं। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 की कार्यकर्ता लाजो देवी बताती हैं कि पीएमएमवीवाई के तहत गर्भवती महिलाओं के बैंक अकाउंट में पहली डिलीवरी के समय पांच हजार रूपए और दूसरी डिलीवरी के समय छह हजार सरकार की ओर से दिए जाते हैं। यह एक गरीब परिवार के लिए बहुत अहम साबित होता है।

इन आंगनबाड़ी केंद्रों से करणीसर गांव की विभिन्न गर्भवती महिलाएं लाभ उठा रही हैं। इस संबंध में 27 वर्षीय मंगला देवी बताती हैं कि उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। पति दैनिक मजदूरी करते हैं। जिससे घर की आमदनी काफी कम है। उनके तीन बच्चे हैं जिन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना काफी कठिन था। लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र के कारण उनके बच्चों को समय पर यह सुविधाएं उपलब्ध हो गईं। जिससे वह कुपोषण मुक्त जीवन जीने में सफल हुए हैं। वहीं एक अन्य महिला 24 वर्षीय सुशीला कहती हैं कि गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक आंगनबाड़ी केंद्र से उन्हें काफी मदद मिली है। न केवल समय पर उनका टीकाकरण होता था बल्कि पीएमएमवीवाई के तहत उन्हें पांच हजार रूपए भी प्राप्त हुए, जिससे आर्थिक रूप से उन्हें काफी सहायता मिली है। वह कहती हैं कि इस प्रकार की योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं 17 वर्षीय किशोरी गुंजन कहती है कि उसके घर की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है। उसके पास प्रति माह सेन्ट्री पैड खरीदने के पैसे नहीं हैं। लेकिन उड़ान योजना के तहत आंगनबाड़ी केंद्र से उसे प्रति माह पैड्स उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र की सेविका प्रति माह उसे माहवारी के दौरान बरते जाने वाली सावधानियों और साफ सफाई के बारे में भी आगाह करती रहती है। वह बताती है कि केंद्र के माध्यम से हर बुधवार को किशोरियों के बीच आयरन और कैल्शियम की टेबलेट भी वितरित की जाती है।

हालांकि इन आंगनबाड़ी केंद्रों में कुछ समस्याएं भी हैं। इन केंद्रों पर बिजली और पानी की सुविधा की कमी देखी गई। केंद्र संख्या 1 की कार्यकर्ता गीता देवी कहती हैं कि अक्सर इस केंद्र पर बिजली नहीं रहती है। जिससे गर्मी के दिनों में बच्चों को काफी परेशानी होती है। वहीं पीने के साफ पानी की कमी भी इस केंद्र के लिए एक बड़ी समस्या रहती है। वह बताती हैं कि बच्चों का खाना बनाने के लिए आसपास के घरों से पीने का पानी मांग कर लाना पड़ता है। कई बार वहां भी उपलब्ध नहीं होने से इसकी व्यवस्था करवाना एक बड़ी समस्या हो जाती है। जबकि आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 2 में शौचालय की सुविधा की कमी है। केंद्र की कार्यकर्ता लाजो देवी कहती हैं कि शौचालय की व्यवस्था नहीं होने से न केवल केंद्र में आने वाले बच्चों बल्कि उनके लिए भी अक्सर असहज स्थिति उत्पन्न कर देती है। लेकिन इस प्रकार की कुछ कमियों के बावजूद इन दोनों ही केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं से करणीसर गांव के बच्चों और गर्भवती महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं।

वर्तमान में देश में करीब 13।63 लाख आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हैं। इनमें राजस्थान में 304 परियोजनान्तर्गत करीब 62, 020 आंगनबाड़ी केन्द्रों संचालित हो रहे हैं। जिसके माध्यम से बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और उन्हें कुपोषण मुक्त बनाया जा रहा है। इन आंगनबाड़ी केंद्रों का सफलतापूर्वक संचालन इन्हीं कार्यकताओं और सहायिकाओं के माध्यम से मुमकिन होता है। जो विषम परिस्थितियों में भी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में अपना विशेष योगदान दे रही हैं। वास्तव में, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए गए हैं करणीसर गांव में वह पूरा होता हुआ नजर आ रहा है।

बुढ़ापे का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बनाने की सराहनीय पहल

वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ निजी व राजकीय अस्पतालों में ले सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से बताया गया है कि जो सत्तर साल से अधिक के नागरिक प्राइवेट बीमा योजना या फिर राज्य कर्मचारी बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं, वे भी नई योजना का लाभ लेने के अधिकारी होंगे। लेकिन उन्हें इस योजना के लिये आवेदन करना होगा। सरकार ने फिलहाल इस योजना के लिये करीब साढ़े तीन हजार करोड़ का बजट रखा है और आवश्यकता पड़ने पर बजट बढ़ाने की बात कही है। सरकार ने बजट में स्वास्थ्य के लिए कोटा बढ़ाया है।

-ललित गर्ग-
लेखक स्वतंत्र पत्रकार

केंद्र सरकार ने अब सत्तर साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है, जो सुखद एवं स्वागतयोग्य कदम है। अपने देश के करीब साढ़े चार करोड़ परिवार के छह करोड़ बुजुर्ग इस योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज करा सकेंगे। दरअसल वर्ष 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना में अब तक केवल गरीब परिवार ही शामिल हो सकते थे, जिन्हें पांच लाख का कैशलेस कवर दिया जाता था। अब इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना का लाभ सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा। इस योजना से हम एक ऐसी दुनिया बना सकेंगे जहाँ हर बुजुर्ग अपने बुढ़ापे को गरिमा, आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्वस्थता के साथ जी सकेंगे। इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी जनकल्याणकारी सरकार को साधुवाद दिया जाना चाहिए। पारिवारिक एवं सामाजिक घोर उपेक्षा एवं उदासीनता के कारण बुढ़ापा अपने आप में एक रोग ही बनता गया है। जब आय के स्रोत सिमट जाते हैं और बच्चों से पर्याप्त मदद नहीं मिलती तो शरीर में रोग दस्तक देने लगते हैं, फिर महंगे इलाज की चिंता और बढ़ जाती है। संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने इस स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की नयी पहल का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हुआ तो यह फैसला इस आयुवर्ग के बुजुर्गों की सेहत को लेकर सुरक्षा कवच का काम करेगा। यह जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही थी क्योंकि आने वाले बीस वर्ष में भारत की बुजुर्ग आबादी तीन गुना होने की संभावना है। नये भारत-विकसित भारत की उन्नत एवं आदर्श संरचना बिना वृद्धों की सम्मानजनक स्थिति के संभव नहीं है। यदि परिवार के वृद्ध कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रुग्णावस्था में बिस्तर पर पड़े कराह रहे हैं, भरण-पोषण एवं उचित स्वास्थ्य-सेवाओं को तरस रहे हैं तो यह हमारे लिए वास्तव में लज्जा एवं शर्म का विषय है। वर्तमान युग की बड़ी विडम्बना एवं विसंगति है कि वृद्ध अपने ही घर की दहलीज पर सहमा-सहमा खड़ा है, वृद्धों की उपेक्षा स्वस्थ एवं सृसंस्कृत परिवार परम्परा पर तो काला दाग है ही, शासन-व्यवस्थाओं के लिये भी लज्जाजनक है। हम सुविधावादी एकांगी एवं संकीर्ण सोच की तंग गलियों में भटक रहे हैं तभी वृद्धों की आंखों में भविष्य को लेकर भय है, असुरक्षा और दहशत है, दिल में अन्तहीन दर्द है। इन त्रासद एवं डरावनी स्थितियों से वृद्धों को मुक्ति दिलाने एवं उनके स्वास्थ्य विषयक खर्चों एवं चिन्ताओं को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय लाभ देने का फैसला लिया है, वह सराहनीय एवं प्रासंगिक निर्णय है। इस फैसले की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत बहुत पीछे है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019-21 की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में ऐसे परिवारों की संख्या केवल 41 प्रतिशत है, जिनके कम से कम एक सदस्य का स्वास्थ्य बीमा हो। बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में तो यह राष्ट्रीय औसत के करीब आधे के बराबर है। स्वास्थ्य बीमा को लेकर यह उदासीन रवैया हमारी उस आदत की वजह से है, जिसमें ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि जब बीमारी आएगी तो देखा जाएगा। बहुत से लोग जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को एक ही चीज समझ लेते हैं। लेकिन, जब बीमारी सिर पर आती है, तो पूरे घर के बजट को तहस-नहस एवं असंतुलित कर देती है। सरकार का मौजूदा कदम कई परिवारों को ऐसे आर्थिक दुष्चक्र में फंसने से बचा सकता है।

श्राद्धकर्म : पितृऋण चुकाने का सहज एवं सरल मार्ग

श्रीमती प्राची जुवेकर

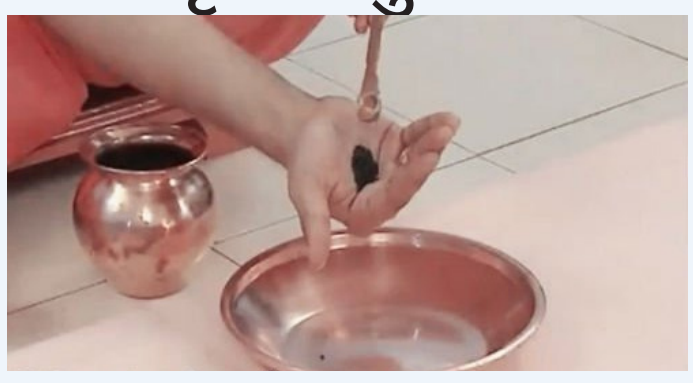

हिंदू धर्म में उल्लेखित ईश्वरप्राप्ति के मूलभूत सिद्धांतोंमेंसे एक सिद्धांत देवऋण, ऋषिऋण, पितृऋण एवं समाजऋण, इन चार ऋणों को चुकाना है । इनमें से पितृऋण चुकाने के लिए श्राद्ध करना आवश्यक है । माता-पिता तथा अन्य निकटवर्ती संबंधियोंकी मृत्योपरांत, उनकी आगेकी यात्रा सुखमय एवं क्लेशरहित हो तथा उन्हें सद्गति प्राप्त हो, इस उद्देश्यसे किया जानेवाला संस्कार है श्राद्ध । श्राद्धविधि करने से अतृप्त पितरों के कष्टसे मुक्ति होनेसे हमारा जीवन भी सुखमय होता है। वर्तमान वैज्ञानिक युगकी युवा पीढी के मनमें ऐसी संभ्रांति उभरती है कि, श्राद्ध अर्थात अशास्त्रीय एवं अवास्तव कर्मकांड का आडंबर । धर्मशिक्षा का अभाव, अध्यात्मके विषय में अनास्था, पश्चिमी संस्कृतिका प्रभाव, धर्मद्रोही संगठनोंद्वारा हिंदु धर्म की प्रथा-परंपराओंपर सतत द्वेषपूर्ण प्रहार इत्यादिका यह परिणाम है । श्राद्धांतर्गत मंत्रोच्चारण में पितरों को गति प्रदान करनेकी सूक्ष्म शक्ति समाई हुई है; इसलिए श्राद्धविधि द्वारा पितरों को मुक्ति मिलना संभव होता है ।

१. श्राद्ध मृत्यु-तिथि पर क्यों करना चाहिए ?

प्रत्येक कार्य का कोई-न-कोई कारण होता है । उसका प्रभाव कर्ता, समय, स्थल आदि पर निर्भर होता है । इन सभी का उचित मेल होने पर, कार्य की सफलता निच्छित होती है तथा कर्ता को विशेष लाभ होता है । जब कार्य ईश्वर की योजनानुसार होता है, तब वह इच्छा, क्रिया एवं ज्ञान, इन तीन शक्तियों की सहायता से सगुण रूप धारण कर, साकार होता है । प्रत्येक तिथि, उस दिन जन्मे व्यक्ति को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करनेवाली स्रोत होती है । अतः, विशिष्ट तिथि पर जन्मे विशिष्ट जीव के नाम से किया जानेवाला कर्म, उसे ऊर्जा प्रदान करता है । प्रत्येक कार्य विशिष्ट तिथि अथवा मुहूर्त पर करना विशेष लाभदायक है; क्योंकि उस दिन उन कर्मों का कालचक्र, उनका प्रत्यक्ष होना तथा उनका परिणाम, इन सभी के स्पंदन एक-दूसरे के लिए सहायक होते हैं । तिथि, उस विशिष्ट घटनाचक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक तरंगों को सक्रिय करती है ।

२. पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों करना चाहिए ?

पितृपक्ष में वायुमंडल में तिर्यक (रज-तमात्मक) तथा यम तरंगों की अधिकता होती है । इसलिए, पितृपक्ष में श्राद्ध करने से रज-तमात्मक कोषवाले पितरों के लिए पृथ्वी के वायुमंडल में आना सरल होता है । इससे ज्ञात होता है कि हिन्दू धर्म में बताए गए धार्मिक कृत्य विशिष्ट काल में करना अधिक कल्याणकारी है ।

२ अ. वार्षिक श्राद्ध करने के उपरांत भी पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों करना चाहिए ?

वार्षिक श्राद्ध किसी एक व्यक्ति की मृत्यु तिथि पर किया जाता है । इसलिए, ऐसे श्राद्ध से उस विशेष पितर को गति मिलती है और उसका ऋण चुकाने में सहायता होती है । यह हिन्दू धर्म में व्यक्तिगत स्तर पर ऋणमुक्ति की व्यष्टि उपासना है तथा पितृपक्ष में श्राद्ध कर सभी पितरों का ऋण चुकाना, समष्टि उपासना है । व्यष्टि ऋण चुकाने से उस विशेष पितर के प्रति कर्तव्यपालन होता है तथा समष्टि ऋण चुकाने से एक साथ सभी पितरों से लेन-देन पूरा होता है । जिनसे हमारा घनिष्ठ संबंध होता है, उन्हीं की एक-दो पीढियों के पितरों का हम श्राद्ध करते हैं; क्योंकि उन पीढियों से हमारा प्रत्यक्ष संबंध रहा होता है । ऐसे पितरों में, अन्य पीढियों की अपेक्षा पारिवारिक आसक्ति अधिक होती है । उन्हें इस आसक्ति-बंधन से मुक्त कराने के लिए वार्षिक श्राद्ध करना आवश्यक होता है । इनकी तुलना में उनके पहले के पितरों से हमारा उतना गहरा संबंध नहीं रहता । उनके लिए पितृपक्ष में सामूहिक श्राद्ध करना उचित है । इसलिए, वार्षिक श्राद्ध तथा पितृपक्ष का महालयश्राद्ध, दोनों करना आवश्यक है ।

२ आ. पति से पहले मरनेवाली पत्नी का श्राद्ध पितृपक्ष की नवमी (अविधवा नवमी) तिथि पर ही क्यों करना चाहिए ?

नवमी के दिन ब्रह्मांड में, रजोगुणी पृथ्वी-तत्त्व तथा आप-तत्त्व से संबंधित शिवतरंगों की अधिकता रहती है। ये शिव-तरंगें श्राद्ध में प्रक्षेपित होनेवाली मंत्र-तरंगों की सहायता से सुहागन की लिंगदेह को प्राप्त होती हैं । इस दिन शिवतरंगों का प्रवाह भूतत्त्व और आपतत्त्व से मिलकर संबंधित लिंगदेह को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने में सहायता करता है । इससे, सुहागिन के शरीर में पहले से स्थित स्थूल शक्तितत्त्व का संयोग सूक्ष्म शिवशक्ति के साथ सरलता से होता है और सुहागिन की लिंगदेह तुरंत ऊपरी लोकों की ओर प्रस्थान करती है ।

इस दिन शिवतरंगों की अधिकता के कारण सुहागिन को सूक्ष्म शिव-तत्त्व मिलता है । फलस्वरूप, उसके शरीर में स्थित सांसारिक आसक्ति के गहरे संस्कारों से युक्त बंधन टूटते हैं, जिससे उसे पति-बंधन से मुक्त होने में सहायता मिलती है । इसलिए, रजोगुणी शक्तिरूप की प्रतीक सुहागिन का श्राद्ध महालय (पितृपक्ष) में शिवतरंगों की अधिकता दशार्नेवाली नवमी तिथि पर करते हैं ।

३. श्राद्ध का महीना ज्ञात है, किंतु तिथि ज्ञात नहीं है, तब उस माह की शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी अथवा अमावस्या तिथि पर श्राद्ध क्यों करना चाहिए ?

इस दिन वायुमंडल में पितरों के लिए सहायक यमतरंगें अधिक होती हैं । अतः, इस दिन जब पितरों का मंत्र से आवाहन किया जाता है, तब मंत्र की शक्ति यमतरंगों के माध्यम से पितरों तक पहुंची है । इससे पितर अल्पकाल में आकर्षित होते हैं और यमतरंगों के प्रबल प्रवाह पर आरूढ होकर, पृथ्वी के वायुमंडल में सहजता से प्रवेश करते हैं ।

संदर्भ : सनातन का ग्रंथ भगवान दत्तात्रेय

https://t.me/AINewsPaperPdf

जो लोग अन्न को बर्बाद करते हैं, उनसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए आपको बहुत सख्ती से इस नियम का पालन करना चाहिए कि, कभी भी अन्न बर्बाद न हो। अगर पकाया हुआ खाना बचता है तो उसे पशु-पक्षियों को आप खिला सकते हैं, लेकिन गलती से भी अन्न को कूड़े में न फेंके। चाणक्य कहते हैं कि, जिन घरों में अन्न बर्बाद नहीं किया जाता वहां भी धन की आवाजाही हमेशा बनी रहती है।

चाणक्य

सन्मार्ग
पटना, रविवार, 15 सितंबर, 2024
www.live7tv.com

हिंसा हमारी संस्कृति नहीं, कानून हाथ में लेने पर किसी की स्वीकृति नहीं

श्यौराज सिंह बेचैन

शिक्षक दिवस के दिन जब कुछ छात्र बधाई देने आए, तो मेरी आंखों के सामने बारहवीं कक्षा के बीस वर्षीय छात्र आर्यन मिश्रा की तस्वीर कौंध गई। गत 23 अगस्त को गो-तस्कर समझकर उसकी हत्या कर दी गई थी। एसपी अनिल यादव की टीम ने हत्या के मामले में कृष्ण, आदेश, सौरव और अनिल को गिरफ्तार कर लिया। प्रश्न कौंधा, गो-निगरानी कताओं के दल को उसकी हत्या का अधिकार कहां से मिला। यह अनुदारता, क्रूरता और अराजकता कहां से आ रही है? यह कितने रूपों और कितने क्षेत्रों में भय और अशांति की वजह बन रही है। आए दिन अखबारों में प्रकाशित हो रही ऐसी क्रूरतापूर्ण अमानवीय घटनाओं की खबरें नजर अंदाज नहीं की जा सकतीं। अपराधियों का कहना कि हमें पता नहीं था कि आर्यन मिश्रा गो-तस्कर नहीं है। सवाल है कि यदि आर्यन मिश्रा गो-चोरी करके ले जा रहा होता, तब भी क्या किसी को उसकी हत्या का हक था? यदि कुछ गैर-कानूनी या गैर-सांस्कृतिक घटित होता दिख रहा था, तो वे पुलिस की मदद ले सकते थे। दंड देने का अधिकार तो पुलिस को भी नहीं है। पुलिस मुकदमा चलाकर उसे कोर्ट में तो पेश कर सकती है, परंतु उसे भी हत्या का अधिकार नहीं है। लिंग, जातिगत या सांप्रदायिक हिंसा कोई नई बात नहीं है। सोशल मीडिया के दौर में अब इन बातों की जानकारी तेजी से फैलती है। इन दिनों पश्चिम बंगाल में प्रशिक्षु डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना चर्चा के चरम पर है। हिंसक अनैतिक प्रवृत्ति का विस्तार शांति, प्रगति, सद्भाव और सामाजिक सौहार्द की भावना के लिए चिंताजनक है। दुखद है कि ऐसी घटनाओं का अंत नहीं दिखता। कानपुर की 24 वर्षीय बीबीए की छात्रा मॉडलिंग करती थी। पुलिस के अनुसार, इंस्टाग्राम पर विपिन नामक युवक से उसकी दोस्ती हुई। उसने भोजपुरी फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर विगत तीन सितंबर को एक होटल में एक अन्य विनय नामक युवक के साथ मॉडल के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। दो सितंबर को बागपत में आठवीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और नमाज पढ़वाने का मामला प्रकाश में आया। आरोपी रिजवान को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। मध्य प्रदेश के शहडोल में 31 अगस्त को एक दलित किशोर को निर्ममता से पीटा गया। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके इसे सार्वजनिक भी किया गया, जिससे पता चलता है कि अपराधियों को कानून की कोई परवाह नहीं है। नतीजा एससी/एसटी ऐक्ट के तहत पांच लोग कानून की गिरफ्त में हैं। सोशल मीडिया और जन जागरूकता के कारण ये घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। इनमें ज्यादातर घटनाएं दलितों व उनकी महिलाओं के उत्पीड़न की हैं, जिन्हें अपराधियों ने स्वयं इंटरनेट पर वीडियो अपलोड कर दशार्या है। ऐसे बहुत से मामले हैं, जिनकी रिपोर्ट थानों-कचहरियों में दर्ज नहीं होतीं या जिनकी खबरें प्रकाशित नहीं होतीं। दो सितंबर को खबर आई कि मसौली थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एसपी से शिकायत की कि उसकी भांजी को 22 अगस्त को गांव के ही युवक ने कार में खींच कर अपहरण कर लिया। बंधक बनाकर लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। कार्रवाई करने के बजाय पुलिसकर्मियों द्वारा उसे दस घंटे थाने में बिठाया गया। तीन सितंबर को बहराइच जिले में एक ग्रामीण किशोरी के प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने उसके शरीर के छह टुकड़े कर दिए। बेटी के सिर को हाथ में लिए वह घर के बाहर एक घंटे तक बैठा रहा। 16 जुलाई की एक खबर में खतौली (मुजफ्फरनगर) गांव मढ़करीमपुर में अनुसूचित जाति के युवक अमृत कुमार की घुड़चढ़ी के दौरान दो पक्षों में मारपीट के बाद पथराव में दो युवक घायल हो गए। पुलिस ने राजपूत समाज के आठ नामजद और आठ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 20 मई को मध्य प्रदेश के अशोक नगर जनपद में बुजुर्ग दंपती को खंभे से बांधकर पीटा और उन्हें जूतों की माला पहना दी। ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के अनेक हिस्सों में आए दिन होती रहती हैं। हिंसा व्यक्ति की गरिमा और आत्मसम्मान को क्षति पहुंचाती है। हिंसा और अनुदारता की प्रवृत्ति शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक पाई जा रही है। दुष्कर्म व हत्या जैसे मामले जब किन्हीं खास व्यक्तियों से ताल्लुक रखते हैं, तब ही काबिले-ऐतराज क्यों होते हैं? सामान्य लोगों के साथ तो यह सदियों से होता रहा है, तब क्यों नहीं नाराजगी दिखाई देती? ऐसी अमानवीय अनुदारता क्यों? हिंसा हमारी संस्कृति नहीं हो सकती।

योजना ढंग से लागू हो

सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है, जो कि एक अच्छा कदम कहा जाएगा। इस फैसले से देश के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिल सकेगा। साथ ही, इतनी ही कीमत का हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा। इस फैसले की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के मामले में भारत बहुत पीछे है। नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में ऐसे परिवारों की संख्या केवल 41% है, जिनके कम से कम एक सदस्य का हेल्थ इंश्योरेंस हो। बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में तो यह राष्ट्रीय औसत के करीब आधे के बराबर है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर यह उदासीन रवैया हमारी उस आदत की वजह से है, जिसमें ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि जब बीमारी आएगी तो देखा जाएगा। बहुत से लोग जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को एक ही चीज समझ लेते हैं। लेकिन, जब बीमारी सिर पर आती है, तो पूरे घर के बजट को तोड़कर रख देती है। सरकार का मौजूदा कदम कई परिवारों को ऐसे आर्थिक दुष्चक्र में फंसने से बचा सकता है। भारत में इलाज दिनों-दिन महंगा होता जा रहा है। ब्रोकरेज फर्म मर्सर एंड मास बेनिफिट के सर्वे के मुताबिक, भारत में 2023 में मेडिकल इन्फ्लेशन 9.6% थी, जो मौजूदा साल में 11% हो सकती है। कोरोना के दौर में पूरे एशिया में चिकित्सा पर महंगाई की सबसे ज्यादा मार हिंदुस्तान पर ही पड़ी थी। तब हमारे यहां मेडिकल इन्फ्लेशन 14% हो गई थी, चीन से भी ज्यादा। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) का डेटा बताता है कि भारत में जीवन प्रत्याशा 67.3 साल है। पिछले दो दशकों में ही जन्म के समय लाइफ एक्सपेटेंसी में पांच बरस से अधिक का इजाफा हो चुका है। निश्चित ही यह अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ यह चिंता भी जुड़ी हुई है कि देश में दिल से जुड़े रोगों और डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में नन कम्युनिकेबल से हर साल लगभग 58 लाख लोगों की मौत होती है। इनमें सबसे ज्यादा लोग मरते हैं हार्ट डिजीज और कैंसर से। सरकार ने बजट में स्वास्थ्य के लिए कोटा बढ़ाया है। हालांकि चीन और अमेरिका की तुलना में यह अब भी कम है। मेडिकल इंफ्रा बढ़ाने के साथ यह इंतजाम भी करना होगा कि आम जनता उसका फायदा उठा सके। सरकार का हालिया फैसला इसी दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि योजना को सही ढंग से लागू किया जाए।

श्रीलंका में चुनाव और दक्षिण एशियाई संतुलन, अमेरिका-चीन और भारत की नजर

महेंद्र वेद

श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ने वहां राजनीति को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि वर्ष 2022 की आर्थिक मंदी से कुछ हद तक उबरने के बाद श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी चल रही है। 21 सितंबर को होने वाले मतदान से एक व्यापक धारणा सामने आ सकती है कि कौन-सा विजेता किस देश को फायदा पहुंचा सकता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत, अमेरिका और चीन जैसे तीन बड़े खिलाड़ी सक्रिय हैं। श्रीलंका के 1.7 करोड़ योग्य मतदाताओं के सामने सवाल यह है कि क्या वे अपने पुराने नेतृत्व को चुनेंगे, जो मुख्य रूप से आर्थिक संकट के लिए जिम्मेदार था या बदलाव के लिए किसी नए नेता को चुनेंगे। चूंकि मैदान में 38 उम्मीदवार हैं, इसलिए आकलन करना कठिन हो गया है। श्रीलंका ने अप्रैल, 2022 में 83 अरब डॉलर के कर्ज के साथ दिवालिया होने की घोषणा की थी। उसके ऊपर आधे से ज्यादा कर्ज विदेशी कर्जदाताओं का था। श्रीलंका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से भी 2.9 अरब डॉलर की राहत की मांग कर रहा है। राहत पैकेज की शर्तों को लेकर भी चुनाव में चर्चा हो रही है। पिछले साल 2.3 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2024 में अर्थव्यवस्था के तीन प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। छह बार प्रधानमंत्री रह चुके मौजूदा राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे अपनी पार्टी यूनाइटेड नेशनल पार्टी (यूएनपी) में विभाजन के बाद निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उनके दो साल के शासन में देश की अर्थव्यवस्था में आंशिक सुधार हुआ है। चूंकि महंगाई और वस्तुओं की कमी बनी हुई है, इसलिए चुनाव को उनके शासन के जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन वह नुकसान में हैं, क्योंकि वह उन पुराने नेताओं से जुड़े रहे हैं, जिन्हें श्रीलंका के लोग आर्थिक पतन के लिए दोषी मानते हैं। उन्हें संसद में विपक्ष के नेता से कड़ी चुनौती मिल रही है। इसके अलावा, उन्हें एक शक्तिशाली गठबंधन वाले वामपंथी नेता से भी चुनौती मिल रही है, जो युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। उनके दो सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी समागी जन बालावेगया (एसजेबी) पार्टी के सजित प्रेमदासा और अनुरा कुमार दिसानायके हैं। नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) नामक मार्क्सवादी नेतृत्व वाले गठबंधन के नेता दिसानायके, विक्रमसिंघे के लिए प्रमुख चुनौती के रूप में तेजी से उभर रहे हैं। उन्हें 2022 के विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले कुछ लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। पूर्व वामपंथी दिसानायके अब आर्थिक स्वतंत्रता और मजदूर वर्गों के लिए कल्याणकारी उपायों का वादा करते हैं। राजनीतिक विश्लेषक उन्हें मजबूत दावेदार मानते हैं क्योंकि उनका संबंध उन व्यापारिक और राजनीतिक अभिजात वर्ग से नहीं है, जिन्होंने अतीत में देश को चलाया था। विक्रमसिंघे के उपराष्ट्रपति रहे सजित प्रेमदासा अब अलग हुए यूएनपी का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रेमदासा ने आईएमएफ कार्यक्रम को जारी रखने के साथ गरीब लोगों पर बोझ कम करने के लिए बदलाव का वादा किया है। उन्होंने तमिल समुदाय को सत्ता सौंपने का वादा करके लुभाने की कोशिश की है। देश की आबादी का लगभग 11 प्रतिशत हिस्सा तमिल अब भी एक विफल हिंसक आंदोलन से उबर रहा है। अतीत को भूलकर, युवा तमिलों ने 2022 के आंदोलन में भाग लिया था, जिसकी स्मृतियां अब भी ताजा हैं। युवाओं की भागीदारी वाले उस शांत आंदोलन ने गोटाबाया और शक्तिशाली राजपक्षे परिवार को सत्ता से बाहर कर दिया था, हालांकि गोटाबाया को बहुमत हासिल था। ताकतवर राजपक्षे परिवार ने पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व राष्ट्रपति महिंदा के बेटे नमन को मैदान में उतारा है। नमन आर्थिक संकट के लिए अपने परिवार को नहीं, बल्कि कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार ठहराते हैं। राजनीति में उनके प्रवेश से परिवार के प्रभाव का पता चलेगा, क्योंकि पिता महिंदा ने 2009 में तमिल सशस्त्र अलगाववादी आंदोलन को कुचल दिया था। चुनाव का नतीजा 22 सितंबर की शाम तक आ सकता है। मतदाता अपनी पसंद के तीन उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले पहली वरीयता की गणना की जाएगी और 50 प्रतिशत से अधिक वैध मत पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। यदि कोई स्पष्ट विजेता नहीं हुआ, तो पहले दो उम्मीदवारों को दौड़ में बनाए रखा जाएगा, और पहले नंबर के लिए अन्य उम्मीदवारों को चुनने वाले मतपत्रों की जांच की जाएगी कि शीर्ष दो दावेदारों में से कोई दूसरी या तीसरी पसंद है या नहीं। उन वोटों को शेष दो उम्मीदवारों की संख्या में जोड़ा जाएगा। सबसे ज्यादा वोट पाने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाएगा। अब उस बड़ी तस्वीर को देखें, जो क्षेत्रीय खिलाड़ियों की भूमिका को दर्शाती है, जैसा कि नेपाल और मालदीव में भी होता है। द डिप्लोमैट में लिखते हुए, रथिंद्र कुविता ने कहा कि कोलंबो में वामपंथी दल या राजनेता के सत्ता में होने पर चीन-श्रीलंका के संबंध मजबूत हुए हैं। उनका कहना है कि श्रीलंका के राजनीतिक हलकों को अच्छी तरह पता है कि भारत भले ही सजित प्रेमदासा को प्राथमिकता दे, लेकिन अमेरिका विक्रमसिंघे को ही अपना उम्मीदवार बनाए रखना चाहेगा। हालांकि इस पर अनिश्चितता बनी हुई है कि चीन किसे प्राथमिकता देगा और क्या वह इनमें से किसी को वित्तीय मदद दे रहा है। दिसानायके की एनपीपी की जड़ें मध्यमार्गी वामपंथी (सेंटर-लेफ्ट) राजनीतिक परंपरा में निहित हैं। जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) एनपीपी में प्रमुख ताकत है, जो 1960 के दशक में श्रीलंका कम्युनिस्ट पार्टी की चीन समर्थक शाखा से उभरी थी। दूसरी ओर, सजित प्रेमदासा यूएनपी के परिष्कृत संस्करण का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि उनकी एसजेबी एक अलग गुट है।

क्या देश ने सुनी झोली में भरे पदकों की खनक

नरेश कौशल

पेरिस पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने कामयाबी की नई इबारत लिखते हुए सात सोने के तमगों समेत 29 पदक हासिल किये। पदकों की यह नफरी पिछले टोक्यो पैरालंपिक में मिले पदकों से दस पदक ज्यादा रही। साल 2016 से पैरालंपिक में भाग लेना शुरू करने वाले भारत की यह कामयाबी अभूतपूर्व है। इस साल के पेरिस ओलंपिक में जहां हमारे खिलाड़ी एक अदद सोने के तमगे के लिये तरसते रहे, वहीं पैरा खिलाड़ियों ने सात चमचमाते सोने के तमगे भारत की झोली में डाल दिए। इसके अलावा नौ चांदी के व 13 कांस्य पदक भी इस कामयाबी में इसमें शामिल हैं। इस काबिले तारीफ प्रदर्शन के बूते भारत पेरिस पैरालंपिक में पूरी दुनिया में 18वें स्थान पर रहा। जबकि पेरिस ओलंपिक में हमें एक रजत व पांच कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 71 वें स्थान पर रहना पड़ा था। जबकि हमारा चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान सिर्फ एक स्वर्ण तमगे के बूते 62वें स्थान पर जा पहुंचा था। लेकिन इन आंकड़ों के बावजूद पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन करके भारत लौटे खिलाड़ियों के प्रति हमने जैसा ठंडा व्यवहार किया, वो कहीं न कहीं पैरा खिलाड़ियों के मनोबल को कम करने वाला ही कहा जाएगा। भारत जैसे देश में, जहां आम खिलाड़ियों के लिये भी ठीक-ठाक खेल सुविधाएं छोटे शहरों व ग्रामीण इलाकों में नहीं हैं, तो दिव्यांग खिलाड़ियों की जरूरत के हिसाब से तो ऐसी पर्याप्त सुविधाएं होना दूर की कौड़ी ही कही जाएगी। स्टेडियमों में व्हील चेयर वाले खिलाड़ियों के लिये रैंप तक जाने की व्यवस्था कम ही होती है। उनके लिये शौचालयों व अन्य सुविधाओं का अभाव होता है। वैसे भी उनका निजी जीवन का संघर्ष काफी बड़ा होता है। परिवारों में भी उन्हें भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। समाज उनके प्रति संवेदनशील व्यवहार नहीं करता है। उन्हें या तो दोयम नजरिये से देखता है या दया का पात्र मान लेता है। पैरालंपिक में गए खिलाड़ियों के दल में तमाम कहानियां ऐसी हैं, जो हैरत में डालती हैं कि उनका संघर्ष कितना बड़ा था। कोई गंभीर दुर्घटना से दिव्यांग बना तो कोई असाध्य बीमारी से शारीरिक अपूर्णता का शिकार हुआ। किसी ने जन्मजात अपूर्णता पायी तो कोई गलत इलाज से अभिशप्त जीवन जीने को मजबूर हुआ। लगातार दो पैरालंपिक में भाला फेंक में सोने का तमगा जीतने वाले हरियाणा के सुमित अंतिल को एक दुर्घटना के चलते एक पैर कटवाना पड़ा। सड़क दुर्घटना में शरीर के निचले हिस्से को निष्क्रिय पाने वाले अवनि लेखरा ने फिर दूसरी बार सोने का तमगा हासिल किया। करंट लगने से शारीरिक अपूर्णता से ग्रस्त होने वाले कपिल परमार ने पहली बार भारत को जूडो में पदक दिलाया। बिना हाथों के जन्म लेने वाली शीतल देवी का संघर्ष कितना बड़ा रहा, सोच कर हैरानी होती है। उसने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता। ऐसे में देखें तो पैरालंपिक खिलाड़ियों का संघर्ष सामान्य ओलंपिक खिलाड़ियों से कई गुना ज्यादा है। भारत के 84 सदस्यीय दल ने पैरालंपिक इतिहास में ट्रैक स्पर्धाओं में 17 पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं पेरिस ओलंपिक में 110 सामान्य खिलाड़ियों का दल सिर्फ एक रजत समेत छह पदक ही जीत पाया था। एक बात तो तय है कि इतनी बड़ी संख्या में पदक जीतने वाले पैरालंपिक खिलाड़ियों को देश लौटने पर जो सम्मान दिया जाना था, वो हमने नहीं दिया। ऐसा लगा कि सरकारों से लेकर मीडिया तक को जो तरजीह इन खिलाड़ियों को देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई। जिस तरह सामान्य पदक विजेता खिलाड़ियों के सम्मान में हम जुटे रहे, वैसा उत्साह पैरा खिलाड़ियों के प्रति हमने नहीं दिखाया। इन खिलाड़ियों ने अपने जीवन के कठिन संघर्ष के बावजूद देश का जो सम्मान बढ़ाया, उसका प्रतिसाद देने में हम चूके हैं। उनके लिये सरकार व निजी क्षेत्रों द्वारा वैसे पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई और न ही उनके लिये नौकरियों व अन्य सुविधाओं के अवसर मुहैया कराये गये। सात स्वर्ण पदक जीतना छोटी कामयाबी नहीं थी। नौ चांदी के तमगों की चमक कम नहीं होती। विडंबना यह कि उन्हें परंपरागत मीडिया व सोशल मीडिया पर वैसा सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। यदि खिलाड़ियों के स्तर पर ऐसा भेदभाव न होता तो नये खिलाड़ियों में भी पैरा खेलों में भाग लेने का जुनून पैदा होता। इन खिलाड़ियों को, जिनका निजी व सार्वजनिक जीवन में संघर्ष बहुत बड़ा है, पर्याप्त सम्मान मिलना चाहिए। इन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए देश का नाम रौशन किया। सच्चे अर्थों में, आज देश को दिव्यांग खिलाड़ियों के प्रति अधिक संवेदनशील होने व उनके प्रति ज्यादा सम्मान का भाव रखने की जरूरत है। उन्हें दया नहीं, प्रोत्साहन की जरूरत है। हमें ऐसी प्रतिभाओं को पहचान कर स्कूल स्तर से ही उनके पसंद के खेलों के लिये प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उनमें आत्मगौरव का भाव भरने की जरूरत होती है ताकि उन्हें पैरालंपिक जैसी स्पर्धाओं में बेहतर प्रदर्शन के लिये प्रेरित किया जा सके। कायदे से हमें पेरिस से लौटे पैरा खिलाड़ियों को पलक-पांवडों पर बैठाकर भरपूर सम्मान देना चाहिए था। उनके लिये नगद पुरस्कारों की घोषणा की जानी चाहिए थी। उन्हें सरकारी व निजी क्षेत्र की नौकरियों में तरजीह मिलनी चाहिए थी। उनके लिये अनुकूल खेल वातावरण बनाने के लिए प्रोत्साहन की जरूरत थी। लेकिन दुखद कि 145 करोड़ लोगों के देश ने ऐसा नहीं किया। बावजूद इसके कि इन पैरा खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देशवासियों को हैरान किया। ये देश व खेल प्रेमियों के लिये खुशी व गर्व की बात थी कि इन खिलाड़ियों ने पदक जीतने के तमाम पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिये। वैसे ओलंपिक खेलों व पैरालंपिक खेलों में तकनीकी रूप से कुछ फर्क होता है। सामान्य खिलाड़ियों में इस बात का परीक्षण किया जाता है कि उनकी शारीरिक क्षमता कितनी है। वहीं पैरालंपिक में खिलाड़ी की दृढ़ इच्छाशक्ति व साहस की पड़ताल होती है। यही वजह है कि पैरालंपिक में सामान्य ओलंपिक के मुकाबले देशों की संख्या कम व पदक ज्यादा होते हैं। वैसे तो जो देश ओलंपिक में ज्यादा पदक जीतते हैं, वे ही पैरालंपिक में भी सामान्य तौर पर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। किसी देश में शारीरिक अपूर्णता वाले खिलाड़ियों के लिये कितनी खेल सुविधाएं हैं और समाज का दृष्टिकोण कैसा रहता है, इस पर भी खिलाड़ियों की सफलता निर्भर करती है। किसी देश में चिकित्सा सुविधाओं का स्तर भी दिव्यांग खिलाड़ियों की सफलता तय करता है। यही वजह है कि चीन व ब्रिटेन ने अधिक पदक जीते और अमेरिका व जापान पीछे रहे। बड़ी आबादी वाले देश चीन, भारत व ब्राजील को अधिक आबादी का लाभ भी पैरालंपिक खेलों में मिला। भारत में सस्ती चिकित्सा सुविधाएं होने का लाभ भी दिव्यांग खिलाड़ियों को मिलता रहा है, जबकि अमेरिका में महंगा इलाज उनकी राह में एक बड़ी बाधा है। वैसे सामान्य खिलाड़ियों पर अपेक्षाओं का दबाव अधिक होता है। वहीं शारीरिक अपूर्णता वाले खिलाड़ियों पर ऐसा दबाव कम होता है और वे अधिक बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। वैसे मनोवैज्ञानिक रूप से भी दिव्यांग खिलाड़ियों में पदक जीतने का बड़ा जुनून होता है। उनकी कोशिश होती है कि वे भी सामान्य नागरिकों जैसी शोहरत हासिल कर सकें। यानी पैरा खिलाड़ी में समाज में कुछ खास जगह बनाने का जुनून होता है। मेडल जीतने की ललक उन्हें बेहतर करने को प्रेरित करती है। दरअसल, शारीरिक रूप से चुनौती वाले प्रतियोगियों में पदक जीतने का जुनून ज्यादा पाया जाता है। उनकी एकाग्रता सफलता की राह खोलती है। वक्त की नजाकत यह है कि क्या हम उनके विशिष्ट गुण को उचित सम्मान दे पा रहे हैं? क्या हम उन्हें ओलंपिक खिलाड़ियों के समान मान-सम्मान प्रदान कर रहे हैं? क्या पुरस्कार राशि व उनकी प्रतिष्ठा के अनुरूप रोजगार देने में निष्पक्ष हैं? यदि हम उन्हें उनका वाजिब हक और सम्मान देंगे तो देश में पैरा खिलाड़ियों की नई पौध विकसित होगी। फिर हर पैरालंपिक में झोली में भरे पदकों की खनक पूरी दुनिया में सुनाई देगी।

https://t.me/AINewsPaperPdf

केंद्र का सराहनीय फैसला

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को शामिल करने का निर्णय की सराहना की जानी चाहिए। इस फैसले से देश के लगभग 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिल सकेगा। साथ ही, इतनी ही कीमत का हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा।इस फैसले की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सोशल सिक्योरिटी के मामले में भारत बहुत पीछे है। नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में ऐसे परिवारों की संख्या केवल 41% है, जिनके कम से कम एक सदस्य का हेल्थ इंश्योरेंस हो। बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में तो यह राष्ट्रीय औसत के करीब आधे के बराबर है। स्वास्थ्य बीमा को लेकर यह उदासीन रवैया हमारी उस आदत की वजह से है, जिसमें ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि जब बीमारी आएगी तो देखा जाएगा। बहुत से लोग जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को एक ही चीज समझ लेते हैं। लेकिन, जब बीमारी सिर पर आती है, तो पूरे घर के बजट को तोड़कर रख देती है। सरकार का मौजूदा कदम कई परिवारों को ऐसे आर्थिक दुष्चक्र में फंसने से बचायेगा। भारत में इलाज आम आदमी की पहुंच से होता जा रहा है। एक सर्वे के मुताबिक, भारत में 2023 में मेडिकल इन्फ्लेशन 9.6% थी, जो मौजूदा साल में 11% हो सकती है। कोरोना के दौर में पूरे एशिया में चिकित्सा पर महंगाई की सबसे ज्यादा मार हिंदुस्तान पर ही पड़ी थी। तब हमारे यहां मेडिकल इन्फ्लेशन 14% हो गई थी, चीन से भी ज्यादा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का डेटा बताता है कि भारत में जीवन प्रत्याशा 67.3 साल है। देश में दिल से जुड़े रोगों और डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत में गैर संचारी रोगों से हर साल लगभग 58 लाख लोगों की मौत होती है। इनमें सबसे ज्यादा लोग मरते हैं हृदय रोग और कैंसर से। सरकार ने बजट में स्वास्थ्य के लिए कोटा बढ़ाया है। हालांकि चीन और अमेरिका की तुलना में यह अब भी कम है। मेडिकल इंफ्रा बढ़ाने के साथ यह इंतजाम भी करना होगा कि आम जनता उसका फायदा उठा सके। सरकार का हालिया फैसला इसी दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि योजना को सही ढंग से लागू किया जाए। कोई इस लाभ से वंचित न हो।

भारत विरोधियों को क्यों अच्छे लगे राहुल?

महेश खरे

(वरिष्ठ पत्रकार)

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राहुल ने आखिर ऐसा क्या कह या कर दिया जिससे भारत में बवाल मचा हुआ है। सिखों ने दिल्ली में उनके बंगले पर जंगी प्रदर्शन किया और 1984 के लिए माफी मांगने की मांग करते हुए नारे लगाए। केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने आरोप लगाया- नेता प्रतिपक्ष विदेश में संवेदनशील मुद्दों पर 'खतरनाक विमर्श' गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसे देशद्रोह कहा।

गोरख पांडेय की एक बहुचर्चित कविता है। पहले सुन लीजिए फिर बात को आगे बढ़ाते हैं-

राजा बोला रात है,
रानी बोली रात है,
मंत्री बोला रात है,
संतरी बोला रात है,
यह सुबह सुबह की बात है।

कांग्रेस की सियासत में यही हो रहा है। अमेरिकी यात्रा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब आरक्षण और सिखों पर बवाल मचा देने वाले बयान दिए तो भारत में कांग्रेस अपने नेता की बात को आंख मूंद कर सही साबित करने में जुट गई। बड़े-बड़े नेताओं में से किसी ने भी यह जानने या सवाल करने की कोशिश नहीं की कि राहुल बाबा ये किस तरह की बात है? दलीय अनुशासन अपनी जगह है और देश का हित अपनी जगह।

राहुल के समर्थन में स्वर उठे जरूर लेकिन वह खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत पन्नू के थे। दूसरी समर्थक वह अमेरिकी डेमोक्रेटिक सांसद रल्हान उमर थीं, जिनका लक्ष्य ही भारत विरोध रहा है। सवाल यही है कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर ऐसा क्या कह दिया कि भारत विरोधी ताकतों को उनके विचारों में अपनी छवि दिखाई देने लगी?

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि राहुल ने आखिर ऐसा क्या कह या कर दिया जिससे भारत में बवाल मचा हुआ है। सिखों ने दिल्ली में उनके बंगले पर जंगी प्रदर्शन किया और 1984 के लिए माफी मांगने की मांग करते हुए नारे लगाए। केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह ने आरोप लगाया- नेता प्रतिपक्ष विदेश में संवेदनशील मुद्दों पर 'खतरनाक विमर्श' गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इसे देशद्रोह कहा।

लगे हाथ राहुल के बयान को समझ लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राहुल विदेशी धरती पर भारत के सिखों का मुद्दा उठाते हुए बोले- सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि लड़ाई किस बारे में है। लड़ाई राजनीति के लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए लड़ी जा रही है कि एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने का अधिकार रहेगा या नहीं? एक सिख के रूप में वे गुरुद्वारा जा सकते हैं या नहीं?

बड़े ही नाटकीय अंदाज और सधे हुए शब्दों में अमेरिका में कहे गए इन वाक्यों ने भारत में हंगामा बरपा दिया। पहले तो यह समझा जा रहा था कि राहुल गांधी के मुंह से अनायास ही ऐसे शब्द निकल गए होंगे। आखिर एक भारतीय नेता अपने देश की ऐसी तस्वीर को कैसे सामने ला सकता है? लेकिन जब उन्होंने स्वयं आरक्षण के मुद्दे पर उनके बयान को लेकर उपजे भ्रम पर सफाई दी और सिखों के बारे में कहे गए अपने बयान को छुआ तक नहीं, तब लगा कि राहुल ने यह बात बहुत सोच समझकर विचार- मंथन के बाद ही कही है।

लेकिन, लगता है खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को राहुल की बात में बहुत अपनापन नजर आया। पन्नू की प्रतिक्रिया देखिए- 'राहुल गांधी ने बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया है। उनका यह बयान सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) की अलग खालिस्तान की मांग को जस्टिफाई करता है। राहुल का बयान न केवल साहसिक है, बल्कि 1947 के बाद से भारत में सिखों पर हो रहे अत्याचार को दशार्ता है।'

जाने- अनजाने दिया गया राहुल का यह बयान भारत विरोधी ताकतों को ही रास आया। भारत में सिख समाज राहुल के कथन से हतप्रभ और आक्रोशित है। फिर भी नेता प्रतिपक्ष को इसमें किसी सिख का साथ दिख रहा हो या दिखा हो तो और बात है। पन्नू को यह बयान इसलिए राहत देने वाला नजर आया क्योंकि वो कई वर्षों से अलग खालिस्तान देश की मांग को लेकर विदेश में प्रोपेगेंडा चला रहा है। भारत में तो इस मांग पर वह जनमत संग्रह कराने की कोशिश तक कर चुका है।

अमेरिका में राहुल गांधी के साथ खड़ी दिखाई दी एक और सख्शियत हैं अमेरिकी सांसद रल्हान उमर। वे भारत विरोध का कभी कोई मौका नहीं चूकतीं। दो साल पहले 2022 में वह पीओके का विवादास्पद दौरा कर चुकी हैं। हिंदुत्व को हिंदू फोबिया बताकर भारत विरोधी बयान देना उनकी नीति में शामिल है। वे भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की घोर विरोधी और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की प्रशंसक हैं। कनाडा में खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह नजर की हत्या वाले मामले में भी एक्स पर ट्वीट कर उन्होने बाइडेन सरकार से कहा था कि इस मामले की जांच में अमेरिका को कनाडा की मदद करना चाहिए। अमेरिकी दौरे में राहुल के साथ उमर की मुलाकात को लेकर भी सियासत गर्म है।

ऐसी स्थिति में हो सकता है राहुल का यह बयान सियासत चमकाने और सिखों का समर्थन पाने की दिशा में सोचा समझा प्रयास हो। लेकिन भारत में इसकी जिस तरह से सिख समाज में ही तीखी प्रतिक्रिया हुई है उसे देख कर तो यही कहा जा सकता है कि उन्हें इस तरह की बयानबाजी से दूर ही रहना चाहिए था। वैसी स्थिति में जबकि कांग्रेस की सियासी यात्रा पर 1984 का धब्बा लगा हो। अगर यह सियासी दांव है तो यह कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए उल्टे बांस बरेली जैसा ही साबित हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए।

भारत के दो राज्यों में इस समय चुनाव हैं। इसलिए भी क्या कांग्रेस आक्रामक तेवर अपना कर जनता को आकर्षित करने के प्रयास में है? मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत की राजनीति से किसका भला हुआ है? यह कांग्रेस के नेतृत्व से पूछने की आवश्यकता उस समय आन पड़ी है जब इसके नेता ही मोदी विरोध की धुन में टकराव को न्यौता देने से भी नहीं हिचक रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनावी भाषण का अंश देखिए -यदि लोकसभा चुनाव में 20 और सीटें मिल जातीं तो ये (बीजेपी वाले) जेल में होते। ये इसी लायक हैं। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि कांग्रेस यदि सत्ता में लौटी तो बदले की राजनीति का दौर शुरू हो जाएगा?

राजनीति में जिस प्रकार से कटुता का समावेश हुआ है, वह देश को किस ओर ले जाएगा? चिंता की बात यह है कि यह टकराव और कड़वाहट चुनाव के समय ज्यादा खुल कर सामने आ जाती है। इन दिनों जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हैं। दोनों राज्यों में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस के साथ कांग्रेस का गठजोड़ है। चुनावी मैदान में अलगाववादी ताकतें भी जोर आजमा रही हैं। इसलिए चुनाव के बहाने देश विरोधी हरकतों पर सतर्क नजर रखने की आवश्यकता है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अरुणाचल में खिलती- खिलखिलाती हिंदी

राजीव रंजन प्रकाश

शाम का समय, पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में भीड़-भाड़ वाले गंगा मार्केट में गुजरते हुए स्थानीय उच्चारण में लोगों द्वारा शुद्ध हिंदी में बातचीत सुनकर एक सुखद आश्चर्य हुआ। पीछे मुड़कर देखा, तो तीन-चार महिलाएं और बच्चे आपस में हिंदी में बातचीत कर रहे थे। पता चला कि यहां के लोग अपने घर-परिवारों में तो स्थानीय भाषाएं बोलते हैं, परंतु बाजारों, स्कूल-कॉलेजों और कार्यालयों में धड़ल्ले से हिंदी में ही बातचीत करते हैं, वह भी वर्षों से।यह भारत में सबसे पहले सूर्योदय वाले प्रदेश में निरंतर बढ़ती और खिलती-खिलखिलाती हिंदी की कहानी है।

दशकों से यहां के जनजातीय समुदायों में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। यहां लगभग 26 जनजातियां तथा उनकी 100 से अधिक उप जनजातियां निवास करती हैं और भाषायी दृष्टि से ये जनजातियां एक-दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, जिसके कारण संचार एवं संवाद स्थापित करने में काफी समस्याएं आती थीं। वर्ष 1962 में चीन द्वारा अरुणाचल के सीमावर्ती क्षेत्रों पर आक्रमण के समय संचार एवं भाषायी समस्याओं के कारण भारत को काफी नुकसान झेलना पड़ा था। उस समय असमिया यहां संपर्क भाषा के रूप में प्रचलित थी, जिसे सभी अच्छी तरह से समझ-बोल नहीं पाते थे। इसलिए केंद्र सरकार ने भाषायी एकरूपता स्थापित करने के लिए सभी स्कूल-कॉलेजों में हिंदी को लागू किया।

इसके अलावा, चीन के आक्रमण के उपरांत इन क्षेत्रों में तेजी से हुए विकास कार्यों के कारण यहां अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में हिंदी व अन्य भाषा-भाषी लोग आए और धीरे-धीरे संपर्क भाषा के रूप में हिंदी ने असमिया का स्थान ले लिया। स्थानीय लोगों ने भी सहर्ष एवं स्वेच्छा से हिंदी को अपना लिया है और हिंदी यहां मुख्य संपर्क बोली नहीं, बल्कि भाषा बन गई है। यहां से हिंदी की कई पत्र-पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं।

वर्ष 1977 में भारत रत्न भूपेन हजारिका द्वारा निर्देशित पहली फिल्म 'मेरा धर्म-मेरी मां' हिंदी में ही बनी थी, जो अरुणाचल की अब तक की सर्वाधिक लोकप्रिय फिल्म है। यहां से हिंदी फिल्मों का निर्माण भी हो रहा है और वे लोकप्रिय भी हो रहे हैं। पूर्वोत्तर ?में अरुणाचल ही एक ऐसा राज्य है, जहां संचार प्रणाली में पूर्णतया हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। बेशक अंग्रेजी यहां की आधिकारिक राजभाषा है, जो औपचारिक दस्तावेजी कागजों तक ही सीमित है, लेकिन प्रशासनिक कामकाज के लिए यहां हिंदी भाषा का ही बहुधा प्रयोग किया जाता है। नतीजतन हिंदी व्यावहारिक भाषा के रूप में पूरे अरुणाचल में स्वीकार्य भाषा बन गई है। यहां हिंदी का प्रचार-प्रसार भाषा के रूप में नहीं, बल्कि बोली के रूप में अधिक हो रहा है।

निस्संदेह अरुणाचल में हिंदी तेजी से अपने पांव पसार रही है, लेकिन यहां की क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग काफी कम हो गया है तथा कई स्थानीय जनजातीय भाषाएं लुप्त होने के कगार पर हैं। इसलिए हमें हिंदी को बढ़ाने के साथ-साथ स्थानीय जनजातीय भाषाओं और संस्कृति को भी बचाने का प्रयास करना होगा।

एक दिन क्यों 365 दिन हो हिंदी

विनोद पाठक

साल 1975 में फिल्म आई थी 'चुपके-चुपके'। ऋषिकेश मुखर्जी निर्देशित इस फिल्म में मुख्य किरदार के रूप में अभिनेता धर्मेंद्र थे, जो वनस्पति शास्त्र के प्रोफेसर बने थे, लेकिन अपनी पत्नी अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के जीजा अभिनेता ओमप्रकाश को परेशान करने के लिए वो शुद्ध हिंदी का सहारा लेते हैं। धर्मेंद्र ऐसी शुद्ध हिंदी बोलते हैं, जो जीजा जी को समझ नहीं आती और वो परेशान हो जाते हैं। यह सत्य है कि यदि हम शुद्ध हिंदी का प्रयोग आम बोलचाल में करने लगेंगे तो शायद हिंदी बोलने वाले अधिकांश लोगों को भी यह ठीक से समझ नहीं आएगी। आज 14 सितंबर है। इस तिथि को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आप स्वयं से सवाल कीजिए, जिस वर्तनी का आप प्रयोग करते हैं, क्या वो शुद्ध हिंदी की है? जवाब न में होगा।

भारत लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं से जूझता रहा। अरब आए, तुर्क आए, मुगल आए, पुर्तगाली आए, स्पेनिश आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए और सभी अपनी-अपनी भाषा साथ लाए। हमने सभी भाषाओं के शब्दों को हिंदी के साथ आत्मसात कर लिया। हिंदी के साथ 3500 फारसी, ढाई हजार अरबी, 50 पोश्तों, 125 तुर्की के शब्द समाहित हो गए। हमने पुर्तगाली, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रांसिसी आदि के शब्दों का समावेश भी हिंदी के साथ कर लिया। जैसे, हम किसी से समय नहीं टाइम पूछते हैं। कुल मिलाकर आज हम शुद्ध नहीं, मिश्रित हिंदी का उपयोग कर रहे हैं। आज जिस हिंदी की खड़ी बोली का हम प्रयोग करते हैं, उसकी नींव भारतेंदु हरिश्चंद्र ने डाली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नाटकों, कविता, किस्सागोई और कहावतों के माध्यम से हिंदी के उत्थान के भगीरथ प्रयास शुरू किए। फिर समय के साथ हिंदी आगे बढ़ती चली गई। 19वीं सदी के प्रारंभ में स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने में हिंदी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

एक तरह से हिंदी पूरे भारत की सर्वमान्य भाषा बनकर उभरी। शायद यही कारण था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की पहल न केवल महात्मा गांधी, बल्कि उस दौर के देश के कई बड़े नेता कर रहे थे। साल 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन की महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। उस सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि हिंदी ही देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 351 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। हालांकि, साल 1965 में जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनने के प्रयास चल रहे थे, तब दक्षिण भारत के राज्यों में विरोध के कारण हिंदी राजभाषा तक सीमित होकर रह गई। सरकारी कामकाज मुख्य रूप से अंग्रेजी में होता रहा, लेकिन नब्बे के दशक में हिंदी को एक बार फिर नए पंख मिले।

मीडिया, बाजार, इंटरनेट, शिक्षा समेत करीब-करीब सभी जगह हिंदी दिखने लगी। आज हिंदी का दबदबा न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर में बढ़ा है। दुनिया में बोली जाने वाली सर्वाधिक भाषाओं में हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। आज हिंदी 60 करोड़ से अधिक लोगों की भाषा है। देसी नहीं, मल्टीनेशनल कंपनियां भी हिंदी को लेकर सहज हुई हैं। पिछले 10 वर्षों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के हर मंच पर हिंदी में बात करते हैं। आज केंद्र सरकार का अधिकतर काम हिंदी में होना प्रारंभ हो गया है, जो हिंदी के लिए एक सुखद बात है। फिर भी हिंदी को लेकर बहुत काम करने की आवश्यकता है।

खासकर हिंदी व्याकरण और वर्तनी को मजबूत करने की जरूरत है। आज बाजारों में हिंदी के बिल बोर्ड लगे मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अशुद्ध हिंदी इन्हीं बिल बोड्र्स पर लिखी होती है। सरकारी बिलबोड्र्स भी इससे अछूते नहीं हैं। एक विडंबना यह भी कि देश के सुप्रीम कोर्ट में आज भी हिंदी स्वीकार्य नहीं है। केवल एक दिन हिंदी दिवस मनाने के बजाय हमारे 365 दिन हिंदी को समर्पित होने चाहिए।

सुभाषित *कुछ लोगोंकी लापरवाही आसानीसे डूबा सकती है लेकिन यदि सभीकी सही सहभागिता हो तो सुरक्षित रूपसे बाहर आया जा सकता है।* ❑ सरदार वल्लभभाई पटेल

चीनकी इच्छाके निहितार्थ

चीनका यह कहना कि वह भारतसे सम्बन्ध मजबूत करना चाहता है, बेहद कर्णप्रिय है और स्वागतयोग्य है। चीनके इस वक्तव्यके निहितार्थको समझना होगा, क्योंकि वह एक धुर्त देश है, यह जगजाहिर है। उसपर सहसा विश्वास करना खुदको धोखा देना है, क्योंकि उसका इस तरहका कोई भी कदम निजी स्वार्थसे प्रेरित होता है और अन्तत: छलावा साबित होता है। चीनकी ओरसे ऐसे किसी बयानका पूर्वानुमान भी नहीं था। यह बयान तब आया जब भारतीय परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरने एक दिन पहले ही जेनेवामें कहा था चीनसे ७५ फीसदी विवाद हल हो चुका है। एस. जयशंकरके कहनेका मतलब चीन चाहे जो भी समझता हो लेकिन इसके तत्काल बाद भारतसे सम्बन्ध मजबूत करनेका बयान उसकी कूटनीतिक चाल भी हो सकती है। इसपर भारतको गम्भीरतासे विचार करनेकी जरूरत है। रूसमें ब्रिक्स देशोंके वरिष्ठ अधिकारियोंकी बैठकसे इतर चीनके विदेश मंत्रालयकी प्रवक्ता माओ निंग और भारतके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभालके बीच हुई बैठकके बाद माओ निंगने शुक्रवारको कहा कि पूर्वी लद्दाखके चार क्षेत्रोंमें सेनाओंके बीच तनातनी कम हुई है और दोनों देश द्विपक्षीय सम्बन्धोंको मजबूती देनेके लिए सहमत हैं। निंगने स्वीकार किया पूर्वी लद्दाखमें दोनों देशोंकी सेनाओंके बीच तनातनीके बाद बीते चार वर्षोंसे द्विपक्षीय सम्बन्ध सुस्त पड़े हैं लेकिन दोनों देशोंकी सेनाओंको सीमापर चार क्षेत्रोंमें शान्ति बनाये रखनेका अहसास भी हुआ है। हालांकि सीमापर अभी स्थिति स्थिर है। भारतसे सम्बन्ध सुधारने और मजबूत करनेकी पेशकश चीनकी ओरसे की गयी है। भारतकी ओरसे इसपर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी है। इस दिशामें भारत फूंक-फूंककर कदम उठानेकी रणनीतिपर कायम है जो उचित है। पूर्वमें कभी हिन्द-चीन भाई-भाईका नारा लगता था जिसकी परिणति युद्धके रूपमें सामने आया और इसके बाद जो सीमा विवाद शुरू हुआ वह अबतक बना हुआ है। भारत-चीनके सम्बन्धोंमें जो कटुता आयी है, उसका चीन प्रमुख कारण है। चीनकी सीमा विस्तारकी महत्वाकांक्षा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि सही मायनोंमें वह भारतसे बेहतर सम्बन्धका इच्छुक है तो उसे पूर्वकी बाधाओंको दूर करना होगा। सीमा विवादोंका समाधान न्यायसंगत होना चाहिए। चीन यदि भारतसे मधुर सम्बन्धके प्रति गम्भीर है तो उसे पूर्वकी स्थितिमें आना होगा। व्यापारिक दृष्टिसे भारत बहुत बड़ा बाजार है। भारतसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध आर्थिक रूपसे चीनके हितमें है। इसके लिए उसे अपनी मानसिकता बदलनी होगी, तभी सम्बन्धोंमें सुधारकी उम्मीद की जा सकती है।

चिकित्सकोंकी कमीका संकट

उत्तर प्रदेशमें बीते कुछ सालोंमें स्वास्थ्य सेवाओंके ढांचेको मजबूत करनेके लिए काफी कुछ हुआ है। हर जिलेमें मेडिकल कालेज खोले जा रहे हैं। इसके बावजूद २५ करोड़की आबादीवाले प्रदेशमें डाक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफकी कमी प्रदेश सरकारके लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। ऐसेमें शुक्रवारको डाक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊके चतुर्थ स्थापना दिवस समारोहमें मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथने भरोसा दिलाया है कि आनेवाले पांच-सात सालोंमें प्रदेशमें डाक्टरोंकी कमीकी समस्या खत्म हो जायगी। प्रदेशके सभी पीएचसी, सीएचसीको डाक्टर मिलेंगे। आंकड़ोंके हिसाबसे प्रदेशमें १९ हजार डाक्टरोंके स्वीकृत पदोंमें लगभग सात हजार पद खाली हैं, वहीं विश्व स्वास्थ्य संघटनके मानक एक हजारकी आबादीपर कमसे कम एक डाक्टर जरूरी है, जबकि राज्यमें १९ हजारसे ज्यादाकी आबादीपर एक डाक्टर है। विशेषज्ञ चिकित्सकोंके तो ८५ प्रतिशतसे अधिक पद खाली हैं। प्रदेशको इस समय लगभग ३३ हजारसे ज्यादा विशेषज्ञ डाक्टरों और लगभग छह हजारसे ज्यादा एमबीबीएसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सरकार चिकित्सकोंकी नियुक्ति नहीं कर रही है, चिकित्सक ही सरकारी अस्पतालोंके बजाय निजी अस्पतालोंमें नौकरीको प्राथमिकता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोगने बीते साल ४०१ पदोंके लिए वैकेंसी निकाली, जिसमेंसे ४० पद ही भरे जा सके, बाकी पद रिक्त रह गये। इससे ही अन्दाजा लग जाता है कि राज्य सरकारकी सेवाओंके प्रति चिकित्सकोंमें कितनी अरुचि है। पिछले साल ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनके तहत संविदापर १२ सौ विशेषज्ञ डाक्टरोंकी भर्ती निकाली गयी, परन्तु बमुश्किल सौ डाक्टर ही मिल सके। चिकित्सकोंकी कमीको कम करनेके लिए सरकारने सेवानिवृत्तिकी उम्रसीमा भी बढ़ायी है। नियमित चिकित्सकोंकी नियुक्तिके लिए सरकारको ठोस नीति बनानी होगी जिससे डाक्टर सरकारी अस्पतालोंमें सेवा देनेके बाद ही निजी अस्पतालोंकी ओर रुख कर सके। ऐसा नहीं करनेसे राज्यमें डाक्टरोंकी कमी बनी रहेगी। इतनी बड़ी आबादीको संविदा या सेवानिवृत्त डाक्टरोंपर नहीं छोड़ा जा सकता है।

लोक संवाद

बच्चोंमें एलर्जीकी संभावना

महोदय,-के. अर्चना हालमें एक रैस्टोरैंटसे आर्डर की गयी मिठाई खानेके बाद एक बहुत ही खराब अनुभवसे गुजरीं। उन्हें कई घंटोंतक गम्भीर ऐंठन होती रही। लक्षण उनके लिए जाने-पहचाने थे। जब वह अंडेवाली कोई चीज खाती हैं तो उन्हें यह प्रतिक्रिया होती है। हालांकि इस बार उन्होंने विशेष रूपसे अपनी एलर्जीका जिक्र किया और ऐसी चीज मांगी जिसमें अंडे न हों। ३९ वर्षीय अर्चनाने कहा कि उन्हें बचपनसे ही अंडोंसे एलर्जी है। उनकी पहली यादें उनके गृहनगर कोयंबटूरमें एक रैस्टोरैंटमें जानेके बाद हुई गम्भीर प्रतिक्रिया की हैं। शायद यह एक शाकाहारी रैस्टोरैंट था। यह पहली बार था जब मैंने नान खाया था। जब में घर लौटी तो मुझे उल्टी हो गयी। ऐसा कुछ भी खानेके बाद होता है, जिसमें अंडे होते हैं। जब उनके पिताने बादमें रैस्टोरैंटसे पूछा तो उन्हें बताया गया कि नानमें अंडे डाले गये थे। अर्चनाकी किसी खाद्य पदार्थके प्रति प्रतिक्रिया नयी या दुर्लभ नहीं है। बाल रोग विशेषज्ञ बच्चोंमें खाद्य एलर्जीपर साहित्यका हवाला देते हैं। उनका कहना है कि बच्चोंको अंडे, सी फूड और अखरोटसे एलर्जी हो सकती है। इस संवाददाताने जिन सभी बाल रोग विशेषज्ञोंसे बात की, उनका मानना है कि एलर्जी पश्चिमीकरणका परिणाम है। बाल रोग विशेषज्ञोंका कहना है कि आम एलर्जीमें अंडे, अखरोट और सी फूड खानेके बाद होनेवाली एलर्जी शामिल है। सूर्या अस्पतालमें कंसल्टेंट बाल रोग विशेषज्ञ आर. अशोकनने कहा कि मैंने मूंगफली या अन्य अखरोटसे एलर्जी अपने अभ्यासमें नहीं देखी है लेकिन मांसाहारी भोजन या यहांतक कि अंडेसे एलर्जी देखी है। कुछ लोगोंमें अनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। कुछ लोगोंमें यह अधिगृहित हो सकती है। एलर्जी लगातार हो सकती है। मैं लगातार एलर्जीके एक या दो मामले देख सकती हूं। कभी-कभी जब हम उन्हें असंवेदनशील बनाते हैं तो रोगी कुछ समयके लिए सामान्य एलर्जी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। फिर हम भोजनको फिरसे पेश कर सकते हैं और व्यक्ति एलर्जीसे मुक्त हो सकता है। मूंगफलीकी एलर्जीका इलाज करनेके लिए बच्चोंपर किये गये अध्ययनसे उम्मीद जगी है। शरीर किसी खाद्य पदार्थके सम्पर्कमें आनेपर अलग तरहसे प्रतिक्रिया करता है। यह संक्रमण, बैक्टीरिया, वायरस और प्रोटीन अणुओं जैसे एंटीजनके प्रति अलग तरहसे प्रतिक्रिया करता है। हम नहीं जानते कि वे इम्युनोग्लोबुलिन-ईका इस्तेमाल अलग तरीकेसे क्यों करते हैं। यह शायद अनुवांशिक रूपसे मध्यस्थतावाला है। यह शरीर द्वारा किया जानेवाला चुनाव है तो क्या इस कथनमें सचाई है कि स्तनपान करनेवाले बच्चे एलर्जीके प्रति इतनी आसानीसे संवेदनशील नहीं होते। स्तनपान करनेवाले बच्चोंमें प्रोटीनका सेवन कम होता है, इसलिए एलर्जीकी संभावना कम होती है। एक बाल रोग विशेषज्ञने कहा कि गायके दूधमें चार प्रतिशत प्रोटीन होता है। स्तनके दूधमें केवल एक होता है। जब शरीर दूधको पचाता है तो यह अमीनो एसिड और पेप्टाइड्स जैसे रसायनोंमें परिवर्तित हो जाता है। हम पेप्टाइड्सको सामान्य रूपसे अवशोषित नहीं करते हैं लेकिन अमीनो एसिड बनानेके लिए उन्हें और पचाते हैं। वयस्कोंके विपरीत, नवजात शिशु अमीनो एसिडको अवशोषित करते हैं। जब बच्चेके सिस्टममें पेप्टाइड्स जा रहे होते हैं तो यह एलर्जीकी संभावनाको बढ़ाता है। गायके दूधमें मौजूद फार्मूला एलर्जीकी संभावनाको बढ़ाता है। यदि बच्चेको पहले छह महीनोंतक स्तनपान कराया जाता है तो एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस जैसी एलर्जी संबंधी बीमारियोंकी संभावना कम होती है। कभी-कभी बच्चोंमें रक्त परीक्षणके आधारपर खाद्य एलर्जीका निदान किया जाता है। उन्हें विशेष खाद्य पदार्थसे बचनेकी सलाह दी जाती है लेकिन अधिकांश रोगियोंमें समस्या बनी रहती है। ऐसे मामलोंमें किसी एलर्जिस्टसे परामर्श किया जाना चाहिए और त्वचा परीक्षण समस्याका सही निदान करनेमें मदद करेगा। एलर्जी हल्की या गम्भीर हो सकती है। कुछ बच्चोंमें चकत्ते हो सकते हैं या यहांतक कि एनाफिलैक्सिस भी हो सकता है। **-आर.सुजाता, वाया ईमेल।**

मस्तकके तिलकपर प्रहार

भारतमें १९५३ से १४ सितम्बरसे एक सप्ताहतक हिन्दी दिवस मनाया जाता है। देशमें दिन-प्रतिदिन हिन्दीकी उपेक्षा होती जा रही है। राजनीतिक कारणोंसे हिन्दीको संघर्षोंका सामना करना पड़ रहा है। हिन्दीकी राहमें यूं तो कई बाधाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बाधा शासनमें उसकी उपेक्षा और अंग्रेजीदां नौकरशाहीका वर्चस्ववादी रवैया है।

❑ **ललित गर्ग**

हिंदीपर अंग्रेजीका प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हिन्दी राष्ट्रीयताकी प्रतीक भाषा है इसलिए हिन्दीको उचित सम्मान देते हुए, उसको राजभाषा बनाने एवं राष्ट्रीयताके प्रतीकके रूपमें प्रतिष्ठापित करना हिन्दी दिवसकी प्राथमिकता होना ही चाहिए। आजादीके अमृतकालतक पहुंचनेके बावजूद हिन्दीको उसका उचित स्थान न मिलना विडम्बना एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतसे ठीक दो वर्ष पहले १७ अगस्त १९४५ को इंडोनेशिया डच शासनसे मुक्त हुआ और अपनी भाषा 'बहासा इंडोनेशिया' को राष्ट्रभाषाके रूपमें लागू कर दिया। कुछ इसी तरह २३ अक्तूबर १९२३ को जब आधुनिक तुर्की गणराज्यकी स्थापना हुई तो तत्काल तुर्की भाषाको राजकाजकी भाषाके रूपमें लागू कर दिया। आज हिन्दी विश्वकी सर्वाधिक प्रयोग की जानेवाली तीसरी भाषा है, विश्वमें हिन्दीकी प्रतिष्ठा एवं प्रयोग दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन देशमें उसकी उपेक्षा एक बड़ा प्रश्न है। सचाई तो यह है कि देशमें हिन्दी अपने उचित सम्मानको लेकर जूझ रही है। राजनीतिकी दूषित एवं संकीर्ण-स्वार्थी सोचका परिणाम है कि हिन्दीको जो सम्मान मिलना चाहिए, वह स्थान एवं सम्मान राष्ट्रमें अंग्रेजीको मिल रहा है। भारत सहित दुनियाके अनेक देशोंमें विश्व हिन्दी दिवस मनाया जाने लगा, क्योंकि भारत और अन्य देशोंमें १२० करोड़से अधिक लोग हिन्दी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। पाकिस्तानकी तो अधिकांश आबादी हिन्दी बोलती एवं समझती है। बंगलादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तानमें भी लाखों लोग हिन्दी बोलते और समझते हैं। फिजी, सुरिनाम, गुयाना, त्रिनिदाद जैसे देश तो हिन्दी भाषियों द्वारा ही बसाये गये हैं। हिन्दीका हर दृष्टिसे इतना महत्व होते हुए भी भारतमें प्रत्येक स्तरपर इसकी इतनी उपेक्षा क्यों। हिन्दीकी राह आजादीके बाद ज्यादा जटिल बनी है। आजादीसे पहले ज्यादा बाधाएं नहीं थीं। इसी कारण भारतीय स्वाधीनता आन्दोलनके सूत्रधार महात्मा गांधी स्वयं हिन्दीके हिमायती थे। उनके पहले केशव चंद्र सेन, लोकमान्य तिलक जैसी हस्तियां भी देशके हृदयोंको नजदीक लानेमें हिन्दीको ही सक्षम एवं प्रभावी मानते थे। स्वतंत्रतासंग्रामके इन महानायकोंने भावी भारतकी भाषायी जरूरतोंके लिहाजसे हिन्दीको तैयार करनेकी कोशिश भी की। लेकिन आजाद भारतमें हिन्दीकी दशा एवं दिशा ज्यादा चिन्ताजनक बनी है। महात्मा गांधीने अपनी अन्तर्वेदना प्रकट करते हुए कहा था कि भाषा संबंधी आवश्यक परिवर्तन अर्थात् हिन्दीको लागू करनेमें एक दिनका विलम्ब भी सांस्कृतिक हानि है। मेरा तर्क है कि जिस प्रकार हमने अंग्रेज लुटेरोंके राजनीतिक शासनको सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, उसी प्रकार सांस्कृतिक लुटेरे रूपी अंग्रेजीको भी तत्काल निर्वासित करें। हिन्दीके लिए इस तरहका दर्द, संवेदना एवं अपनापन हर नागरिकमें जागना जरूरी है। वर्तमानमें हिन्दीकी दयनीय दशा देखकर मनमें प्रश्न खड़ा होता है कि कौन महापुरुष हिन्दीको प्रतिष्ठित करनेका प्रयत्न करेगा। हिन्दी राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रका प्रतीक है, उसकी उपेक्षा एक ऐसा प्रदूषण है, एक ऐसा अंधेरा है जिससे छांटनेके लिए ईमानदार प्रयत्न करने होंगे, क्योंकि हिन्दी ही भारतको सामाजिक-राजनीतिक-भौगोलिक और भाषायिक दृष्टिसे जोड़नेवाली भाषा है। हिन्दीको दबानेकी नहीं, ऊपर उठानेकी आवश्यकता है। राष्ट्र भाषा सम्पूर्ण देशमें सांस्कृतिक और भावात्मक एकता स्थापित करनेका प्रमुख साधन है। भारतका परिपक्व लोकतंत्र, प्राचीन सभ्यता, समृद्ध संस्कृति तथा अनूठा संविधान विश्वभरमें एक उच्च स्थान रखता है, उसी तरह भारतकी गरिमा एवं गौरवकी प्रतीक राष्ट्र भाषा हिन्दीको हर कीमतपर विकसित करना हमारी प्राथमिकता होनी ही चाहिए। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीके शासनमें हिन्दीको राजभाषा एवं राष्ट्रभाषाके रूपमें स्कूलों, कालेजों, अदालतों, सरकारी कार्यालयों और सचिवालयोंमें कामकाज एवं लोकव्यवहारकी भाषाके रूपमें प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए।

राजनेता बात हिन्दीकी करते हैं, परन्तु उनका दिमाग अंग्रेजीपरस्त है। हिन्दीको वोट मांगने और अंग्रेजीको राज करनेकी भाषा बनाना हमारी राष्ट्रीयताका अपमान है। कुछ लोगोंकी संकीर्ण मानसिकता है कि केन्द्रमें राजनीतिक सक्रियताके लिए अंग्रेजी जरूरी है। महात्मा गांधीने सही कहा था कि राष्ट्र भाषाके बिना राष्ट्र गूंगा है। यह कैसी विडम्बना है कि जिस भाषाको कश्मीरसे कन्याकुमारीतक समझा जाता हो, उसकी घोर उपेक्षा हो रही है, हिन्दी सप्ताहपर इस विडम्बनापूर्ण स्थितिको मोदी सरकारको ठोस संकल्पोके साथ प्रतिबद्ध होना चाहिए।

हालांकि इंटरनेटके बढ़ते इस्तेमालने हिन्दी भाषाके भविष्यके संबंधमें नयी राहें दिखाई है। गूगलके अनुसार भारतमें अंग्रेजी भाषामें जहां विषयवस्तु निर्माणकी रफ्तार १९ फीसदी है तो हिन्दीके लिए ये आंकड़ा ९४ फीसदी है। इसलिए हिन्दीको नयी सूचना-प्रौद्योगिकीकी जरूरतोंके मुताबिक ढाला जाय तो ये इस भाषाके विकासमें बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसके लिए सरकारी और गैर-सरकारी संघटनोंके स्तरपर तो प्रयास किये ही जाने चाहिए, निजी स्तरपर भी लोगोंको इसे खूब प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बात चाहे राष्ट्र भाषाकी हो या राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत इन सबको समूचे राष्ट्रमें सम्मान एवं स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। कुछ राजनीतिज्ञ अपना उल्लू सीधा करनेके लिए भाषायी विवाद खड़े करते रहे हैं और वर्तमानमें भी कर रहे हैं। यह देशके साथ मजाक है। जबतक राष्ट्रके लिए निजी स्वार्थको विसर्जित करनेकी भावना पुष्ट नहीं होगी, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक उन्नयन एवं सशक्त भारत एवं विकसित भारतका नारा सार्थक नहीं होगा।

हिन्दीको सम्मान एवं सुदृढ़ता दिलानेके लिए केन्द्र सरकारके साथ-साथ प्रांतोंकी सरकारोंको संकल्पित होना ही होगा। नरेन्द्र मोदीने विदेशोंमें हिन्दीकी प्रतिष्ठाके अनेक प्रयास किये हैं, लेकिन उनके शासनमें देशमें यदि हिन्दीको राजभाषा एवं राष्ट्रभाषाके रूपमें प्रतिष्ठापित नहीं किया जा सका तो भविष्यमें इसकी उपेक्षाके बादल घनघोर ही होंगे, यह एक दिवास्वप्न बनकर रह जायेगा। हालमें कर्नाटक एवं तमिलनाडुमें हिन्दीविरोधकी स्थितियां उग्र बनी। हिन्दीका हर दृष्टिसे इतना महत्व होते हुए भी दक्षिण भारतमें इसकी इतनी उपेक्षा क्यों। क्षेत्रीय भाषाके नामपर हिन्दीकी अवमानना एवं उपेक्षाके दृश्य उभरते रहे हैं, लेकिन प्रश्न है कि हिन्दीको इन जटिल स्थितियोंमें कैसे राष्ट्रीय गौरव प्राप्त होगा। भाषायी संकीर्णता न राष्ट्रीय एकताके हितमें है और न ही प्रान्तके हितमें। प्रान्तीय भाषाके प्रेमको इतना उभार देना, जिससे राष्ट्रीय भाषाके साथ टकराहट पैदा हो जाये, यह देशके लिए उचित कैसे हो सकता है। दरअसल बाजार और रोजगारकी बड़ी संभावनाओंके बीच हिन्दी विरोधकी राजनीतिको अब उतना महत्व नहीं मिलता, क्योंकि लोग हिन्दीकी ताकतको समझते हैं। पहलेकी तरह उन्हें हिन्दी विरोधके नामपर बरगलाया नहीं जा सकता। हिन्दी भाषाका मामला भावुकताका नहीं, ठोस यथार्थका है, राष्ट्रीयताका है। हिन्दी विश्वकी एक प्राचीन, समृद्ध तथा महान भाषा होनेके साथ ही हमारी राजभाषा भी है, यह हमारे अस्तित्व एवं अस्मिताकी भी प्रतीक है, यह हमारी राष्ट्रीयता एवं संस्कृतिकी भी प्रतीक है। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृतिसे आक्सीजन लेनेवाले दल एवं नेता भी अंग्रेजीमें दहाड़ते देखे गये हैं। राजनेता बात हिन्दीकी करते हैं, परन्तु उनका दिमाग अंग्रेजीपरस्त है, क्या यह अन्तर्विरोध नहीं है। हिन्दीको वोट मांगने और अंग्रेजीको राज करनेकी भाषा बनाना हमारी राष्ट्रीयताका अपमान नहीं हैं। कुछ लोगोंकी संकीर्ण मानसिकता है कि केन्द्रमें राजनीतिक सक्रियताके लिए अंग्रेजी जरूरी है। महात्मा गांधीने सही कहा था कि राष्ट्र भाषाके बिना राष्ट्र गूंगा है। यह कैसी विडम्बना है कि जिस भाषाको कश्मीरसे कन्याकुमारीतक सारे भारतमें समझा जाता हो, उसकी घोर उपेक्षा हो रही है, हिन्दी दिवसपर इन त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण स्थितिको नरेन्द्र मोदी सरकार कुछ ठोस संकल्पों एवं अनूठे प्रयोगोंसे दूर करनेके लिए प्रतिबद्ध हो, हिन्दीको मूल्यवान अधिमान दिया जाये। ऐसा होना हमारी सांस्कृतिक परतंत्रतासे मुक्तिका एक नया इतिहास होना।

भाषा और राजनीतिको हृदयसे हटायें

बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा लिखी अंतरराष्ट्रीय ख्यातिकी कविता वंदे मातरम्के एक हिस्सेको संविधान सभाने राष्ट्रगीत घोषित किया था। परन्तु भारतको आजादी मिलनेके बाद नये सत्ताधीश राष्ट्रवादसे पृथक हो गये।

❑ **हृदयनारायण दीक्षित**

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सौ बरसका होने जा रहा है। संघ संप्रति दुनियाका सबसे बड़ा स्वयंसेवी संघटन है। दुनियाका कोई भी देश ऐसा स्वयंसेवी संघटन नहीं बना पाया। डा. हेडगेवारने इसकी स्थापना विजयदशमी (सन् १९२५) के दिनकी थी। तबसे अब तक हजारों झंझावात झेलते हुए संघ लगातार सक्रिय है। संघ की कार्य पद्धति विशिष्ट है इसके बारेमें कम लोग जानते होंगे। कई स्वयंभू विद्वान संघको ब्रेनवाश कर देनेवाला संघटन मानते हैं। कई इसे सांप्रदायिक भी कहते हैं। केवल कहते ही नहीं संघका विरोध करनेके लिए हिन्दू विरोधी तमाम घटनाओंमें संघकी साजिश बताते हैं, लेकिन संघ अपने सेवा कार्योंमें संलग्न रहता है। सो डा. हेडगेवार द्वारा रोपा गया बीज अब विराट वृक्ष बन गया है। संघ और भाजपाके रिश्तोंपर बहसें चलती हैं। तब भाजपाका नाम जनसंघ था। देशकी राजनीतिमें तुष्टीकरण था। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियोंके दबावमें ब्रिटिश प्रधान मंत्री एटलीने भारतीय स्वाधीनताकी घोषणा (२०-२-१९४७) की। मुस्लिम लीगकी अलग मुल्ककी मांगपर युद्ध जैसी आक्रामकता थी। कट्टरपंथी अलगाववादको तुष्टीकरणका पुष्टाहार मिला। देश बंट गया। हजारों हिन्दू मारे गये। महात्मा गांधीकी भी हत्या हुई। संघपर प्रतिबंध लगा। पाकिस्तानी कबाइली हमला (१९४८) हुआ। तत्कालीन राजनीतिक दल एवं नेता राष्ट्रवादसे दूर थे। हिन्दुओंके मर्मसे दूर थे। एक राष्ट्रवादी दलकी आवश्यकता थी। श्री गुरुजीकी प्रेरणासे भारतीय जनसंघकी स्थापना (१९५१) हुई। जम्मू-कश्मीरके दो निशान, दो प्रधान, दो विधानका विरोध, गोवध निषेध और समान नागरिक कानून जैसे राष्ट्रवादी मुद्दे गरमाये। सरसंघचालक गुरु जीने गोवध निषेध एवं हिन्दू श्रद्धा स्थानको नष्ट करनेकी प्रवृत्तिपर लिखते १९५२) हुए कहा 'गाय अनादि कालसे आराध्य है। समाज विजेताके उन्मादमें पराजित जातिको अपमानित करते हुए श्रद्धा स्थानोंको नष्ट करना, धन, मान लूटना, मानो विजय आनन्द लेना है।' तिब्बतपर चीनी कब्जा हुआ गुरु जीने इसे हृदय विदारक (१८ मई १९५९) बताया। भारतपर चीनका हमला १९६२ में हुआ था। तत्कालीन सरसंघचालकने दिल्लीमें कहा था 'सेनाके लोगोंको प्रोत्साहन देना चाहिए। उनके परिवारोंकी सहायता करनी चाहिए। जाति, भाषा और राजनीति सहित सभी मतभेदोंको हृदयसे हटायें। हमारा समूचा राष्ट्र और उसके सामने खड़ा शत्रु, केवल इतना ही ध्यानमें रखें।' संघ चीन युद्धके दौरान सरकारके साथ था। राजनीतिक दलों एवं संघके ध्येय एवं लक्ष्योंमें भी अंतर है। संघकी दृष्टिमें पृथ्वी माता है। भारत माता है। संघके लोग इसी सेवामें नि:स्वार्थ भावसे जुटे हैं। संघके स्वयंसेवकोंने स्वाधीनता संग्राममें हिस्सा लिया था। लेकिन राहुल गांधीने संघके सम्बंधमें अपनी समझमें एक मजेदार टिप्पणी की है। उनकी इस टिप्पणीकी खासी चर्चा है। उन्होंने कहा है कि 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ मतों एवं भाषाओंको कमतर आंकता है। राहुल गांधीकी टिप्पणी निराधार है। राहुल गांधीने कुछ समय पहले संघको समझनेका प्रयास किया था। उन्होंने कहा था कि संघसे सीधी लड़ाई लड़नेके लिए उपनिषद और गीता पढ़ेंगे। आलोचना बुरी नहीं होती। प्रत्येक व्यक्ति और संघटनको आलोचनाका अधिकार है। लेकिन संघ कार्य पारदर्शी है। कह सकते हैं कि संघ एक ओपन यूनिवर्सिटी है। राष्ट्रका सर्वांगीण विकास एवं अभ्युदयके लिए संघके स्वयंसेवक सदा तत्पर रहते हैं। नासमझीमें अनेक सुशिक्षित विद्वान भी संघके आलोचक हैं। तुष्टीकरणवादी वोट बैंकके कारण संघकी निंदा करते हैं। राष्ट्रीय स्तर के एक वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंहसे द्वितीय सरसंघचालक म.स. गोलवलकरकी भेंट हुई थी। उनसे मिलनेके बाद खुशवंत सिंहने लिखा था, 'कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बिना समझे ही हम घृणा करते हैं। ऐसे लोगोंकी मेरी सूचीमें गुरु गोलवलकर प्रथम थे।' खुशवंत सिंहने 'आरएसएस एंड हिन्दू मिलिटरिज्म' के हवालेसे कई सवाल पूछे। ईसाइयोंके सम्बंधमें पूछे गये सवालके जवाबमें गुरु जीने कहा, 'धर्मांतरित करनेके तरीकोंके अलावा हमारा उनसे कोई विरोध नहीं है।' मुसलमानोंके बारेमें कहा कि 'मुसलमानोंको भारतीयताके प्रवाहमें मिल जाना चाहिए।' ईरानी मूलके पत्रकार डा. जिलानीसे कहा, पाकिस्तानने पाणिनिकी ५०००वीं जयंती मनायी है। पाणिनि पूर्वज हैं। भारतके मुसलमान पाणिनिए व्यास और वाल्मीकि आदिको महान पूर्वज क्यों नहीं मानतेघ् भारतीय राष्ट्रवाद प्राचीन धारणा है। यहां राष्ट्र संस्कृति आधारित है। इस राष्ट्रवादके स्रोत वैदिक वांगमयमें हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेदमें राष्ट्र शब्दकी आवृत्ति कई बार हुई है। स्वयंभू विद्वान स्वाधीनता संग्रामके दौरान विकसित राष्ट्रभावको अलग मानते हैं और सनातन राष्ट्रवादको कमतर। स्वाधीनता आन्दोलन हर तरहसे प्रत्येक भारतवासीको प्रिय है। स्वाधीनता आन्दोलनके आदर्श एवं मूल्य आदर योग्य हैं। दुर्भाग्यसे भारतको आजादी मिलनेके बाद नये सत्ताधीश राष्ट्रवादसे पृथक हो गये। बंकिम चन्द्र चटर्जी द्वारा लिखी गयी अंतरराष्ट्रीय ख्यातिकी कविता 'वंदे मातरम' के एक हिस्सेको संविधान सभाने राष्ट्रगीत घोषित किया था। लेकिन स्वाधीनताके बाद अनेक पंथिक मजहबी संस्थाओंने वंदे मातरम गानेसे इनकार किया, लेकिन संघके कार्यक्रमोंमें वंदे मातरम प्रशंसापूर्वक गाया जाता है। आज भारतके कोने-कोनेमें वंदे मातरमका गान होता है। वंदे मातरम गानेसे इनकार करनेवाले संघटन अकड़ते रहे। संघने सबको साथ लेते हुए भारतीय राष्ट्रवादको सर्वोपरि बताया है। सांस्कृतिक प्रतीकोंको सम्मान देनेकी परम्परा संघने यत्र तत्र सर्वत्र प्रसारित की। संघकी सांघटनिक क्षमता बढ़ी है। उच्च शिक्षित युवा संघ कार्यको राष्ट्रीय दायित्व मानते हैं। वे उच्च शिक्षासे प्राप्त अवसरोंकी चिन्ता नहीं करते। वे घर परिवार छोड़कर संघ कार्यमें जुटते हैं। वे संघका अनुशासन मानते हैं और देशके लिए काम करते हैं। संघ राजनीतिक दलकी तरह मेम्बरी नहीं कराता। संघके पास सैकड़ों पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं। दुनियाका कोई भी देश ऐसे सुशिक्षित समर्पित कार्यकर्ताओंका स्वयंसेवी संघटन नहीं बना पाया। आनेवाली विजयादशमीके दिन संघ सौ बरसका हो जायगा। संघ शाखापर प्रार्थनामें लक्ष्य सुस्पष्ट हैं। परं वैभवं नेतुमेतत् स्वराष्ट्रं, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्। यहां राष्ट्रका परम वैभव ही संघका लक्ष्य है। संघके कार्यकर्ता सुबह उठते ही भारत भक्ति स्तोत्र पढ़ते हैं। इस स्तोत्रमें अनेक महापुरुषोंके मध्य डाक्टर अम्बेडकरको भी प्रणाम किया गया है। जाति-पाति, पथ, मत और मजहबसे भिन्न राष्ट्रकी सर्वोपरिता संघकी मान्यता है। संघ कार्य देशके सनातन विचार प्रवाहका हिस्सा है। राष्ट्रवादसे ओत-प्रोत कार्यकर्ताओंका निर्माण होता रहता है। संघ राष्ट्रवादी संस्कार देनेके काममें संलग्न है। संघके कार्यकर्ता नि:स्वार्थ भावसे काम करते हैं।

लघुतासे प्रभुता मिले

❑ **सलिल पांडेय**

श्रीमद्भगवतगीतामें भगवान श्रीकृष्णने पीपल वृक्षको भी अपना स्वरूप बताया है। पीपल ऐसा वृक्ष है जिसके बीजोंमें इतनी कोमलता होती है कि हवाओं, पक्षियों, कीड़ों तथा जानवरोंके जरिये चट्टानों एवं दीवारोंमें पेड़ बनकर उगने लगता है। रामचरित मानसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदासने तो 'पीपर पात सरिस मन डोला' चौपाईमें इस वृक्षको इतना संवेदनशील कहा कि जिस प्रकार बहुत ही हल्की भी हवासे पीपलके पत्ते डोलने लगते हैं, उसी तरह मन भी बहुत हल्की परिस्थितियोंमें डोलने लगता है। यानी थोड़ी-सी अनुकूल परिस्थिति आती है तो मन प्रसन्न होने लगता है और विपरीत परिस्थितियां आनेपर बोझिल होने लगता है। जब जीवनमें सकारात्मक रवैया अपनाया जाता है तब स्वाभाविक रूपसे प्रसन्नता मिलती है और नकारात्मक रूप अपनानेपर कठिनाइयां आती हैं इस सम्बंधमें संत कवि कबीर भी 'लघुतासे प्रभुता मिले प्रभुतासे प्रभु दूरी, चींटी शककर लै चलिय हाथीके सिर धूरी' दोहेमें विनम्रताका ही उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जब मनमें अहंकार उत्पन्न होता है तब आन्तरिक तंत्रमें विकृतियां भी उत्पन्न होती हैं। जो तन-मनपर बुरा प्रभाव डालती हैं। ऐसा ही एक प्रसंग दैत्योंके राजा बलिकी कथा है। राजा बलिको दानका अहंकार हो गया। उसके अहंकारको खत्म करनेके लिए भगवान विष्णुने लघु रूप धारण कर बलिसे आध्यात्मिक उपासनाके लिए तीन पग भूमि ले ली। जब बलिने तीन पग जमीन दे दिया तो पहले पगमें पूरी धरती, दूसरेमें आकाशके बाद तीसरा पग राजा बलिके सिरपर वामनने रख दिया। भगवान विष्णु रूप वामनके पैर रखते राजा बलिका अहंकार पाताल लोकमें चला गया। चूंकि वामन विष्णुके अवतार थे। दैत्योंके गुरु शुक्राचार्यके मना करनेके बावजूद बलिने दान देनेका वचन भगवानको दे दिया। वामन भगवानके तीन पग भूमि मांगनेका लौकिक अर्थ यही है कि मनुष्य यदि जीवनमें सात्विक जनोंके साथ रहता है तो वह उन्नत अवस्थामें पहुंचता है तथा सदाचारका जीवन जीता है तो विपरीत परिस्थितियोंसे दूर रहता हैं जबकि अंतर्जगतकी आवाजकी उपेक्षा नहीं करता तब वह वाह्य आकर्षणोंकी बुराइयोंसे बचता है। वामनके तीसरे पगको बलिके सिरपर रखनेको आधा पग ही कहा गया है। यानी ढाई पग। विद्वानोंने ढाई अक्षर प्रेमकी महत्ताका उल्लेख किया है। भगवान रामका नाम भी ढाई अक्षरका है। इस प्रकार जब मस्तिष्कमें विनम्रताका प्रभाव रहता है तो जीवन यशस्वी रहता है।

जीवनशैलीमें बदलावसे हृदय रहेगा स्वस्थ

❑ **रजनीश कपूर**

दिल-ए-नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्दकी दवा क्या है। मशहूर शायर मिर्जा गालिबकी यह गजल काव्यात्मक और रूपकात्मक रूपसे जीवनके शाश्वत एवं मौलिक प्रश्न पूछती है। गालिबकी यह प्रसिद्ध गजल वास्तविकताओंको काव्यात्मक रूपसे व्यक्त करनेकी कुशलताका एक बेहतरीन उदाहरण है। परन्तु आज हम जिस विषयको उठा रहे हैं वह इससे भी ज्यादा गम्भीर है। हृदय रोगसे संबंधित बीमारियों और उनसे होनेवाली जवान मौतोंके बढ़ते हुए आंकड़े हम सभीके मनमें कुछ अहम सवाल पैदा कर रहे हैं। कुछ लोग इसे कोविडके लम्बे असरसे भी जोड़ रहे हैं परन्तु कोविडके अलावा भी अन्य कारण हैं जो अल्पायुमें हृदय रोगको बढ़ावा दे रहे हैं। ज्यादातर देखा गया है कि दिलका दौरा या हार्ट अटैक ६० वर्ष या उससे अधिक उम्रके लोगोंको आता है। दिलका दौरा पड़नेके और कारणोंमेंसे प्रमुख है मधुमेह या शुगरके मरीज और ब्लड प्रैशरके मरीज। इन मरीजोंमें हार्ट अटैककी संभावना काफी अधिक होती है। इसके साथ ही धूम्रपान करनेवाले व्यक्ति भी दिलके मरीज कब बन जाते हैं इसका पता नहीं चलता। इसका कारण यह है कि धूम्रपान करनेसे दिलका दौरा पड़नेकी संभावन तीन गुना बढ़ जाती है। धूम्रपान करनेवाले व्यक्तिको जब पता चलता है कि वह दिलका मरीज बन गया है तबतक काफी देर हो जाती है। ४० वर्षकी आयु वर्गके लोगोंको दिलका दौरा पड़ना अधिक धूम्रपान करनेकी वजहसे होता है। साथ ही जो व्यक्ति तनावकी जिन्दगी जीते हैं, नियमित व्यायाम नहीं करते, बेवजह और हर समय जंक फूडका सेवन करते हैं, वे भी इस जानलेवा बीमारीकी चपेटमें आ जाते हैं। क्या कभी आपने सुना है किसी हट्टे-कट्टे व्यक्तिको अचानक दिलका दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गयी। पिछले कुछ वर्षोंसे ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं जहां व्यक्ति अपने रोजमर्राके काम या आरामके समय अचानक बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गयी। मृत्युका कारण दिलका दौरा। कुछ लोग इसे चीनसे आये कोरोनाके वायरसका साइड इफैक्ट बता रहे हैं। एक शोधके अनुसार अमेरिकामें कोविडसे ठीक हुए व्यक्तियोंमें बीस प्रकारके हृदय रोगके लक्षण पाये गये। इनमें उन लोगोंके मुकाबले, जिन्हें कोविड नहीं हुआ, हृदय गति रुक जाने या हार्ट फेल होनेकी संभावना ७२ फीसदी अधिक पायी गयी। इनमें औरोंके मुकाबले स्ट्रोक आनेकी संभावना भी १७ प्रतिशत अधिक पायी गयी। हालमें एमरजैंसी मेडिकल रिसर्च इंस्टीच्यूट (ईएमआरआई) की एक रिपोर्ट सामने आयी है। जिसके नतीजे कहते हैं कि हार्ट अटैकवाले ज्यादातर लोगोंकी उम्र ५० सालसे कम है। यदि आप सोच रहे हैं कि इस सबके पीछे आपकी जीवनशैली है तो ऐसा सही है। परन्तु आपकी जीवनशैलीमें ऐसी कौन-सी कमी है जो हार्ट अटैकका कारण बन रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका दोषी पाम ऑयल है। इतना ही नहीं, यह पाम ऑयल मदिरापान और धूम्रपानसे कहीं अधिक खतरनाक है। सोशल मीडियामें मुंबईके जगजीवन राम अस्पतालके डाक्टर पीके समांतरायका एक संदेश काफी चर्चामें है। वे कहते हैं कि दुनियामें भारत पाम ऑयलका सबसे बड़ा आयातक है। हमारे देशमें पाम ऑयल माफिया बहुत ताकतवर है। इनके कारण हमारे बच्चे, जो देशका भविष्य हैं, एक बड़े खतरेमें जी रहे हैं। आज हमारे देशमें पाम ऑयलके बिना कोई फास्ट फूड नहीं मिलता। यदि आप किरानेकी दुकानपर जाते हैं और पाम ऑयलके बिना बच्चोंके लिए कोई खाद्य पदार्थ लेनेका प्रयास करें तो आप सफल नहीं होंगे। देशमें ज्यादातर बिस्किट और चॉकलेट भी बिना पाम ऑयलके नहीं बनते। डा. समांतराय आगे कहते हैं कि हमें विज्ञापनोंके द्वारा यह विश्वास दिलाया जाता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ स्वस्थ हैं। लेकिन हम जानलेवा पाम ऑयल या पामिटिक एसिडके बारेमें कभी नहीं जानते थे। लेज जैसी बड़ी कम्पनियां पश्चिमी देशोंमें अलग तेल बेचती हैं और भारतमें पाम ऑयलका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करती हैं, क्योंकि यह सस्ता है। जब भी हमारा बच्चा पाम ऑयल युक्त उत्पाद खाता है तो मस्तिष्क अनुचित व्यवहार करता है और हृदयके आसपास और हृदयमें वसा स्रावित करनेका संकेत देता है। जिससे बहुत कम उम्रमें मधुमेह हो जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरमने अनुमान लगाया है कि कम उम्रमें मरनेवाले ५० प्रतिशत लोग मधुमेह और हृदय रोगसे मरेंगे। समय-समयपर होनेवाले शोध भी बताते हैं कि रेडी-टू-ईट और पैकेज्ड फूड्समें अकसर पाम ऑयल होता है, जो हमारी सेहतको कई नुकसान पहुंचा सकता है। पाम ऑयलमें सैचुरेटेड फैट काफी मात्रामें पायी जाती है। यह बॉडीमें कोलैस्ट्रॉलका स्तर बढ़ाता है। इसके कारण दिलकी बीमारियां होनेका खतरा बना रहता है। साल २०२२ में भारतमें पाम ऑयलकी खपत आठ मिलियन मीट्रिक टनसे अधिक हुई थी। यदि हमें अपने हृदयको स्वस्थ रखना है तो अपनी जीवनशैलीमें उचित सुधार लाने होंगे और अपने बच्चोंको भी स्वस्थ जीवनशैली अपनानेके लिए प्रेरित करना होगा, वरना भारतमें हृदय रोगके आंकड़े बढ़ते ही रहेंगे।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

छात्र समुदाय का प्रतिरोध उचित

किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए राजनीतिक विचार-विमर्श में भाग ना लेने की शर्त कैसे थोपी जा सकती है? किसी विरोध में भाग ना लेने का वचन दाखिले से पहले ही कैसे लिया जा सकता है? भारत में अन्य स्थलों की तरह ही शिक्षा संस्थानों में भी असहमति या विरोध जताना जोखिम भरा हो चुका है, यह आम तुजर्बा है। लेकिन पूर्व शर्त के तौर पर दाखिले से पहले इस पर हामी भरवाना एक नई घटना के रूप में सामने आया है। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि अभी तक जो चलन व्यवहार में था, उसे अब लिखित एवं औपचारिक रूप दिया जा रहा है। खबर मुंबई स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टिस) से है। वहां लागू नए हॉनर कोड के तहत छात्रों को दाखिले से पहले यह वचन देना होगा कि वे किसी "राजनीतिक और व्यवस्था विरोधी गतिविधियों तथा देशभक्ति विहीन चर्चाओं" आदि में हिस्सा नहीं लेंगे। वे ऐसे प्रदर्शनों या धरना आदि में भाग नहीं लेंगे, जिनसे संस्थान के "शैक्षिक वातावरण में रुकावट" पड़ती हो। हॉनर कोड पर दस्तखत की रवायत 2017 में शुरू की गई थी, जिसमें अब नई शर्तें जोड़ी गई हैं। टिस एक मानित (डीम्ड) विश्वविद्यालय है। इसकी फंडिंग का एक बड़ा हिस्सा टाटा ग्रुप से आता है। इस संस्थान ने भारत में जातीय एवं अन्य अस्तमिता आधारित विमर्श को फैलाने में अहम भूमिका निभाई है। इससे जनमत के एक बड़े हिस्से में यह धारणा बनी कि यह प्रगतिशील विचारों का वाहक संस्थान है। मगर देश में बदले माहौल का असर वहां भी हुआ। हाल के वर्षों ऐसे कई घटनाएं हुई हैं, जिनसे पुरानी धारणा को चोट पहुंची। बहरहाल, ये सवाल सिर्फ किसी संस्थान विशेष का नहीं है। मुद्दा यह है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी उच्च शिक्षा संस्थान में दाखिले के लिए राजनीतिक विचार-विमर्श में भाग ना लेने की शर्त कैसे थोपी जा सकती है? साथ ही किसी विरोध में भाग ना लेने का वचन दाखिले से पहले ही कैसे लिया जा सकता है? आखिर किसी भी संस्थान में, कभी कोई ऐसा मसला खड़ा हो सकता है, जिसका विरोध करना छात्र जरूरी समझें। विरोध की हर गतिविधि से सामान्य वातावरण में बाधा आती है। इसलिए हॉनर कोड की नई शर्तों के प्रति छात्र समुदाय का प्रतिरोध उचित है। बेहतर होगा कि प्रशासन इन्हें तुरंत वापस ले ले।

राजनैतिक दलों में परस्पर सम्मान क्यों नहीं?

पिछले दिन विनेश फोगट और पूनिया के कांग्रेस में शमिल होने पर भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पिछले साल पहलवानों का आन्दोलन बृजभूषण के खिलाफ कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था । पहले भी खिलाड़ियों ने राजनैतिक दलों की सदस्यता ली है । गौतम गंभीर को सन् 2019 में दिल्ली से लोकसभा के लिए चुनाव लड़वाया गया था । राजवर्धन तो मंत्री भी रहे हैं । अनेक विभिन्न खेलों के खिलाड़ी किसी खास राजनैतिक दल के पक्ष में वक्तव्य दे चुके हैं । ज्यादातर खिलाड़ी सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं । इससे उन्हें सुविधा मिलती है । यूं मोदी जी के कार्यकाल में खिलाडि़यों को काफी प्रोत्साहन मिला है । अब जीतने वाले खिलाडि़यों को करोड़ों में ईनाम मिलता है । विनेश फोगट के मन की टीस को कौन समझ सकता है । आज भाजपा, कांग्रेस तथा लेफ्ट पश्चिमबंगाल में हुये टेप काण्ड के बाद ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं । क्या रेप घटना मात्र पश्चिम बंगाल में होती है? रोज तो किसी न किसी प्रदेश में ऐसी घटनाओं की खबर आती रहती है । भाजपा के एक मंत्री जो अपने को संत भी कहते थे, ऐसे आरोप सिद्ध होने के बाद त्यागपत्र दे गये । कुश्ती संघ के तत्कालीन अध्यक्ष के खिलाफ इन महिला पहलवानों ने घृणित आरोप लगाये हैं । तब इन प्रदर्शनकारियों के साथ कोई नहीं आया । पुलिस ने भी इनके साथ अन्याय किया । तो क्या इसका आक्रोश इन महिला खिलाडि़यों को नहीं होना चाहिए ? बृजभूषण का असर कम से कम पांच-छः लोकसभा सीटों पर है तो ये अब भी भाजपा के सदस्य हैं । असल में भारत में किसी भी राजनैतिक दल में आंतरिक स्वराज्य नहीं है । शायद सी.पी.एम. या सी.पी.आई. में हो । बी.एस.पी. में मायावती सर्वेसर्वा हैं । कांग्रेस में सोनिया गांधी सर्वेसर्वा हैं । खडग़े तो नाममात्र के अध्यक्ष हैं । किसी मीटिंग में बीच की कुर्सी पर राहुल गांधी बैठते हैं । सपा में अखिलेश यादव सर्वेसर्वा हैं । लाल प्रसाद प्रसाद अपनी पार्टी के सर्वेसर्वा हैं । जे.डी.यू. में नितीश कुमार शिवसेना की एक गुट के सर्वेसर्वा शिंदे हैं । दूसरे गुट के उद्धव ठाकरे । सभी लोग परिवारवाद की आलोचना करते हैं परन्तु तृणमूल कांग्रेस में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक की चलती है । उद्धव ठाकरे का बेटा मंत्री रहा है । अभी हरियाणा में वहां कम से कम आठ-दस उम्मीदवार वहां के प्रभावशाली नेताओं के पुत्र, पुत्री, माता या अन्य रिश्तेदार हैं । अब तो पार्टी में दरी बिछाने वाले कहने लगे हैं कि भाजपा में भी अब पैराशूट प्रत्याशी उतारे जाते हैं यानि दूसरी पार्टी से आये प्रत्याशी । भाजपा में अंतिम निर्णय मोदी जी का ही है । गांधी जी के भाषणों की एक किताब नवजीवन प्रेस ने छापी है । उसमें एक जगह गांधी जी पूछते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष तो खादी पहनता है और तीसरे दर्जे में सफर करता है परन्तु कुछ प्रांतों के प्रधानमंत्री (तब मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे) विलायती कपड़े पहनते हैं ।

भारत के मार्च 2026 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के संकेत

आरती कुमारी

भारत के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 3.93 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। जबकि, जापान के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.21 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है एवं जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद का आकार 4.59 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर का है। भारत की आर्थिक विकास दर लगभग 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष बनी हुई है और जापान एवं जर्मनी की आर्थिक विकास दर लगभग स्थिर है अथवा इसके ऋणात्मक रहने की भी प्रबल सम्भावना है। इस दृष्टि से मार्च 2025 तक भारत जापान की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा एवं मार्च 2026 तक भारत जर्मनी की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हाल ही के समय में जर्मनी एवं जापान की अर्थव्यवस्थाओं में विभिन्न प्रकार की समस्याएं दृष्टिगोचर हैं, जिनके कारण इन दोनों देशों की आर्थिक विकास दर आगे आने वाले वर्षों में विपरीत रूप से प्रभावित रह सकती है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात लगातार 4 दशकों तक जर्मनी पूरे यूरोपीयन यूनियन में तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहा। इस दौरान विनिर्माण इकाईयों के बल पर जर्मनी ने अपने आप को विश्व में विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित कर लिया था एवं विभिन्न उत्पादों, विशेष रूप से कार, मशीनरी एवं केमिकल उत्पादों का निर्यात पूरे विश्व को भारी मात्रा में किया जाने लगा था। पिछले 20 वर्षों के दौरान जर्मनी पूरे यूरोपीयन यूनियन के विकास का इंजिन बना हुआ था। चूंकि चीन की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से विकास कर रही थी अतः पिछले 20 वर्षों के दौरान चीन, जर्मनी से लगातार मशीनरी, कार एवं केमिकल पदार्थों का भारी मात्रा में आयात करता रहा है। परंतु, अब परिस्थितियां बदल रही हैं क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था भी हिचकोले खाने लगी है और चीन ने विभिन्न उत्पादों का जर्मनी से आयात कम कर दिया है। अतः अब जर्मनी अर्थव्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बदली हुई परिस्थितियों में चीन, जर्मनी में निर्मित विभिन्न उत्पादों का आयात करने के स्थान पर वह जर्मनी का प्रतिस्पर्धी बन गया है और इन्हीं उत्पादों का निर्यात करने लगा है। दूसरे, पिछले लगभग 2 वर्षों से रूस ने भी ऊर्जा की आपूर्ति यूरोप के देशों को रोक दी है, रूस द्वारा निर्यात की जाने वाली इस ऊर्जा का जर्मनी ही सबसे अधिक लाभ उठाता रहा है। तीसरे, जर्मनी में प्रौढ़ नागरिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और एक अनुमान के अनुसार जर्मनी में आगे आने वाले एक वर्ष से कार्यकारी जनसंख्या में प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की कमी आने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इससे उपभोक्ता खर्च पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। चौथे, जर्मनी में नागरिकों की उत्पादकता भी कम हो रही है। जर्मनी में प्रत्येक नागरिक वर्ष भर में केवल 1300 घंटे का कार्य करता है जबकि OECD देशों में यह औसत 1700 घंटे का है। पांचवे, यूरोपीयन यूनियन में वर्ष 2035 में पेट्रोल एवं डीजल पर चलने वाले चार पहिया वाहनों के उत्पादन पर रोक लगाई जा सकती है जबकि इन कारों का निर्माण ही जर्मनी में अधिक मात्रा में होता है तथा जर्मनी की कार निर्माता कम्पनियों ने बिजली पर चलने वाले वाहनों के निर्माण पर अभी बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया है। साथ ही, जर्मनी ने नवाचार पर भी कम ध्यान दिया है एवं स्टार्ट अप विकसित करने में बहुत पीछे रहा है आज इन क्षेत्रों में अमेरिका एवं चीन बहुत आगे निकल गए हैं एवं जर्मनी आज अपने आप को असहाय सा महसूस कर रहा है। अतः जर्मनी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव आगे आने वाले लम्बे समय तक चलने की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव भी जर्मनी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है एवं अब पूरे विश्व में गैरवैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। आज प्रत्येक विकसित एवं विकासशील देश अपने पैरों पर खड़ा होकर स्वावलंबी बनना चाहता है। अतः जर्मनी जैसे देशों से मशीनरी एवं कारों का निर्यात कम हो रहा है साथ ही इन उत्पादों की तकनीकि भी लगातार बदल रही है जिसे जर्मनी की विनिर्माण इकाईयां उपलब्ध कराने में असफल सिद्ध हुई हैं। पिछले 5 वर्षों के दौरान जर्मनी अर्थव्यवस्था में विकास दर हासिल नहीं की जा सकी है। जर्मनी में सितम्बर 2023 माह में वोक्सवेगन (Volkswagen) कम्पनी ने अपनी दो विनिर्माण इकाईयों को बंद करने का निर्णय लिया है। यह कम्पनी जर्मनी में 3 लाख से अधिक रोजगार के प्रत्यक्ष अवसर उपलब्ध कराती है तथा अन्य लाखों नागरिकों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती हैं। इस कम्पनी ने जर्मनी में अपनी विनिर्माण इकाईयों में उत्पादन कार्य को काफी हद्द तक कम कर दिया है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से इस कम्पनी के उत्पादों की बिक्री लगातार कम हो रही है। पिछले 5 वर्षों के दौरान इस कम्पनी की बाजार कीमत आधे से भी कम रह गई है। इस कम्पनी की उत्पादन इकाईयों में चार पहिया वाहनों का निर्माण किया जाता रहा है परंतु अब इन उत्पादन इकाईयों में बिजली पर चलने वाली कारों के निर्माण में बहुत परेशानी आ रही है। बिजली पर चलने वाली कारों का जर्मनी में उत्पादन बढ़ाने के स्थान पर चीन से इन कारों का बहुत भारी मात्रा में आयात किया जा रहा है। अपनी आर्थिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए जर्मनी ने यूक्रेन को टैंकों की आपूर्ति भी रोक दी है। दरअसल कोरोना महामारी के बाद से ही, वर्ष 2020 के बाद से, जर्मनी की अर्थव्यवस्था अभी तक सही तरीके से पूरे तौर पर उबर ही नहीं सकी है। एक अनुमान के अनुसार जर्मनी अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2024 में भी कम होने जा रहा है, यह वर्ष 2023 में भी कम हुआ था और इसके वर्ष 2025 में भी सुधरने की सम्भावना कम ही दिखाई दे रही है। जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2024 के दौरान 0.1 प्रतिशत की कमी की सम्भावना व्यक्त की जा रही है। बेरोजगारी की दर भी 6.1 प्रतिशत के स्तर तक ऊपर जा सकती है। जर्मनी अर्थव्यवस्था केवल चक्रीय ही नहीं बल्कि संरचनात्मक क्षेत्र में भी समस्याओं का सामना कर रही है। इसमें सुधार की कोई सम्भावना आने वाले समय में नहीं दिख रही है। हालांकि यूरोपीयन यूनियन में जर्मनी की अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है परंतु फिर भी भारत, उक्त कारणों के चलते, जर्मनी की अर्थव्यवस्था को मार्च 2026 तक पीछे छोड़ देगा, ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है। इसी प्रकार, पिछले लगभग 30 वर्षों के दौरान जापान की अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति, ब्याज दरें एवं येन की कीमत स्थिर रही है। परंतु, हाल ही के समय में येन का अंतरराष्ट्रीय बाजार में अवमूल्यन हो रहा है एवं यह 160 येन प्रति अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गया है, जो वर्ष 2009 के बाद से कभी नहीं रहा है। जापान की अर्थव्यवस्था कई उत्पादों के आयात पर निर्भर करती है। जापान अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं का 90 प्रतिशत एवं खाद्य सामग्री का 60 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। जापान द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने से जापान में भी आयातित मुद्रा स्फीति की दर बढ़ रही है जो पिछले एक दशक के दौरान लगातार स्थिर रही है। वर्ष 1955 से वर्ष 1990 के बीच जापान की अर्थव्यवस्था औसत 6.8 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आगे बढ़ती रही। वर्ष 1990 तक जापान का स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ता रहा एवं अचानक वर्ष 1990 में यह बुलबुला फट पढ़ा और जापान में आवासीय मकानों की कीमत 50 प्रतिशत तक गिर गई एवं व्यावसायिक मकानों की कीमत 85 प्रतिशत तक गिर गई। जापान के पूंजी बाजार में निक्के स्टॉक सूचकांक भी 75 प्रतिशत तक गिर गया। जापान की अर्थव्यवस्था में तेजी के दौरान आस्तियों की बढ़ी हुई कीमत पर ऋण लिए गए थे परंतु जैसे ही इन आस्तियों की कीमत बाजार में कम हुई, नागरिकों को ऋणराशि की किश्तें चुकाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और इससे भी जापान में आर्थिक समस्याएं बढ़ी थी। दिवालिया होने वाले नागरिकों की संख्या बढ़ी और देश में अपस्फीति की समस्या प्रारम्भ हो गई थी। जापान की सरकार ने आर्थिक तंत्र में नई मुद्रा की मात्रा बढ़ाई और ब्याज दरों को लगभग शून्य कर दिया। इन समस्त उपायों से भी जापान में आर्थिक समस्याओं का हल नहीं निकल सका। वर्ष 2022 में जापान में भी विश्व के अन्य देशों की तरह मुद्रा स्फीति बढ़ने लगी थी परंतु जापान ने ब्याज दरों को नहीं बढ़ाया। अब कुल मिलाकर जापान अपनी आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है एवं वहां पर आगे आने वाले समय में आर्थिक विकास के पटरी पर आने की सम्भावना कम ही नजर आती है अतः भारत जापान की अर्थव्यवस्था को मार्च 2025 तक पीछे छोड़कर विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।

क्षमा आत्मा का स्वभाव है ('क्षमा वीरस्य भूषणम')

अनादिकाल से जैन आगमानुसार दशलक्षण धर्म का समापन क्षमावणी पर्व के द्वारा किया जाता है. जिसमें मुख्यरूप से आपस में एक-दूसरे से वर्ष भर में हुई भूलों के लिए परस्पर हाथ जोडकर मन-वचन-काय से क्षमायाचना की जाती है। एकमात्र हम जैन आगम में ही यह देखते हैं कि एक दूसरे से व्यक्ति आपस में हुई कलुषता के लिए क्षमावाणी पर्व मनाता है। दशलक्षण धर्म का प्रारंभ क्षमा से प्रारंभ होकर क्षमा पर ही समापन होता है। जैनाचार्यों के अनुसार कषाय मनुष्य को अनेक भवों तक नरक और तिर्यंच गति में भ्रमण करवाता है। यदि आपस में चैर-भाव हो जाये, तो उसे 6 माह के अंदर ही हाथ जोड़कर समाप्त कर लीजिए। अन्यथा कोड़ाकोडी सागर वर्ष तक वह कषाय साथ-साथ चलती है। भगवान पार्श्वनाथ और कमठ का जीव दश भव तक चलता हुआ वैर इस बात का उदाहरण है। बंधुओं वैर से वैर कभी भी समाप्त नहीं होता है, जिस प्रकार से अग्नि से अग्नि नहीं समाप्त होती है। कोधरूपी अग्नि को बुझाने के लिए क्षमारूपी जल अवश्य डालना पड़ता है। इसी प्रकार से हम इस दुर्लभ मनुष्य भव में किसी भी प्रकार से वैर को स्थान न देकर हमेशा क्षमा को अपनाए। भारतवर्ष महात्मा और संतों का देश रहा है। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी अपने स्वयं के प्राणघात करने वाले को भी क्षमा प्रदान की। यह साक्षात् क्षमा का एक उदाहरण है। हम देखते हैं कि बच्चा कितनी भी गलती करे लेकिन अंत में मां उसे क्षमा कर देती है। यह सबसे उत्तम उदाहरण है। खम्मामि सव्वजीवाणं, सब्बे जीवा खमंतु मे।
मित्ती मे सव्वभूदेसु, वैरं मज्झं ण केणवि।।3।1
अर्थात् सब जीवों से मैं क्षमा याचना करता हूं। सब जीव मुझे क्षमा करें। यह हमारे जैन साधु प्रतिदिन दिन में 3 बार सामायिक करते हैं। उस सामायिक पाठ में यह बोलते हैं। जैन श्रावक प्रतिदिन मंदिर में जाकर आलोचना पाठ के माध्यम से अपने द्वारा दिनभर में की गई मूलों के लिए जिनेन्द्र प्रभु के आगे क्षमा याचना करता है। जैन शास्त्रों में कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे पाण्डव मुनियों के ऊपर अग्नि जला दी, लेकिन उन्होंने उसको समता परिणामों से स्वीकार किया, न कि कोध करके अपने कोध को प्रगट किया। इसी प्रकार से अनेक मुनियों और संतों के ऊपर उपसर्ग आते हैं, लेकिन यह उस उपसर्ग को सहन करते हुए सभी को क्षमा कर देते हैं। 'क्षमा वीरस्य भूषण' के बारे में आचार्यों ने ग्रंथों में कहा कि क्षमा वीरों का आभूषण है। इसे कायर व्यक्ति नहीं धारण कर सकता है। क्योंकि क्षमा भी वीर पुरुष के पास होती है। कायर व्यक्ति क्षमा जैसे आभूषण को न ग्रहण कर सकता है न दे सकता है। क्षमा आत्मा का गुण है। यह आत्मा का स्वभाव होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति को यदि कोध आ जाये, तो वह कितनी भी देर कोध करे, लेकिन अंततोगत्वा उसे अपने स्वभाव में आना पड़ता है और इसी की अपेक्षा यदि हम देखें कि कोई व्यक्ति हंसता है, कितना हंस सकता है। एक समय आता है कि उसे रुककर अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ता है। क्योंकि शांत गुण क्षमा का है और क्षमा आत्मा का गुण है। इसलिए आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्षमावाणी पर्व मनाकर सम्पन्न किया जाता है। जैन साध्वी आर्यिका श्री चंदनामती माताजी द्वारा रचित भजन के माध्यम से कहती है-
क्षमा गुण को मन में धर लो, क्षमा को वाणी में कर लो।
शत्रु-मित्र सबमें समता का, भाव हृदय भर लो।। क्षमा गुण को मन में धर लो। । टेक. ।। मैत्री का हो भाव सभी, प्राणी के प्रति मेरा।
गुणी जनों को देख हृदय, आल्हादित हो मेरा।। वही आल्हाद प्रगट कर लो, कोध वैर भावों को तजकर, मन पावन कर लो।
क्षमा गुण को मन में घर लो।।
सारंगी सिंहशावं स्पृशति सुतधिया नंदिनी व्याघ्र पोतं। मार्जारी हंसबालं प्रणयपरवशा केकिकांता भुजंगीम् ।।
वैराण्याजन्मजातान्यपि गलितमदा जंतवोन्ये त्यजंति।
श्रित्वा साम्यैकरूढं प्रशमितकलुषं योगिनं क्षीणमोहम् ।।
हरिणी सिंह के बच्चे को पुत्र की बुद्धि से स्पर्श करती है, गाय व्याघ्र के बच्चे को दूध पिलाती है, बिल्ली हंसों के बच्चों को प्रीति से लालन करती है एवं मयूरी सर्पों को प्यार करने लगती है। इस प्रकार से जन्मजात भी वैर को क्रूर जंतुगण छोड़ देते हैं। कब ? जबकि वे पापों को शांत करने वाले मोहरहित और समताभाव में परिणत ऐसे योगियों का आश्रय पा लेते हैं अर्थात् ऐसे महामुनियों के प्रभाव से हिंसक पशु अपनी द्वेष भावना छोड़कर आपस में प्रीति करने लगते है। ऐसी शांत भावना का अभ्यास इस क्षमा के अवलंबन से ही होता है। वर्तमान में जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणिनीप्रमुख श्री ज्ञानमती माताजी हमारे बीच में विद्यमान हैं, जो कि दिगम्बर जैन समाज में वर्तमान समय में लगभग 1500 साधु साध्वियां विराजमान हैं, उन सबमें सबसे प्राचीन दीक्षित हैं। 66 वर्ष संयम की साध् ाना के व्यतीत हो चुके हैं। उनका यह कहना है कि क्षमा धर्म को धारण करके हम भव से पार होकर मुक्ति को प्राप्त हो सकते हैं। क्षमा धारण करने वाला व्यक्ति इस भव में भी और पर भव में भी सुख को प्राप्त करता है। कोधी व्यक्ति के पास कोई भी व्यक्ति बैठना नहीं चाहता है, उस व्यक्ति से बात करना नहीं चाहता है। उससे कोई संबंध नहीं करना चाहता है और परस्पर व्यवहार में भी आपस में उसकी निंदा करते हैं। जो व्यक्ति सौम्य स्वभावी होता है, सभी उससे जुड़ना चाहते हैं एवं उसे ही अपने पास बैठना चाहते हैं। कोधी व्यक्ति को जब कोच आता है, तब आंखें लाल हो जाती है, होंठ कपकपाने लग जाते हैं एवं वह बोलना कुछ चाहता है, शब्द मुख से कुछ और निकलता है। एक वैज्ञानिक ने कोच व्यक्ति का खून इंजेक्शन में लेकर एक चूहे के लगा दिया, तो यह चूहा कुछ समय बाद तड़पकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसलिए कोध हर प्रकार से बुरा होता है।
आज वर्तमान में सामाजिक जो भी समस्याएं हैं, एक देश का दूसरे देश से वैर विरोध है, वह सभी हल अहिंसा और क्षमा के द्वारा ढूंढे जा सकते हैं। यह क्षमावाणी पर्व हमें यही संदेश देता है।

**- प्रतिष्ठाचार्य विजय जैन
भगवान महावीर जन्मभूमि कुण्डलपुर, महामंत्री तीर्थंकर ऋषभदेव जैन**

https://t.me/AllNewsPaperPaid

मेष राशि-आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आज रूका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। आज आप समाजिक कार्यों में सहयोग देने की सोचेंगे। आज परिस्थितियों को ठीक से देखेंगे तो हर एक समस्या को हल कर पाएंगे। जिन लोगों की संगत में आप नकारात्मक बन रहे हैं, फिलहाल उन लोगों से दूरियां बनाने का विचार करेंगे। किसी जरूरी काम से की गई यात्रा सुखद रहेगी।

वृष राशि-आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज ऑफिस में सहयोगी आपके विचारों से प्रभावित होंगे, लेकिन दूसरों के कामों में दखल देने से आपको बचना चाहिए। आज अपने काम को आसान तरीके से करने का रास्ता मिल सकता है। नई योजना पर काम शुरू हो सकता है। परिवार की जिम्मेदारी सही तरीके से निभाएंगे, जिससे प्रसन्नता बनी रहेगी। पैसों से संबंधित चिंता दूर होगी।

मिथुन राशि-आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपका कोई रुका काम पूरा होने से मानसिक शांति मिलेगी। आप काम करने के नए तरीको पर विचार करेंगे। आज आपको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज अपनी इच्छा शक्ति के बल पर योजनाओं पर काम कर पाएंगे। जो बातें आपको बेहतर बनाती हैं, केवल उन पर ध्यान दें और खुद को सुधारें।

कर्क राशि-आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। अचानक हुये धन लाभ से आज अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे। दाम्पत्य जीवन में और मधुरता आएगी। आज गलत विचारों को दूर करके खुद में सुधार करेंगे और गलत संगत से बचेंगे। आज क्रोध को नियंत्रित करने की कोशिश करें। स्वभाव की नकारात्मक बातों को सुधारने की कोशिश करें। काम की जगह नए अवसर मिलेंगे। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल होगी।

सिंह राशि-आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज कार्यक्षेत्र में आपके सहकर्मी और सीनियर आपकी परफॉरमेंस से खुश रहेंगे और आपकी तारीफ करेंगें। आज काम के हिसाब से फल मिलेंगे। जिस बड़े लक्ष्य को पूरा करने की इच्छा है, उससे संबंधित रास्ता मिलेगा। आपके काम पर अंतिम परिणाम निर्भर करेगा। समय का सही इस्तेमाल करके काम पूरा करें। आज सभी जरूरी काम आसानी से पूरा कर लेंगे।

कन्या राशि-आज का दिन आपके लिए नयी उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपकी आर्थिक स्थित मजबूत बनी रहेगी आप सामान की खरीददारी करने मार्केट जा सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का समय अनुकूल है मेहनत के अच्छे परिणाम आपको हासिल होंगे। आज शाम को किसी मित्र की बर्थडे पार्टी में जायेंगे जहाँ आपके अन्य दोस्त भी होंगे। ऑफिस में किसी काम को लेकर थोड़ा विचार-विमर्श करना पड़ सकता है, शत्रु पक्ष आपकी योजनाओं से प्रभावित होंगे।

तुला राशि-आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आपका विनम्र स्वभाव साराहा जाएगा। आपका धन कहां खर्च हो रहा है, इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आज आपको बेकार की उलझन लेने की जरूरत नहीं है।

वृश्चिक राशि-आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज आपके मकान, प्लॉट, दुकान को खरीदने की इच्छा पूरी होगी। संतान को अच्छी नौकरी मिलने से माता-पिता काफी खुश नजर आएंगे। आपको काफी समय से चल रही किसी स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आज किसी भी व्यक्ति के लिए प्रतिशोध की भावना न रखें। जैसी आपकी सोच रहेगी, वैसे ही अनुभव मिलेंगे। अपनी नकारात्मकता के कारण किसी भी व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार न हो, इस बात का ध्यान रखें। आज आपको जिद से बचना होगा।

धनु राशि-आज का दिन आपके अनुकूल रहने वाला है। आज का दिन तरक्की के नये मार्ग खोलेगा। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस बनाए रखें, जल्द ही आपको परीक्षा में सफलता हासिल होगी। प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों को आज प्रमोशन मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मांगलिक उत्सव में सम्मिलित हो सकते हैं।

मकर राशि-आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। आज आप खुद को बदली हुई भूमिका में महसूस करेंगे। पैसों का उपयोग सही तरीके से करेंगे। जीवन में संतुलन बनाए रखेंगे और कुछ बातों में बदलाव होने में समय लगेगा। आज किसी कामों को सही तरीके से पूरा करने की कोशिश करें। आपको अपने पद और आय को एक समान या बढ़ाने के अवसर प्राप्त होंगे। जीवन में खुशियों की प्राप्ती होगी।

कुंभ राशि-आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज व्यापार में अच्छा लाभ मिलने से उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना आज पूरा होगा। आज आप किसी से अपने मन की बातों को शेयर करेंगे और वह आपकी बातों को अहमियत देंगे। परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे।

मीन राशि-आज का दिन जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। आज आप अपना ध्यान किसी रचनात्मक कार्य में लगायेंगे जिससे आपका अनुभव और अधिक बढ़ेगा। कुछ लोग आपके काम में रूकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपना स्वभाव सुधारना होगा। किसी को उधार देने से पहले सोच-विचार करेंगे।

शब्द सामर्थ्य -178

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. संघर्ष, दौड़धूप (उर्दू.) 5. सुपुत्र, लायक पुत्र 7. ताकतवर, बलशाली 9. खुशबू, सुरभि, सुगंध 10. अकारण, व्यर्थ, बेवजह 12. गर्म तेल आदि में खाद्य वस्तु छोड़कर पकाना 13. यात्रा 15. मृत, जो मर गया हो 16. छोटे कद का, वामन, बौना 18. सांप का सिर, गुण, कला, कौशल 20. निरुत्तर, बेमिसाल 23. गोल हरे दानों वाला एक प्रसिद्ध पौधा, या इस पौधे की फली 24.माता, जननी 25. संतान, औलाद 26. अधीन, अधीनस्थ, कर्मचारी 27. चिड़िया, खग तरफदार।

ऊपर से नीचे

1.पानी में डूबा हुआ, जल प्लावित 2. पाकेटमार, जेब काटने वाला 3. समाधान, खेत जोतने का यंत्र 4. औषधालय 6. युक्ति, उपाय 8. गीला, तर, भीगा हुआ 11. झटके से मुंह से आवाज के साथ हवा बाहर आना, बलगम आदि का बाहर आना 14. तुरंत, झटपट 15. स्त्री, नारी, अबला 17. एक और एक चौथाई 19. आदमखोर 21. दुनिया, संसार, जग 22. वर्ष की छः ऋतुओं में एक ऋतु जिसमें मौसम सुहावना रहता है 23. बुद्धि, दिमाग।

1		2	3	4	■	5		6
	■	7			8	■	■	
9			■	10		11	■	
		12				13	14	
	15					16		
			17				18	19
	20	21		22		23		
24				25				
	26						27	

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 177 का हल

पी	चि	दं	ब	र	म	■	■	स
ट	■	भ	ला	ई	■	अ	स	म
ना	म	■	■	स	मा	धि	■	झ
■	ज	■	बे	■	न	का	र	ना
बा	बू	■	आ	य	क	र	■	■
■	र	की	ब	■	■	■	प्र	था
ज	■	■	रू	प	क	■	ज	न
हा	■	पा	■	ना	म	ची	न	■
ज	हां	प	ना	ह	■	ता	न	ना

सूडोकु नवताल- 7189

★★★★☆ मध्यम

	8	1				2	5	
2								9
5			1		7	4		
9	5			4			2	
		3	9		6	7		
	7			8			1	5
		7	2		5			1
6								7
	1	5				6	9	

Jagrutidaur.com, Bangalore

- प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरे जाने आवश्यक हैं.
- प्रत्येक आड़ी और खड़ी पंक्ति में एवं 3×3 के वर्ग में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका विशेष ध्यान रखें.
- पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते.
- पहेली का केवल एक ही हल है.

सूडोकु नवताल -7188 का हल

5	9	4	2	3	6	1	8	7
8	7	3	1	4	5	2	9	6
6	1	2	8	7	9	3	5	4
1	6	7	9	8	2	4	3	5
3	8	5	4	1	7	6	2	9
2	4	9	6	5	3	7	1	8
7	5	6	3	9	1	8	4	2
4	2	1	5	6	8	9	7	3
9	3	8	7	2	4	5	6	1

संपादकीय

केजरीवाल को जमानत

कई महीने जेल में गुजारने के बाद आखिरकार आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल ही गई। लेकिन हरियाणा विधानसभा चुनाव से महज कुछ हफ्ते पहले हुई इस रिहाई की राजनीतिक चश्मे से अलग-अलग व्याख्या की जा रही है। भले ही फैसले से आप ने राहत की सांस ली हो, लेकिन जमानत के विरोध को लेकर सीबीआई की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठे हैं। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी द्वारा दर्ज मामले में यह जमानत दी है। हालांकि, अब केजरीवाल हरियाणा में चुनाव लड़ रहे आप उम्मीदवारों के लिये प्रचार करने के लिये स्वतंत्र हैं, लेकिन वे इस मामले के गुण-दोष को लेकर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। साथ ही सामान्य रूप से वे मुख्यमंत्री के रूप में अपने दायित्वों का भी पालन नहीं कर सकेंगे। बहरहाल, इन सीमाओं और शर्तों के बावजूद उनकी पार्टी राहत की सांस ले सकती है। निस्संदेह, रिहाई से हरियाणा में पार्टी के उम्मीदवारों का मनोबल बढ़ेगा। रिहा होने के बाद केजरीवाल ने कहा भी है कि जेल से आने के बाद मैं सौ गुना ताकतवर महसूस कर रहा हूं। वहीं सीबीआई के लिये यह असहज करने वाली स्थिति है कि मामले की सुनवाई कर रही बेंच के एक न्यायाधीश ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने में सीबीआई द्वारा बाधा डालने की बात कही है। वैसे जमीनी हकीकत यह भी है कि इस मुकदमे के निकट भविष्य में निबटने की संभावना कम ही है। बहरहाल, शीर्ष अदालत ने केजरीवाल की रिहाई के आदेश देकर संवैधानिक और कानूनी रूप से सही कदम उठाया है। सार्वजनिक विमर्श में भी यह बात उठती रही है कि एक मुख्यमंत्री व एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता को सामान्य अपराधी की तरह ज्यादा समय तक जेल में नहीं रखा जाना चाहिए। अदालत ने कुछ समय पहले इस मुद्दे को लेकर अपनी राय प्रकट की थी। वहीं दूसरी ओर अदालत ने इस आशंका को भी खारिज किया कि रिहाई के बाद मुख्यमंत्री सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। बहरहाल, इसके बावजूद केजरीवाल न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में हैं। वहीं सवाल सीबीआई की कार्यशैली व विश्वसनीयता को लेकर भी उठे हैं। वैसे भी यदि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत थे तो उसे जमानत को लेकर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। जिसके चलते विपक्ष को सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के रूप में कार्रवाई करने के आरोप लगाने का मौका मिला। बहरहाल, केजरीवाल की रिहाई के बाद दिल्ली कांग्रेस प्रमुख की तीखी प्रतिक्रिया से कयास लगाये जा सकते हैं कि इस फैसले का असर हरियाणा चुनाव पर पड़ सकता है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि राज्य की जनता में सत्ता विरोधी आक्रोश का जो पूरा लाभ अब तक कांग्रेस को मिलने के आसार थे, उसमें केजरीवाल की सक्रियता से असर पड़ सकता है। एक तो हरियाणा केजरीवाल का गृह राज्य है और दूसरी ओर राज्य में स्टार प्रचारक के रूप में केजरीवाल की सक्रियता आप का जनाधार बढ़ा सकती है। इससे कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ेगा और वे पार्टी प्रत्याशियों को सफल बनाने की कवायद में भी जुट सकते हैं। जिससे भाजपा विरोधी वोटों का बंटवारा हो सकता है। जाहिरा तौर पर हरियाणा में कांग्रेस जिस बड़ी कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठी थी, उसके ताजा घटनाक्रम से प्रभावित होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के साथ सहमति न बनने के कारण आप राज्य की सभी सीटों पर ताल ठोक रही है। यह भी कि 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद केजरीवाल को कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान जमानत दी थी। उन्हें 26 जून को फिर से सीबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से वे जेल में ही थे। जमानत पर पांच सितंबर को सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

पुलिस के आते ही सारा माजरा साफ हो गया मुन्नी ने पुलिस को बताया किस तरह सड़क पर खेलते हुए सोनू को ऑटो में खींच लिया गया था और वह किस तरह ऑटो से लटक कर बचाव के लिए शोर मचाती रही थी,जिसको सुनकर लोगों द्वारा ऑटो रिक्शा का पीछा कर अपराधी को पकड़ लिया और सोनू तथा मुन्नी को घर तक पहुंचाया था। शीला आश्चर्य से मुन्नी का बयान सुन रही थी और सोच रही थी जिसे मैं आज तक असंस्कारी समझती रही और अभी मनहूस कह कर मानसिक प्रताड़ना दे रही थी भला बुरा कह रही थी

शीला सोनू को मुन्नी के साथ आंगन में खेलते हुए देखकर जोर से चिल्लाई ÷सोनू तुम्हें कई बार कहां है,इस मुन्नी के साथ मत खेला करो कितना गंदा रहती है बच्ची,साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती खबरदार जो आगे मुझे खेलते दिखी पिटाई कर दूंगी तुम्हारी।÷ मां की डांट सुनकर सोनू सहम गई। मुन्नी बाई की बेटी है,सर्वेंट क्वार्टर में रहती है,बाप पियक्कड़ है,घर का माहौल बिगड़ा हुआ है। इसलिए शीला सोनू को मुन्नी से दूर रखना चाहती है। सोनू ने बचने के लिए यूं ही कह दिया ÷मम्मी मैं नहीं बुलाती उसे वही जबरदस्ती आ जाती है।÷ शीला सोनू को खींचते हुए घर के अंदर ले गई और दरवाजा बंद कर दिया। मां का यह बर्ताव ना सोनू को भाया ना मुन्नी को परंतु दोनों सहम गई थी। मुन्नी भी अपने घर चली गई, परंतु उसके बाल मन में कई सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे,छोटी उम्र होने के बावजूद भी उसे अमीरी गरीबी का फर्क समझ में आने लगा था। दूसरे दिन सुबह होते ही सोनू आंगन में खेलने आ गई सोनू ने मुन्नी को आवाज़ लगाई ÷ मुन्नी जल्दी आ हम लुका छुप्पी खेलते हैं। सोनू शीला के कल के बर्ताव से घबराई हुई थी वह बोली ÷नहीं सोनू तुम मेरे साथ मत खेलो चाची तुम्हें डांटेगी÷ परंतु सोनू ने एक न सुनी मुस्कुराते हुए मुन्नी का हाथ

पकड़ कर खींच लाई बोली ÷अरे थोड़ी देर खेलते हैं,मम्मी अभी नहा रही है। वह अभी नहीं डांटेगी÷ सुनकर मुन्नी भी निश्चित हो गई और दोनों सखियां लुका छुप्पी खेलने लगी खेलने में इतनी मगन हो गई दोनों को समय का पता ही नहीं चला। तभी अचानक शीला सोनू को ढूंढते हुए बाहर चली आई दोनों को साथ में खेलते देख आग बबूला हो गई कर्कश स्वर मे चिल्ला कर बोली ÷सोनू तुम नहीं मानोगी न कल से तुम्हारा बाहर खेलना ही बंद करा देती हूं।÷ मुन्नी तो शीला को देखकर घबरा ही गई और अपने घर की ओर भाग गई इधर सोनू भी डर के मारे कांपने लगी सोनू बोली ÷सॉरी मम्मी अब नहीं खेलूंगी कभी मुन्नी के साथ÷ शीला बोली÷बेटा मैं तुम्हारे भले का बोल रही हूं मुन्नी कितना गंदा रहती है। उसके साथ खेल कर तुम बीमार हो जाओगी वह ना पढ़ती लिखती है,ना रहन-सहन ही अच्छा है। घर का माहौल भी उसके ठीक नहीं है,ऐसे बच्चों के साथ रहने से अच्छे संस्कार नहीं मिला करते इसलिए मैं तुम्हें मुन्नी के साथ खेलने से मना करती हूं लाडो।÷ सुनकर सोनू को बहुत बुरा लगा उसका बाल मन यह स्वीकारने को तैयार नहीं था की मुन्नी उससे कुछ अलग है। उसे अमीरी गरीबी का फर्क,अच्छे बुरे का फर्क अभी नहीं पता इसलिए मां की बातें उसे नहीं सुहाती और वह चोरी छिपे मुन्नी के साथ जरूर खेलती,अपने खिलौने,किताबें भी उसे दे देती मां से छुपा कर।

आज स्कूल की छुट्टी का दिन रविवार था,सोनू के पापा सुशील बाजार सामान लेने गए थे,छुट्टी होने से मां भी घर के साफ सफाई के काम में व्यस्त थी। सोनू मौका देखकर खेलने बाहर निकल गई और मुन्नी को साथ खेलने बुला लाई थी,सोनू घर के सामने सड़क पर खेल रही थी,कि एक ऑटो रिक्शा सोनू के पास आकर रुका और उसमे बैठे एक व्यक्ति ने सोनू को ऑटो में खींच कर जबरदस्ती बैठा लिया और ऑटो स्टार्ट करके भागने लगे, मुन्नी यह देखकर घबरा गई और शोर मचाते हुए उस ऑटो के पीछे दौड़कर ऑटो को पड़कर लटक गई वह दूर तक घसीटते चली गई परंतु छोड़ती ना चिल्लाना बंद करती।ऑटो में बैठा व्यक्ति एक हाथ से सोनू को पकड़े था और एक हाथ से मुन्नी को नीचे गिरने की कोशिश कर रहा था। उसके हाथ पर वह मार रहा था ताकि ऑटो को छोड़ दे परंतु मुन्नी यथावत लटकी रही। मुन्नी का चिल्लाना सुनकर राह चलते कुछ राहगीर ऑटो का पीछा करने लगे और आगे जाकर ऑटो को जबरदस्ती रोक लिया मुन्नी की हालत बहुत खराब थी। दोनों पैरों से खून रीस रहा था,क्योंकि वह सड़क से घिस गए थे मुन्नी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी परंतु अपनी सखी सोनू को बचाने की खातिर वह ऑटो से लटकी रही, शोर भी मचती रही इसी कारण राहगीरों का ध्यान ऑटो रिक्शा की ओर गया और वह आटो रिक्शा वाले को रोकने में सफल हो पाये और सोनू को बचाने में कामयाब हो पाए थे। लोगों ने मुन्नी और सोनू को घर पहुंचाया,किसी ने शीला को आवाज़ लगाई और किसी ने पुलिस को फोन कर बुलाया तभी शीला बाहर आई बाहर का दृश्य देखकर वह बदहवास सी सोनू की और दौड़ी ÷क्या हुआ मेरी बेटी को सोनू क्या हुआ बेटा बोलो इस लड़की ने तुम्हारे साथ क्या किया है, बताओ बेटा बताओ,इसलिए मैं तुम्हें इस लड़की के साथ खेलने मना करती थी छोटे लोग कभी अपनी औकात दिखाना नहीं छोड़ते ना ÷ वह सोनू को झंझोड़ कर पूछते रही मगर सोनू इतनी घबरा गई थी उसके मुंह से एक बोल भी ना फूट रहा था। अब तक सुशील भी घर पहुंच गया था और वह भी मुन्नी को ही खरी-खोटी सुनाते रहा वास्तव में चोट तो मुन्नी को आई थी,परंतु शीला और सुशील का ध्यान बस अपनी बेटी पर था। उसने मुन्नी के खून सने पैरों को एक नजर भी नहीं देखा बस उसे कोसती रही बोली ÷मनहूस कहीं की, दिखा दी ना अपनी औकात ÷ राहगीरों की भीड़ ने ऑटो रिक्शा वाले और सोनू को अपहरण करने वाले व्यक्ति को पकड़ रखा था और पुलिस को भी बुला लिया था। सभी राहगीर मुन्नी की बहादुरी पर मुन्नी को सराह रहे थे,मुन्नी को शाबाशी दे रहे थे।

पुलिस के आते ही सारा माजरा साफ हो गया मुन्नी ने पुलिस को बताया किस तरह सड़क पर खेलते हुए सोनू को ऑटो में खींच लिया गया था और वह किस तरह ऑटो से लटक कर बचाव के लिए शोर मचाती रही थी,जिसको सुनकर लोगों द्वारा ऑटो रिक्शा का पीछा कर अपराधी को पकड़ लिया और सोनू तथा मुन्नी को घर तक पहुंचाया था। शीला आश्चर्य से मुन्नी का बयान सुन रही थी और सोच रही थी जिसे मैं आज तक असंस्कारी समझती रही और अभी अभी मनहूस कह कर मानसिक प्रताड़ना दे रही थी भला बुरा कह रही थी,आखिर उसी लड़की के बहादुरी से सोनू सही सलामत है,वरना कितनी बड़ी मुसीबत में हम सब होते सोचकर वह कांप गई। अब तक मुन्नी के माता-पिता भी आ गए वे लोग मुन्नी को ही डांटने लगे मुन्नी की मां बोली ÷इसी मनहूस ने सोनू को मुसीबत में डाला होगा मैडम जी यह है ही ऐसी शैतान कहीं की÷ कह कर गाल पर एक चांटा जड़ दिया,मुन्नी और बिलख बिलख कर रोने लगी। शीला को उनकी बातें सुनकर लगा जैसे किसी ने कानों में पिघला सीसा उंडेल दिया हो। उसे लगा उसके शब्द लौट लौट कर कानों के पर्दे फाड़ रहे हो। वह शर्मिंदगी से मुन्नी तथा उसके माता-पिता से नजरे नहीं मिल पा रही थी सोच रही थी जिस जुबान से मुन्नी को इतना भला बुरा कहा उसी जुबान से उसका शुक्रिया कैसे अदा करूं,उसने दौड़कर मुन्नी को गले लगा लिया बार बार क्षमा याचना करती रही,आंखों से बहते आंसुओं की धार से मन का मैल धुल गया था,अब तक शर्मिंदगी और आंसुओं ने अमीरी,गरीबी की खाई को भर दिया था,अमीरी गरीबी का निस्वार्थ,सरल मन का कोई संबंध नही होता वह समझ चुकी है,आज वह निशब्द हो गई।

(रचना -मौलिक)
प्रस्तुति- चित्रा धोटे

आज का इतिहास

- नेपोलियन के नेतृत्व में 1812 को फ्रांसीसी सेना मास्को के क्रैमलिन पहुंची।
- प्योंगयांग की लड़ाई में 1894 को जापान ने चीन को करारी मात दी।
- प्रथम विश्व युद्ध में 1916 को पहली बार सोम्मे की लड़ाई में टैंक का इस्तेमाल किया गया।
- गांधी-इरविन समझौता 1931 हुआ।
- द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान ब्रिटेन की वायुसेना ने 1940 में दावा किया कि इसने हिटलर की जर्मन वायुसेना को शिकस्त दे दी है।
- स्वतंत्र भारत का पहला ध्वजपोत आईएनएस 1948 में दिल्ली बंबई (अब मुंबई) के बंदरगाह पर पहुंचा।
- रूसी नेता निकिता ख्रुश्चेव 1959 में अमेरिका की यात्रा करने वाले सोवियत संघ के पहले नेता बने।
- भारत की राष्ट्रीय प्रसारण सेवा दूरदर्शन की शुरुआत 1959 में हुई।
- हरी-भरी और शांति पूर्ण दुनिया के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में की गई।
- वानुअतु संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1981 में बना।
- लेबनान के निर्वाचित राष्ट्रपति बशीर गेमायेल की पदासीन होने के पूर्व ही 1982 को बम बिस्फोट में हत्या।
- सिडनी में 27वें ओलम्पिक खेलों का शुभारम्भ 2000 में हुआ।
- अमेरिकी सीनेट ने 2001 में राष्ट्रपति को अफ़ग़ानिस्तान पर सैनिक कार्यवाही की मंजूरी दी।
- न्यूयार्क में 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के अवसर पर भारत, चीन एवं रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित, थाईलैंड के सट्टाहिम में श्रीलंका सरकार व लिट्टे के बीच सीधी वार्ता शुरू।
- सिंगापुर के मुद्दे पर 2003 में विकासशील देशों के भड़क उठने से डब्ल्यूटीओ वार्ता विफल।
- ब्रिटिश नागरिक गुरिंदर चड्ढा को 2004 में 'वूमैन आफ़ द ईयर' सम्मान।
- क्राम्पटन गीब्स ने 2008 में अमेरिका की एमएसआई ग्रुप कंपनी का अधिग्रहण किया।
- अमरीका के सबसे बड़े बैंकों में से एक लीमैन ब्रदर्स ने 2008 में अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। यह अब तक की अमरीकी इतिहास कि दिवालिया होने की सबसे बड़ी घटना थी।
- बंगलूर के मुंदिर शिवराजी ने 2009 में सब जूनियर बिलियर्ड्स का ख़िताब जीता। पेनसुला फाउंडेशन के चेयरमैन सुब्रतो चटोपाध्याय 2009-10 के लिए 'आडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन' के अध्यक्ष चुने गये।
- कासीनी अंतरिक्ष यान 2017 में शनि के उपग्रह टाइटन से टकरा गया।
- फ़ारसी विद्वान् लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ तथा विचारक अलबेरूनी का जन्म 973 को हुआ था।
- इंजीनियर, वैज्ञानिक और निर्माता मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्म 1861 को हुआ था।
- बंगाली उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म भी आज ही दिन 17 सितम्बर 1876 को हुआ था।
- हरक्यूल पॉयरॉट, मिस मार्पल और पार्क पाइन जैसे जासूसी किरदारों में जान डालने वाली अगाथा क्रिस्?टी का जन्?म 1890 में हुआ था।
- भारत प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार डॉ. रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 को हुआ था।

राजनीति के साथ दिलों को जीतने का हुनर

समय से पहले चले जाने वाली किसी असाधारण शख्सियत पर लिखना वास्तव में बहुत कठिन होता है। पांच दशकों तक सक्रिय राजनीतिक जीवन में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय धरातल पर अपनी छाप छोड़ने वाले सीताराम येचुरी केवल 72 वर्ष के ही थे। 12 सितंबर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से उनकी दुखद मृत्यु की खबर बड़े झटके जैसी थी। देश भर से शोक व्यक्त करने हेतु लोगों द्वारा सीताराम येचुरी के साथ जिस तरह से अपने अपने फोटो पोस्ट किये जा रहे हैं वह पुष्टि करता है कि वे जहां भी गए वहीं दिलों पर अपनेपन की छाप छोड़ आए।

इन पंक्तियों के लेखक के उनसे समकालीन साथी के तौर पर 50 वर्ष सरोकार रहे। सीताराम येचुरी जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। साल 1975 में आपातकाल का विरोध करने पर दोनों गिरफ्तार हुए। पार्टी की जिम्मेदारियों के चलते साथ काम करने की लंबी अवधि गुजरी।

सीताराम येचुरी बहुप्रतिभावान व्यक्तित्व थे। उत्कृष्ट वामपंथी नेता, प्रखर विचारक, संवैधानिक बारीकियों के ज्ञाता थे। राज्य सभा में अपने बेहतरीन योगदान के लिए 2017 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद के पुरस्कार से नवाजा गया। कम्युनिस्टों की जो कट्टरता वाली परंपरागत छवि गढ़ कर बनाई जाती है उसको बदलते हुए एक असल उदारतावादी और मानवीय सरोकारों वाली पहचान स्थापित करने का श्रेय उन्हें अवश्य जाता है। बता दें कम्युनिस्टों को धर्म के विरुद्ध बताकर विभिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले लोगों के बीच उनकी छवि अकसर कट्टरवादी के रूप में गढ़ी जाती रही।

येचुरी ने बीते दिनों अपने संबोधन में धर्म और राजनीति के बीच आवश्यक दूरी को जरूरी बताया था। उनके मुताबिक, 'धर्म और राजनीति के बीच में एक रेखा होती है। उसे लक्ष्मण रेखा माना जाना चाहिए। यदि उसका उलंघन होता है तो वह न केवल राजनीति बल्कि धर्म के लिए भी हानिकारक है। वे आगे कहते हैं कि धर्म हर व्यक्ति का निजी मामला होता है। धर्म आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। किस व्यक्ति का परमात्मा कौन है वह केवल उस व्यक्ति की आत्मा जानती है। आत्मा और परमात्मा के बीच में किसी का हस्तक्षेप स्वीकार्य नहीं।'

कम्युनिस्ट होते हुए रामायण व महाभारत जैसे भारतीय पौराणिक ग्रंथों के लोकप्रिय संदर्भों को निकाल कर उन्हें समकालीन परिस्थितियों के साथ जोड़ कर प्रासंगिक बनाने

में सीताराम येचुरी को महारत हासिल थी। भारतीय संविधान की बुनियादी प्रस्थापनाओं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर की गई समीक्षाओं को आधार बनाकर मौजूदा संदर्भों में व्याख्या करने के मामले में सीताराम येचुरी को संसद के भीतर और बाहर कोई हल्के में नहीं ले सकता था। राज्य सभा में जनतंत्र, आर्थिक स्थिति, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय संप्रभुता, केन्द्र-राज्य संबंधों के स्वरूप और एक स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर उनके भाषण आने वाले चुनौतीपूर्ण दौर में धरोहर से कम नहीं।

सीताराम येचुरी की शख्सियत की तीसरी खासियत यह थी कि वे राजनीतिक दलों के बीच तालमेल बिठाने के एक ऐसे शिल्पकार थे जिसकी स्वीकार्यता सर्वमान्य रही। हाल की जटिलतम राजनीतिक परिस्थितियों में विभिन्न विचारधाराओं वाले दलों को साथ लाकर इंडिया गठबंधन की स्थापना करने जैसे कठिन काम को अंजाम देने में सीताराम येचुरी की भूमिका निर्णायक मानी जाती है। वैचारिक स्पष्टता और वचनबद्धता उनमें ऐसे गुण थे जिनकी बदौलत उन्हें अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच एक विश्वसनीयता प्राप्त थी। प्रकाश करात और सीताराम येचुरी उस नई पीढ़ी के नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के पुरोधा ईएमएस नंबूदरीपाद, ज्योति बसु, हरकिशन सिंह सुरजीत सरीखे कद्दावर नेताओं से जिम्मेदारी धारण करने का साहस दिखाया और इस दायित्व को बखूबी निभाया भी। कम्युनिस्ट पार्टियों में ऐसा इसलिए संभव हो पाता है कि ये पार्टियां सामूहिक कार्यपद्धति से संचालित होती हैं। हिंदी व अंग्रेजी में एक समान दक्षता से लिखने व बोलने वाले सीताराम येचुरी तेलुगू भाषी परिवार में पैदा हुए थे। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में वह लोकप्रिय वक्ता के रूप में जाने जाते थे। अर्थशास्त्र के विषय में उन्होंने स्नातक व स्नातकोत्तर की डिग्री बतौर टॉपर सेंट स्टीफंस कॉलेज से की और जेएनयू में पीएचडी में प्रवेश लिया। छात्र संघ के अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भारत के छात्र फेडरेशन के अध्यक्ष और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय कमेटी और पोलित ब्यूरो के सदस्य रहते हुए गत दस साल से अब तक पार्टी के महासचिव रहे।

एक जिंदादिल इंसान, काबिल विद्वान,देश की एकता और उसके इंसानों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ताउम्र सक्रिय रहने वाले राजनेता सीताराम अलविदा!

ममता बनर्जी की दुविधा !

ममता दी प. बंगाल की जमीन से उठी नेता मानी जाती हैं और जनसंघर्ष के रास्ते से वह मुख्यमन्त्री की कुर्सी तक पहुंची है। अतः उनकी राजनीति समझना भी आसान काम नहीं माना जाता। ममता जानती हैं कि उनके राज्य में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं और कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा के साथ पिछले दिनों बहुत ही जघन्य परिस्थितियों में ऐसी घटना हुई जिसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई।

प. बंगाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल ने जो रुख अख्तियार किया है उससे दुखी होकर राज्य की मुख्यमन्त्री सुश्री ममता बनर्जी ने अपना पद तक छोड़ने की इच्छा व्यक्त की है। पिछले लगभग एक महीने से राज्य के सभी अस्पतालों के जूनियर डाक्टर अपनी एक साथी के साथ बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या हो जाने की घटना पर उत्तेजित हैं और न्याय किये जाने की मांग कर रहे हैं। ममता दी की सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं के साथ बलात्कार व हत्या की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष कानून भी बनाया जिसमें बलात्कारी को फांसी की सजा दिये जाने का प्रावधान है। यह विधेयक बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया परन्तु राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए अग्रसरित कर दिया। डॉक्टरों की हड़ताल के मुद्दे पर राज्य में जमकर राजनीति भी हो रही है और विपक्षी पार्टी भाजपा इस मामले में मुख्यमन्त्री का इस्तीफा चाहती है। समझा जाता है कि हड़ताली डॉक्टरों के एक गुट को भी भाजपा का समर्थन प्राप्त है। हड़ताली डॉक्टरों का मामला सर्वोच्च न्यायालय में है और इसने डॉक्टरों को निर्देश दिया था कि वे अपनी हड़ताल समाप्त करके काम पर लौटें। इसके लिए न्यायालय ने एक अन्तिम समय भी दिया था मगर हड़ताली डॉक्टरों ने उस पर अमल नहीं किया। इस वजह से राज्य की समस्त स्वास्थ्य सेवाएं विपरीत रूप से प्रभावित हो रही हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ममता दी ने हड़ताली डाक्टरों से वार्ता का प्रस्ताव रखा था। उनके इस प्रस्ताव को भी डॉक्टरों ने निरस्त कर दिया। ममता दी अपनी सरकार की साख रखने के लिए डॉक्टरों से बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकालना चाहती थीं और हड़ताल समाप्त कराना चाहती थीं परन्तु डॉक्टरों के कड़े रुख की वजह से यह भी संभव नहीं हो सका। राज्य सरकार ने बीते कल के सायंकाल तक का समय डॉक्टरों को दिया था कि उनके प्रतिनिधि बातचीत करने के लिए सरकार द्वारा नियत स्थान पर पहुंचें परन्तु उन्होंने इस वार्ता प्रस्ताव का भी बहिष्कार किया और बातचीत करने कोई नहीं पहुंचा। ममता दी ने हड़ताली डॉक्टरों के प्रतिनिधियों का अन्तिम क्षण तक इन्तजार किया मगर वे वार्ता स्थल तक पहुंचने पर ये नारे लगाने लगे कि उन्हें न्याय नहीं बल्कि ममता बनर्जी का इस्तीफा चाहिए। ममता बनर्जी ने इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को सम्बोधित किया और घोषणा की कि वह डॉक्टरों की समस्या न सुलझा पाने के लिए राज्य के लोगों से माफी मांगती है और इस्तीफा देने को तैयार है। उन्हें पद का मोह नहीं है। ममता दी प. बंगाल की जमीन से उठी नेता मानी जाती हैं और जनसंघर्ष के रास्ते से वह मुख्यमन्त्री की कुर्सी तक पहुंची है। अतः उनकी राजनीति समझना भी आसान काम नहीं माना जाता। ममता जानती हैं कि उनके राज्य में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं और कोलकाता के आर जी कर मेडिकल कॉलेज की पोस्ट ग्रेजुएट छात्रा के साथ पिछले दिनों बहुत ही जघन्य परिस्थितियों में ऐसी घटना हुई जिसके बाद उसकी हत्या भी कर दी गई। अतः इस मुद्दे पर पहले कोलकाता के जूनियर डॉक्टर उत्तेजित हुए और बाद में पूरे राज्य में उनका आन्दोलन फैल गया। डॉक्टरों की तरफ से विपक्षी पार्टी भाजपा ने भी जमकर पैरवी की। अतः ममता दी के लिए डॉक्टरों का आन्दोलन दुधारी तलवार बन गया। एक तरफ राजनैतिक मोर्चे पर वह अकेली पड़ती गई और दूसरी तरफ आम नागरिकों की सहानुभूति भी डॉक्टरों के साथ होती चली गई। परन्तु इसका मतलब यह नहीं होता है कि प. बंगाल के राज्यपाल श्री सी.वी. आनंदबोस यह कहने लगे कि वह मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी का सामाजिक बहिष्कार करेंगे। उनका ऐसा कथन पूरी तरह संविधान विरोधी व राज्यपाल के पद की गरिमा के विरुद्ध है। श्री बोस यह कह रहे हैं कि वह अब ऐसे किसी भी समारोह में नहीं जायेंगे जिसमें मुख्यमन्त्री शामिल होंगी। श्री बोस दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ममता दी जनता की भावनाओं को समझने में असफल रही हैं अतः उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया है। श्री बोस शायद भूल रहे हैं कि ममता दी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग दो-तिहाई बहुमत मिला था।

बीते एक महीने के दौरान चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत की यह तीसरी उच्च स्तरीय बैठक थी। इससे पहले कजाखिस्तान के अस्ताना में और फिर लाओस के विएनियाना में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की उनसे मुलाकात हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग में एलएसी तनाव घटाने पर एनएसए डोभाल और वांग यी की बातचीत के बीच ही एक अहम बयान विदेश मंत्री जयशंकर का भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि लद्दाख में आमने-सामने की मोर्चाबंदी को करीब 75 प्रतिशत तक सुलझा लिया गया है।

भारत-चीन 'जटिल' रिश्ते

2020 में पैंगोंग झील क्षेत्र में भारत और चीन के जवानों में हिंसक झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध पैदा हो गया था, जो अब तक कायम है। गतिरोध सुलझाने के लिए कोर कमांडर स्तर की वार्ताओं के दौर जारी हैं लेकिन अभी तक गतिरोध को पूरी तरह सुलझाया नहीं जा सका है। 2013 में देपसांग, 2014 में चुमार, 2017 में डोकलाम, 2020 में गलवान और 2022 में तवांग में हुई सैन्य झड़पों को दोनों देशों की रणनीतिक वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है। दोनों देशों के संबंधों का विश्लेषण किया जाए तो संबंधों में उतार-चढ़ाव हमेशा आता-जाता रहा है। दोनों देशों का व्यापार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके बावजूद दोनों को एक-दूसरे पर भरोसा नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विश्व व्यवस्था के दो बड़े राष्ट्र सीमा ि?ववाद के कारण?आपस में उलझे हुए हैं। भारत और चीन दोनों ने लगभग एक साथ साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाई। भारत ने सच्चे अर्थों में लोकतंत्र के मूल्यों को अपनाया, तो वहीं चीन ने छद्म लोकतंत्र को अपनाया।

भारत-चीन संबंधों की इस गाथा में कई स्याह मोड़ आए। हिन्दी-चीनी भाई-भाई के नारे से लेकर 1962 के भारत-चीन युद्ध से होते हुए दोनों देशों के संबंध उस दौर में हैं कि भारत और चीन विभिन्न मंचों पर एक-दूसरे की मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों पक्ष गलवान घाटी पैंगोंग झील, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा से अपने सैनिक पीछे हटाने पर सहमत हुए हैं। भारत चाहता है कि चीन की सेनाएं देपसांग और डैमचौक से हटकर पूर्व की स्थिति को बहाल करें। भारत लगातार स्पष्ट?करता आ रहा है कि सीमाओं पर स्थिति असामान्य रहते दोनों देशों के संबंध सामान्य नहीं हो सकते। पिछले कुछ महीनों से चीन की सेना के पूर्वी लद्दाख में हथियार और ईंधन के भंडारण के ि?लए बंकर बनाने की रिपोर्टें और वहां सैन्य बेस और सुरंगे बनाने की ि?रपोर्टें आती रही हैं। पैंगोंग झील के पास सिरजैप में चीनी सैनिकों का बेस है। इस बेस में बख्तरबंद गाड़ियों की आवाजाही भी देखी गई। कई एजैंसियों ने उपग्रह तस्वीरों से पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन की बढ़ती गतिविधियों की तस्वीरें भी जारी की थीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि चीन ने सीमा पर बुनियादी ढांचे का विकास किया है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के सेंट पिटसबर्ग में चीन के विदेश?मंत्री वांग यी से मुलाकात की? और सीमा गतिरोध को हल करने के ि?लए बातचीत की। दोनों पक्षों ने तय किया कि सीमा पर सैन्य तनाव जल्द कम करने और आमने-सामने की मोर्चाबंदी खत्म करने के प्रयास दोगुने किए जाएंगे।

बीते एक महीने के दौरान चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत की यह तीसरी उच्च स्तरीय बैठक थी। इससे पहले कजाखिस्तान के अस्ताना में और फिर लाओस के विएनियाना में विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर की उनसे मुलाकात हुई थी। सेंट पीटर्सबर्ग में एलएसी तनाव घटाने पर एनएसए डोभाल और वांग यी की बातचीत के बीच ही एक अहम बयान विदेश मंत्री जयशंकर का भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि लद्दाख में आमने-सामने की मोर्चाबंदी को करीब 75 प्रतिशत तक सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार जारी बातचीत और प्रयासों से हालात को सामान्य बनाने की कोशिशें चल रही हैं। जानकारों के मुताबिक ताजा भारत-चीन वार्ताओं सिलसिला रूस के कजान में 22-24 अक्तूबर, 2024 को होने वाली ब्रिक्स शिखर बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति की मुलाकात की जमीन तैयार करना है। दोनों नेता ब्रिक्स शिखर बैठक के लिए रूस में होंगे और अगर चीनी सेना एलएसी पर अप्रैल 2020 की स्थिति में लौट जाती है तो यह तनाव कम सीमा तनाव का पारा कम करेगा।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा ि?क यद्यपि दोनों देशों ने कुछ प्रगति की है लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बड़ा मुद्दा यह है कि इस समय दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो सीमा पर सैन्यीकरण ही हो रहा है। झड़पों के बाद रिश्ते प्रभावित हुए हैं। सीमा पर ि?हंसा हो तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि दोनों देशों के बाकी रिश्ते इससे अलग हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

प्रार्थना के अभ्यास से क्या परमात्मा मिला ?

-आत्माराम यादव पीव वरिष्ठ पत्रकार

जन्म के समय हर बच्चा निश्छल आकाश की अनंत गहराइयाँ लिए महाशून्य होता है, जिसमे सारा ब्रह्माण्ड मृत्यु तक व्याप्त होता है। माँ कि कोख से वह जैसे ही इस धरा पर पहला कदम रख विश्वदर्शन करते ही रुदन करना शुरू करता है, वह सुंदर सा बच्चा अपनी आँखों कि भवों को सिकोड़ते हुये कमरे का अंदर बाहर, खिड़की दरवाजे के पास खड़ा करने कमरे का बाहर हमारे पूवार्नुमानों कि शक्ल में होंठों को खोल मुसकुराता है, तब से लेकर उसकी अंतिम सांस लेने तक उसके बाल सुलभ चेहरे कि मासूम बनावट में परमात्मा के दर्शन के साथ उसकी आयु के बढ़ते क्रम में शैतान तक कि छवि पाते है। हम माता पिता बहन भाई या किसी भी करीबी रिश्ते कि शक्ल में नौनिहाल शिशु को संस्कारों कि घूटी पिलाते हुये उसके उज्जवल भविष्य को तय कर उसका हर पल विकास के साथ उसे सभी ओर से विजयी देखने की आकांक्षा लिए होते है । यह बात मैं अपने लिए नहीं अपितु इस धरा पर जन्म लेने वाले हर उस शिशु की बात कर रहा हूँ जो किसी भी देश, समाज, वर्ग में जन्मने के बाद अभ्यास के साँचे में भाषायी परिमाप में प्रवेश कराने हेतु प्रत्येक घर परिवार में घटित होती है ओर उसके भविष्य का जाल बुनते लोग उसकी मांस थैलीयों में रूढ़ियों का कालारक्त भर उनके विकास का उज्जवल ताना बाना बुन रहे होते है।

घर परिवार में जन्म लिए बच्चे को ममता के झूले में झूलते, घुटनों के बल चलते, अपने पैरों पर खड़ा होकर गिरते उठते उसकी धमनियों में कुछ अर्थहीन आकार के शब्दो के सम्बोधन की थपथपाहट के बीच शब्दों का अर्थ न समझते हुये किसी समझदार की तरह उसके मुस्कुराने पर हमारी खुशी का पैमाना उबाल मारने लगता है ओर हम एक योग्य शिक्षक समझ अपनी प्रतिभा का खुद लोहा मनवाने के लिए परिवार के दूसरे सदस्य को उलाहने देना शुरू कर देते है कि उनका शिशु उनके अभ्यास से कितना योग्य हो गया है। असल बात यह भी है कि - जो भी तुम स्वयं में स्थित होने के लिए करते हो, वही अभ्यास कहलाता है ओर यह अभ्यास एक बच्चे को कुशलतापूर्वक करते देख हम द्दष्टा बन जाते है। बच्चे के साथ जन्म से लेकर उसके किशोर होने, युवा होने, पुरुष होने सहित वृद्धावस्था तक यह अभ्यास चलता ही रहता है जो कभी समाप्त नही हो है । जन्मने वाले हर प्राणी के जन्म ओर मृत्यु के बीच जीवन की अविरल धारा प्रवाहित है ओर जीने के लिए इस जगत से साक्षात्कार आवश्यक है। जगत के साक्षात्कार से पहले उस बच्चे की निर्दोष आँखों में जो भी द्दश्यमान होगा वह उसके लिए विस्मयकारी होगा, जो भी शब्द वह सुनेगा वह शब्द उसे आश्चर्य करेगा। जन्म के बाद प्रत्येक शिशु को प्रतिदिन अभ्यास कराया जाता है कि उसका फलां नाम है ओर घर में जो रिश्ते के सदस्य है उसका परिचय का अभ्यास उसे जानने समझने तक जारी रहता है। सदियों से वेद पुराणों में ऋषि मुनियों कि गाई हुई प्रार्थनाओं के बलबूते हम बिना प्रयास ही परमात्मा को पाने कि परिपाटी में शामिल है इसलिए हमारे हाथ खाली है। जन्म के बाद मृत्यु तक हम जीवन में प्रवेश तो करते है किन्तु होश में नही होते है, एक खुमारी है जो हमें यंत्रवत यह सभी करा रही होती है। हम सुबह शाम प्रभु से प्रार्थना करते भक्त बन अपनी भावुकता को सामने रखे भक्ति कि शुरूआत करते है जिसमें जप, तप ओर योग हमारी अनुरक्ति का साध्य भी बंता है तो कभी साधन भी बन जाता है । शब्दों में खुद को घोर पापी, कामी, दुराचारी आदि का प्रयोग कर प्रभु कि शरण में नतमस्तक होते अपने गुनाह कि माफी मांगकर क्षमाप्रार्थना करते है। जब भी वह उधार की प्रार्थना करता है, दूसरों की प्रार्थना के बासे गीत आरतियों का उच्चारण करता है तो वह सब उथले होते है, ऊपर मन से भी दूर के भाव होते है, जिनका उसकी आत्मा से कोई संबंध या सरोकार नही होता तब वे प्रार्थना भी निरर्थक साबित होती है, प्रार्थना वे ही स्वीकार होती है जो प्राणों से उद्भूत हो ।

जीवन में किसने संकट नहीं देखा, किसने कठिनाइयाँ नहीं झेली, किसने विभिन्न रोग शोक का सामना नहीं किया, किसने सफलता-सफलता नहीं चखी, किसने लाभ-हानि , हर्ष-विषाद व सुख दुख नहीं देखा है, अगर मनुष्य का जीवन मिला है तो यह सब उसके संगी साथी रहे है। कोई न कोई जीवन में डर से भयभीत मिल जाएगा, निराशा से घबराता हुआ, विघ्न बाधाओं के चक्रव्यूह में फंसा हुआ मिलेगा तो कोई इसके विपरीत आनंद में डूबा हुआ प्रसन्नचित्त मुसकुराता हुआ मिल जाएगा, यानी मनुष्य जीवन में सुख ओर दुख उसके साथ आँख मिचौली करते है यह बात खुद में प्रमाणित है। जिस प्रकार जीवन में सुख दुख है उसी प्रकार प्रकाश ओर अंधकार है , धूप छाँह है ओर वे लोग अपने जीवन में परमात्मा को सदैव स्मरण करते हुये उसकी शरण में होते है वे सुख के साथ मन में शांति प्राप्त कर निश्चिंत बना रहता है जबकि जो परमात्मा को सदैव उलाहना देकर उन्हे भूल चुका होता है वह जीवन में अंधकार पक्ष की चपेट में होता है ओर दुख की अधीरता के कारण परमात्मा को कई प्रकार के तर्क कुतर्क करता है। जिन्हे बचपन से प्रार्थना का अभ्यास कराया जाता है वह अभ्यास अगर उसकी आदत हो जाये तो यह अच्छी आदत में जीवन का सकारात्मक उसकी लगन बन जाती है ओर नकारात्मकता उससे दूर हो जाती है। वेद, पुराण, शास्त्र ओर उपनिषद के ऋषियों के मंत्र ओर प्रार्थना के बार बार अभ्यास से प्राप्त ऊर्जा मन को तरंगित रख काम में मन लगाए रखती है ओर वह धीरे धीरे आपका स्वभाव बन जाती है ओर स्वभाव पूजा पाठ ,जाप आदि संस्कारों से मन को रमाए रखता है ओर जिसका मन इसमे रमा होता है वह जीवन में उन्नति ओर सुख शांति की अपार संपदा पा जाता है फिर उसके मन में कोई भी अभिलाषा शेष नहीं होती है। जो खुद को परमात्मा पर समर्पित कर सौंप देता है उसके मनोरथ ओर उसका भविष्य भी परमात्मा के हाथों होता है, जो परमात्मा की भक्ति को अपना कर्तव्य समझता है, परमात्मा उनकी सारी प्रार्थनाएं, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते है। प्रार्थनाए परमात्मा की प्रकृति बन जाती है ओर प्रार्थना करने वाला आनंद में खो जाता है, इसलिए जिन्होने प्रार्थना का अभ्यास बचपन से किया है वे आनंद में होते है, मैंने बालभारती स्कूल में बच्चों को संस्कारित हो प्रार्थना करते देखा है ओर उनके जीवन में बचपन की प्रार्थना के अभ्यास को उनकी आदत बनते ओर उस आदत की लत में प्राप्त संस्कारों में डूबकर प्रार्थना करने ओर भोजन के समय किए गए मंत्रोपचार की स्तुति आदि देखा है जो बच्चों में एक वरदान के रूप में सहज ही प्राप्त हुई है। बचपन में बच्चों को संस्कारित यह प्रार्थना उनके बाल सुलभ मन में परमात्मा से नित्य कल्याण की कामना करते देखना ओर बच्चों को अपने भविष्यमुख आगे बढ़ते देखना कितना आनंदप्रद होता है, उस सुख को मैं बिना प्रार्थना किए आभास करता आ रहा हूँ। बच्चो को प्राप्त यह सद्गुण उन्हे अपने आप में धैर्यवान ओर प्रार्थना के प्रति द्दढ़विश्वासी बनाए हुये है, भले वे त्रिसंध्या पाठ न करे किन्तु जब भी उन्हे समय मिलता है वे नित्यकर्म के बाद स्नानादी से निर्वृत हो अपनी प्रार्थना के अभ्यास में रमे रहते है भले उन्हे परमात्मा की प्राप्ति नही हुई किन्तु परमात्मा के करीब रहने का सुअवसर वे कभी भी खोना नहीं चाहते है,उस जैसे सभी की आदत बन जाये यही प्रार्थना में सभी के लिए करता हूँ।

घुटती सांसों से कम होती औसत आयु की चिन्ता

-ललित गर्ग

वायु प्रदूषण का संकट भारत की राष्ट्रव्यापी समस्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की हाल ही में जारी रिपोर्ट इस चिन्ता को बढ़ाती है जिसमें कहा गया कि वायु प्रदूषण के चलते भारत में जीवन प्रत्याशा में गिरावट आ रही है। जिसमें फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले पी.एम. 2.5 कण की बड़ी भूमिका है। रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक मानकों से कहीं अधिक प्रदूषण भारत में लोगों की औसत आयु तीन से पांच वर्ष एवं दिल्ली में दस से बाहर वर्ष कम कर रहा है। बहरहाल प्रदूषण के खिलाफ योजनाबद्ध ढंग से मुहिम छेड़ने की जरूरत है। अध्ययन कहता है कि देश की एक अरब से अधिक आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जहां प्रदूषण डब्ल्यूएचओ के मानकों से कहीं अधिक है। दरअसल, देश के बड़े शहर आबादी के बोझ से त्रस्त हैं। बढ़ती आबादी के लिये रोजगार बढ़ाने व अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो औद्योगिक इकाइयां लगायी गई, उनकी भी प्रदूषण बढ़ाने में भूमिका रही है। डीजल-पेट्रोल के निजी वाहनों को बढ़ता काफिला, निर्माण कार्यों में लापरवाही, कचरे का निस्तारण न होना और जीवाश्म ईंधन ने प्रदूषण बढ़ाया है। यह बढता वायु प्रदूषण हमारी जीवन शैली से उपजे प्रदूषण की देन भी है।

यह निराशाजनक खबरों के बीच उत्साहवर्धक खबर यह भी है कि भारत में सूक्ष्म कणों से पैदा होने वाले जानलेवा प्रदूषण में गिरावट आई है। लेकिन अभी जीवन प्रत्याशा घटाने वाले प्रदूषण को लेकर जारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ह्यवायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक-2024ह्न बताती है कि भारत में साल 2021 की तुलना में 2022 के वायु प्रदूषण में 19.3 फीसदी की कमी आई है। हालांकि, यह उपलब्धि मौजूदा हालात में बहुत बड़ी तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन यह बात उत्साहवर्धक है कि प्रत्येक भारतीय की जीवन प्रत्याशा में इक्यावन दिन की वृद्धि हुई है। हालांकि, हम अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन एक विश्वास जगा है कि युद्ध स्तर पर प्रयासों से भयावह प्रदूषण के खिलाफ किसी हद तक जंग जीती भी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही सूचकांक-2024 में यह चेताया भी है कि यदि भारत में डब्ल्यूएचओ के वार्षिक पीएम 2.5 के सांद्रता मानक के लक्ष्य पूरे नहीं होते तो भारतीयों की जीवन प्रत्याशा में करीब साढ़े तीन साल की कमी आने की आशंका पैदा हो सकती है। पीएम 2.5 श्वसन प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर सकता है और सांस संबंधी समस्याओं को जन्म देता है। यह स्वास्थ्य को एक बड़ा खतरा है और वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है।

हालांकि, राजधानी समेत कई अन्य राज्यों में मेट्रो ट्रेन शुरू होने के बाद प्रदूषण में काफी कमी आई है। इस दिशा में हमें दीर्घकालीन नीतियों के बारे में सोचना होगा। हमारी कोशिश हो कि घनी आबादी के बीच चलायी जा रही औद्योगिक इकाइयों को शहरों से दूर स्थापित किया जाए। हमारे उद्यमियों को भी जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रदूषण नियंत्रण में योगदान देना चाहिए। नीति-नियंताओं को सोचना चाहिए कि प्रदूषण में अप्रत्याशित वृद्धि के बाद दिल्ली आदि महानगरों में चलाये जाने वाले ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप जैसी व्यवस्था को नियमित रूप से लागू क्यों नहीं किया जा सकता? ताजा कुछ अध्ययनों में बताया गया है कि बढ़ता प्रदूषण नवजात शिशुओं तथा बच्चों की जीवन प्रत्याशा पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में हमें पराली के निस्तारण, औद्योगिक कचरे के नियमन तथा कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन पर रोक लगाने जैसे फौरी उपाय तुरंत करने चाहिए। ऐसे तमाम प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने की जरूरत है जो हमारे जीवन पर संकट पैदा कर रहे हैं।

अध्ययन कहता है कि भारत के सबसे कम प्रदूषित शहर भी डब्ल्यूएचओ के निर्धारित मानकों से सात गुना अधिक प्रदूषित हैं। हम न भूलें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की गिनती लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में होती रही है। दीवाली के बाद जब दिल्ली गहरे प्रदूषण के आगोश में होती है तो कोर्ट से लेकर सरकार तक अति सक्रियता दशार्ते हैं। लेकिन थोड़ी स्थिति सामान्य होने पर परिणाम वही ह्यढाक के तीन पातह्न। कभी पेट्रोल-डीजल के नये मानक तय होते हैं तो कभी जीवाश्म ईंधन पर रोक लगती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2019 में प्रदूषण कम करने को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम देश के सौ से अधिक शहरों में शुरू किया था। चार साल बाद पता चला कि किसी भी शहर ने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया। विकासशील देश पहले ही निर्धारित वायु गुणवत्ता के मानक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वहीं डब्ल्यूएचओ ने मानकों को और कठोर बना दिया है। सभी सरकारों व नागरिकों का दायित्व बनता है कि अपने-अपने स्तर पर प्रदूषण को कम करने वाली जीवन शैली अपनाएं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया में सत्तर लाख मौतें हर साल प्रदूषित वायु के चलते हो रही हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक के अनुसार हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 के वार्षिक स्तर की सुरक्षित सीमा क्रमशः चालीस माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और साठ माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए। हालांकि, ये मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानकों से कहीं ज्यादा हैं। दरअसल, हमारे नीति-नियंता प्रदूषण कम करने के लिये नागरिकों को जागरूक करने में भी विफल रहे हैं। हमारी सुख-सुविधा की लालसा एवं भौतिकतावादी जीवनशैली की चमक ने भी वायु प्रदूषण बढ़ाया है। अब चाहे गाहे-बगाहे होने वाली आतिशबाजी हो, प्रतिबंध के बावजूद पराली जलाना हो, या फिर सार्वजनिक परिवहन सेवा से परहेज हो, तमाम कारण प्रदूषण बढ़ाने वाले हैं। कल्पना कीजिए बच्चों और दमा, एलर्जी व अन्य सांस के रोगों से जूझने वाले लोगों पर इस प्रदूषण का कितना घातक असर होगा?

रिपोर्ट में उल्लेखित प्रदूषण में आई गिरावट की वजह अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां बतायी गई हैं। हालांकि, हकीकत यह भी है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिये चलायी जा रही कई योजनाओं के सकारात्मक परिणामों का भी इसमें योगदान रहा है। खासकर भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जिन शहरों को शामिल किया गया था, वहां भी पीएम-2.5 सांद्रता में गिरावट देखी गई है। वहीं स्वच्छ ईंधन कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव प्रदूषण नियंत्रण पर नजर आया है। इससे भारत के रिहाइशी इलाकों में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिली है। ऐसी योजनाओं को पूरे देश में लागू करने का सुझाव भी दिया गया है। बहरहाल, हमें वर्ष 2022 के उत्साहजनक परिणामों के सामने आने के बाद व्यापक लक्ष्यों के प्रति उदासीन नहीं होना है। यह एक लंबी लड़ाई है और इसमें सरकार व समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि सरकारों के भरोसे ही लगातार गहराते पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है।

निश्चित ही वायु प्रदूषण से उत्पन्न दमघोटू माहौल का संकट जीवन का संकट बनता जा रहा हैं। वायु प्रदूषण का ऐसा विकराल जाल है जिसमें मनुष्य सहित सारे जीव-जंतु फंसकर छटपटा रहे हैं, जीवन सांसों पर छाये संकट से जूझ रहे हैं। यह समस्या साल-दर-साल गंभीर होती जा रही है। सरकारें अनेक लुभावने तर्क एवं तथ्य देकर समस्या को कमतर दिखाने की कोशिशें करती है। लेकिन हकीकत यही है कि लोगों का दम घुट रहा है। अगर वे सचमुच इससे पार पाने को लेकर गंभीर हैं, तो वह व्यावहारिक धरातल पर दिखना चाहिए। प्रश्न है कि पिछले कुछ सालों से लगातार इस महासंकट से जूझ रहे राष्ट्र को कोई समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती? वास्तव में यह विभिन्न राज्य सरकारों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, जिसने सबको जहरीले वायुमंडल में रहने को विवश किया है। इस विषम एवं ज्वलंत समस्या से मुक्ति के लिये हर राजनीतिक दल एवं सरकारों को संवेदनशील एवं अन्तर्दृष्टि-सम्पन्न बनना होगा। प्रदूषण से ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा जैसे एक नन्हा-सा दीपक गहन अंधेरे से लड़ता है। छोटी औकात, पर अंधेरे को पास नहीं आने देता। क्षण-क्षण अग्नि-परीक्षा देता है। पर हां! अग्नि परीक्षा से कोई अपने शरीर पर फूस लपेट कर नहीं निकल सकता।

हिंदीः राजभाषा, राष्ट्रभाषा और विश्वभाषा

एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। यह विश्व में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, जो हमारे पारंपरिक ज्ञान, प्राचीन सभ्यता और आधुनिक प्रगति के बीच एक सेतु भी है। हिंदी भारत संघ की राजभाषा होने के साथ ही ग्यारह राज्यों और तीन संघ शासित क्षेत्रों की भी प्रमुख राजभाषा है। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य इक्कीस भाषाओं के साथ हिंदी का एक विशेष स्थान है। आज देश में तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के साथ-साथ अंग्रेजी पूरे देश पर हावी होती जा रही है। देश की राजभाषा हिंदी होने के बावजूद आज हर जगह अंग्रेजी का वर्चस्व कायम है। हिंदी जानते हुए भी लोग हिंदी में बोलने, पढ़ने या काम करने में हिचकने लगे हैं। इसलिए भारत सरकार का प्रयास है कि हिंदी के प्रचलन के लिए उचित माहौल तैयार किया जा सके। राजभाषा हिंदी के विकास के लिए खासतौर से भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग का गठन किया गया है। भारत सरकार का राजभाषा विभाग इस दिशा में प्रयासरत है कि केंद्र सरकार के अधीन कार्यालयों में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में हो।

केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करना अधिक आसान एवं सुविधाजनक हो गया है। राजभाषा विभाग द्वारा वेब आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गई है, जिससे भारत सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्टें राजभाषा विभाग को त्वरित गति से भिजवाना आसान हो गया है। सभी मंत्रालयों और विभागों ने अपनी वेबसाइटें हिंदी में भी तैयार कर ली हैं। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा संचालित जन कल्याण की विभिन्न योजनाओं की जानकारी आम नागरिकों को हिंदी में मिलने से गरीब, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग भी लाभान्वित होते हुए देश की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।

देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक हिंदी ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। भारत सरकार द्वारा विकास योजनाओं तथा नागरिक सेवाएं प्रदान करने में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदी तथा प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से हम बेहतर जन सुविधाएं लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय द्वारा ह्यविश्व हिंदी सम्मेलन और अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के माध्यम से हिंदी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय बनाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जिसमें विश्व भर में रहने वाले प्रवासी भारतीय भाग लेते हैं। विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की उपलब्धियों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम से भारतीय मूल्यों का विश्व में और अधिक विस्तार हो रहा है। विश्वभर में करोड़ों की संख्या में भारतीय समुदाय के लोग एक संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को एक नई पहचान मिली है। हिंदी भारतीय विचार और संस्कृति का वाहक होने का श्रेय हिंदी को ही जाता है। आज संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में भी हिंदी की गूंज सुनाई देने लगी है।

हिंदी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। सभी भारतीय भाषाओं की बड़ी बहन होने के नाते हिंदी विभिन्न भाषाओं के उपयोगी और प्रचलित शब्दों को अपने में समाहित करके सही मायनों में भारत की संपर्क भाषा होने की भूमिका निभा रही है। हिंदी जन-आंदोलनों की भी भाषा रही है। हिंदी के महत्त्व को गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था, भारतीय भाषाएं नदियां हैं और हिंदी महानदी। हिंदी के इसी महत्व को देखते हुए तकनीकी कंपनियां इस भाषा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही हैं। यह खुशी की बात है कि सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। आज वैश्वीकरण के दौर में, हिंदी विश्व स्तर पर एक प्रभावशाली भाषा बनकर उभरी है। आज पूरी दुनिया में 260 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है। ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकें बड़े पैमाने पर हिंदी में लिखी जा रही हैं। सोशल मीडिया और संचार माध्यमों में हिंदी का प्रयोग निरंतर बढ़ रहा है। भाषा का विकास उसके साहित्य पर निर्भर करता है। आज के तकनीकी के युग में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी हिंदी में काम को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि देश की प्रगति में ग्रामीण जनसंख्या सहित सबकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इसके लिए यह अनिवार्य है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी ज्ञान से संबंधित साहित्य का सरल अनुवाद किया जाए। इसके लिए राजभाषा विभाग ने सरल हिंदी शब्दावली भी तैयार की है। राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन योजना के द्वारा हिंदी में ज्ञान-विज्ञान की पुस्तकों के लेखन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे हमारे विद्यार्थियों को ज्ञान-विज्ञान संबंधी पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध होंगी। हिंदी भाषा के माध्यम से शिक्षित युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकें, इस दिशा में निरंतर प्रयास भी जरूरी है। भाषा वही जीवित रहती है, जिसका प्रयोग जनता करती है। भारत में लोगों के बीच संवाद का सबसे बेहतर माध्यम हिंदी है। इसलिए इसको एक-दूसरे में प्रचारित करना चाहिए। हिंदी भाषा के प्रसार से पूरे देश में एकता की भावना और मजबूत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के माध्यम से हम हिंदी के संपर्क भाषा और राजभाषा, दोनों रूपों की तरक्की में बेहतर योगदान कर पाएंगे।

- प्रो. (डॉ.) संजय द्विवेदी

लादेन को मारने वाली अमरीकी नेवी सील चीन को टक्कर देगी

गुप्त अमरीकी नौसेना कमांडो इकाई सील टीम 6,जिसने 2011 में ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था, चीन द्वारा ताईवान पर आक्रमण किए जाने की स्थिति में उसकी मदद करने के लिए मिशनों के लिए प्रशिक्षण ले रही है, यह जानकारी तैयारियों से परिचित लोगों ने दी है। नौसेना के विशेष बलों की यह विशिष्ट टीम, जिसे सेना के कुछ सबसे संवेदनशील और कठिन मिशनों का काम सौंपा गया है, वाशिंगटन से लगभग 250 कि.मी. दक्षिण-पूर्व में वर्जीनिया बीच पर स्थित अपने मुख्यालय डैम नेक में एक वर्ष से अधिक समय से ताईवान संघर्ष की योजना बना रही है और प्रशिक्षण ले रही है।

यह गुप्त प्रशिक्षण चीन को ताईवान पर हमला करने से रोकने पर अमरीका के बढ़ते फोकस को रेखांकित करता है, साथ ही ऐसी घटना के लिए तैयारियों को भी आगे बढ़ाता है। उस समय यू.एस. इंडो-पैसिफिक कमांडर फिल डेविडसन द्वारा 2021 में चेतावनी दिए जाने के बाद से तैयारियां और भी बढ़ गई हैं कि चीन 6 साल के भीतर ताईवान पर हमला कर सकता है। जबकि अमरीकी अधिकारी इस बात पर जोर देते हैं कि चीन के साथ संघर्ष ह्यन तो आसान है और न ही अपरिहार्य। अमरीकी सेना ने आकस्मिक तैयारियों को तेज कर दिया है क्योंकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आदेश को पूरा करने के लिए तेजी से आधुनिकीकरण कर रही है क्योंकि उसके पास 2027 तक ताईवान पर बलपूर्वक कब्जा करने की क्षमता है। अमरीकी सेना में सबसे कुलीन सेना के प्रसिद्ध डेल्टा फोर्स के साथ सील टीम 6 एक टियर वन बल है। यह संयुक्त विशेष संचालन कमान को रिपोर्ट करता है, जो विशेष संचालन कमान का हिस्सा है।

इस इकाई ने 2009 में सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा बंधक बनाए गए मेर्सक अलबामा कंटेनर जहाज के कप्तान रिचर्ड फिलिप्स को बचाया था, जिसने सैन्य इतिहास में अपनी जगह पक्की करने में मदद की है। पेंटागन ने हाल के वर्षों में ताईवान में नियमित रूप से विशेष बल भेजे हैं, जिसमें ताईवान की सेना को प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है। सील टीम 6 की गतिविधियां बहुत अधिक संवेदनशील हैं क्योंकि इसके गुप्त मिशन अत्यधिक गोपनीय हैं। टीम की योजना से परिचित लोगों ने मिशनों के बारे में विवरण नहीं दिया। स्पैशल ऑपरेशंस कमांड, जो सील टीम 6 के बारे में शायद ही कभी चर्चा करती है, ने ताईवान की अपनी योजना के बारे में पेंटागन को प्रश्न भेजे, जिसने विशिष्ट विवरणों पर टिप्पणी नहीं की। एक प्रवक्ता ने कहा कि रक्षा विभाग और उसके बल विभिन्न प्रकार की आकस्मिकताओं के लिए तैयारी और प्रशिक्षण करते हैं। जैसे-जैसे आतंकी समूहों से खतरा कम होता गया, विशेष अभियान बल बाकी अमरीकी सेना और खुफिया समुदाय के साथ मिलकर चीन पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। सी.आई.ए. निदेशक बिल बर्न्स ने पिछले सप्ताह बताया कि उनके बजट का 20 प्रतिशत चीन को समर्पित है, जो पिछले 3 वर्षों में 200 प्रतिशत की वृद्धि है। ज्वाइंट स्पैशल ऑपरेशंस कमांड पर एक किताब रिलें टलेस स्ट्राइक के लेखक सीन नायलर ने कहा, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सील टीम 6 संभावित ताईवान से संबंधित मिशनों की योजना बना रही है। वे एक ऑनलाइन राष्ट्रीय सुरक्षा प्रकाशन, द हाई साइड चलाते हैं। नायलर ने आगे कहा, पिछले कुछ वर्षों में पेंटागन के महाशक्ति प्रतिस्पर्धा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुनर्निर्देशन के साथ, यह अपरिहार्य था कि देश की सबसे कुलीन आतंकवाद विरोधी इकाइयां भी उस क्षेत्र में भूमिकाएं तलाशेंगी, क्योंकि यह मार्ग प्रासंगिकता, मिशन और धन की ओर ले जाता है। ताईवान अमरीका-चीन संबंधों में सबसे संवेदनशील मुद्दा है, और इस द्वीप पर तनाव पिछले एक साल में अमरीकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन और चीन के शीर्ष विदेश नीति अधिकारी वांग यी के बीच बैकचैनल चचाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जैसा कि अमरीकी और चीनी अधिकारियों ने बताया। चीन के खतरे के बढ़ने के साथ ताईवान के सैन्य अभ्यास गंभीर हो गए हैं। 2023 में हान कुआंग सैन्य अभ्यास के हिस्से के रूप में एक टैंक और बंदूकों के साथ ताईवान के सैनिक ताइपे के बंदरगाह से भागे थे। चीन का कहना है कि वह ताईवान के साथ शांतिपूर्ण पुनर्मिलन के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन उसने बल प्रयोग से इन्कार नहीं किया है। शी ने पिछले साल एक यूरोपीय अधिकारी से कहा था कि उनका मानना है कि वाशिंगटन चीन को युद्ध में उकसाने की कोशिश कर रहा है।

ताईवान संबंधी अधिनियम के तहत वाशिंगटन ताईवान को अपनी रक्षा प्रदान करने में मदद करने के लिए बाध्य है। अमरीका की लंबे समय से रणनीतिक अस्पष्टता की नीति रही है, जिसमें वह यह नहीं कहता है कि वह ताईवान की रक्षा के लिए आएगा या नहीं। लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कई मौकों पर कहा है कि चीन की ओर से बिना उकसावे के किए गए हमले के सामने अमरीकी सेना ताईवान की रक्षा करेगी। वाशिंगटन में चीनी दूतावास ने कहा कि ताईवान चीन के मूल हितों का मूल है और पहली लाल रेखा है जिसे चीन-अमरीका संबंधों में पार नहीं किया जाना चाहिए।

राजनीतिक दलों की आधी शक्ति, रूठों को मनाने में लग जाती है

दुर्भाग्य ही कहेंगे कि क्षेत्रीय दलों और राष्ट्रीय दलों को पराए दलों से लड़ने की बजाय अपनों को मनाने में अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। हाल ही में मैंने शिरोमणि अकाली दल (बादल) को बिखरते देखा, हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला को चौ. देवी लाल के परिवार और उसके द्वारा चलाए जा रहे राजनीतिक दल को तार-तार होते देखा। जम्मू-कश्मीर में भूतपूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पी.डी.पी. दल को महबूबा ने अपनी आंखों के सामने आपस में भिड़ते देखा, तमिलनाडु में द्रमुक के कई हिस्से हो गए। आप आपसी संघर्ष में उलझी हुई है, कांग्रेस जो आल इंडिया राजनीतिक दल है आंतरिक उलझनों से उलझ रहा है। 1977 में बनी जनता पार्टी आंतरिक विरोधों के कारण 1980 में ही टूट गई। जनता दल, लोकदल जाने कहां खो गए? सभी राजनीतिक दल अपनों से ही उलझ कर मर-खप रहे हैं। अंतर्कलह से कोई भी राजनीतिक दल मुक्त नहीं।

पार्टी विद-ए-डिफरैंस यानी अनुशासित दल भारतीय जनता पार्टी भी इस अंतर्कलह से अछूती नहीं है। यह बात हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनावों ने सिद्ध कर दिखाई। टिकट वितरण लिस्टों को बदलना पड़ा। सब दलों में एक अराजकता-सी फैली हुई है। यह अंतर्कलह किसी सिद्धांत के लिए नहीं अपितु अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण है। प्रत्येक नेता सत्ता के लिए लड़ रहा है। त्याग की भावना तो किसी राजनीतिक दल में दिखाई ही नहीं देती। सत्ता, निजी महत्व सब राजनेताओं पर हावी है। कुछ भी राजनीति में स्थिर नहीं। भागमभाग मची हुई है। चलो आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर ही एक बार बात करते हैं। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में भाजपा गुटों में बंटी दिखी। इसके कई नेता टिकट छिन जाने से मायूस और सोशल मीडिया में रोते दिखाई दिए। कई स्थानों पर मोदी भय ने अंतर्कलह को दबा दिया तो कहीं चाणक्य नीति की ललकार से ऐसे नेता डर गए। कई भाजपा नेता बलशाली थे उन्होंने दूसरी पार्टियों को अपना लिया। लोकतंत्र में गुटबंदी और अंतर्कलह राजनीतिक दलों के प्रभाव को कम करती जा रही है परन्तु ऐसा तो हर चुनाव में होगा ही। फिर भारतीय जनता पार्टी भला इस गुटबंदी से अछूत कैसे रह सकती है।

भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं बोली लगा रखी है। अपना दल छोड़ो इसके एवज में टिकट ले लो। भाजपा का वर्तमान में एक ही लक्ष्य है उम्मीदवार की विनएबिल्टी उसके लिए 20 अन्य योग्य, निष्ठावान, विश्वसनीय पुराने कार्यकत्रा की राजनीतिक बलि भी देनी पड़े तो भी भाजपा को चिंता नहीं। ऐसे में पार्टी के भीतर अंतर्कलह तो रहेगी ही न? चाहे थोड़े समय के लिए यह अंतर्कलह दब जाएं परन्तु कभी तो यह लावा फूटेगा ही? आज तो मोदी और अमित शाह का सिक्का चल रहा है। कल की राम जाने। हां, यह सत्य है कि टिकट वितरण के बाद अंतर्कलह उभरती तो जरूर है। मोदी-अमित शाह की जोड़ी की चुनाव संरचना ही ऐसी है कि हमें चुनाव जीतना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से भिन्न है। राजनीति में विशेष रुचि रखने वाले भली-भांति जानते हैं कि 1950-51 में जब जनसंघ का जन्म हुआ और फिर 1977 में जनसंघ का दीपक गुल कर जनता पार्टी में विलय कर दिया था और फिर एक नए राजनीतिक दल का गठन 1980 में कर लिया, तब से अब तक भारतीय जनता पार्टी में 4 ही नेता हमें दिखाई दिए।

अटल-अडवानी, मोदी-अमित शाह या अधिक हुआ तो पांचवां नेता मुरली मनोहर जोशी ही दिखाई दिए। छठा माई का लाल कोई ध्यान में ही नहीं आता। भाजपा व्यक्ति विशेष के लिए राजनीति नहीं करती अपितु ह्यकोलैटिव-लीडरशिप में विश्वास करती है। केवल नरेंद्र मोदी ही एक अपवाद हैं। संघ पीछे हटा तो अडवानी जी राजनीतिक वनवास में चले गए। मुरली मनोहर जोशी एक प्रख्यात प्रोफैसर थे अतः विवाद से बचे रहे परन्तु उन पर 75 साल का दंश लग गया। अतः आराम से बैठ गए। आज सिर्फ पार्टी में सर्वेसर्वा या मोदी है या अमित शाह। जनसंघ ने जिस जनता पार्टी के लिए अपना दीपक बुझा दिया उसी जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव पारित कर जनता पार्टी का कोई भी सांसद, कोई भी पदाधिकारी या विधायक राष्ट्रीय स्वयं संघ की कार्यविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता। अतः 1980 में जनसंघ जनता पार्टी से अलग हो गया। 5 अप्रैल, 1980 में जनसंघ ने दिल्ली में एक नई पार्टी के गठन पर विचार किया। नई बनी भारतीय जनता पार्टी में गैर जनसंघ के नेता भी शामिल हो गए। जैसे सिकंदर बख्त, शांति भूषण, राम जेठमलानी बढ़िया नेता।

6 अप्रैल 1980 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक भव्य और सफल सम्मेलन बंबई के बांद्रा में हुआ। इस अधिवेशन में पूर्व शिक्षा मंत्री मोहम्मद करीम छागला विशेष रूप से पधारे और इसी अधिवेशन में उन्होंने वाजपेयी जी को आने वाले प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। भाजपा अपने जन्म से लेकर 2014 तक हमेशा ह्यकिंग मेकरह्न की भूमिका में रही। 16 मई 1996 को पहली बार भाजपा सरकार बनी परन्तु मंत्रीपद प्राप्त करने के कारण गुटबंदी बनी रही। अगस्त 1996 में गुटबंदी के कारण गुजरात में पार्टी दो फाड़ हो गई। इस गुटबंदी के कारण यू.पी. में कल्याण सिंह के स्थान पर राम प्रकाश गुप्ता को चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ा। ऐसे में सोचो भाजपा गुटबंदी से अछूती कैसे रह सकती है।

- मोहन लाल(पूर्व परिवहन मंत्री, पंजाब)